भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

मई 2023

खंड 77 अंक 5

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
मुनिश कपूर
रेखा मिश्र
इन्द्रनील भट्टाचार्य
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
तुषार बरन दास
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2023

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **https://bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण
शक्तिकान्त दास 1

भारत के युग का उदय
माइकल देबब्रत पात्र 7

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 15

निर्यात समानता सूचकांकों के माध्यम से भारत की निर्यात क्षमता का पता लगाना 55

भारत की स्थिर साम्य मुद्रास्फीति: पुनर्मूल्यांकन 73

भारत और सीओपी-26 प्रतिबद्धताएं: खनन क्षेत्र के लिए चुनौतियां 89

अंतिम पड़ाव पर बुनियादी और डिजिटल वित्तीय साक्षरता:
ग्रामीण पश्चिम बंगाल की एक झलक 105

वर्तमान सांख्यिकी **119**

हाल के प्रकाशन **172**

भाषण

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण
शक्तिकान्त दास

भारत के युग का उदय
माइकल देबब्रत पात्र

*भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण**

शक्तिकान्त दास

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा वित्तीय लचीलापन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) की सराहना करता हूं। मैं पिछले दो वर्षों में सीओएस को उसकी उपलब्धियों के लिए भी बधाई देता हूं।

कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और वित्तीय क्षेत्र पर अमेरिका और यूरोप में हाल की बैंकिंग क्षेत्र की घटनाओं के समग्र प्रभाव के संदर्भ में, अब वित्तीय लचीलापन और स्थिरता के मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। दुनिया भर के विनियामक और सरकारें अब इन पहलुओं को अधिक तीव्रता के साथ देख रही हैं। मौजूदा विनियमों और पर्यवेक्षी प्रणालियों की पर्याप्तता का नए सिरे से मूल्यांकन किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय लचीलापन पर यह वैश्विक सम्मेलन बहुत उपयुक्त और समयोचित है।

किसी देश में वित्तीय क्षेत्र और उसमें व्यक्तिगत संस्थाओं, जैसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं, को हर समय लचीला रहना जरूरी है। उनके पास सबसे तनावपूर्ण समय का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। जहां तक भारत का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के संबंध में अपने विनियमों और पर्यवेक्षण को काफी मजबूत किया है। हमारा दृष्टिकोण लचीलेपन के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को बढ़ाने के लिए रहा है ताकि व्यक्तिगत संस्थाएं तनावपूर्ण परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान देना जारी रख सकें। आज अपने संबोधन में मैं भारतीय वित्तीय प्रणाली के हितधारकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में, केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करने का भी अधिकार है। बैंकों और अन्य वित्तीय बाजार की संस्थाओं को आपातकालीन चलनिधि सहायता प्रदान करने के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक अस्थिरता के संकेत मिलने पर बैंकों और वित्तीय बाज़ारों पर कड़ी नजर रखें। इसके अलावा, मौद्रिक नीति बड़े पैमाने पर बैंकों और वित्तीय बाजारों के माध्यम से लागू की जाती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का संचरण मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों के सुचारू संचालन के साथ-साथ बैंकों और एनबीएफसी जैसे वित्तीय मध्यस्थों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में केंद्रीय बैंकों के प्रमुख और पूरक कार्य, जैसे ब्याज दर तय करना, चलनिधि प्रबंधन, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों पर विनियमन और पर्यवेक्षण, अधिक आवश्यक हो जाते हैं। ये कार्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय संस्थानों के बीच जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

अब मैं विशेष रूप से 'लचीलापन' की अवधारणा की ओर मुड़ता हूं जो आज के सम्मेलन का विषय है। प्रणालीगत लचीलापन व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों के लचीलेपन के साथ-साथ उनके बीच परस्पर निर्भरता, दोनों पर आधारित है।

भविष्य के लिए लचीला रहने के लिए तैयार बैंक को वित्तीय, परिचालन और संगठनात्मक रूप से लचीला होना चाहिए। वित्तीय रूप से लचीला होने के लिए, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी बफर होना चाहिए और गंभीर समष्टि-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) झटकों के समय भी अर्जन उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त चलनिधि भी होनी चाहिए। इसलिए वित्तीय लचीलापन बैंक के व्यापार मॉडल और रणनीति से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से रिज़र्व बैंक ने बैंकों के कारोबारी मॉडल को ज्यादा

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा आयोजित *ग्लोबल कॉन्फरेंस ऑन फिनान्शियल रिज़िलियन्स* में दिया गया भाषण। - 27 अप्रैल 2023 - मुंबई

बारीकी से देखना शुरू किया है। व्यवसाय मॉडल का कोई पहलू या कमियां ही किसी समय संकट पैदा कर सकती हैं। हमने न केवल पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि अनुपात के लिए विनियामकीय मानदंड निर्धारित किए हैं, बल्कि बैंकों को अच्छे समय में और समय रहते पूंजी बफर बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। हमने कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा किया था जब बहुत अधिक चलनिधि उपलब्ध थी, ब्याज दरें कम थीं और वित्तीय क्षेत्र पर महामारी का पूरा प्रभाव अभी भी अत्यधिक अनिश्चित था।

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विवेकपूर्ण विनियामकीय ढांचे भी स्थापित किए हैं। इनमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आवश्यकताएं, लाभांश वितरण ढांचा और चलनिधि प्रबंधन ढांचा शामिल हैं। इसके अलावा रिज़र्व बैंक समय-समय पर प्रणालीगत स्तर पर निर्मित जोखिमों से निपटने के लिए समष्टि विवेकपूर्ण (मैक्रोप्रूडेंशियल) उपायों को भी लागू करता है। रिज़र्व बैंक और स्वयं बैंकों, दोनों, द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में देखी गई वित्तीय अस्थिरता का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। यह हमारे हालिया तनाव परीक्षण परिणामों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2022 के अंत में 4.41 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2022 को 5.8 प्रतिशत और 31 मार्च 2021 को 7.3 प्रतिशत था। दिसंबर 2022 के अंत में सीआरएआर 16.1 प्रतिशत था, जो न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से बहुत अधिक है। ऋण जोखिम संबंधी किए गए मैक्रो तनाव परीक्षण से संकेत मिलता है कि एससीबी गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होंगे।

फिर भी, अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग परिदृश्य में हाल की घटनाओं से पता चलता है कि बैंक के लिए जोखिम उसकी बैलेंस शीट के ऐसे खंडों से उत्पन्न हो सकता है जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया हो। इसलिए, हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल वित्तीय जोखिमों का लगातार आकलन करे और लचीलापन बनाए रखने और सतत संवृद्धि के लिए विनियामकीय न्यूनतम से परे भी पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर बनाने पर ध्यान केंद्रित करे।

अब मैं परिचालनिक लचीलेपन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परिचालनिक लचीलेपन का तात्पर्य यह है कि बैंक के समक्ष व्यवधान होने पर भी उसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक इस तरह के व्यवधानों का संबंध है, साइबर जोखिम और संभावित साइबर हमले ऐसी सूची में सबसे ऊपर हैं।

वित्तीय संस्थानों के वैश्विक सर्वेक्षण[1] के आधार पर 2023 के लिए शीर्ष दस परिचालन जोखिमों में साइबर जोखिम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने 2021 में परिचालन जोखिम के ठोस प्रबंधन के सिद्धांतों को संशोधित करते हुए इस जोखिम के महत्व को दर्शाते हुए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जोखिम प्रबंधन' पर एक विशिष्ट सिद्धांत पेश किया। मजबूत आईटी और सूचना सुरक्षा प्रशासन से पूर्वानुमान बढ़ाने और परिचालन में अनिश्चितता को कम करने, सूचना सुरक्षा से संबंधित घटनाओं से नुकसान को कम करने और परिचालनिक लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा किए जा रहे आउटसोर्सिंग के व्यापक स्तर को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने की और भी अधिक आवश्यकता है कि इस संबंध में प्रभावी नीतियां और प्रथाएं मौजूद हैं। यहां तक कि जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर तीसरे पक्ष की निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों और अन्य पर्यवेक्षित संस्थाओं में आईटी और साइबर सुरक्षा शासन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए फिशिंग सिमुलेशन और साइबर सर्वेक्षण अभ्यास जैसी तकनीकों के साथ-साथ उन्नत विश्लेषणात्मक और निगरानी उपकरणों के उपयोग के साथ कई उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाएं प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष पर निर्भरता से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों के संबंध में विनियमित संस्थाओं (आरई) के बढ़ते जोखिम के संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को बैंकों, एनबीएफसी

[1] स्रोत: Risk.Net

और अन्य आरई द्वारा की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए लचीलापन का तीसरा घटक संगठनात्मक स्तर पर लचीला होना है ताकि वे जोखिमों का अनुमान जल्दी लगा सकें और कुशलतापूर्वक उसको निपटा सकें। संगठनों में प्रतिकूल घटनाओं से खुद को बचाने और अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने की क्षमता और लचीलापन होना चाहिए। संगठनात्मक लचीलापन प्राप्त करने के लिए विनियमित संस्थाओं को नीतियों, प्रक्रियाओं, संगठनात्मक संस्कृति और अभिशासन को मानकीकृत करके लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें संगठन के भीतर विविध विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक की विनियामकीय और पर्यवेक्षी रणनीति के स्तंभ

बैंकिंग प्रणाली सहित भारतीय वित्तीय प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने की हमारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्वारा स्थापित मजबूत और उन्नत विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचा है। विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हमारा वर्तमान दृष्टिकोण प्रमुखत: तीन स्तंभों पर बना है।

सबसे पहले, हाल के वर्षों में हमारे प्रमुख क्षेत्रों में से एक विनियमित संस्थाओं के भीतर अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करना रहा है। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता प्रभावी अभिशासन पर गंभीर रूप से निर्भर करती है, ताकि सभी हितधारकों, विशेष रूप से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सुशासन का सार तत्व विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का वातावरण बनाना है। जमाकर्ता, जिनका पैसा बैंकों के संसाधनों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी जीवन भर की बचत और कड़ी मेहनत की कमाई को बैंकों के पास रखते हैं। इसलिए जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा एक पवित्र कर्तव्य है जिसे सुशासन के माध्यम से पूरा किया जाना है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रिज़र्व बैंक इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि विनियमित संस्थाओं में ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हों जो सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देती हों। बैंकों में आश्वासन कार्य यानी जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा अभिशासन और व्यवसाय के बीच महत्वपूर्ण लिंक हैं। आश्वासन कार्य बोर्ड के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन को यह पता लगाने में सहायता करते हैं कि बैंक या एनबीएफसी के व्यावसायिक संचालन बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों और रणनीतियों के अनुरूप चलाए जा रहे हैं या नहीं। रिज़र्व बैंक ने अभिशासन और आश्वासन कार्यों की गुणवत्ता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों को गहन पर्यवेक्षी मूल्यांकन के अधीन भी रखा गया है।

दूसरा, हमने कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए प्रयास किए हैं। कई बार कमजोरियां बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार मॉडल से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, अति-आक्रामक विकास रणनीतियाँ या निचले स्तर की नासमझी अक्सर भविष्य की समस्याओं के पूर्व कारक होते हैं। हालांकि हम व्यावसायिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, विनियमित संस्थाओं की स्थिति से दिखना चाहिए कि उनके आंतरिक नियंत्रण और हानि अवशोषण क्षमता उनके व्यावसायिक मॉडल से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। हमारा दृष्टिकोण इस क्षेत्र की कमियों को अलग-अलग संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक मंडल को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए ध्यान दिलाना है। हम बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ भी संपर्क में रहते हैं और सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर उन्हें ध्यान दिलाते हैं। हाल के दिनों में, 'मूल कारण' पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कुछ हाउसकीपिंग सुधार को अनिवार्य करना पड़ा है जैसे कि अनर्जक ऋणों की स्वचालित पहचान और प्रावधान, आंतरिक और कार्यालय खातों के उपयोग में उचित नियंत्रण, धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) और आईटी तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण आदि का कार्यान्वयन।

तीसरा, रिज़र्व बैंक के भीतर हमने अपने पर्यवेक्षी विश्लेषण को काफी मजबूत किया है। हम संभावित और उभरते जोखिमों, दायरे से बाहर की संस्थाओं और बैंकों के बड़े किंतु कमजोर ऋणों

[2] सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश

को पहचानने के लिए डेटा एनालिटिक्स - मैक्रो और माइक्रो, दोनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे ऑनसाइट पर्यवेक्षक ऑफसाइट पर्यवेक्षण टीमों द्वारा इंगित चिंता वाले क्षेत्रों की गहराई से जांच करते हैं। अब हम आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) सहित उन्नत विश्लेषणात्मक आधारित तकनीकी समाधानों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमारे पास प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की एक प्रणाली है जो जोखिम निर्माण के प्रमुख संकेत प्रदान करती है। तनाव परीक्षण भी निरंतर आधार पर किए जाते हैं। ये तनाव परीक्षण न केवल व्यक्तिगत संस्थाओं को शामिल करते हैं, बल्कि प्रणालीगत तनाव को भी शामिल करते हैं।

जहां आस्ति की गुणवत्ता और पूंजी की स्थिति वित्तीय संस्थानों की मध्यम अवधि के लचीलेपन और मजबूती का संकेत देती है, वहीं चलनिधि को अक्सर संकट के तत्काल कारण के रूप में देखा जाता है। हम अपनी इकाइयों की चलनिधि की स्थिति की बहुत बारीकी से निगरानी करते हैं और यदि कोई विचलन होता है, तो उसे उपचारात्मक उपायों के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ तुरंत उठाया जाता है। इस प्रकार, पर्यवेक्षण के मामले में हमारा पूरा दृष्टिकोण अचानक होने वाली घटनाओं का कम करने, चिंताओं को पहचानने और कमजोरियों को शीघ्रतापूर्वक ठीक करने के लिए रहा है।

संक्षेप में, रिज़र्व बैंक के भीतर पर्यवेक्षी व्यवस्था का एकीकरण (अर्थात, वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग में जोड़ना); स्वामित्व निष्पक्ष और जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण; सामयिक पर्यवेक्षण से निरंतर पर्यवेक्षण में बदलाव; डेटा एनालिटिक्स और सुपटेक समाधानों की मदद से ऑफ-साइट निगरानी; बेहतर ऑन-साइट पर्यवेक्षण; समस्याओं के मूल कारण का विश्लेषण और दायरे से बाहर की संस्थाओं की पहचान; और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशिष्ट निगरानी रखना हमारी पर्यवेक्षी रणनीति का प्रमुख आधार रहा है।

रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में एनबीएफसी और यूसीबी में अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों को मजबूत करने के लिए कई विनियामकीय पहलें भी की हैं। इनमें अक्टूबर 2021 में जारी एनबीएफसी के लिए नया स्केल आधारित विनियामकीय ढांचा और जुलाई 2022 में जारी यूसीबी के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा शामिल है। इन नए विनियामकीय ढांचों को लाने से पहले हमने कुछ उपाय किए थे जैसे कि - बड़ी एनबीएफसी में मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) और मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना; ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात; बड़ी एनबीएफसी (₹5000 करोड़ और उससे अधिक की आकार वाली) और ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्तिआकार वाले यूसीबी के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) मानदंड; और वाणिज्यिक बैंकों के समान एनबीएफसी और यूसीबी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाना।

प्रभावी आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा का महत्व

अब मैं वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा के महत्व पर बात करना चाहूंगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों की स्थिरता और विकास हितधारकों के बीच विश्वास पर निर्भर है। भविष्य तत्पर होने के लिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों, दोनों का विश्वास अर्जित करने की आवश्यकता है। कोई भी 'विश्वास' को हल्के में नहीं ले सकता। अर्थव्यवस्था के अधिक खुलेपन और प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण सूचना और पूंजी प्रवाह के तेजी से प्रसारण के साथ, प्रणाली में विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य के लिए, हितधारकों को स्वतंत्र मूल्यांकन और आश्वासन प्रदान करने के लिए कि विनियमित इकाई का संचालन निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है, आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से एक मजबूत आश्वासन तंत्र आवश्यक है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर बाजार के विश्वास को बनाए रखने में सांविधिक लेखा परीक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग उद्योग में यह सार्वजनिक भूमिका वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि बैंकों के पास सार्वजनिक जमाराशियां रखी होती हैं। लेखा परीक्षण की गुणवत्ता इस सार्वजनिक भूमिका की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इन

कारणों से, पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण में गहरी रुचि है। जहां भी आवश्यक हो, हम अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रकृति के मुद्दों पर बाहरी सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क में रहते हैं।

हमने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके अनुसार किसी बैंक के न्यूनतम 70% क्रेडिट एक्सपोजर को कवर करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023-24 से, पीएसबी का निदेशक मंडल शाखा लेखा परीक्षा और शाखाओं के चयन के कवरेज पर निर्णय लेगा। ऐसा करते समय, बोर्डों को अलग-अलग बैंकों की विशिष्ट विशेषताओं जैसे - बैंक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, भौगोलिक प्रसार, प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण का स्तर आदि को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि बैंकों के निदेशक मंडल इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय उच्चतम स्तर की सावधानी बरतेंगे। जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा का संबंध है, हम ऐसी लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता और दायरे का नए सिरे से मूल्यांकन कर रहे हैं।

रिज़र्व बैंक में कौशल और क्षमता निर्माण

रिज़र्व बैंक में हम अपने कर्मचारियों के कौशल निर्माण और क्षमता विकास को बहुत महत्व देते हैं। हम पर्यवेक्षण विभाग को संख्या और गुणवत्ता, दोनों में मजबूत कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए विशेष कौशल और परिपक्व निर्णय की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स अपनी प्रशिक्षण पद्धतियों में सुधार जारी रखेगा, अधिक केस स्टडी-आधारित शिक्षण को अपनाएगा, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक व्यावहारिक सत्र आयोजित करेगा, और अपने प्रशिक्षण प्रयासों के प्रभाव का उद्देश्यपरक मूल्यांकन विकसित करेगा। प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कार्यक्रम सामग्री में सुधार करने और पहचान की गई कमियों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कठिन तकनीकी कौशल सिखाने के साथ-साथ नेतृत्व, निर्णय लेने, समय प्रबंधन और संघर्ष समाधान जैसे सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्तीय प्रणाली में तेजी से विकास और नवाचार, विशेष रूप से फिनटेक और डिजिटल उत्पादों के क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ-साथ जोखिम भी पैदा हो रहे हैं। ये वित्तीय मध्यस्थता, भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इन उभरती प्रवृत्तियों के प्रभावों की निगरानी और आकलन को जारी रखना होगा, और साथ ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं और ढांचों को भी विकसित करना होगा।

हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी, फिनटेक और ऋण ऐप द्वारा डिजिटल ऋण का प्रसार हो रहा है। इस तरह के उधार अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आए हैं, विशेष रूप से उचित प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 में डिजिटल ऋण के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विनियमित संस्थाएं और उनके भागीदारों, जैसे कि - ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी), द्वारा विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से उधार देने की गतिविधियां संचालित की जाएं।

संक्षेप में

संक्षेप में, रिज़र्व बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली को भविष्य के लिए मजबूत करने और सतत विकास के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा भारत और विदेश के विशेषज्ञों की सहभागिता के साथ वित्तीय लचीलापन पर आयोजित यह वैश्विक सम्मेलन लचीली वित्तीय प्रणालियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय मूल्य जोड़ेगा। मुझे बताया गया है कि निर्धारित विषयों पर कई शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और चुनिंदा पत्रों को जर्नल ऑफ फाइनेंशियल रेजिलिएंस के पहले अंक का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आज जारी किया गया था। मुझे विश्वास है कि सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से विचार करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण के विकास पर नए परिप्रेक्ष्य प्राप्त होंगे।

मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं!

धन्यवाद।

*भारत के युग का उदय**

माइकल देबब्रत पात्र

इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) के निदेशक डॉ. बसंत कुमार प्रधान, सम्मेलन समिति के संयोजक प्रोफेसर सुब्रत सरकार, आईजीआईडीआर के संकाय सदस्य, संस्थान के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, देवियों और सज्जनों, नमस्कार और गुड आफ्टरनून!

मैं आईजीआईडीआर पूर्व छात्रों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र और संकाय एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आप में से कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यात्रा की बेहतर रूपरेखा बनाते हुए अपने रास्ते पर हैं; अन्य लोग भविष्य के साथ अपना खुद का संबंध शुरू करने की तैयारी में हैं। यह वास्तव में खुशी की बात है कि आप सभी ने आईजीआईडीआर के मातृ आह्वान को कितने अच्छे ढंग से प्रतिसाद दिया है - आखिरकार, जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स कहता है, एक पूर्व छात्र वह है जो पोषित (संस्कारित) है।

एक महान राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला उसकी मानव पूंजी का पोषण है। आईजीआईडीआर ने देश के कुछ प्रतिभाशाली और सबसे अधिक स्वयं प्रेरित विद्वानों को तैयार किया है। उनकी व्यावसायिक सफलताएं अंगभूत रूप से संस्था को परिभाषित करती हैं। पूर्व छात्र प्राप्तकर्ता भी हैं और दाता भी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में, "यह हर आदमी का दायित्व है कि वह कम से कम दुनिया को उतना वापस करे जितना उसने दुनिया से लिया हो।" जब आप अपनी सफलता की यात्रा पर चल रहे होते हैं, तो इस बात पर विचार करें कि आप अपने नक्शेकदम पर चलने वाले दूसरों की यात्रा को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। मैं आपको प्रकाश की किरणों के रूप में देखता हूं जो आपके द्वारा पार किए गए क्षेत्र को रोशन करती हैं, और यही प्रकाश आपके मातृ संस्थान का भी परिचय देता है। आपकी उपलब्धियों की समृद्ध विविधता हमारी संपत्ति है, अनुकरण के योग्य है, और उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आज आपके साथ जुड़ते हैं।

जीवन में सफलता की कुंजी के एक प्रेरणादायक वर्णन से प्रेरणा लेते हुए[1] कहा जा सकता है कि राष्ट्रों के मामलों में बाढ़ के रूप में एक ऐसा समय आता है जो उसे भाग्य की ओर ले जाता है। भारत अपने इतिहास में एक ऐसे लहर के शिखर पर है जो इसे अपने नागरिकों के भविष्य के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने और वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका रखने में अपनी पूरी क्षमता से ले जाएगी, तथापि इसमें कई चुनौतियों भी रहेंगी। इसी संदर्भ और भावना को लेकर मैंने सोचा कि मैं भारत के युग के शुभारंभ की कल्पना पर कुछ बात करूं।

जनसांख्यिकी

संयुक्त राष्ट्र[2] के अनुसार, भारत इस वर्ष दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जो 2018 से शुरू होने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश की शुरूआत को प्रमाणित करता है। इस विषय पर हमारी सोच में आमूलचूल परिवर्तन आया है। थॉमस माल्थस[3] के विचार में जिसे विकास में बाधा माना जाता था, हमारी वही बड़ी आबादी को अब एक ऐसी दुनिया में एक संपत्ति और अवसर के रूप में माना जाता है जिसमें कई देश उम्र बढ़ने और यहां तक कि जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत, हमारी आबादी युवा है - औसत आयु 28 वर्ष है। दुनिया में हर छठा कामकाजी उम्र (15-64 वर्ष) का व्यक्ति भारतीय है। बचत और निवेश को बढ़ावा देने की क्षमता, जो इसमें है वह भावी दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उद्भव को काफी बढ़ाती है। वास्तव में, इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को 'दुनिया

* मुंबई में 10 मई 2023 को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। सितिकंठ पट्टनायक, महुआ रॉय, रजनी प्रसाद, पल्लवी चव्हाण, अत्री मुखर्जी, धीरेंद्र गजभिये, धन्या वी., पूर्णा बनर्जी, साक्षी अवस्थी, नवीन सिंह से बहुमूल्य टिप्पणियां और विनीत कुमार श्रीवास्तव तथा समीर रंजन बेहरा से संपादकीय मदद प्राप्त हुई।

1 विलियम शेक्सपियर, *जूलियस सीज़र*।

2 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-no-153-india-overtakes-china-as-the-worlds-most-populous-country/#:~:text=In%20April%202023%2C%20India's%20population,to%20grow%20for%20several%20decades

3 "द पॉवर ऑफ़ पापुलेशन इस सो सुपीरियर टू द पॉवर ऑफ़ द अर्थ टू प्रोड्यूस सुब्सिस्टेन्स फॉर मन, दैट प्रीमाइच्युर डेथ मस्ट इन सम शेप और अदर विजिट द ह्यूमन रेस" - थॉमस माल्थस, 1798। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। अध्याय VII, पृष्ठ 61।

4 द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 अप्रैल 2023

के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित करना' कहा गया है क्योंकि यह वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका में एक अमुलाग्र परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा, भारत की आबादी अगले चार दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 2063 में 1.7 बिलियन के नज़दीक हो जाएगी। अब से 2050 के बीच दुनिया की कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि का छठा हिस्सा भारत द्वारा प्रदान किया जाएगा।

पहले से ही, भारत बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने गणना की है कि पीपीपी के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था 2048 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।

हमें इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ मायनों में हमने शुरुआत की है। भारत भौतिक बुनियादी ढांचे को विश्व स्तर पर उन्नत कर रहा है जिनमें सड़कें और हवाई अड्डे सबसे अधिक दिखाई देने वाले आयाम हैं। हम डिजिटल भुगतान क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। फिर भी हमारी सबसे विकट चुनौतियां बनी हुई हैं: मौजूदा कामकाजी उम्र की आबादी का केवल आधा हिस्सा श्रम शक्ति का हिस्सा है। इसके अलावा, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दुनिया में सबसे कम है, यहां तक कि कम आय वाले देशों की तुलना में भी कम है। भारत की श्रम उत्पादकता (प्रति घंटे काम करने वाली जीडीपी) उन देशों के निम्न मध्यम आय वर्ग के समकक्षों से भी कम है, जिनमें हमें वर्गीकृत किया गया है। नतीजतन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 16 प्रतिशत आबादी गरीबी में रह रही है। हमें कामकाजी उम्र की आबादी के विस्तार के अनुरूप रोजगार पैदा करके, कार्यबल को कुशल बनाकर और उसे एक ऐसा संस्थागत वातावरण प्रदान करके, जो बदलती प्रौद्योगिकियों और मांग के स्वरूप के अनुसार काम के लचीलेपन को सक्षम बनाता है, इन सभी को बदलना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें काम की गरिमा और कार्यस्थल की शालीनता सुनिश्चित करके कार्यबल में अधिक महिला भागीदारी को सक्षम करना चाहिए। हमारी आबादी एक सुअवसर प्रस्तुत करती है जिसे केवल तभी महसूस किया जा सकता है जब हम इसे आर्थिक तौर पर अवसर प्रदान करने में सफल होते हैं।

प्रवासी

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का एक बाहरी प्रतिबिंब दुनिया भर में भारतीय समुदायों का जीवंत विस्तार है। भारत हमेशा एक खुली अर्थव्यवस्था रहा है। 3000 ईसा पूर्व में कांस्य युग से ही अंतरराष्ट्रीय प्रवासन शेष दुनिया के साथ भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करने वाली एक प्रमुख शक्ति रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी डेटाबेस के 2022 के प्रकाशन में अनुमान बताया गया है कि भारतीय प्रवासी आंकड़ा 18 मिलियन[5] है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और 2020 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों (281 मिलियन) की कुल मात्रा का 6.4 प्रतिशत है। यह प्रवासन दुनिया भर में बिखरा हुआ है, जिसमें वर्तमान में प्रमुख गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात और इसके बाद अमेरिका है। दिलचस्प बात यह है कि जनसांख्यिकीय लाभांश पर आंतरिक प्रवासन का भी प्रभाव पड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, प्रवासी भारतीयों के बारे में हमारी धारणाएं भी 'प्रतिभा पलायन' से 'प्रतिभा लाभ' में बदल गई हैं, जो भारतीयों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चिकित्सा, कला और संस्कृति सहित वैश्विक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान से प्रेरित है, जिनमें से कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त अमेरिका में लगभग 500 यूनिकॉर्न के 1078 संस्थापकों में से 90 से अधिक भारतीय मूल[6] के व्यक्ति हैं। हाल के एक अध्ययन[7] के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के क्षेत्रों में ये पेशेवर यूएस अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अत्याधुनिक विचार और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराते हुए रोजगार निर्मित करते हैं और जीवन स्तर बढ़ाते हैं। भारत आप्रवासी जन्म समूह का सबसे बड़ा देश है, जो सभी विदेशी मूल के एसटीईएम श्रमिकों का 28.9 प्रतिशत है।

---

5 संयुक्त राष्ट्र प्रवासी स्टॉक डेटाबेस

6 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1889765

7 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/foreign-born-stem-workers-united-states

भारतीय अर्थव्यवस्था को इस गतिशील और उद्यमशील प्रवासी समूह से लाभ हुआ है। भारत वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्रवाह प्राप्तकर्ता है। 2022 में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो एक साल पहले की तुलना में 24.6 प्रतिशत अधिक है, और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पास फरवरी 2023 के अंत तक भारतीय बैंकों में 136 बिलियन यूएस डॉलर जमा हैं।

आने वाले समय में तकनीकी सफलताओं, ऊर्जा संक्रमण और भू-अर्थशास्त्र से प्रेरित श्रम बाजार में बदलाव से विदेशों में काम करने और भारत में काम करने के बीच का अंतर धुंधला हो जाएगा। जनसांख्यिकीय लाभ भारत को इस बदलाव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार कर सकता है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023 श्रम बाजारों में वैश्विक मंथन की ओर इशारा करती है – 69 मिलियन नौकरियों का निर्माण और 83 मिलियन नौकरियों की गिरावट – इसमें आपूर्ति शृंखला और परिवहन, मीडिया, मनोरंजन और खेल उद्योग प्रमुख क्षेत्र होंगे। भारत के श्रम बाजारों में परिवर्तन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) जैसे प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाले क्षेत्रों द्वारा संचालित होगा, इसके बाद डेटा विश्लेषक और वैज्ञानिक होंगे। भारत में नियोक्ता भविष्य की प्रतिभा की उपलब्धता के मामले में सबसे अधिक उत्साहित हैं और उत्तरदाताओं का मानना है कि मौजूदा कार्यबल को अपेक्षित कार्य के लिए अधिक कुशल बनाया जा सकता है और साथ ही प्रतिभा को बनाए रखा जा सकता है। भारतीय समूह में उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रतिभा की प्रगति और पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार के साथ-साथ व्यावसायिक प्रथाओं के रूप में प्रभावी कौशल और उन्नयन प्रदान करने पर विचार करने के इच्छुक हैं जो वैश्विक समूह की तुलना में प्रतिभा तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिकता देते हुए भारत को अपनी कौशल रणनीति को सही करने की जरूरत है।

विविधता

भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्थिर लेकिन मौलिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। संभवत: सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन भारत के सेवा निर्यात क्षेत्र में हो रहा है, जो महामारी से अप्रभावित रहा तथा जो 2020 के बाद से प्रति वर्ष 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ रहा है, और बाहरी क्षेत्र की व्यवहार्यता के लिए मूल्यवान समर्थन प्रदान कर रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएं इस मजबूत प्रदर्शन के मुख्य चालक हैं, आईटी में हुई प्रगति ने न केवल सेवाओं को अधिक व्यापार योग्य बना दिया है बल्कि तेजी से विस्तारित भी कर दिया है: वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकल सेवा गतिविधि अब विभाजित रूप में हो सकती है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर अलग-अलग की जा सकती है। तदनुसार, क्षेत्राधिकार व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आपूर्ति शृंखलाओं का विकेंद्रीकरण और उनमें विविधता ला रहे हैं। इन कारकों ने आईटी-सक्षम सेवाओं के एक नए माध्यम को जन्म दिया है – बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित कर रहे हैं, जो अपतटीय कार्यालय हैं, जो समग्र आईटी विशिष्ट क्षेत्र में सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं।

वैश्विक जीसीसी में भारत की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है और कुल आईटी सेवा निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत होने का अनुमान है। जीसीसी भी विविधीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों की फर्में है, जो भारत में जीसीसी स्थापित कर रहे हैं। जीसीसी सेवाओं में लेखांकन, कानूनी सेवाएं, व्यापार परामर्श, संचालन, क्षमता विकास और अनुसंधान शामिल है। जीसीसी डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग, चिप डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, रोबोटिक्स और नए युग के अन्य प्रौद्योगिकी समाधानों जैसी उच्च-मूल्य और ज्ञान-गहन परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करते हैं जिनकी मांग वैश्विक तकनीकी बाजार में उच्च है। भारत इंजीनियरिंग आर एंड डी (ईआर एंड डी) केंद्रों के लिए भी एक हब बन रहा है क्योंकि प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न व्यावसायिक डोमेन में अपने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) विकसित कर रही हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) का अनुमान है कि भारत 2026 तक 500 जीसीसी जोड़ेगा। वे भर्ती करने जा रहे हैं। भारत के भविष्य के नागरिकों को इस क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्व स्तरीय नौकरियों के पद भरने के लिए दुनिया हमारे दरवाजे पर आ रही है।

डिजिटल क्रांति

भारत इस समय चल रही पांचवीं तकनीकी लहर - सूचना और संचार क्रांति[8] में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय के भुगतान लेनदेन में सबसे बड़े सदस्य के रूप में उभरे हैं, जिसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के करीब है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) खुदरा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार है, जिसमें अकेले अप्रैल 2023 में लगभग 9 बिलियन लेनदेन हुए हैं जो वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। दी इंडिया स्टैक हमारी आबादी को डिजिटल युग में ले जाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाता है। इंडिया स्टैक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आधार यूनिवर्सल आईडी नंबर की शुरुआत के साथ होती है; इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ईकेवाईसी) की शुरुआत, जो पहचान विवरणों को कागज़ रहित और शीघ्र सत्यापन को सक्षम बनाता है; ई-साइन, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज़ में कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर संलग्न करते हैं; यूपीआई, कैशलेस भुगतान को सक्षम करता है; और हाल ही में डिजी लॉकर उपलब्ध कराया गया है जो दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। इंडिया स्टैक के लाभों का मोबाइल की बढ़ती पैठ के माध्यम से व्यापक रूप से फायदा हो रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि इंडिया स्टैक दुनिया भर में डिजिटल भुगतान प्रणालियों की ओर तेजी से बढ़ सकता है और नकदी को समाप्त कर सकता है[9]।

डिजिटलीकरण भी सीमा पार भुगतान क्षेत्र में क्रांति को शक्ति प्रदान कर रहा है। भारत यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के साथ जोड़ रहा है। यूपीआई को सिंगापुर के पेनाउ के साथ जोड़ा गया है, जिससे मोबाइल एप्प का उपयोग करके लागत प्रभावी सीमा पार पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) अंतरण होने की उम्मीद है, और दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और प्रेषण प्रवाह गहरा होगा। इसके अलावा अन्य लिंक-अप आने वाले हैं। भारत के भीतर भी घरेलू भुगतान माध्यमों में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत डिजिटल रुपया शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। भूटान और सिंगापुर में क्यूआर कोड-आधारित मर्चेंट भुगतान की अनुमति देने वाले भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से घरेलू भुगतान मोड का अंतरराष्ट्रीयकरण सक्षम किया जा रहा है। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस भुगतान सुविधा को स्थानीय व्यापारी लेनदेन के लिए जी 20 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विस्तारित किया गया है।

आगे की ओर देखें तो डिजिटलीकरण का भविष्य उज्ज्वल है। डिजिटल भुगतान 2026 तक तीन गुना बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जिसमें 3 में से 2 लेनदेन गैर-नकद माध्यम से होंगे। भविष्य में सीमा पार भुगतानों के तात्कालिक अंतरण के लिए भुगतान माध्यम की एक समर्पित व्यवस्था होगी। इसके अलावा डिजिटल और वित्तीय समावेशन तथा सीमा पार भुगतान विनियमों का अधिक सामंजस्य भी सुनिश्चित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्र नीति

भारत की जी-20 अध्यक्षता हमारे इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हम सामूहिक कल्याण के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान खोजने और सभी के लिए एक शाश्वत और समावेशी भविष्य को प्रोत्साहित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण - वसुधैव कुटुम्बकम- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सामूहिक प्रयास, समन्वय और आम सहमति बनाने के लिए जी-20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है।

भारत एक सुधारयुक्त बहुपक्षवाद को प्राथमिकता दे रहा है ताकि 21वीं सदी के लिए अधिक जवाबदेह, समावेशी, न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और प्रतिनिधि बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हो सके। हमारी प्राथमिकताओं में खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभावों से निपटना; जलवायु परिवर्तन; बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमबीडी) का सुदृढ़ीकरण; ऋण स्थिरता; सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय लचीलापन को मजबूत करना; समावेशी, न्यायसंगत और शाश्वत विकास का वित्तपोषण; डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना; जलवायु वित्तपोषण; और तकनीकी परिवर्तन से प्राप्त होने वाले अवसर और जोखिम शामिल हैं।

[8] मानव इतिहास में तकनीकी नवाचार के पांच विस्फोट हुए हैं: औद्योगिक क्रांति; भाप और रेलवे युग; स्टील, बिजली और भारी इंजीनियरिंग का युग; तेल, ऑटोमोबाइल और बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग; और सूचना और दूरसंचार का युग - कार्लोटा पेरेज़, टेक्नोलोजिकल रिवोल्यूशन्स एंड फिनान्शियल कॅपिटल: दी डायनामिक्स ऑफ बबल्स एंड गोल्डन एजेस. चेल्टेनहम: एडवर्ड एल्गर, 2002

[9] "द इंडिया स्टैक: ओपनिंग दी डिजिटल मार्केटप्लेस टू दी मासेस". फाइनेंशियल टाइम्स, 20 अप्रैल 2023

वित्त क्षेत्र में हमारा उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और वित्तीय एकीकरण के मुद्दों से परे विचार करना है ताकि क्रॉस-सेक्टोरल और मैक्रो-वित्तीय प्रभावों और जोखिमों को पहचाना जा सके। हम अन्य बातों के साथ-साथ बिगटेक और फिनटेक से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और वित्तीय क्षेत्र की साइबर समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग भी बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा, दुनिया की उम्मीदें जी-20 दिल्ली घोषणापत्र के कार्यान्वयन पर आम सहमति बनाने पर हैं, जो भारत की ऐतिहासिक पहचान बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 'मानव-केंद्रित वैश्वीकरण' के लिए प्रयास कर रहे हैं जो विकासाधीन देशों की आवाजों के प्रति संवेदनशील है।

सक्रिय संघीयता

भारत में जीवन की गुणवत्ता और कारोबारी माहौल को सार्वजनिक नीति के केंद्र में बदलाव से परिभाषित किया जा रहा है जो सतत आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघीयता को बढ़ावा देता है। प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता प्रत्येक राज्य को अपनी अनूठी विशेषताओं और चुनौतियों को देखते हुए, अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करते हुए डिजाइन, प्रयोग, नवाचार और सुधार करने की अनुमति देती है। प्रतिस्पर्धी संघीयता शक्ति का एक उदाहरण प्रत्येक राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करके घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच होड़ लगना है। प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना को उच्चतम नीतिगत स्तरों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापार सुधारों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को शीर्ष निष्पादक के रूप में मान्यता दी जाती है। इसी प्रकार नीति आयोग ने उप-राष्ट्रीय निर्यात निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 'निर्यात तैयारी सूचकांक' विकसित किया है।

इसके अलावा, राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग योजना ने राज्यों को समर्पित स्टार्ट-अप नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई राज्यों ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अपने श्रम और औद्योगिक संबंधों में ठोस विधायी और प्रशासनिक सुधार भी किए हैं। आज, कई राज्यों ने एकल-खिड़की मंजूरी, उद्यमों द्वारा अनुपालन का स्व-प्रमाणीकरण, पंजीकरण और रिटर्न के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली जैसी प्रक्रियाएं शुरू की हैं। 'स्मार्ट सिटी मिशन' शाश्वत और समावेशी शहरों को बढ़ावा देता है[11]। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मार्च 2023 में 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के आधार पर देश में शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 15 संकेतकों[12] के आधार पर किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित शाश्वत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स[13] भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वैश्विक विकास लक्ष्यों पर रैंक निर्धारित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है।

जैसे-जैसे हमारे राज्य अपने लिए स्थान निर्माण करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, वे व्यवसाय के विकास का पोषण करेंगे, सर्वोत्तम भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करेंगे और हमें बेहतर बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करेंगे। नई प्रौद्योगिकियों और विचारों को लाने वाले विदेशी निवेश के साथ,

[10] ढांचे में चार मुख्य आयाम शामिल हैं: नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात निष्पादन। सभी महत्वपूर्ण पैरामीटरों नामत: निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, कारोबारी माहौल, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त तक पहुंच, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान और विकास अवसंरचना, विकास उन्मुखीकरण और निर्यात विविधीकरण को सूचकांक के चार मुख्य आयामों के तहत उप स्तंभों के रूप में शामिल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में समग्र निर्यात तैयारी स्कोर उच्चतम है।

[11] एक प्रतियोगिता-आधारित पद्धति का उपयोग वित्त पोषण के लिए शहरों का चयन करने के साधन के रूप में किया जाता है जो क्षेत्र-आधारित विकास पर आधारित है। एक राउंड में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले शहरों को तब मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुना गया। 2016 से 2018 की अवधि के दौरान पहले दौर में 20 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया, दूसरे दौर में 27 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया, तीसरे दौर में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया और चौथे दौर में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया।

[12] ये तीन मानदंड - संसाधन जुटाना, व्यय निष्पादन और राजकोषीय अभिशासन हैं। रैंकिंग चार जनसंख्या श्रेणियों पर आधारित होगी- 4 मिलियन से ऊपर, 1-4 मिलियन के बीच, 100K से 1 मिलियन और 100,000 से कम। अंतिम रैंकिंग की घोषणा जुलाई 2023 में होने की उम्मीद है।

[13] एसडीजी इंडिया इंडेक्स एसडीजी प्रगति का दुनिया का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उप-राष्ट्रीय माप है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कोर 16 एसडीजी में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के कुल प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से उत्पन्न होते हैं। यह सूचकांक दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए, केरल सूचकांक पर पहले स्थान पर था जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।

हम व्यापक उपभोक्ता विकल्पों और बेहतर जीवन स्तर के राष्ट्रीय लोकाचार में आगे बढ़ रहे हैं।

डीकार्बोनाइजेशन

जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर चिंताजनक पैमाने और गति से हो रहा है। चरम स्तर की मौसमी घटनाएं अधिक और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे विश्व स्तर पर और भारत में मानव जीवन और पर्यावरण का नुकसान बढ़ रहा है। अब तीव्र चिंता यह है कि जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधि से बहुत प्रभावित है। वास्तव में 20 वीं शताब्दी के मध्य की अवधि को "एंथ्रोपोसीन" युग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जलवायु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी सीमित क्षमताओं और अनुकूलन और शमन के लिए अपर्याप्त निधि के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उनके लिए हरित पथ पर संक्रमण की सापेक्ष लागत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है; संक्रमण पहल उन्हें विकास की सीढ़ी से कई पायदान नीचे ला सकता है। विकासशील देशों में से भारत वैश्विक जलवायु संबंधी मुद्दे पर एक अग्रणी आवाज के रूप में उभरा है जो जलवायु समानता और न्याय विचारों को ध्यान में रखता है।

भारत ने इस दिशा में कई नीतिगत पहल की हैं। 2015 में भारत ने 2030 तक के लक्ष्यों के साथ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (एनडीसी) को प्रस्तुत किया। सीओपी26 में 2021[14] में भारत ने अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किया, जो अब 2021 से 2030 की अवधि के लिए स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण ढांचे का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसने *पंचामृत* की पांच-गुना रणनीति के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसमें 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म-ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाना; अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से जुटाना; और 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत ने सीओपी27 शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों (एलटी-एलईडीएस) को जारी किया है।

भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सह-स्थापना की है और हरित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। 2022 में शुरू किया गया मिशन एलआईएफई (लाइफ) यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, अब पृथ्वी की सुरक्षा के लिए लोगों की शक्तियों को जोड़ने के लिए एक वैश्विक प्रयास है।

आरबीआई भी जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में लगा हुआ है। अप्रैल 2021 में बैंक जलवायु जोखिम प्रबंधन और हरित वित्त में सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाने और योगदान करने के लिए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) में शामिल हुआ। बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के हिस्से के रूप में नवीकरणीय विषयों को शामिल करने के अलावा, आरबीआई ने हाल ही में सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, और ग्रीन डिपॉजिट जुटाने के लिए रूपरेखा जारी की है। इस विषय पर अनुसंधान के अग्रिम मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2023 को मुद्रा और वित्त, 2022-23 पर रिपोर्ट जारी की है, जिसका विषय "एक स्वच्छ हरित भारत की ओर" है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के वृहद-वित्तीय प्रभावों और भारत के लिए संभावित राजकोषीय, मौद्रिक, विनियामकीय और अन्य नीतिगत विकल्पों पर चर्चा की गई है।

विक्टर ह्यूगो के शब्दों में, जिन्हें अब तक के सबसे महान फ्रांसीसी लेखकों में से एक माना जाता है, "दुनिया में और कुछ भी

[14] कॉन्फरेन्स ऑफ दी पार्टीज़ (सीओपी) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। कन्वेंशन के पक्षकार सभी स्टेट्स का सीओपी में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिस पर वे कन्वेंशन के कार्यान्वयन और किसी भी अन्य कानूनी लिखतों की समीक्षा करते हैं जिन्हें सीओपी अपनाता है, और संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्था सहित कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। सीओपी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य पार्टियों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची की समीक्षा करना है। सीओपी हर साल बैठक करता है जब तक कि पार्टियां अन्यथा निर्णय नहीं लेती हैं। पहली सीओपी बैठक मार्च 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी।

नहीं ... सभी सेनाएं नहीं... सिर्फ एक शक्तिशाली विचार है जिसका समय आ गया है (“Nothing else in the world…not all the armies… is so powerful as an idea whose time has come.”)। भारत का समय आ गया है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। आगे विकट परीक्षा की घड़ी और चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम तुलनात्मक लाभों का फायदा उठाते हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है। मैंने भविष्य में भारत की सकारात्मक स्थिति के पक्ष में कुछ परिभाषित आयामों के बारे में बात की है। हमें उन्हें अत्याधुनिक बनाने की जरूरत है जो इस सपने को संभव बना सके।

संक्षेप में

जब आप तेजी से बदलती दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार होते हैं, तो हमेशा उस अटूट बंधन को संजोएं जो आपके मातृ संस्थान के साथ है। इस संदर्भ में, आपकी श्रद्धा सबसे पहले आपके शिक्षकों, आईजीआईडीआर के संकाय, के प्रति होनी चाहिए, जिन्होंने आपको प्रतिबद्धता, समर्पण और ईमानदारी के साथ पोषित किया। हमारे शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते हैं; वे हमारे अंदर आजीवन शिक्षार्थी बनने की इच्छा जागृत करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "गुरु आत्म-साक्षात्कार का माध्यम है"। मैं भारत के भविष्य के जीवन को आकार देने और उस संस्थान की आत्मा बनने के लिए वर्तमान और भूतपूर्व सभी संकाय की सराहना करता हूं जिन्होंने छात्रों को हमारे राष्ट्र और दुनिया के योग्य नागरिक बनने के लिए तैयार किया है।

जब आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमेशा विश्वास करें कि आप सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम हैं। आईजीआईडीआर में आपके शैक्षिक कार्यक्रम का सफल समापन आप में उस शक्ति और जुनून का पहला प्रमाण है। बड़े सपने देखने से डरो मत। इस ज्ञान के साथ दुनिया में बाहर निकलें कि कुछ भी संभव है यदि आप पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अपनी यात्रा में, आप विफलता का सामना करेंगे, लेकिन विफलता सफलता के विपरीत नहीं है; यह सीखने और बढ़ने का अवसर है, और अपने सपनों को नहीं छोड़ता है। सफलता ऐसी चीज नहीं है जो रातोंरात मिल जाए। यह लगातार प्रयास, कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इसलिए, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता की तलाश करने की आदत डालें। प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार विल डुरंट के शब्दों में, "उत्कृष्टता एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। जो काम आप सबसे ज्यादा करते हैं वही काम आप सबसे अच्छा करेंगे (“Excellence is not an act but a habit. The things you do the most are the things you will do best.”)। भविष्य आपके हाथों में है। आपके पास अपने भाग्य को आकार देने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए सार्थक और पूर्ण जीवन बनाने की शक्ति है। इसलिए, अपना सिर ऊंचा करके वहां जाएं और सर्वोच्चता की ओर अथक प्रयास करें।

आप जहां भी रहेंगे और जो कुछ भी करेंगे, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

निर्यात समानता सूचकांकों के माध्यम से भारत की निर्यात क्षमता का पता लगाना

भारत की स्थिर साम्य मुद्रास्फीति: पुनर्मूल्यांकन

भारत और सीओपी-26 प्रतिबद्धताएं: खनन क्षेत्र के लिए चुनौतियां

अंतिम पड़ाव पर बुनियादी और डिजिटल वित्तीय साक्षरता:
ग्रामीण पश्चिम बंगाल की एक झलक

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की क्रॉस-धाराओं में उलझी हुई है, और वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक असहज शांति बनी हुई है क्योंकि वे बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण और जमा बीमा की रूपरेखा पर नीति अधिकारियों से स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अप्रैल और मई 2023 की पहली छमाही में, घरेलू आर्थिक स्थितियों ने 2022-23 की आखिरी तिमाही में देखी गई गति को बरकरार रखा है। नवंबर 2021 के बाद पहली बार अप्रैल 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे आ गई। कॉरपोरेट आय आम सहमति की उम्मीदों से आगे निकल रही है, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र मजबूत राजस्व प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, जो मजबूत क्रेडिट वृद्धि से सहायता प्राप्त है। वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में, विकास को निजी खपत से प्रेरित होने, ग्रामीण मांग को पुनर्जीवित करने और इनपुट लागत दबाव कम होने पर विनिर्माण में नए उछाल से समर्थन मिलने की उम्मीद है।

परिचय

लंबे समय तक ऊपर की ओर बढ़ने के बाद वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में गिरावट और ठहराव के साथ, केंद्रीय बैंकों ने अपनी दर गतिविधियों को या तो कम कर दिया है या रोक दिया है। वित्तीय रूप से संकटग्रस्त बैंकों के सशक्त समाधान के साथ-साथ, इसने वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक असहज शांति ला दी है क्योंकि वे बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण के भविष्य के पाठ्यक्रम और जमा बीमा की रूपरेखा के बारे में नीति अधिकारियों से स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालाँकि, राहत के कारण बाजारों को फिर से उत्साहित होने का मौका मिला है। इक्विटी और बॉन्ड ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ली है, हालांकि बैंक शेयरों ने व्यापक इक्विटी सूचकांकों से कम प्रदर्शन किया है। एक बार जब जोखिम-आधारित भावना वापस आ गई, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रसार कम हो गया। मुद्राएँ एक संकीर्ण दायरे में कारोबार कर रही हैं और अमेरिकी डॉलर पिछले वर्ष के अधिकांश समय में अपनी एक ही ढंग की वृद्धि से पीछे हट गया है। उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह लौट रहा है और इससे उनकी मुद्राओं को समर्थन मिला है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था इन जटिल खींचतान के बीच उलझी हुई है। वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही की शुरुआत में, यानी, अप्रैल में, वैश्विक विकास उच्च आवृत्ति संकेतकों के अनुसार लचीला था, जिसने वर्ष की पहली तिमाही में प्राप्त गति को बरकरार रखा था। महीने-दर-महीने आधार पर, मार्च में खुदरा बिक्री में वृद्धि हुई है। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) ने अप्रैल में मजबूत उत्पादन वृद्धि की ओर इशारा किया - जो 2022 के मध्य के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। यह लचीलापन मुख्य रूप से पर्यटन और वित्तीय सेवाओं सहित सेवाओं द्वारा संचालित है, जबकि विनिर्माण संघर्ष जारी रहा, और नए निर्यात ऑर्डर सुस्त रहे। सामान उत्पादक कंपनियाँ मुख्य रूप से इनपुट के सुरक्षा स्टॉक को ख़त्म करते हुए ऑर्डर बैकलॉग भर रही हैं। तैयार माल का स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है और क्षमता पर दबाव बना हुआ है। इसलिए, सेवाएँ तत्काल विकास चालक होंगी और यह रोजगार की निरंतर ताकत का अनुमान लगाती है।

बाज़ारों और केंद्रीय बैंक संचार के बीच नए सिरे से अलगाव के बीच जोखिमों का समूह नीतिगत चुनौतियाँ बढ़ाता है। यदि विकास धीमा होता है तो 2023 में राजकोषीय समेकन की गुंजाइश के बारे में व्यापक मुद्दे खुल गए हैं, और यह जोखिम मौद्रिक नीति के अवस्फीतिकारी रुख के लिए पैदा हो सकता है। उच्च ऋण स्तर इन तनावों के क्रॉस-करंट पर बैठते हैं क्योंकि उधार लेने की लागत वित्तीय स्थितियों की मजबूती के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

एक और चुनौती वित्तीय स्थिरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता के बीच की बातचीत है: क्या मौद्रिक नीति निर्माताओं को अपने निर्णय लेने में वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर विचार करना चाहिए? या क्या मौद्रिक नीति बहुत ही कुंद उपकरण है और इसलिए, व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होना चाहिए, जबकि केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता के लिए अपनी

* इस आलेख को जी. वी. नथनएल, सुभद्रा शंकरन, योगेश एच.सी., कुणाल प्रियदर्शी, रोहन बंसल, रमेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहरा, सत्यार्थ सिंह, राशिका अरोड़ा, अनूप के सुरेश, देबप्रिया साहा, लव कुमार शांडिल्य, चैताली भौमिक, शैलजा भाटिया, रमेश बी. गोलैत, सौमश्री तिवारी, प्रियंका सचदेवा, साक्षी अवस्थी, अभिनंदन बोराड, अलीशा जॉर्ज, युवराज कश्यप, अक्षरा अवस्थी, मनीष कुमार त्रिपाठी, आदित्य मिश्रा, राहुल जैन, अरुण कुमार, डिंपल भंडिया, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, देब प्रसाद रथ और माइकल देबब्रत पात्र ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चलनिधि प्रबंधन और विवेकपूर्ण नीतियों जैसे अन्य उपकरणों को नियोजित करते हैं? अभी के लिए, केंद्रीय बैंकों ने दूसरा रास्ता चुना है, लेकिन अगर वित्तीय तनाव फिर से बढ़ता है और इस बार व्यापक होता है - विश्लेषकों का मानना है कि वाणिज्यिक अचल संपत्ति 'गिरने वाला अगला जूता' है [1] - यह मौद्रिक नीति के संचालन पर बाध्यकारी बाधा डाल सकता है। केंद्रीय बैंकों की महामारी से प्रभावित बैलेंस शीट को सामान्य बनाना इस दुविधा में जुड़ा हुआ है।

दिनांक 30 अप्रैल 2023 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स सर्वे का चौथा संस्करण 2023-27 की समय सीमा के परिप्रेक्ष्य को एक साथ लाता है, जिसमें 803 कंपनियां सामूहिक रूप से 27 उद्योग समूहों और सभी विश्व क्षेत्रों की 45 अर्थव्यवस्थाओं में 11.3 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देती हैं। इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक संगठन नई और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने, डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाने और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानकों को परिवर्तन लाने की सबसे अधिक संभावना मानते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक कंपनियां बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने पर विचार कर रही हैं, जबकि 86 प्रतिशत को अगले पांच वर्षों में अपने परिचालन में डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स को शामिल करने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार को 75 प्रतिशत व्यवसायों द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद है। दूसरे स्थान की प्रौद्योगिकी में शिक्षा और कार्यबल प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, 81 प्रतिशत कंपनियां 2027 तक इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सोच रही हैं।

बिग डेटा एनालिटिक्स, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियां और एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा नौकरी वृद्धि के सबसे बड़े चालक होने की उम्मीद है। कृषि प्रौद्योगिकियों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स, ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार, और एआई सभी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण श्रम-बाज़ार व्यवधान होने की उम्मीद है। नियोक्ताओं का अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में संरचनात्मक श्रम बाजार में 23 प्रतिशत नौकरियों का सृजन होगा – नई नौकरियाँ जोड़ी जाएंगी और कम होती नौकरियाँ समाप्त हो जाएँगी। आपूर्ति श्रृंखलाओं, परिवहन, मीडिया, मनोरंजन और खेल उद्योगों में औसत से अधिक मंथन और विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार में औसत से कम मंथन की उम्मीद है। उत्तरदाताओं को 69 मिलियन नौकरियों की संरचनात्मक वृद्धि और 83 मिलियन नौकरियों की गिरावट की उम्मीद है। यह 14 मिलियन नौकरियों, या वर्तमान रोज़गार के 2 प्रतिशत की शुद्ध कमी के अनुरूप है। संगठनों का अनुमान है कि व्यवसाय से संबंधित सभी कार्यों में से 34 प्रतिशत वर्तमान में मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जो 2020 के बाद से स्वचालन के स्तर में नगण्य 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उत्तरदाताओं का अनुमान है कि 2027 तक 42 प्रतिशत व्यावसायिक कार्य स्वचालित हो जाएंगे। वर्ष 2027 से पहले 10 में छह श्रमिकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन आज केवल आधे श्रमिकों को ही पर्याप्त प्रशिक्षण अवसरों तक पहुंच मिलती दिख रही है।

कुल मिलाकर, इस बात पर नई अंतर्दृष्टि उभर कर सामने आई है कि अगले पांच वर्षों में श्रम बाजारों के किस तरह विकसित होने की उम्मीद है क्योंकि वे लगातार शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार ले रहे हैं। कार्यस्थल तेजी से बदल रहे हैं और कौशल आवश्यकताएं भी। अगले पांच वर्षों में व्यापक आर्थिक रुझानों और तकनीकी प्रगति से महत्वपूर्ण व्यवधान का अनुभव होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी भविष्य की नौकरियों को प्रौद्योगिकी से संबंधित नौकरियों तक सीमित कर देगी। रोजगार सृजन संभवतः हरित परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानीयकरण से प्रेरित होगा। आबादी की उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सेवा आसन्न मंथन के प्रति लचीली हो सकती है। लिपिकीय और सचिवीय कौशल में सबसे तेजी से गिरावट आने की आशंका है। कार्य पर सीखना और प्रशिक्षण, और कार्य प्रक्रियाओं के स्वचालन में तेजी लाना कार्यबल रणनीतियों के मुख्य चालक होने की संभावना है। नियोक्ता ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके पास 2023-27 के लिए उपयुक्त व्यवहार कौशल हो। इन कौशल वाले लोग अगले पांच वर्षों की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे।

इन मूलभूत बदलावों का भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश और व्यापक आर्थिक लाभ का

[1] 'क्या व्यावसायिक संपत्ति 'अगली चुनौती' है? फाइनेंशियल टाइम्स, 9 मई, 2023।

फायदा उठाने के लिए वैश्विक विकास की झांकी में खुद को उत्तरोत्तर स्थान दे रहा है, जिस पर अब हम विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत इस साल अप्रैल में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जिसे 'वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत'[2] और '1.4 अरब अवसर' [3] कहा गया है। 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है - दुनिया में 5 में से एक [4] - 200 मिलियन युवा अगले दो दशकों में श्रम बल में प्रवेश करेंगे [5] उस आधार पर जब श्रम बल पहले से ही अधिक बढ़ रहा है जनसंख्या की तुलना में तेजी से.

इसे हमारी विकासात्मक आकांक्षाओं को सुरक्षित करने में तुलनात्मक लाभ में कैसे बदला जा सकता है? यह बताया गया है कि हमारी आबादी एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती है जिसे तभी साकार किया जा सकता है जब हम इसे आर्थिक अवसर प्रदान करने में सफल हों। [6] इसे एक संस्थागत वातावरण में कार्यबल को कुशल बनाकर प्राप्त किया जा सकता है जो बदलती प्रौद्योगिकियों और मांग पैटर्न के अनुरूप कार्य लचीलेपन को सक्षम बनाता है। श्रम उत्पादकता बढ़ाना और कार्यबल में महिला भागीदारी बढ़ाना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए तैयार कर सकता है।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक रुझानों के समान भारत में श्रम बाजार में बदलाव आएगा - समाप्त की गई नौकरियों की तुलना में नई नौकरियां पैदा होंगी जो वर्तमान श्रम बल का 22 प्रतिशत होंगी। भारत की नौकरी में वृद्धि ईएसजी मानकों के व्यापक अनुप्रयोगों के 61 प्रतिशत, इसके बाद नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि (59 प्रतिशत) , और डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाने (55 प्रतिशत) से प्रेरित होगी। भारत अपने इतिहास में बदलाव के शिखर पर खड़ा है। [7] इसके पास आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अपने मानव संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर है।

सबसे सुखद घटनाक्रम अप्रैल 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति का 5 प्रतिशत से कम होना है, जो नवंबर 2021 के बाद पहली बार हुआ है, जो 8 अप्रैल, 2023 के मौद्रिक नीति निर्णय और रुख की पुष्टि करता है। यह एक स्वागतयोग्य राहत के रूप में आया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) के सर्वेक्षण अंततः खर्च में कुछ सुधार की रिपोर्ट कर रहे हैं, और यह धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल रहा है। निजी खपत, जो भारत में कुल मांग का मुख्य आधार है, पिछले वर्ष की दूसरी छमाही के बाद से मूल्य दबाव, विशेष रूप से विवेकाधीन खर्च से प्रभावित हुई है। बदले में, इसने कॉर्पोरेट भारत के राजस्व प्रदर्शन और लाभप्रदता को प्रभावित किया है। इस महीने के अंत में जारी होने वाले राष्ट्रीय खातों में, इससे उद्योग और यहां तक कि कुछ सेवाओं में जोड़े गए मूल्य में कमी आने की संभावना है।

अप्रैल और मई 2023 के पहले कुछ दिनों में घरेलू आर्थिक स्थितियों में 2022-23 की आखिरी तिमाही में देखी गई गति में तेजी बनी हुई है। मंडी में आवक और अब तक गेहूं की संचयी खरीद जैसे प्रमुख संकेतकों को देखते हुए, रबी की फसल एक नया रिकॉर्ड बना सकती है , जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, खरीफ विपणन सीजन (अक्टूबर 2022 से आज तक) में धान की मंडी आवक आठ वर्षों में सबसे अधिक रही है। हालांकि धान की मंडी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ी कम हैं, खुदरा कीमतें ऐसे समय में मजबूत हो रही हैं जब वैश्विक चावल की कीमतें और भारत के चावल के निर्यात दोनों में वृद्धि दिख रही है।

2 भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई, दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल रहा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 अप्रैल, 2023।

3 विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)।

4 मुख्य तथ्य क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया, प्यू रिसर्च सेंटर, 9 फरवरी, 2023।

5 भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई, दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल रहा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 अप्रैल, 2023।

6 'द डॉन ऑफ इंडियाज एज', आईजीआईडीआर पूर्व छात्र सम्मेलन, मुंबई में एमडी पात्र द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण, 10 मई, 2023।

7 'द डॉन ऑफ इंडियाज एज', आईजीआईडीआर पूर्व छात्र सम्मेलन, मुंबई में एमडी पात्र द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण, 10 मई, 2023।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्री यातायात में बड़े उछाल के साथ, सेवा क्षेत्र प्रगति पर है। बेहतर बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट और बंदरगाहों पर कम समय के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (अप्रैल 2023 रिलीज) में भारत छह स्थान ऊपर आ गया है। नए व्यवसाय में वृद्धि के कारण अप्रैल 2023 में सेवा पीएमआई 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, और आशावाद भविष्य में भी कायम है।

मार्च 2023 की रीडिंग लगभग सपाट रहने के साथ, 2022-23 में औद्योगिक उत्पादन काफी धीमा हो गया, खासकर विनिर्माण। पहली तिमाही को छोड़कर पूरे साल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं कमजोर रहीं। दूसरी ओर, पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे की वस्तुओं में मजबूत वृद्धि देखी गई, जो निर्माण गतिविधि में तेजी को दर्शाती है। नवंबर 2022 से औद्योगिक उत्पादन में तेजी आनी शुरू हो गई थी और एक बढ़ती प्रवृत्ति बन रही थी; लेकिन मार्च 2023 की रीडिंग ने निराश किया है, खासकर 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत भी इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया क्रांति की लहर पर सवार है और इंडियन प्रीमियर लीग विश्व क्रिकेट पर कब्ज़ा कर रही है और दुनिया की दूसरी सबसे आकर्षक खेल लीग बन रही है। [8]

कॉर्पोरेट आय के नतीजों ने जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में आम सहमति की उम्मीदों को आश्चर्यचकित कर दिया। मात्रा और मूल्य गतिशीलता के संयोजन से गैर-वित्तीय कंपनियों की राजस्व वृद्धि में कमी आई, लेकिन लागत दबाव कम होने के कारण उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ। धीमी वैश्विक मांग की स्थिति में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियों ने आय वृद्धि में नरमी का अनुभव किया। अग्रणी आईटी कंपनियों के प्रबंधन ने मंदी के माहौल के बारे में सतर्क दृष्टिकोण प्रदान किया। धातु क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने भी गिरती कीमतों के अनुरूप अपनी लाभप्रदता (वर्ष-दर-वर्ष) में कमी का अनुभव किया है और इसलिए, धीमी प्राप्ति हुई है। अन्य सभी कंपनियों के लिए, इनपुट लागत दबाव कम होने से उच्च लाभप्रदता प्राप्त हुई; हालाँकि, गिरती लागत का प्रभाव आय विवरणों में अंतराल के साथ प्रवाहित हो सकता है, विशेष रूप से अपनी बैलेंस शीट पर उच्च लागत वाली इन्वेंट्री रखने वाले कॉरपोरेट्स के लिए।

एफएमसीजी क्षेत्र में, जो उपभोग मांग का एक प्रमुख संकेतक है, कई कंपनियों ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है - इनपुट लागत दबाव कम होने से लाभप्रदता वृद्धि ऊपर की ओर बढ़ी है। मूल्य दबाव और परिणामस्वरूप उपभोक्ता मांग में कमी के कारण, कई कंपनियां मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं - जिन्हें आमतौर पर 'प्रीमियमाइजेशन' कहा जाता है। ऑटो सेक्टर ने लचीली मांग दर्ज करना जारी रखा, हालांकि इसने निर्यात पर बाधाओं की सूचना दी।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र लचीला बना रहा, एक और तिमाही में मजबूत राजस्व वृद्धि को मजबूत ऋण वृद्धि से मदद मिली। आरबीआई के क्रेडिट डेटा की क्षेत्रीय तैनाती के साथ मिलान से पता चलता है कि इसमें मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों, व्यापार और व्यक्तिगत ऋण क्षेत्रों का योगदान था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का ट्रेजरी पोर्टफोलियो मौद्रिक नीति के सख्त होते हुए चक्र से अछूता रहा है। इसके अलावा, प्रावधान लागत कम बनी हुई है क्योंकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक आर्थिक विकास को कवर करता है। खंड III घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रदान करता है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों की रूपरेखा बताता है, जबकि खंड V में निष्कर्ष दिया गया है।

II. वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अप्रैल और मई 2023 में लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा और अंतर्निहित गतिविधि पर

[8] प्रति मैच के आधार पर यूएस नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के बाद।

चार्ट 1: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक अनुमान (समायोजित श्रेणी, ति-द-ति)

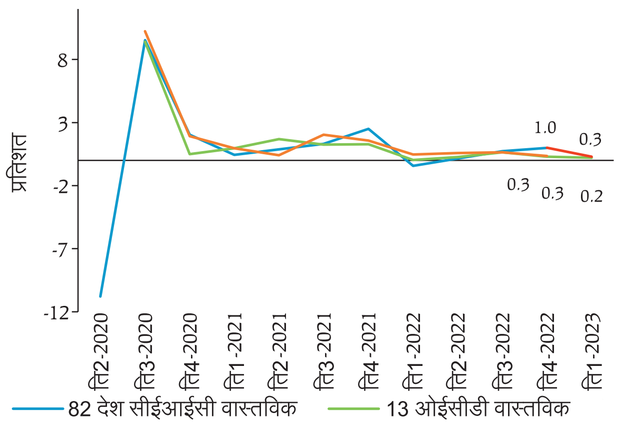

नोट: मॉडल में उच्च आवृत्ति संकेतक और संशोधित राष्ट्रीय लेखा डेटा शामिल है।

स्रोत: सीईआईसी; ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई

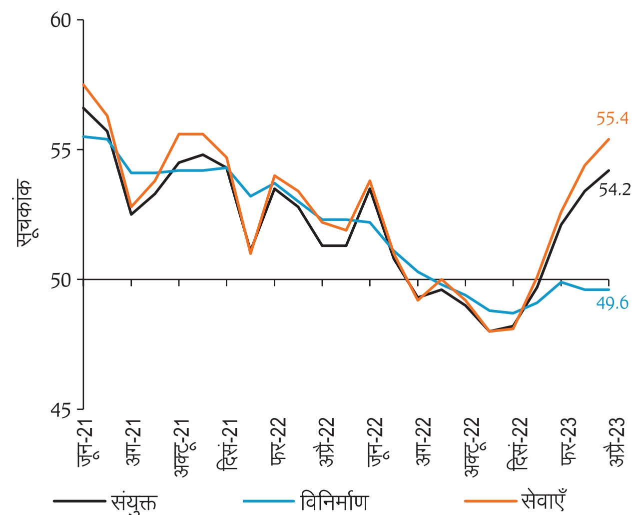

नोट: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं करता है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार को दर्शाती है और इसके विपरीत।

स्रोत: आईएचएस मार्किट

भावनाओं के सर्वेक्षण ने अधिकांश अधिकारक्षेत्रों की अपेक्षाओं को मात दी। ऐसा प्रतीत होता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) बीते वर्षों में आए कई आघातों का रास्ता तय करने में अपने उन्नत साथियों से आगे हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक विकास के लिए जोखिम बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, सख्त वित्तीय स्थितियों और यूक्रेन में संघर्ष के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों से उत्पन्न होंगे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मॉडल-आधारित नाउकास्ट 2023 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास में मंदी की ओर इशारा करता है(चार्ट 1)।

उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच, उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार में व्यापक-आधारित पिक-अप दर्ज करने के साथ वैश्विक समग्र पीएमआई अप्रैल 2023 में पिछले महीने के 53.4 से बढ़कर 16 महीने के उच्चतम 54.2 पर पहुंच गया। जबकि वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अप्रैल 2023 में 49.6 पर अपरिवर्तित रहा, अप्रैल में वैश्विक सेवा पीएमआई 55.4 पर नए व्यवसाय के 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के कारण नवंबर 2021 के बाद से सबसे तेज गति से विस्तारित हुआ (चार्ट 2)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 9, विश्व व्यापार की मात्रा का एक उच्च आवृत्ति संकेतक, फरवरी-मार्च (चार्ट 3) के दौरान तीन गुना वृद्धि के बाद अप्रैल में ज्यादातर सीमाबद्ध रहा।

अप्रैल में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में मजबूती आई, जो प्रमुख रूप से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चे तेल और कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ, लेकिन हाल ही में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मंदी की आशंकाओं के कारण

चार्ट 3: बाल्टिक ड्राई इंडेक्स

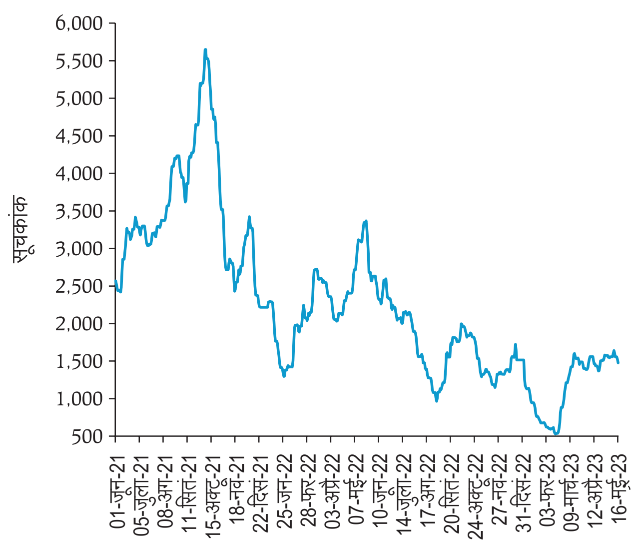

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

9 बाल्टिक ड्राई इंडेक्स सूखी थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक माप है।

उनमें गिरावट आई है [चार्ट 4 ए]। चीनी और मांस की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अप्रैल में खाद्य कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अनाज, डेयरी और वनस्पति तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। महीने-दर-महीने (एम-ओ-एम) 0.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल 2023 में गहरी अपस्फीति [(-) 19.7 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष] में रहा (चार्ट 4बी)।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक)+ द्वारा घोषित उत्पादन कटौती के कारण अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 84.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गईं। हालाँकि, बाद में वैश्विक मंदी की चिंताओं के बीच ये कीमतें पीछे हट गईं, मई की शुरुआत में ब्रेंट की कीमतें 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब गिर गईं (चार्ट 4सी)। सोने की कीमतों में तेजी से उछाल आया क्योंकि बैंकों की स्थिरता के बारे में नए सिरे से आशंकाओं ने सेफ-हेवन मांग को बढ़ावा दिया (चार्ट 4डी)।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में अनिच्छापूर्वक गिरावट जारी रही। अप्रैल में, अमेरिका में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मार्च में 5.0 प्रतिशत से मामूली कम होकर 4.9 प्रतिशत (अप्रैल 2021 के बाद से सबसे कम) हो गई। अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी फरवरी में 5.1 प्रतिशत से कम होकर मार्च में 4.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5 ए)। यूके में, सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में 10.4 प्रतिशत से घटकर मार्च में 10.1 प्रतिशत हो गई, जबकि जापान की सीपीआई (ताजा भोजन को छोड़कर सभी वस्तुएं) मुद्रास्फीति मार्च में 3.1 प्रतिशत पर स्थिर रही। यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति मार्च में 13 महीने के निचले स्तर 6.9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2023 में 7.0 प्रतिशत हो गई।

ईएमई के बीच, रूस की मुद्रास्फीति अनुकूल आधार प्रभाव के कारण मार्च में 3.5 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल में 2.3 प्रतिशत

चार्ट 4: पण्य वस्तु और खाद्यान कीमतें

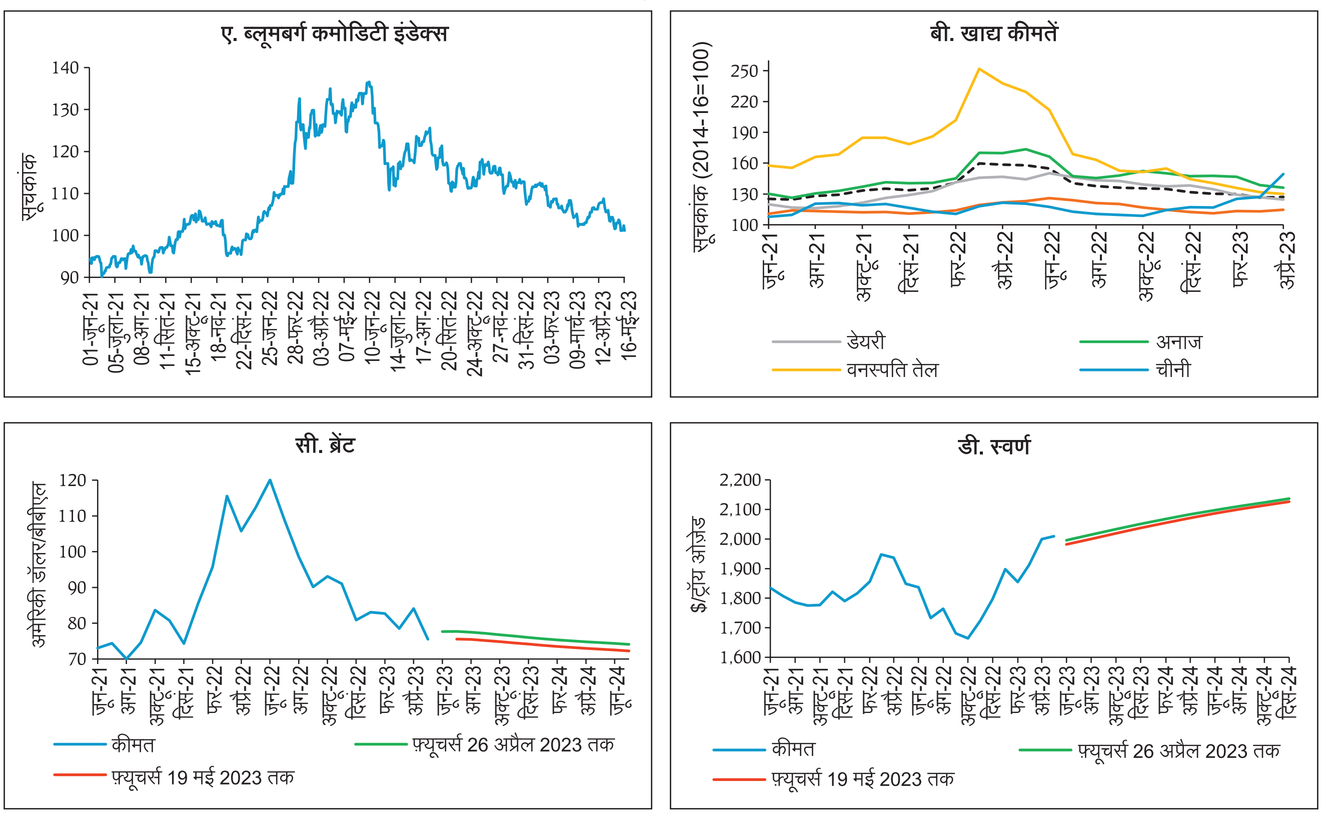

स्रोत: ब्लूमबर्ग, विश्व बैंक पिंक शीट और एफ़एक्यू।

चार्ट 5: मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष)

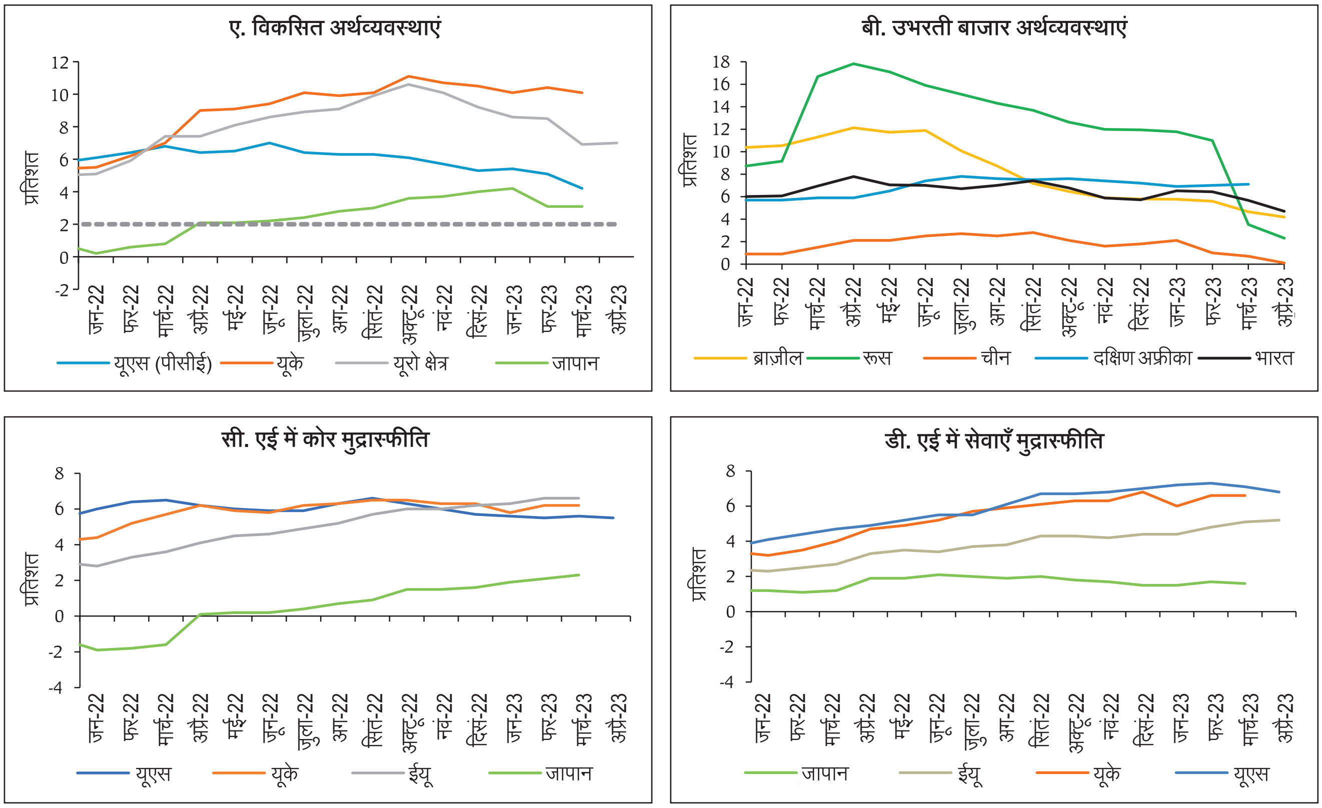

स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

हो गई। अप्रैल में ब्राजील (4.2 प्रतिशत) और चीन (0.1 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति में और कमी आई, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह मार्च में मामूली रूप से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5बी)। हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्रमिक नरमी के बावजूद, मुख्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है, विशेष रूप से एई (चार्ट 5 सी और 5 डी) में मजबूत सेवा मूल्य वृद्धि और वेतन दबाव द्वारा उठाया गया है।

मार्च के अंत से वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार हुआ क्योंकि अमेरिका और यूरोप में हालिया बैंकिंग उथल-पुथल से संक्रमण की आशंका कम हो गई (चार्ट 6 ए)। हालाँकि, बाजार अप्रैल में - मई की शुरुआत में सीमित दायरे में रहे क्योंकि ध्यान भविष्य में दरों में बढ़ोतरी की गति और परिमाण पर केंद्रित हो गया। आगामी कम अस्थिरता को विकल्प विक्रेताओं के प्रभुत्व के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो इंट्राडे रिवर्सन का कारण बनता है जो बाजार की कीमतों को कई दिनों तक अपरिवर्तित रखता है।

07 मार्च, 2023 को पांच प्रतिशत का आंकड़ा छूने के बाद, श्रम बाजार में मंदी के संकेतों को देखते हुए, अप्रैल में अमेरिकी दो-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट आई। दर कार्रवाई में संभावित ठहराव के बारे में 3 मई, 2023 फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के संकेतों पर दो साल की ट्रेजरी प्रतिफल में और नरमी आई। हालाँकि, बाद में ऋण सीमा संबंधी चिंताओं के कारण इसमें वृद्धि हुई (चार्ट 6बी)।

अनुमान से कमजोर नौकरियों के आंकड़ों, ऋण सीमा पर चिंता और बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों के साथ-साथ अमेरिका में संभावित मंदी की आशंकाओं के कारण अप्रैल में अमेरिकी डॉलर में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि, मई की पहली छमाही में घाटे की भरपाई हो गई। ईएमई के लिए मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) मुद्रा सूचकांक में भी 0.3 प्रतिशत की कमी आई क्योंकि पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा (चार्ट 6सी और 6डी)।

चार्ट 6: वैश्विक वित्तीय बाजार

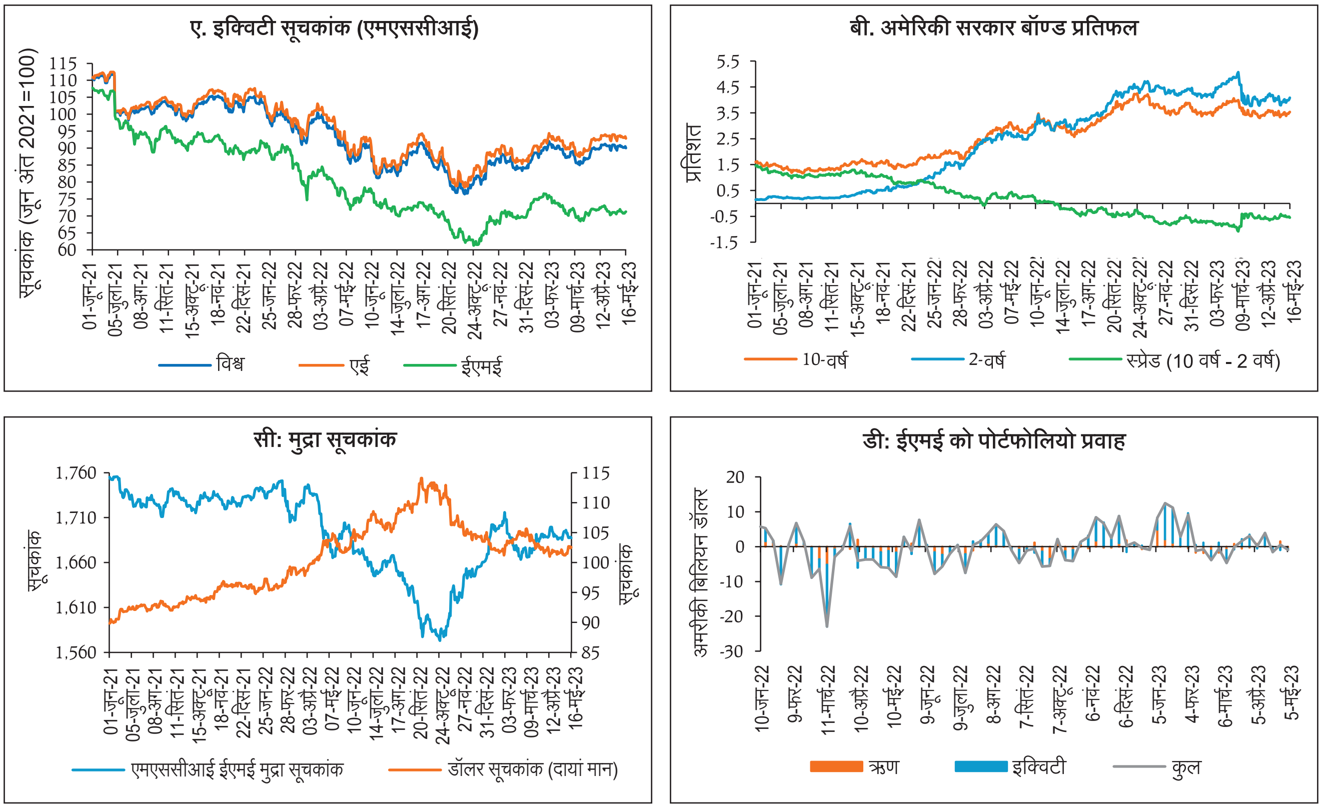

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

एई और ईएमई में केंद्रीय बैंकों ने या तो बढ़ोतरी की मात्रा कम कर दी है या अपने दर वृद्धि चक्र (चार्ट 7ए और 7बी) को रोक दिया है। यूएस एफओएमसी ने 3 मई, 2023 को अपनी नीति दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की और संकेत दिया कि आगे की कार्रवाइयों में मौद्रिक नीति की संचयी सख्ती को ध्यान में रखा जाएगा, मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति को

चार्ट 7: मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयाँ

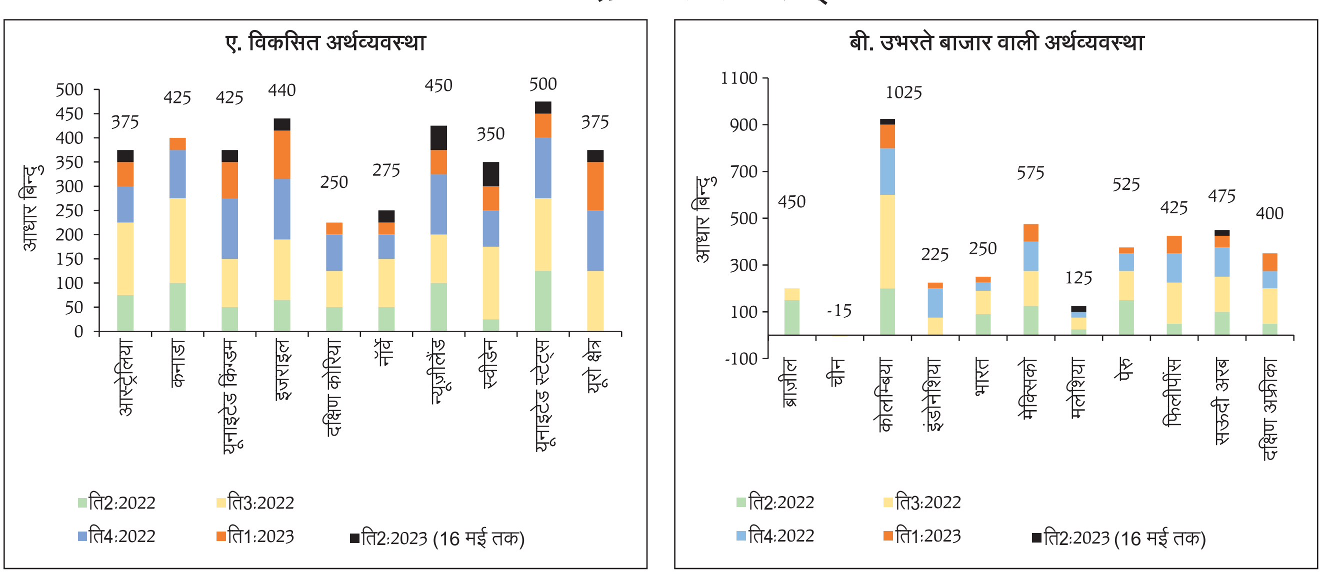

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

प्रभावित करती है, और आर्थिक और वित्तीय विकास" मई में बैंक ऑफ इंग्लैंड और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की। अपनी अप्रैल की बैठक में, स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने अपनी प्रमुख दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जबकि ईसीबी ने मई में तीन प्रमुख दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी अपेक्षाकृत कम आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों (चार्ट 7बी) की ओर रुख किया है। अप्रैल और मई 2023 में, सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना ने 300 बीपीएस, 1000 बीपीएस और 600 बीपीएस के तीन चरणों में अपनी नीति दरों में 1900 बीपीएस की बढ़ोतरी की, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ कोलंबिया ने 25 बीपीएस की वृद्धि लागू की। मई 2023 में, बैंक नेगारा मलेशिया ने भी 2023 में पहली बार अपनी नीति दर 25 आधार अंक बढ़ा दी।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में अब तक गति बरकरार रखी है। भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) जुलाई 2022 से ऐतिहासिक औसत से नीचे के स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 8ए)। समग्र आर्थिक गतिविधि, जैसा कि हमारे आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) द्वारा दर्शाया गया है, लचीली बनी हुई है (चार्ट 8बी)। अप्रैल 2023 के लिए उपलब्ध आंशिक आंकड़ों के आधार पर और 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए 5.1 प्रतिशत की निहित जीडीपी वृद्धि को मानते हुए, आर्थिक गतिविधि सूचकांक अब 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत (चार्ट 8सी) रखता है ।

कुल मांग

मांग की स्थिति के प्रमुख संकेतकों में, अप्रैल 2023 में 84.4 मिलियन पर ई-वे बिल की मात्रा मार्च 2023 के शिखर (चार्ट 9 ए) के बाद अपना दूसरा उच्चतम स्तर है। फास्टैग कार्यक्रम (चार्ट 9 बी) के तहत टोल प्लाजा के विस्तार से अप्रैल 2023 में टोल संग्रह 52 अरब रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बढ़ते तापमान के कारण अप्रैल में बिजली उत्पादन में भी तेजी आई (चार्ट 9 सी)।

ऑटोमोबाइल की बिक्री ने अप्रैल 2023 में सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो बीएस 6 चरण 2 उत्सर्जन मानदंडों (चार्ट 10 ए) में सहज बदलाव का संकेत देता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अप्रैल 2023 में लगातार

चार्ट 8: घरेलू आर्थिक गतिविधि सूचकांक

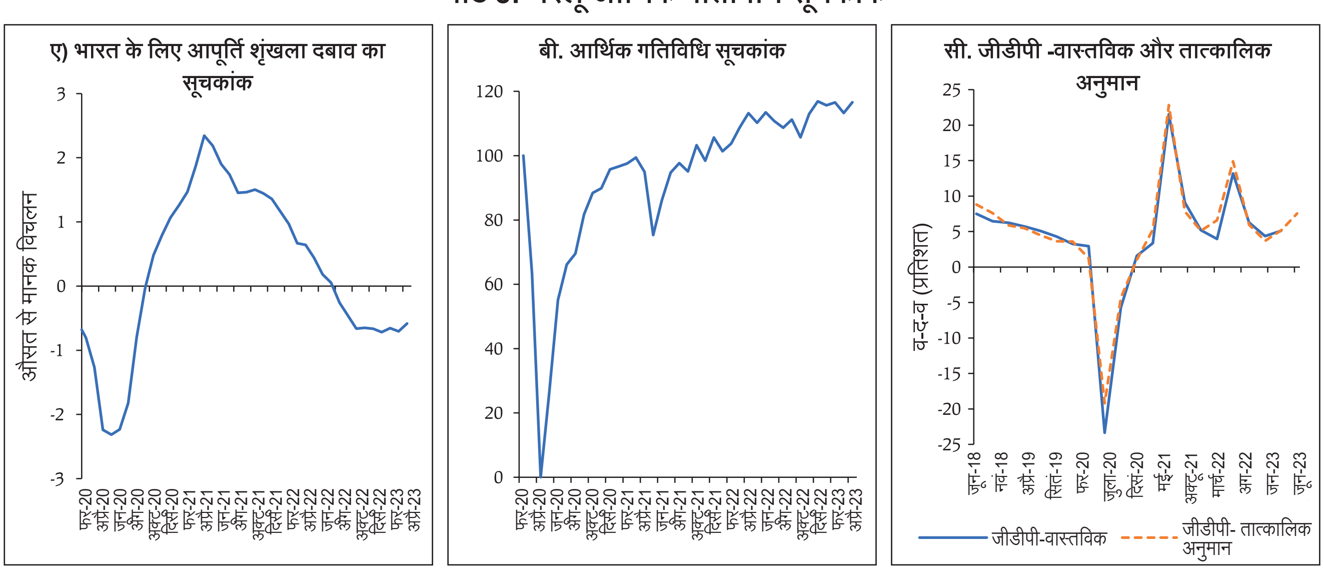

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सावधानी से चयनित उच्च आवृत्ति संकेतकों के समूह में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया गया है। ईएआई को फरवरी 2020 में 100 और अप्रैल 2020 में 0 तक बढ़ाया गया है, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित महीना है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 9 : ई-वे बिल, टोल संग्रह और बिजली आपूर्ति

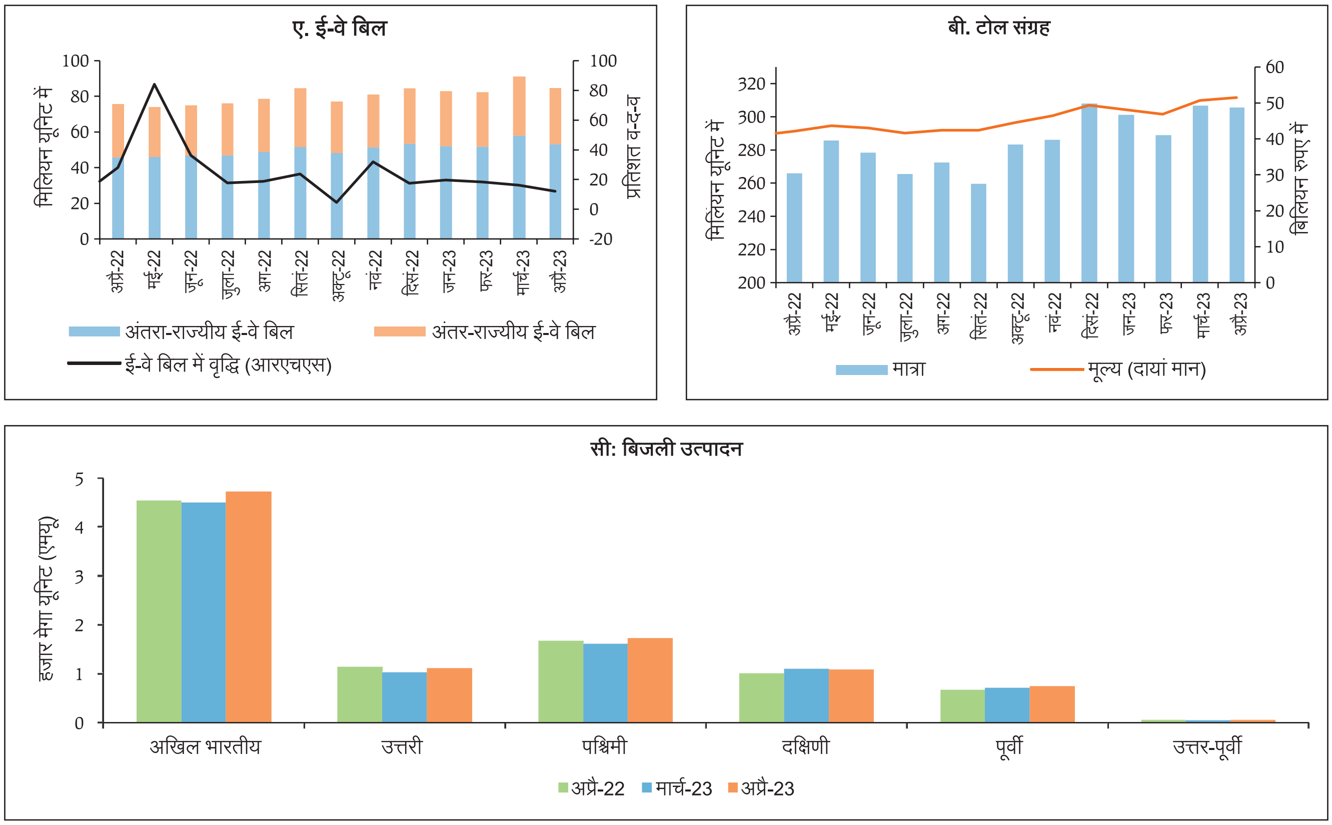

स्रोत : जीएसटीएन; आरबीआई; विद्युत प्रणाली परिचालन निगम; सीईआईसीऔर आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सातवें महीने 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में वार्षिक वृद्धि अप्रैल 2023 में तेज हो गई, तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले साल की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई और पूर्व-महामारी के स्तर (अप्रैल 2019) के करीब पहुंच गई। दूसरी ओर, अप्रैल 2023 में ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट आई क्योंकि नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के उच्च मांग पैदा करने वाले त्योहारों को मार्च (चार्ट 10 बी) तक बढ़ा दिया गया।

बीएस VI मानदंडों के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के कारण अप्रैल 2023 में वाहन पंजीकरण में कमी आई, जिससे खुदरा उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ गई (चार्ट 10सी)। अप्रैल 2023 में पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक औसत खपत में 7.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि पिछले महीने में रिकॉर्ड-उच्च दर्ज की गई थी, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जिसने गैसोलीन, डामर और छोटे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को प्रभावित किया (चार्ट 10डी)।

पर्यटन क्षेत्र में, मार्च 2023 में होटल अधिभोग दर 63 प्रतिशत थी, जबकि फरवरी में महामारी के बाद यह 71 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी (चार्ट 11ए)। क्रमिक गिरावट के बावजूद, औसत कमरे की दर (एआरआर) मार्च में 40 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी, जिससे प्रति उपलब्ध कमरे के राजस्व (रेवपीएआर) में सालाना 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 11बी)।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत थी, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की उच्च दर देखी गई (चार्ट 12ए)। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में क्रमिक रूप से 2.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई और यह 42.0 प्रतिशत (फरवरी 2020 के बाद से उच्चतम) हो गई [चार्ट

चार्ट 10 : परिवहन क्षेत्र संकेतक

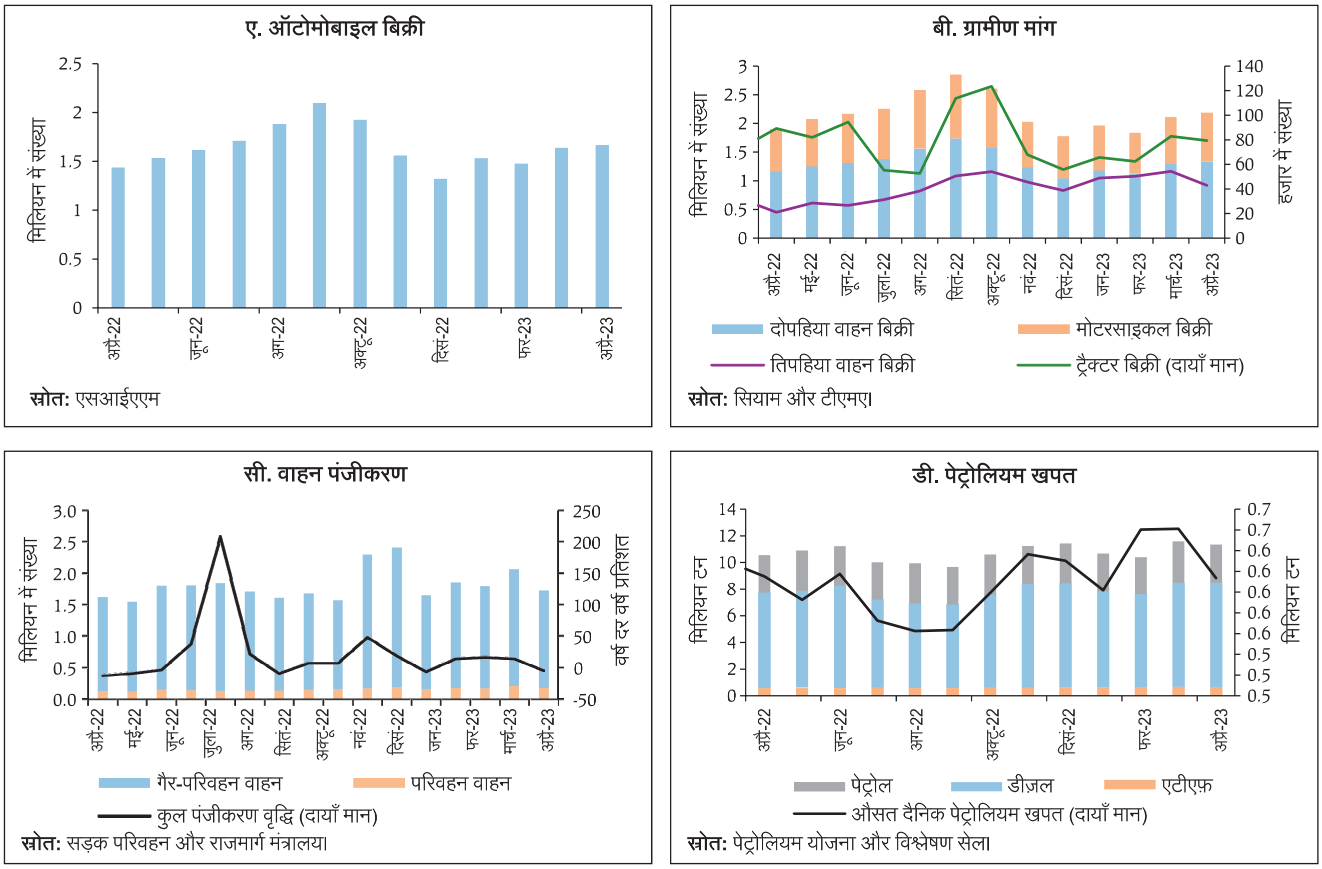

12बी]। श्रम बल में श्रमिकों की महत्वपूर्ण वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। विनिर्माण और सेवाओं में क्रय प्रबंधकों द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में रोजगार का दृष्टिकोण भी अप्रैल में देखा गया (चार्ट 13)।

चार्ट 11: होटल क्षेत्र संकेतक

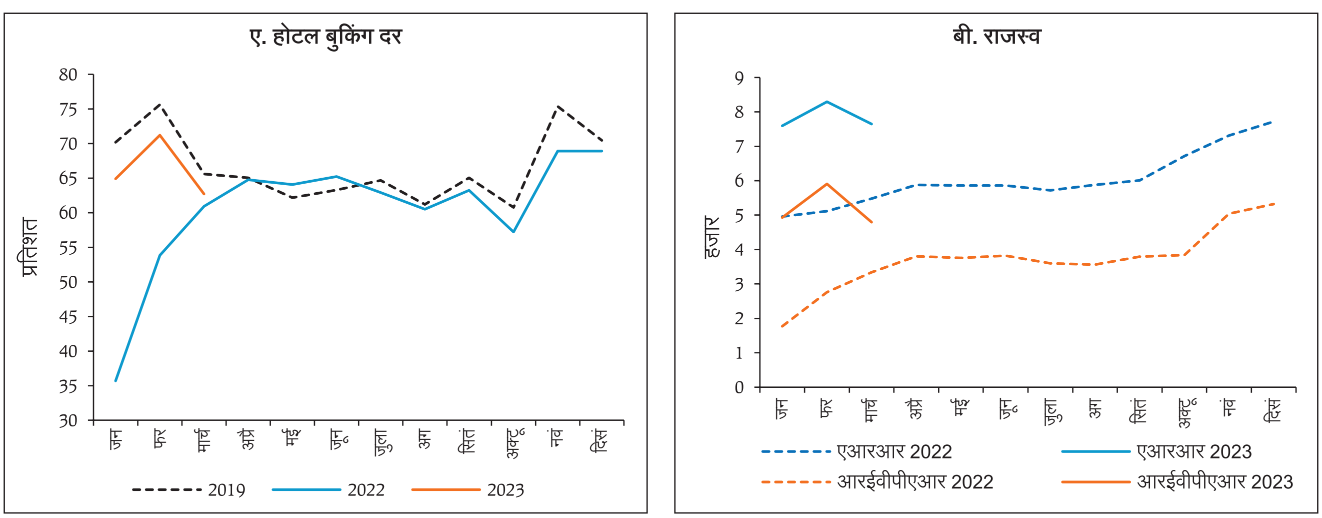

नोट: औसत कमरे की दर (एआरआर) कमरे के राजस्व का बेचे गए / बुक किए गए कमरों की संख्या से अनुपात है; और राजस्व प्रति उपलब्ध कमरा (आरईवीपीएआर) एक निश्चित अवधि में उपलब्ध कमरों की संख्या के लिए कमरे के राजस्व का अनुपात है।

स्रोत: एचवीएस एनारॉक।

चार्ट 12: श्रम बाजार की स्थिति

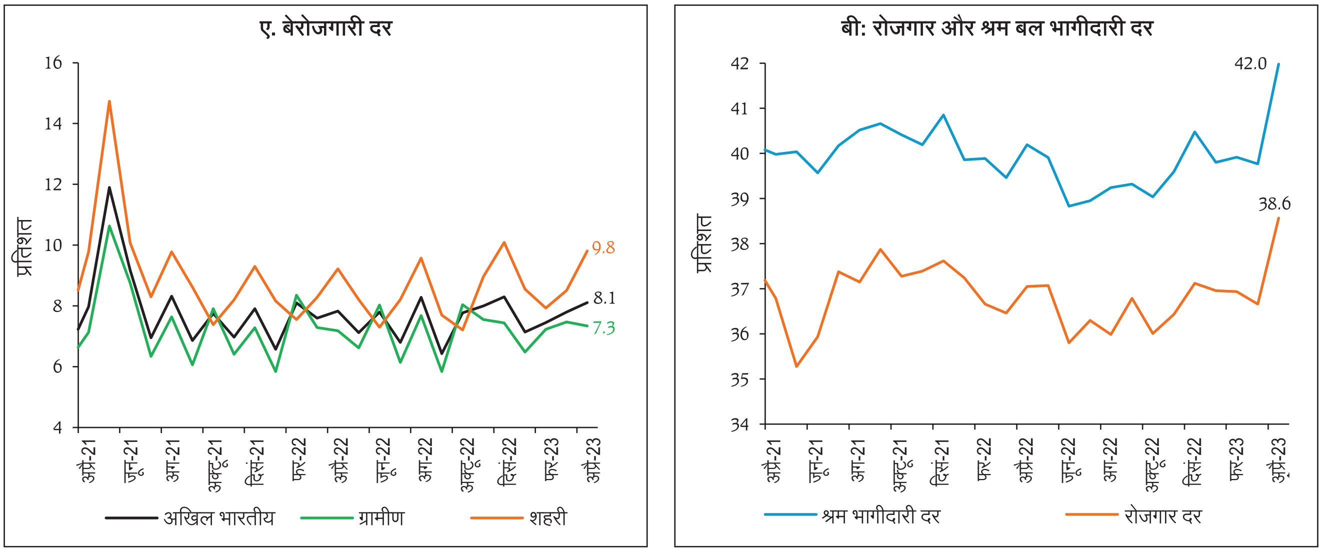

स्रोत: सीएमआईई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग क्रमिक और साल-दर-साल दोनों आधार पर बढ़ी (चार्ट 14)। इस तेजी का श्रेय गर्मियों में कृषि बुआई के लिए श्रम की कम मांग और मनरेगा के तहत सरकार द्वारा हाल ही में वेतन संशोधन जैसे कारकों को दिया जा सकता है। [10]

अप्रैल 2023 में भारत का व्यापारिक निर्यात साल-दर-साल 12.7 प्रतिशत घटकर छह महीने के निचले स्तर 34.7 बिलियन

चार्ट 13: पीएमआई रोज़गार सूचकांक

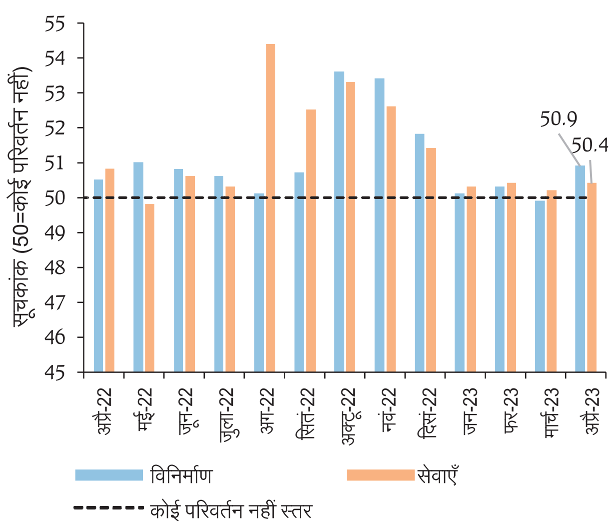

नोट: 50 से ऊपर का क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) मूल्य विस्तार को दर्शाता है।
स्रोत : एसएंडपी ग्लोबल

चार्ट 14: मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग

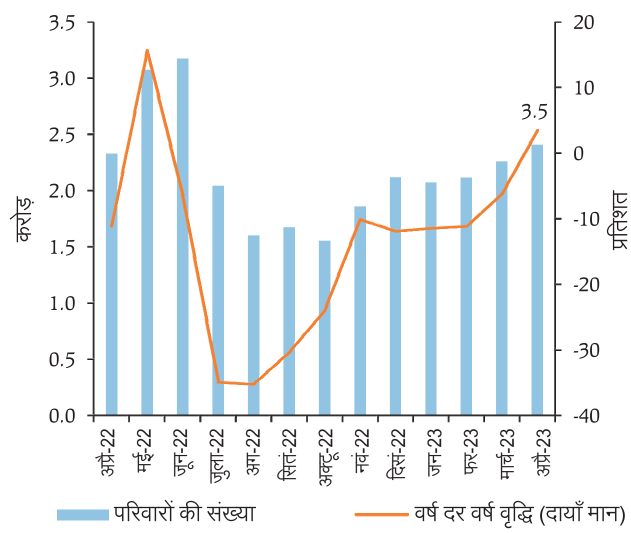

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

चार्ट 15: पण्य वस्तु निर्यात

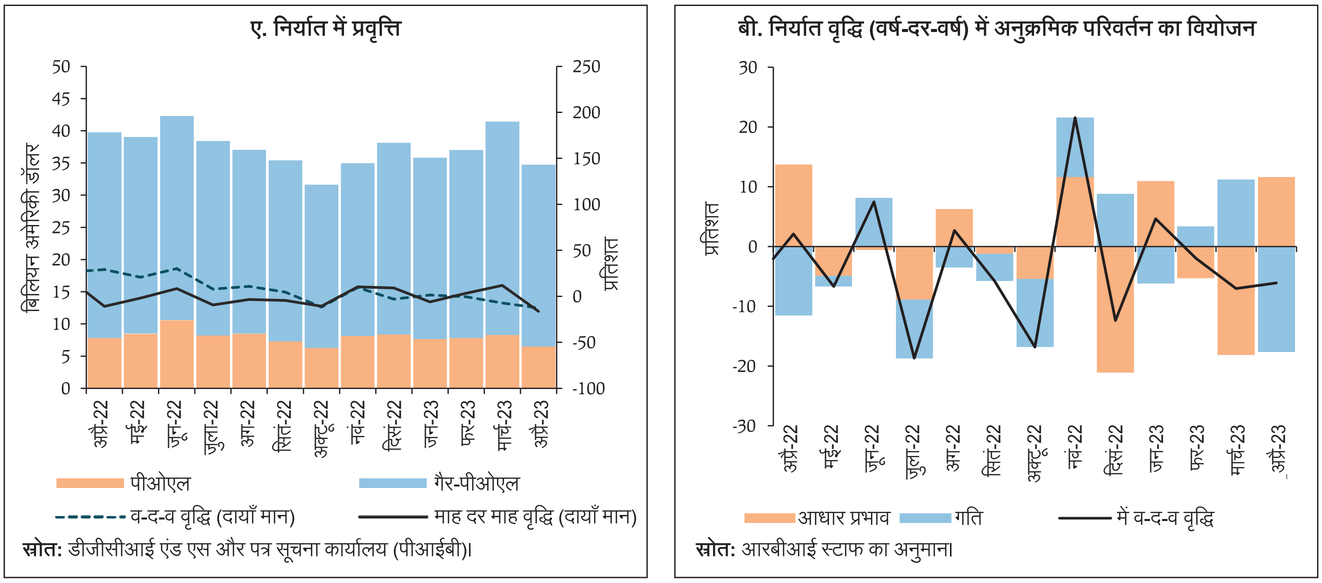

अमेरिकी डॉलर पर आ गया, जो लगातार तीसरा मासिक संकुचन है। क्रमिक आधार पर, मार्च के मुकाबले निर्यात में 16.2 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 15)।

30 प्रमुख वस्तुओं में से, निर्यात टोकरी में 73.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 19 वस्तुओं में अप्रैल में साल-दर-साल संकुचन दर्ज किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों, रत्नों और आभूषणों, इंजीनियरिंग सामानों, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान (आरएमजी) के निर्यात पर दबाव, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, चावल और तेल भोजन में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट था (चार्ट) 16)। गैर-तेल निर्यात में लगातार पांचवें महीने गिरावट रही।

2022-23 के दौरान, वह वर्ष जिसके लिए अब एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई है, पेट्रोलियम उत्पादों के कारण व्यापारिक निर्यात में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-तेल निर्यात में गिरावट आई (चार्ट 17ए) । मूल्य प्रभाव से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप मात्रा के संदर्भ में 0.4 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद मूल्य के संदर्भ में 44.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 17 बी) ।

अप्रैल 2023 में व्यापारिक आयात गिरकर 49.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीस महीने के निचले स्तर पर आ गया, जिसमें 16.9 प्रतिशत का क्रमिक संकुचन और कमोडिटी की कीमतों में कमी और विवेकाधीन वस्तुओं जैसे कि रत्न और आभूषण की मांग में गिरावट के कारण 14.1 प्रतिशत की साल-दर-साल गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 18)।

चार्ट 16: निर्यात वृद्धि में सापेक्षिक योगदान

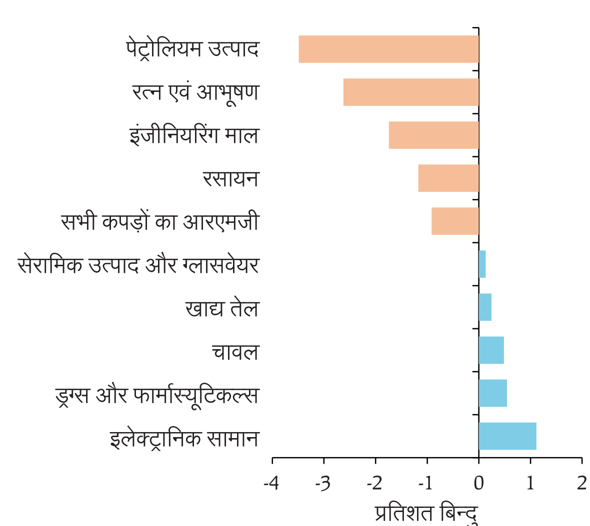

स्रोत : पीआईबी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[10] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1906801

चार्ट 17: 2022-23 में निर्यात वृद्धि का अपघटन

ए. निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

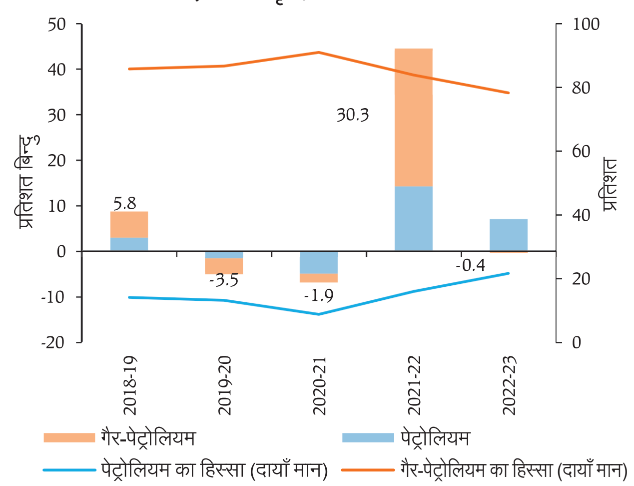

बी. पेट्रोलियम निर्यात का प्रदर्शन

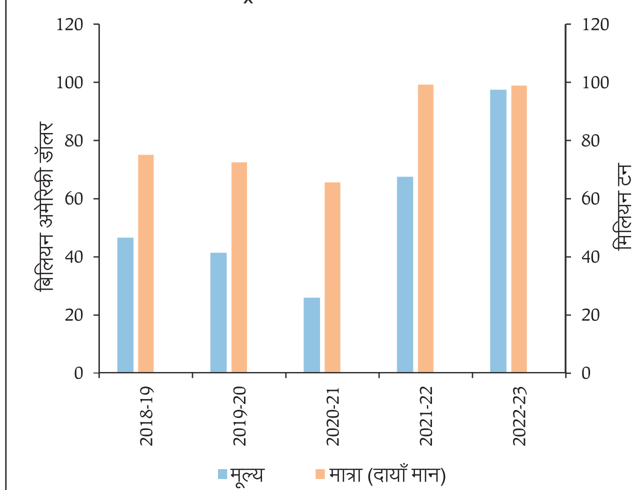

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अलग-अलग स्तर पर, अप्रैल 2023 में आयात टोकरी में 82.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 23 प्रमुख वस्तुओं में संकुचन दर्ज किया गया। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), कोयला और रसायनों ने समग्र आयात को नीचे खींच लिया जबकि मशीनरी, लोहा और इस्पात और दालों ने सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट 19 ए)। 2022-23 में व्यापारिक आयात भी 16.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 714.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 30 प्रमुख आयातित वस्तुओं में से 24 वस्तुओं, जिनका आयात टोकरी में 84.9 प्रतिशत हिस्सा है, ने 2022-23 में विस्तार दर्ज किया।

भारत का वस्तु व्यापार घाटा अप्रैल 2023 में 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीस महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। 2022-23 के दौरान, वस्तु व्यापार घाटा 2021-22 के स्तर की

चार्ट 18: पण्य वस्तु आयात

ए. आयात में प्रवृति

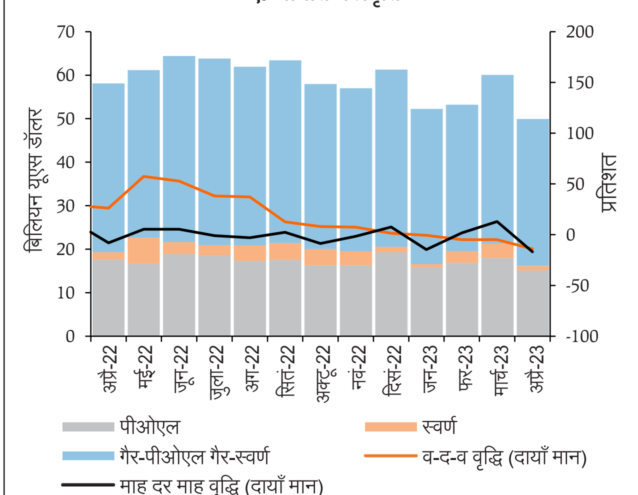

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस और पीआईबी।

बी. आयात वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में अनुक्रमिक परिवर्तन का वियोजन

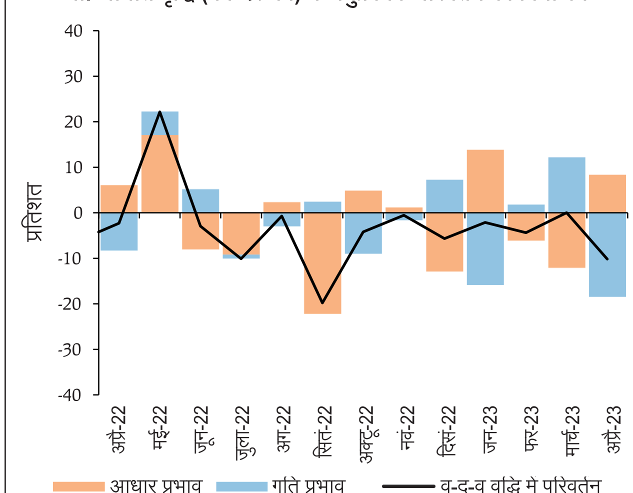

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 19: आयात वृद्धि और पण्य व्यापार घाटे के स्रोतों में सापेक्ष योगदान

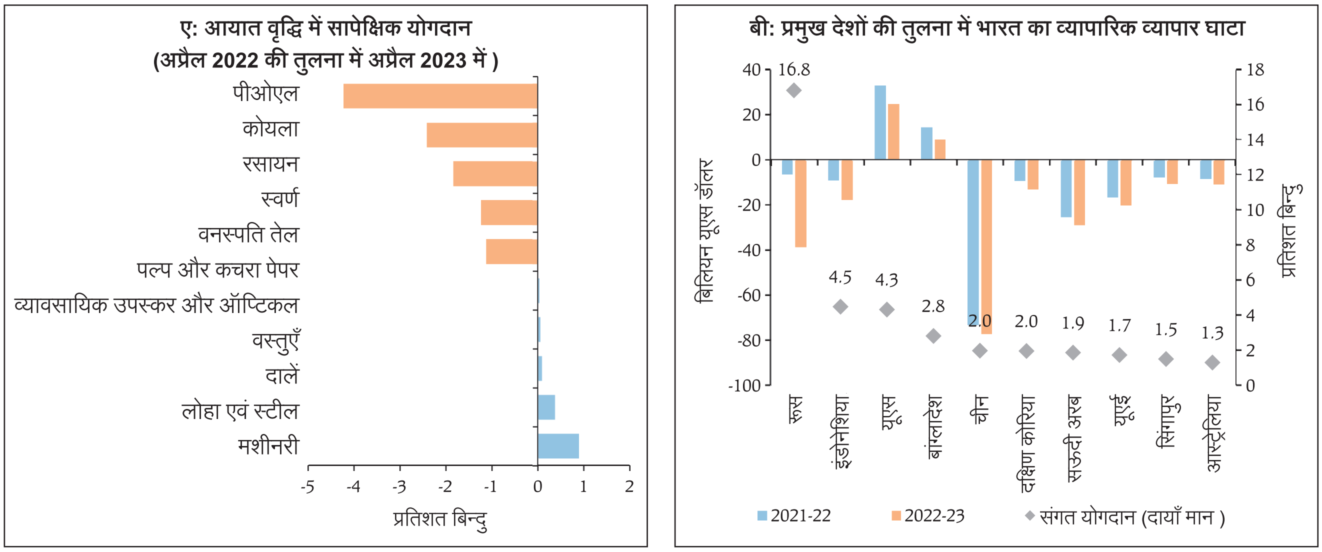

स्रोत : पीआईबी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

तुलना में 72.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया था, जिसमें रूस और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से व्यापार घाटे के निर्माण के पांचवें हिस्से से अधिक के लिए जिम्मेदार थे (चार्ट 19 बी)।

अप्रैल 2023 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.87 लाख करोड़ (जुलाई 2017 में जीएसटी के लॉन्च के बाद से सबसे अधिक मासिक संग्रह) रहा और साल-दर-साल 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका श्रेय साल के अंत में उच्च आर्थिक गतिविधि को दिया जा सकता है क्योंकि अप्रैल डेटा कवर लेनदेन जो मार्च में हुआ था (चार्ट 20)।

2022-23 के अप्रैल-फरवरी के खातों के आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), पूरे वर्ष के बजट अनुमान (बीई) के अनुपात के रूप में, एक साल पहले की तुलना में कम था (चार्ट 21ए और 21बी) । राजस्व संग्रहण में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि व्यापक आधार वाली थी। व्यय के मोर्चे पर, राजस्व और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वृद्धि मध्यम रही (चार्ट 22)।

अप्रैल-फरवरी 2023 के दौरान, राज्यों ने अपने बजटीय पूंजीगत व्यय का 61 प्रतिशत खर्च किया, मार्च 2023 में वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय के इस घटक को बैक-लोड करने की प्रवृत्ति थी।

समेकित राज्यों का जीएफडी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 2023-24 के लिए 3.2 प्रतिशत

चार्ट 20 : मासिक जीएसटी राजस्व

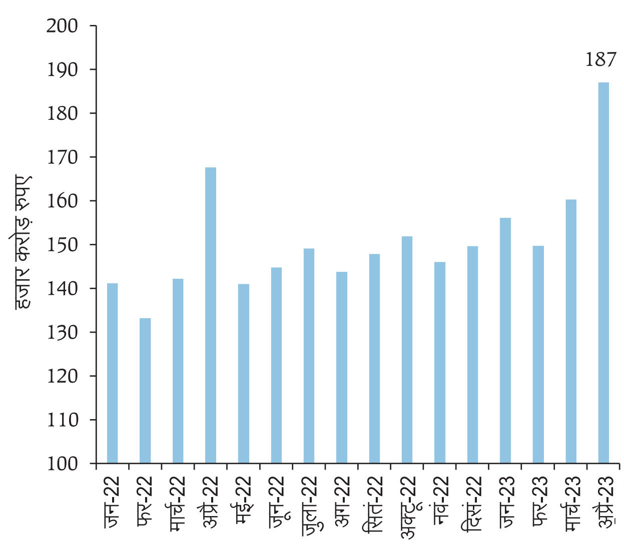

स्रोत : पीआईबी।

चार्ट 21: राज्यों के घाटे के प्रमुख संकेतक (अप्रैल-फरवरी)

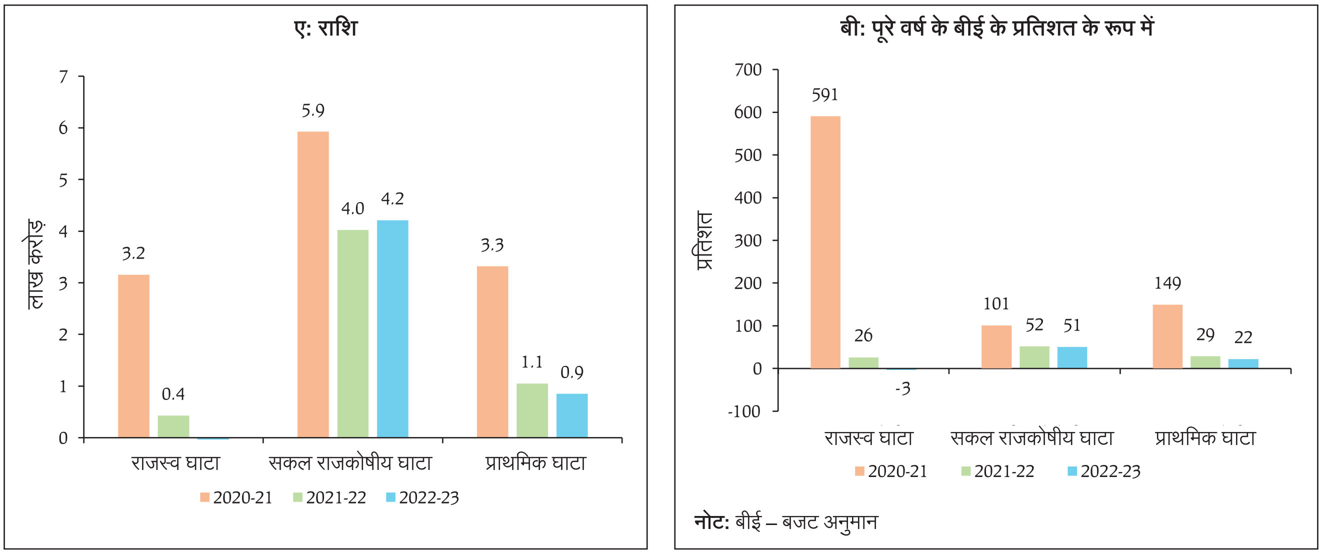

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)।

(26 राज्यों के आंकड़ों के अनुसार) बजट में रखा गया है, जो केंद्र द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर है।[11] कम जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात राजस्व व्यय में कमी के कारण है, जबकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि की उम्मीद है।

चार्ट 22: राज्यों का राजस्व और व्यय (अप्रैल-फरवरी)

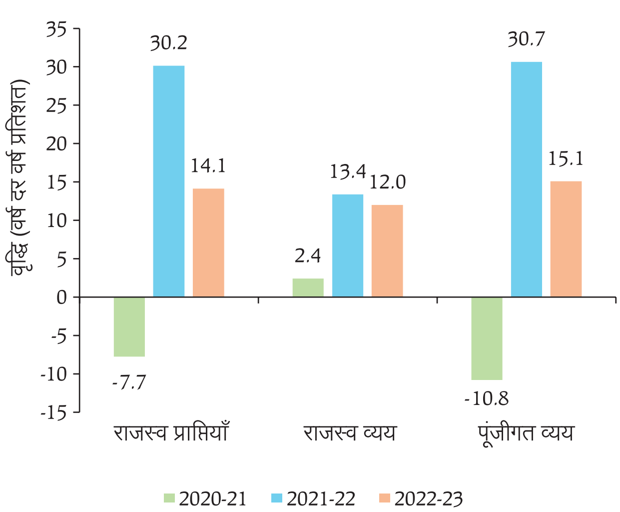

नोट: आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी।

सकल आपूर्ति

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, जून-सितंबर 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) की बारिश ±5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 96 प्रतिशत पर सामान्य होने की संभावना है।[12] तथापि, पूर्वानुमान व्यापक भौगोलिक भिन्नता को दर्शाता है जिसमें कुछ प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों के सामान्य से कम मानसून श्रेणी में आने की संभावना है (चार्ट 23क)। भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में दक्षिणी दोलन तटस्थ स्थिति मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति में बदलने की उम्मीद है, जो आम तौर पर वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हालांकि, अल नीनो का दिखाई देने वाला प्रभाव जून 2023 के बाद ही दिखाई देने की उम्मीद है और इसलिए, मानसून का प्रारंभिक चरण सामान्य होने की उम्मीद है। 16 मई, 2023 को जारी आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार,

[11] बजट अनुमान (बीई) के आंकड़े संबंधित राज्यों के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं।

[12] अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य वर्षा एलपीए के 96-104 प्रतिशत के बीच होती है। 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर, पूरे देश में मौसमी वर्षा का एलपीए 87 सेमी है।

चार्ट 23: दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा (आईएमडी लंबी अवधि पूर्वानुमान 2023)

ए: एसडब्ल्यूएम मौसम 2023 के लिए टेरसिल संभाव्यता वर्षा पूर्वानुमान

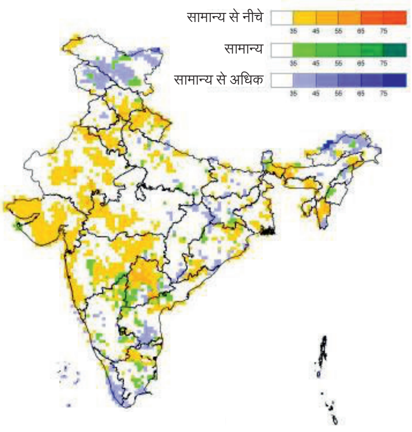

बी: अल नीनो वर्षों के दौरान वर्षा और जलाशय स्तर

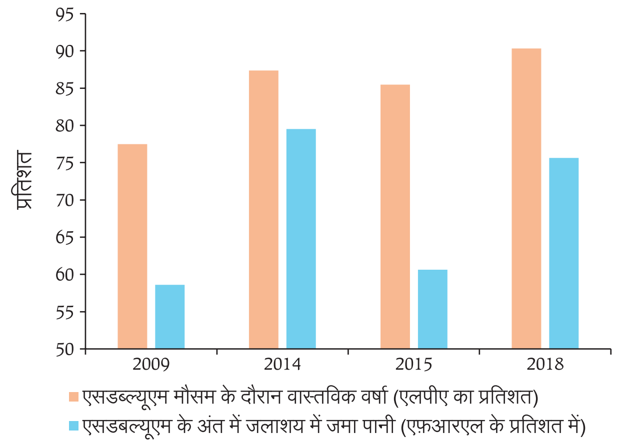

नोट: मानचित्र केवल उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है; और मानचित्र सबसे संभावित श्रेणियों के साथ-साथ एसडब्ल्यूएम वर्षा के लिए उनकी संभावनाओं को दर्शाता है। सफेद छायांकित क्षेत्र सभी टेरसिल श्रेणियों के लिए जलवायु संबंधी संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। टेरसिल श्रेणियों में 33.33 प्रतिशत की समान जलवायु संबंधी संभावनाएं हैं।
स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग; और केंद्रीय जल आयोग।

केरल में एसडब्ल्यूएम की शुरुआत में थोड़ी देरी होने की संभावना है और अब 4 जून, 2023 को इसकी उम्मीद है।[13]

ऐतिहासिक रूप से, पिछले चार अल नीनो वर्षों में एसडब्ल्यूएम सीज़न के अंत में वर्षा सामान्य से कम रही है। इसका असर देश भर में जलाशयों के स्तर पर भी पड़ सकता है, जो सर्दियों के दौरान रबी फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है (चार्ट 23बी)। फिर भी, सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) स्थितियों से 2023 में मानसून के बाद के चरण में अल नीनो के प्रभाव का मुकाबला करने की उम्मीद है।

16 मई, 2023 तक खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चावल की सार्वजनिक खरीद साल दर साल 1.8 प्रतिशत कम थी। 16 मई, 2023 तक, रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अब तक 260.1 लाख टन गेहूं की खरीद, पिछले वर्ष की कुल खरीद से 38.4 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 24)। 1 मई, 2023 को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं का सार्वजनिक स्टॉक क्रमशः बफर मानदंडों से 3.1 और 3.9 गुना था (चार्ट 25)। केएमएस 2022-23 के दौरान चावल की खरीद का लक्ष्य 51.8 मिलियन टन और आरएमएस 2023-24 के दौरान गेहूं के लिए 34.15 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

चार्ट 24: आरएमएस के दौरान संचयी गेहूं खरीद (अप्रैल-मार्च)

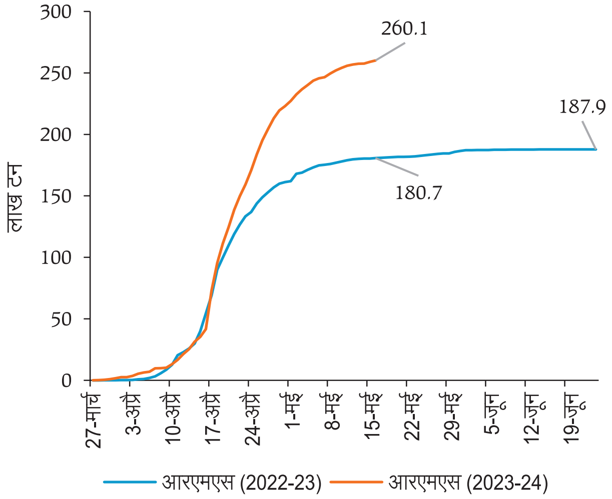

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

[13] https://internal.imd.gov.in/press_release/20230516_pr_2325.pdf

चार्ट 25: बफर मानदंडों के संदर्भ में चावल और गेहूं का सार्वजनिक स्टॉक

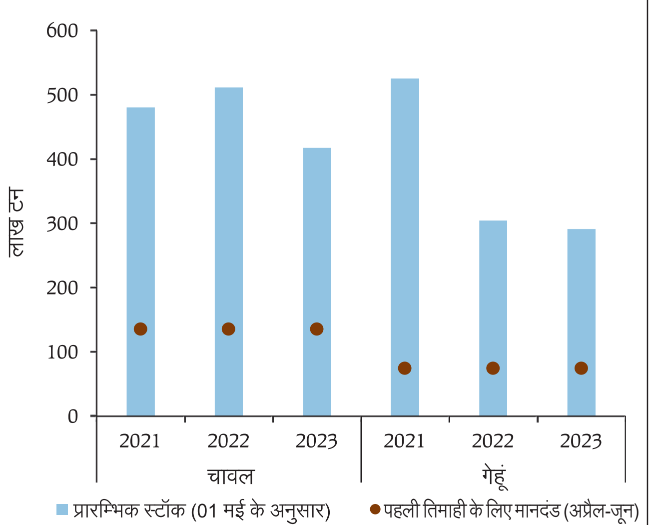

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

चार्ट 26: जलाशय की स्थिति

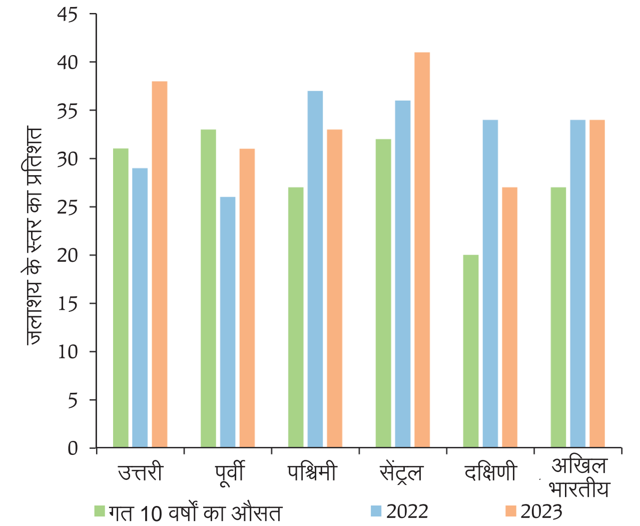

नोट: 11 मई, 2023 तक के आंकड़े।
स्रोत: सीडब्ल्यूसी।

गेहूं की बाजार में आवक, जो मार्च में असामान्य रूप से अधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों की कटाई में देरी के कारण प्रभावित हुई थी, अप्रैल में बढ़ी। परिणामस्वरूप, अप्रैल में गेहूं मंडी की कीमतें नरम बनी रहीं। हालाँकि, धान के संबंध में मूल्य दबाव बना हुआ है, जो आंशिक रूप से उच्च निर्यात मांग को दर्शाता है।

16 मई, 2023 को ग्रीष्म ऋतु की वर्षा (मार्च-मई) सामान्य वर्षा से अधिक थी, जो पूरे देश में ज़ैद (ग्रीष्म) फसलों और समग्र जलाशय स्तर के लिए अच्छा संकेत है। 11 मई, 2023 तक, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा निगरानी किए गए 146 जलाशयों में जल भंडारण कुल जलाशय क्षमता का 34 प्रतिशत था - जो पिछले वर्ष के स्तर से थोड़ा कम है, लेकिन 10 साल के औसत से 22.5 प्रतिशत अधिक है। 146 प्रमुख जलाशयों में से 92 में भंडारण दशकीय औसत से अधिक था (चार्ट 26)।

खनन और विनिर्माण के बाद बिजली के उत्पादन में मजबूत विस्तार के कारण 2022-23 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, विस्तार का नेतृत्व पूंजीगत वस्तुओं, बुनियादी ढांचे की वस्तुओं और प्राथमिक वस्तुओं द्वारा किया गया, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि 0.5 प्रतिशत पर धीमी रही। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी उपयोग-आधारित श्रेणियों का सूचकांक मूल्य 2022-23 में महामारी-पूर्व (2019-20) के स्तर को पार कर गया (चार्ट 27)।

चार्ट 27: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

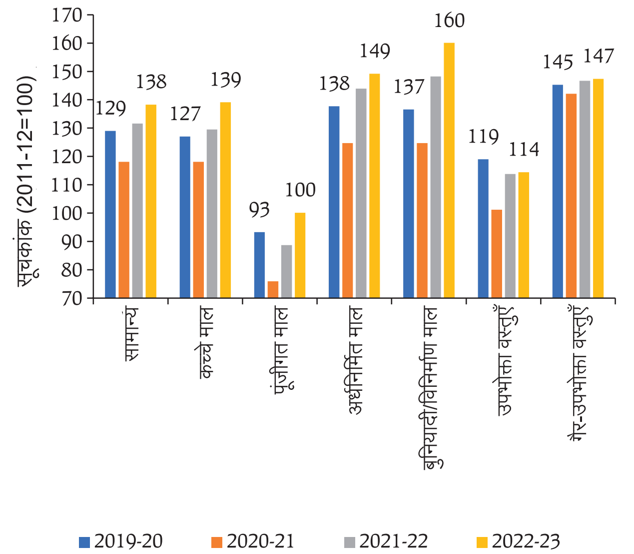

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

चार्ट 28: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

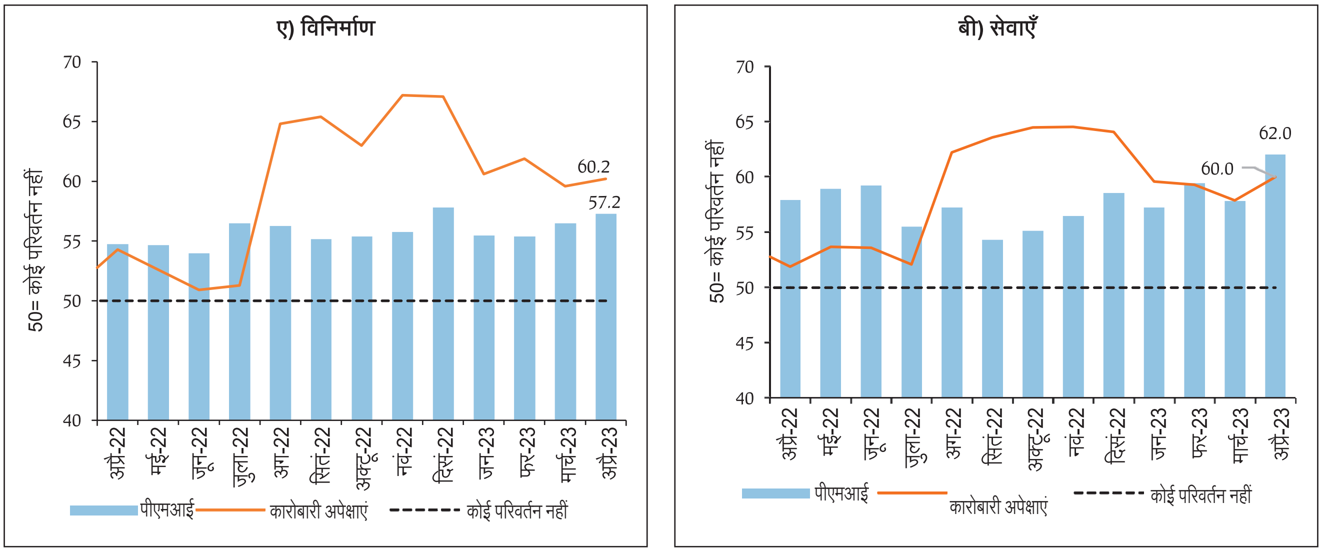

स्रोत: एस&पी ग्लोबल।

विनिर्माण के लिए हेडलाइन पीएमआई अप्रैल 2023 में सभी उप-सूचकांकों (चार्ट 28 ए) में व्यापक आधार पर विस्तार के साथ चार महीने के उच्च स्तर 57.2 पर पहुंच गया। सेवा क्षेत्र में उत्पादन अप्रैल 2023 में 62.0 (जुलाई 2010 के बाद से उच्चतम) पर लगभग 13 वर्षों में सबसे तेज दर से विस्तारित हुआ, जिसका नेतृत्व नए व्यवसाय की वृद्धि और अनुकूल बाजार स्थितियों में तेजी (चार्ट 28 बी) ने किया।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतक अप्रैल में नरम हुए। लौह अयस्क, कच्चे उर्वरक और पीओएल कार्गो में संकुचन के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में वृद्धि घटकर 1.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट 29ए)। खाद्यान्न ढुलाई में गिरावट के कारण रेलवे माल ढुलाई आय में वार्षिक वृद्धि कम हो गई (चार्ट 29बी)।

चार्ट 29: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक

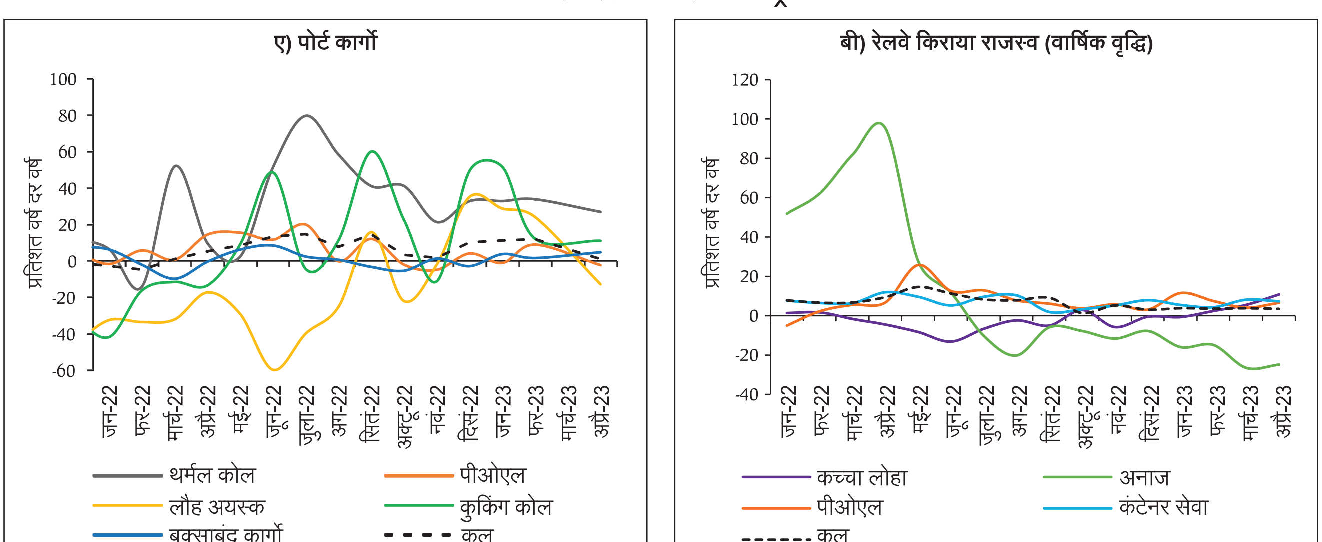

स्रोत: भारतीय पोत संघ

स्रोत: रेल दृष्टि।

निर्माण क्षेत्र गतिविधि संकेतकों के बीच, स्टील की खपत की वृद्धि अप्रैल में घटकर 7.2 प्रतिशत हो गई (वर्ष-दर-वर्ष) जबकि सीमेंट उत्पादन में मार्च में मामूली संकुचन देखा गया (चार्ट 30)।

अप्रैल 2023 के लिए सेवा क्षेत्र में उच्च-आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि में गति बनाए रखने का संकेत देते हैं। दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी के साथ ऑटोमोबाइल की बिक्री में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में दोहरे अंक की वृद्धि जारी रही (सारणी1)।

भारत में मापी गई आर्थिक गतिविधियों का लगभग आधा हिस्सा असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में होता है जिसका उचित मापन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। [14] असंगठित क्षेत्र गतिविधि के लिए एक मासिक समग्र सूचकांक (यूएनसीसीआई) [15] , जो इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को ट्रैक करता है, 2022-23 की चौथी

चार्ट 30: स्टील खपत और सीमेंट निर्माण

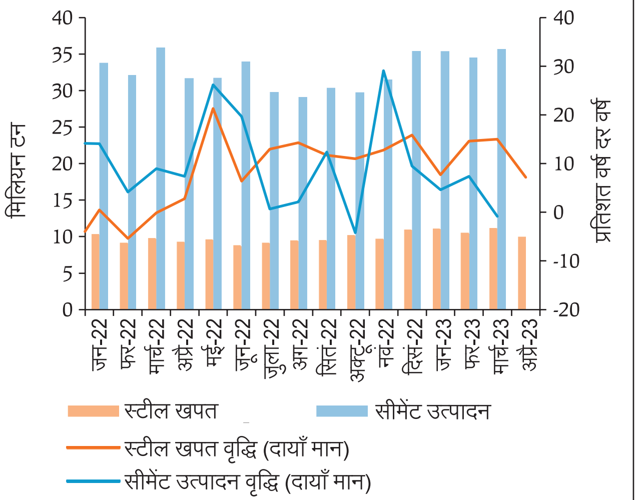

स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति और आर्थिक परामर्शदाता, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यालय

सारणी 1 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-22	नवं-22	दिसं-22	जन-23	फर-23	मार्च-23	अप्रै-23
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	28.6	28.1	7.2	17.2	11.0	4.5	12.9
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहन बिक्री	2.3	17.7	3.9	5.0	7.6	7.7	15.1
	तीन पहिया वाहन बिक्री	70.4	103.2	37.6	103.0	86.1	69.2	104.2
	ट्रैक्टर बिक्री	6.8	6.5	25.6	24.4	20.0	13.7	-11.1
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री		11.5			7.1		
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	1.4	5.2	3.1	3.8	3.6	3.8	3.5
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.1	1.8	10.3	12.2	12.0		1.3
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-22.8	0.1	0.5	-7.5	0.0	-4.4	-1.7
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-21.2	1.5	-10.7	-4.3	-8.1	0.8	-3.0
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	17.2	14.7	19.5	95.3	50.2	22.9	23.2
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	89.8	101.7	91.6	115.1	98.0	62.4	43.9
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	4.6	32.0	17.5	19.7	18.4	16.3	12.2
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	12.0	37.7	23.2	24.1	22.2	20.7	16.2
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	-5.9	23.1	8.6	12.8	12.4	9.3	5.9
	यात्री आगमन	243.2	191.3	204.2	330.8	259.4	132.5	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	11.0	12.8	15.9	7.7	14.6	15.0	7.2
	सीमेंट उत्पादन	-4.2	29.1	9.5	4.6	7.4	-0.8	
पीएमआई #	सेवाएँ	55.1	56.4	58.5	57.2	59.4	57.8	62

नोट: ; #: स्तरों के आधार पर डेटा।
स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी डेटा; आईएचएस मार्किट; सियाम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त संयंत्र समिति।

[14] घरेलू क्षेत्र जीवीए द्वारा प्रस्तुत असंगठित क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का आधिकारिक अनुमान लगभग 10 महीने के अंतराल के साथ वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसके अलावा ये डेटा फिलहाल 2021-22 तक के लिए ही उपलब्ध हैं.

[15] यूएनसीसीआई राज्य-अंतरिक्ष ढांचे में गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके एक संकेतक-आधारित दृष्टिकोण (भौमिक एट अल।, 2022) अपनाता है।

चार्ट 31: असंगठित समग्र संयोग सूचकांक (यूएनसीसीआई)

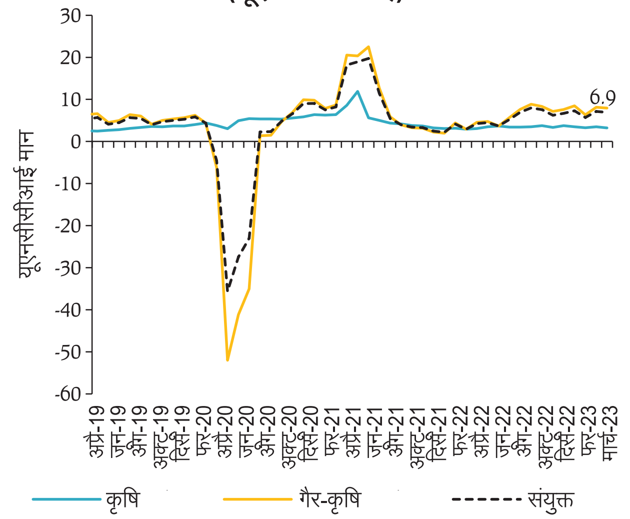

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

तिमाही के दौरान असंगठित गैर-कृषि गतिविधि में सुधार की ओर इशारा करता है (चार्ट 31)।

क्षेत्रीय नीति पहल के संदर्भ में, हरियाणा ने 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड' (एचकेआरएनएल) एंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया जो राज्य में उद्योगों को भर्ती के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। पंजाब ने किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की 10 प्रतिशत राशि खेत मजदूरों के लाभ के लिए निर्धारित करने की पहल की। व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने और विनिर्माण और व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन बोझ को दूर करने के लिए, दिल्ली ने डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी संबंधित सेवाओं के लिए अनुमोदन में तेजी लाने के उद्देश्य से 70 सुधारों को मंजूरी दी। तमिलनाडु उन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में मदद करने के लिए हथकरघा और पावर-लूम की जियो-टैगिंग शुरू करेगा जो वास्तविक बुनकरों की सहायता करेगी, इसके अलावा उन्हें मूल्यवर्धित कपड़े का उत्पादन करने के लिए करघे को उन्नत करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी।

मुद्रा स्फ़ीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल बदलावों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मार्च में 5.7 प्रतिशत से तेजी से कम होकर अप्रैल 2023 में 4.7 प्रतिशत हो गई।[16] मुद्रास्फीति में गिरावट खाद्य, ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में व्यापक आधार पर थी, जो समग्र मुद्रास्फीति (चार्ट 32 ए और चार्ट 32 बी) में

चार्ट 32 : सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक

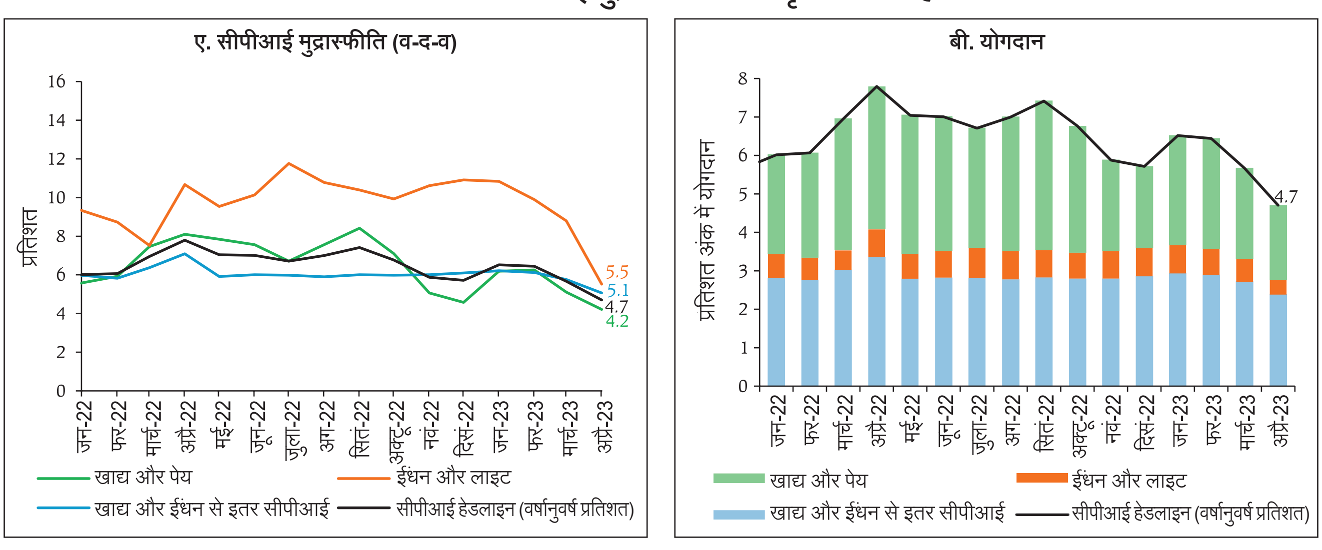

नोट: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।
स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[16] 12 मई, 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

उनके गिरते योगदान में भी परिलक्षित हुई। हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट मौद्रिक नीति को सख्त करने, आपूर्ति बढ़ाने के उपायों और अनुकूल आधार प्रभाव के संयुक्त प्रभाव के कारण थी।

लगभग 145 बीपीएस के बड़े अनुकूल आधार प्रभाव के कारण सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) अप्रैल 2023 में तेजी से घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 5.1 प्रतिशत थी, जो लगभग 55 बीपीएस की सकारात्मक मूल्य गति से ऑफसेट से अधिक थी। इस समूह के भीतर, फल, अनाज, दूध, अंडे, मसाले, गैर-अल्कोहल पेय और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति तेजी से कम हुई। जबकि खाद्य तेलों में एक महीने पहले की तुलना में तीव्र अपस्फीति देखी गई, सब्जियों, मांस और मछली की कीमतों में मार्च की तुलना में अप्रैल में अपस्फीति की कम दर दर्ज की गई। दूसरी ओर, दालों और चीनी की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ी (चार्ट 33)।

ईंधन और प्रकाश समूह में मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी, मुख्य रूप से केरोसिन की कीमतों (पीडीएस और अन्य स्रोतों) में गिरावट के कारण।

कोर मुद्रास्फीति मार्च के 5.8 प्रतिशत से घटकर अप्रैल में 5.1 प्रतिशत पर आ गई, जिसका आधार प्रभाव करीब 120 आधार अंक अधिक है। यह मई 2022 के बाद से कोर मुद्रास्फीति में सबसे तेज मासिक गिरावट है। नौ उप-समूहों में से छह (मनोरंजन और मनोरंजन; कपड़े और जूते; आवास; घरेलू सामान और सेवाएं; स्वास्थ्य; और परिवहन और संचार) में मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ कमी आई। दूसरी ओर, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, शिक्षा, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 34)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति 4.68 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2023 में शहरी मुद्रास्फीति (4.85 प्रतिशत) की तुलना में मामूली कम थी। अधिकांश राज्यों ने 4-6 प्रतिशत की

चार्ट 33 : उप-समूहों में मुद्रास्फीति (व-द-व) और परिवर्तन (माह-दर-माह)

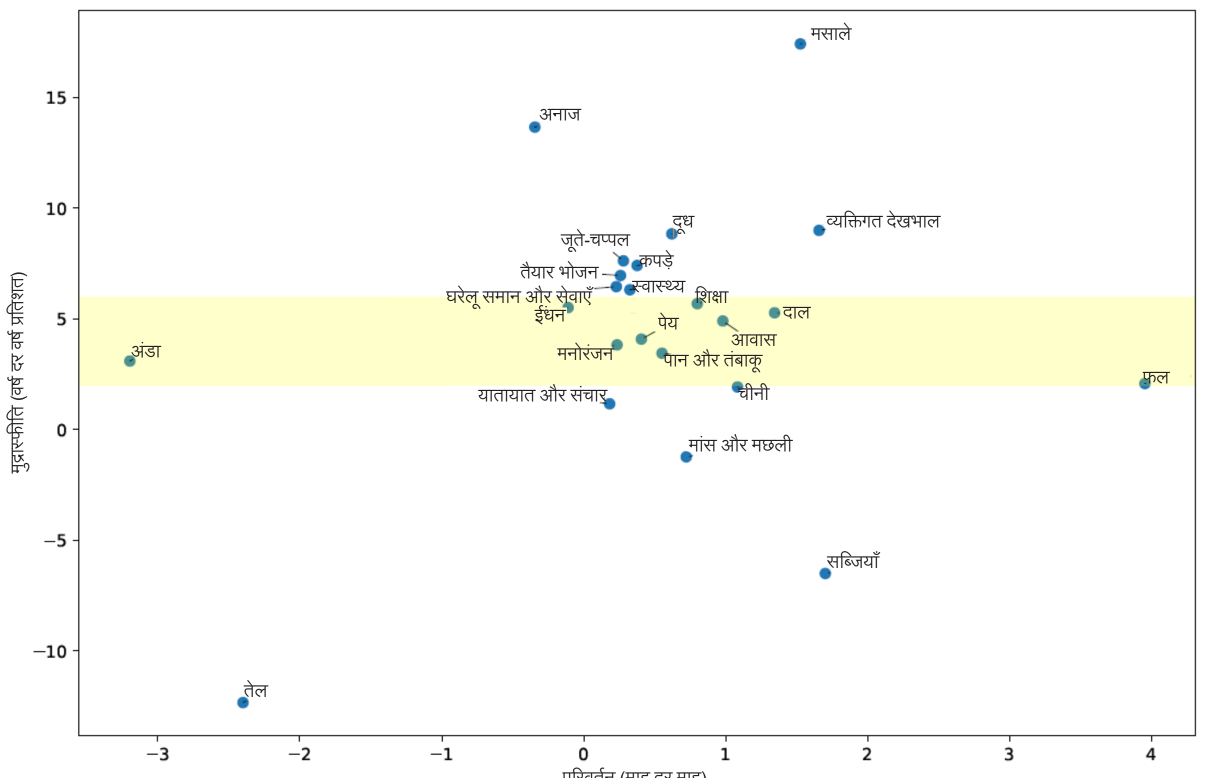

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

चार्ट 34 : मार्च 2023 बनाम अप्रैल 2023 में उप-समूहों के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति

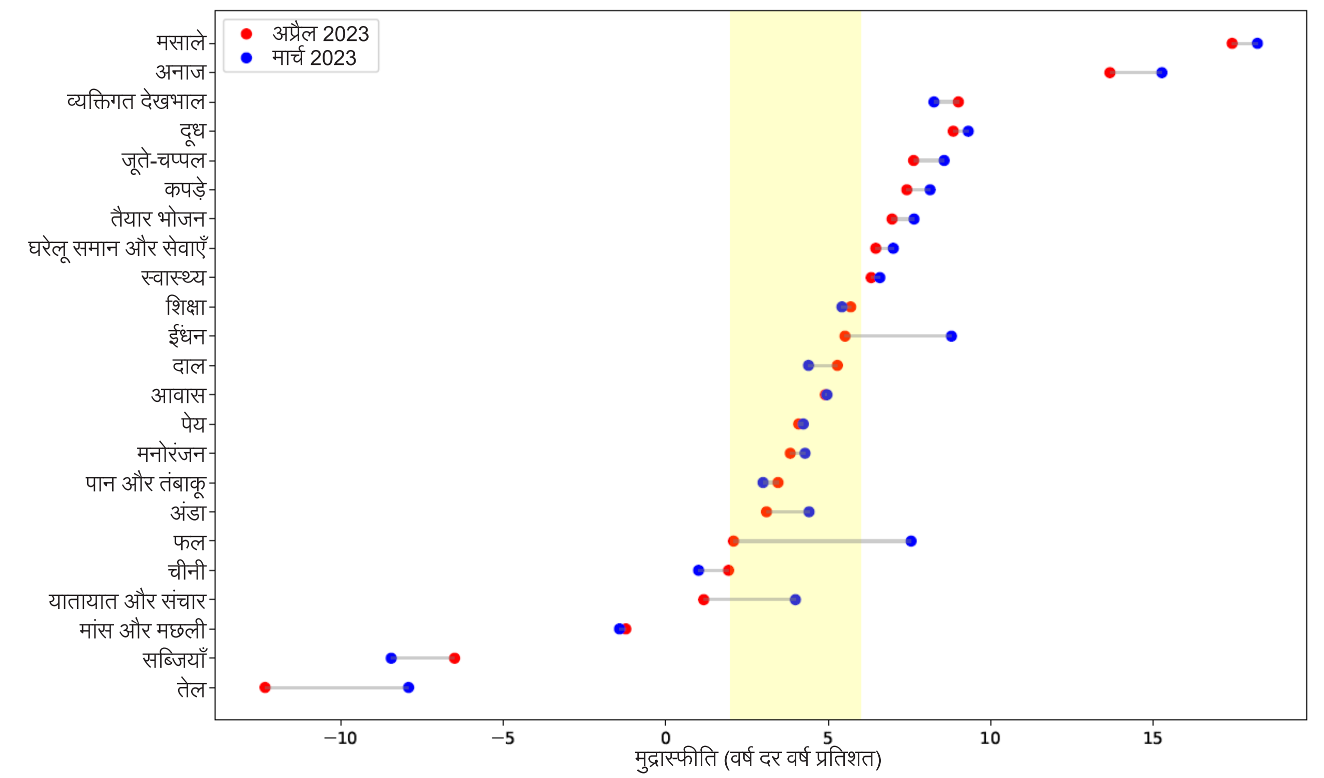

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सीमा में मुद्रास्फीति दर्ज की, केवल त्रिपुरा ने 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव किया (चार्ट 35)।

चार्ट 35: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण अप्रैल 2023 (सीपीआई - संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)

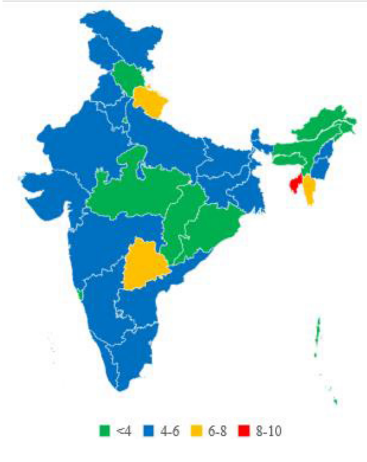

नोट: मानचित्र केवल उदाहरण के उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मई (1-12 मई) के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा अनाज की कीमतों में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, मुख्य रूप से चावल के कारण (चार्ट 36 ए)। दालों की कीमतों, विशेष रूप से अरहर दाल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आई (चार्ट 36 बी और 36 सी)। प्रमुख सब्जियों में, प्याज और टमाटर की कीमतों में नरमी दर्ज की गई जबकि आलू की कीमतों में वृद्धि हुई (चार्ट 36 डी)।

मई के दौरान अब तक, जबकि चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें और एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं, केरोसिन की कीमतों में गिरावट जारी रही (सारणी 2)।

औद्योगिक इनपुट और कृषि इनपुट के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई इनपुट लागत मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में और कम हो गई (चार्ट 37)। औद्योगिक इनपुट लागत में गिरावट मुख्य रूप से गैर-खाद्य वस्तुओं, हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और बिजली की कीमतों में कमी को दर्शाती है,

चार्ट 36 : डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य

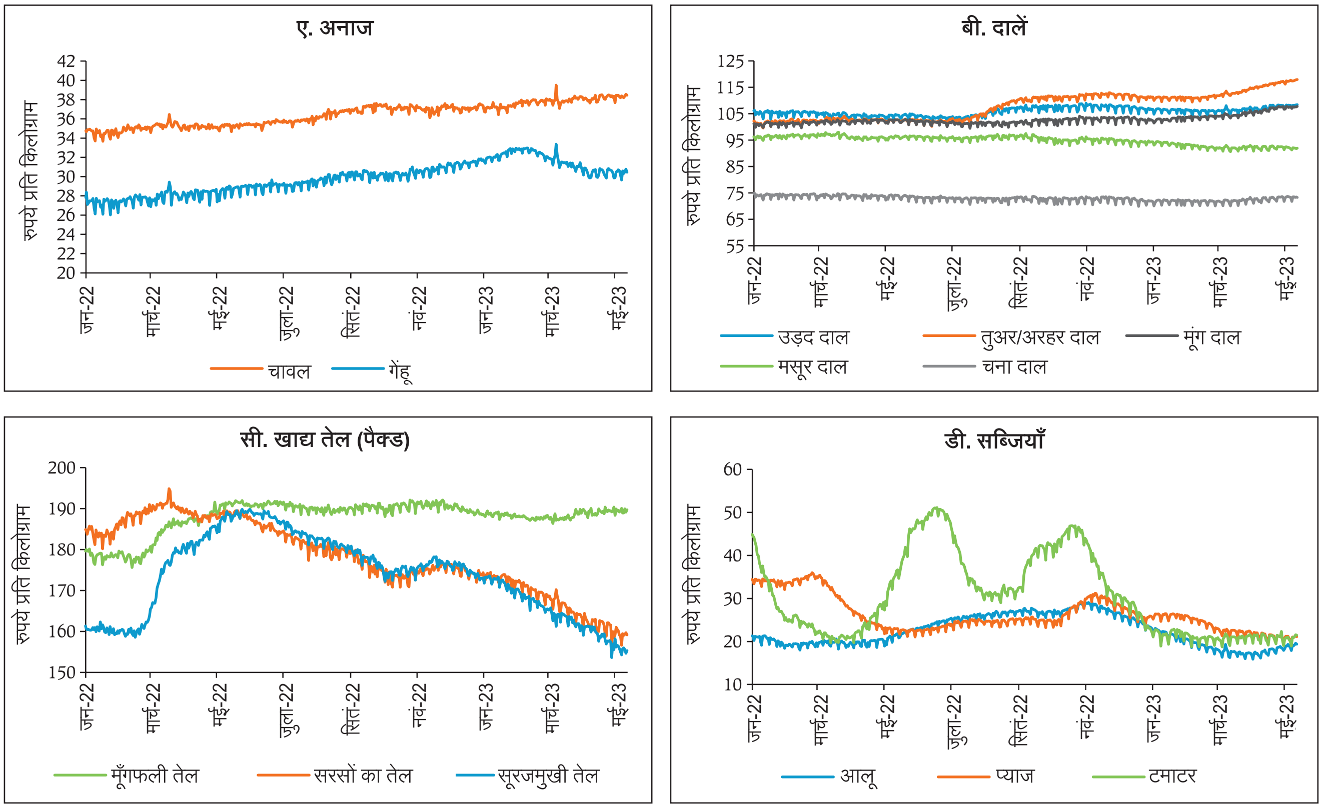

स्रोत : उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ के आकलन

जबकि उर्वरक, एचएसडी और बिजली की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि इनपुट लागत में काफी हद तक कमी आई है।

अप्रैल 2023 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इनपुट लागत में क्रमिक वृद्धि का संकेत दिया। विशेष रूप से सेवाओं (चार्ट 38ए और 38बी) के लिए बिक्री कीमतें भी बढ़ गईं। विनिर्माण और सेवाओं के लिए इनपुट और आउटपुट

सारणी 2: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह दर माह (प्रतिशत)	
		मई-22	अप्रै-23	मई-23^	अप्रै-23	मई-23^
पेट्रोल	₹/लीटर	110.14	102.92	102.92	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	98.27	92.72	92.72	0.0	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	58.81	49.20	47.55	-9.2	-3.3
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सलिंडर	1001.76	1113.25	1113.25	0.0	0.0

^: 1-12 मई 2023 की अवधि के लिए।

नोट: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 37: इनपुट लागत

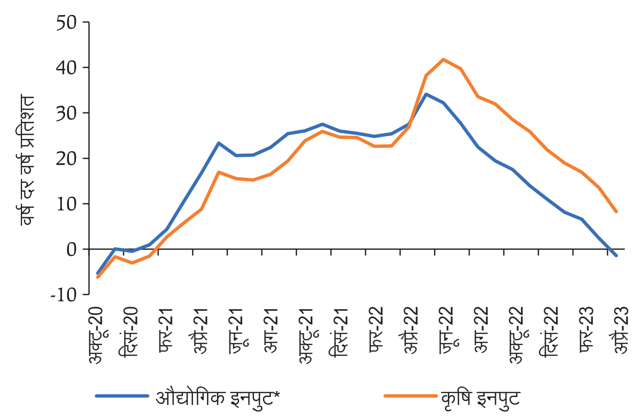

नोट: * प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुओं, खनिजों, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस ऑयल, ल्यूब ऑयल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, सूती धागे और डब्ल्यूपीआई से पेपर और लुगदी शामिल हैं।

$ डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि और वानिकी मशीनरी शामिल है।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 38: पीएमआई - इनपुट और आउटपुट मूल्य

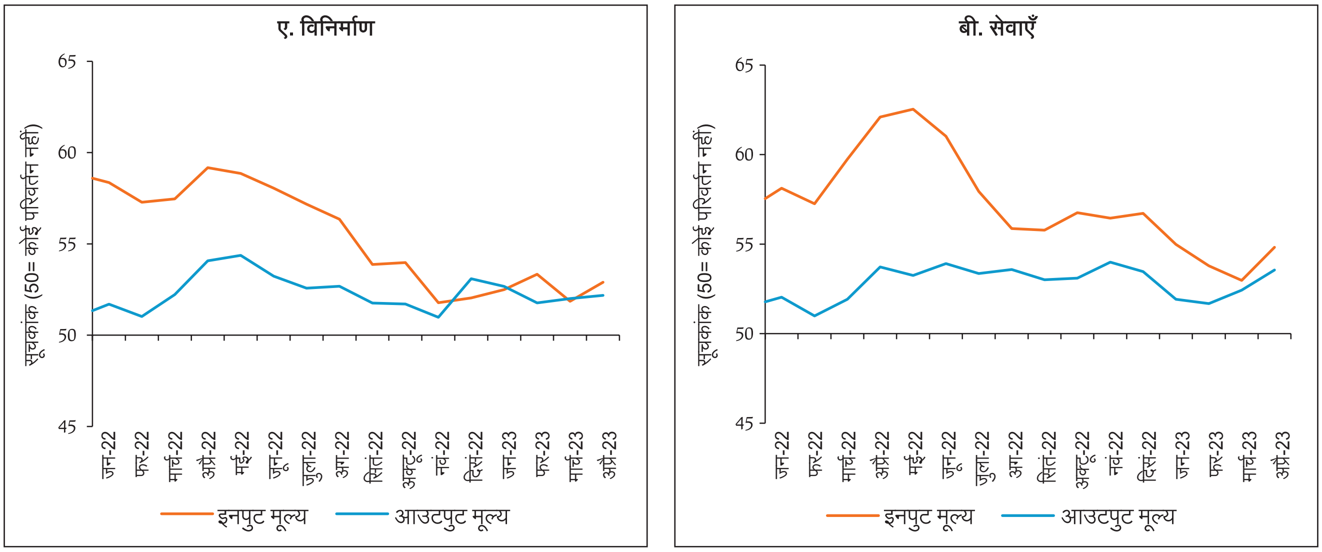

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

कीमतों के बीच का अंतर क्रमशः 0.7 और 1.3 प्रतिशत अंक बढ़ गया।

IV. वित्तीय स्थिति

अप्रैल 2023 की पहली छमाही में काफी ढील देने के बाद, दूसरी छमाही के दौरान सरकारी नकदी शेष के निर्माण के कारण तरलता की स्थिति कड़ी हो गई। इसके बाद, सरकार द्वारा महीने के अंत में खर्च में क्षणिक ढील को छोड़कर, मई 2023 की पहली छमाही के दौरान तरलता की स्थिति ज्यादातर तंग रही। तदनुसार, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत कुल अवशोषण 16 अप्रैल से 15 मई, 2023 के दौरान घटकर 1.3 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2023 के दौरान 2.0 लाख करोड़ रुपये था। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत धन का प्लेसमेंट 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2023 के दौरान 1.6 लाख करोड़ रुपये से घटकर 0.95 लाख करोड़ रुपये रह गया। इन घटनाक्रमों को दर्शाते हुए, 21 अप्रैल और 4 मई को आयोजित पाक्षिक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के लिए बैंकों की ओर से धीमी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के मुकाबले क्रमशः 20,480 करोड़ रुपये और 8,447 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) का सहारा भी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से 15 मई (औसतन 0.22 लाख करोड़ रुपये) में 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2023 (0.11 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में अधिक था। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान एलएएफ के तहत शुद्ध अवशोषण 0.92 लाख करोड़ रुपये था, जो मार्च के मध्य से 15 अप्रैल, 2023 के दौरान 0.93 लाख करोड़ रुपये के समान था (चार्ट 39)।

भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) धीरे-धीरे अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा की ओर

चार्ट 39 : चलनिधि परिचालन

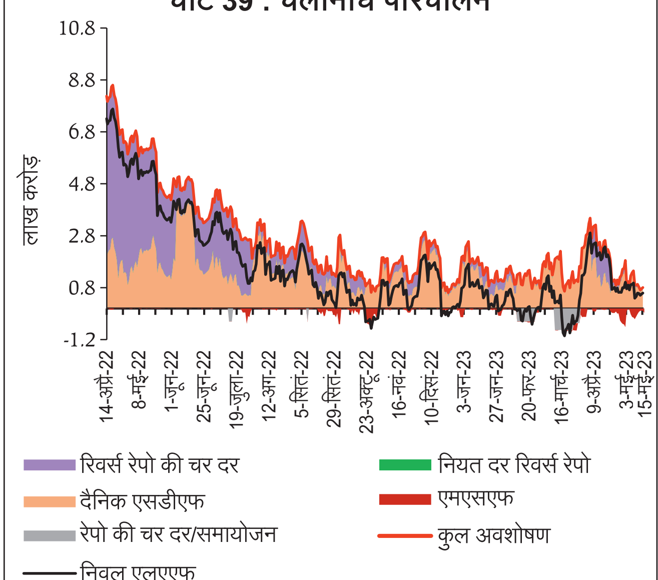

स्रोत: आरबीआई और सीसीआईएल।

मजबूत हो गई। तालमेल में, अन्य रातोंरात मुद्रा बाजार दरें भी कठोर हो गईं। औसत आधार पर, डब्ल्यूएसीआर, ट्राइपार्टी रेपो और मार्केट रेपो दरों ने 16 अप्रैल से 15 मई, 2023 के दौरान पॉलिसी रेपो रेट से ऊपर क्रमशः 17 बीपीएस, 19 बीपीएस और 18 बीपीएस का कारोबार किया (चार्ट 40 ए)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल), जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल 16 अप्रैल से 3 मई, 2023 के दौरान बड़े पैमाने पर एमएसएफ दर से ऊपर कारोबार कर रहा था (चार्ट 40 बी)। प्राथमिक बाजार में सीडी जारी करने के जरिये कोष 2023-24 (पांच मई तक) के दौरान 0.27 लाख करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष के 0.33 लाख करोड़ रुपये से मामूली कम है। दूसरी ओर, 2023-24 (15 मई तक) के दौरान सीपी जारी करना एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 1.5 लाख करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित था।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत रेपो दर पर रोक लगाने के अप्रत्याशित कदम के बाद रुख में बदलाव की संभावना से सरकारी प्रतिभूतियों की मजबूत मांग को दर्शाते हुए बॉन्ड बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिला। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने भी बाजार की भावनाओं का समर्थन किया (चार्ट 41)।

चार्ट 41: 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में परिवर्तन

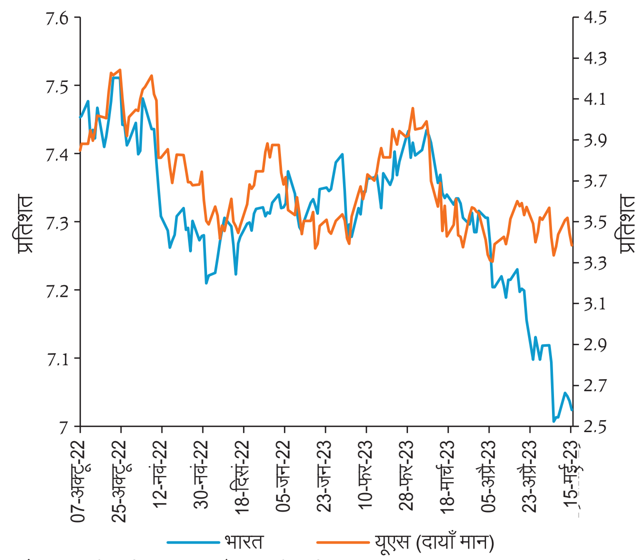

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक (7.26% जीएस 2033) पर प्रतिफल 14 अप्रैल को 7.22 प्रतिशत से घटकर 3 मई, 2023 को 7.00 प्रतिशत हो गया, जो सितंबर 2022 के बाद से इसका

चार्ट 40 : नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर

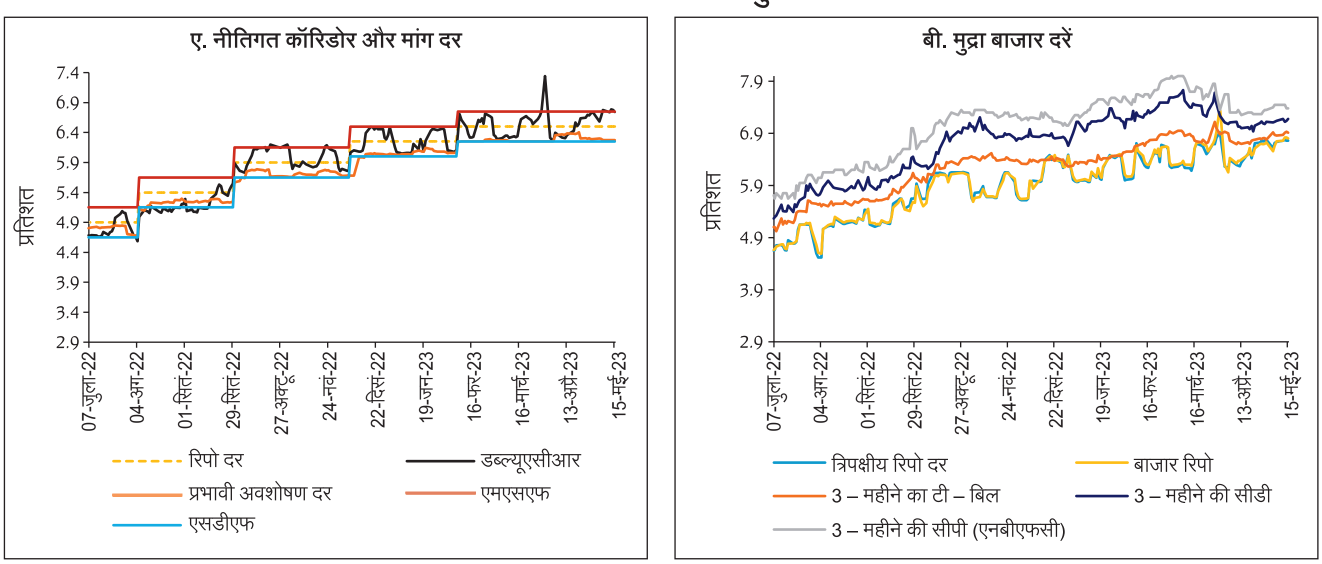

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

सबसे निचला स्तर है। इसके बाद प्रतिफल सीमित दायरे में रहा और 10 वर्षीय जी-सेक 15 मई, 2023 को 6.99 प्रतिशत पर बंद हुआ। विभिन्न परिपक्वता ओं में प्रतिफल अंतर मई 2023 की शुरुआत में कम हो गया (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल अभिसरण: संकेत या शोर?

12 मई, 2023 को 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल (टी-बिल) से बेंचमार्क 10-वर्षीय परिपक्वता प्रतिभूति तक की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर प्रतिफल 5 आधार अंक[17] (बीपीएस) (चार्ट 1) की संकीर्ण सीमा तक पहुंच गया।

नतीजतन, जी-सेक बाजार में टर्म स्प्रेड, जो 2019 की दूसरी छमाही से बढ़ रहा था और 2022 की शुरुआत से कम होने से पहले महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान तेजी से बढ़ रहा था, कई साल के निचले स्तर पर आ गया है। उदाहरण के लिए, 91-दिवसीय टी-बिल और 10-वर्षीय प्रतिभूति के बीच प्रतिफल का फैलाव 2021 के अंत में लगभग 300 बीपीएस से घटकर लगभग 5 बीपीएस हो गया है; 2 साल और 10 साल के जी-सेक के बीच लगभग 200 बीपीएस से लगभग 12 बीपीएस तक; और 5 साल और 10 साल के जी-सेक के बीच लगभग 65 बीपीएस से 6 बीपीएस से कम [चार्ट 2]।

चार्ट 2: चुनिंदा परिपक्वताओं में स्प्रेड

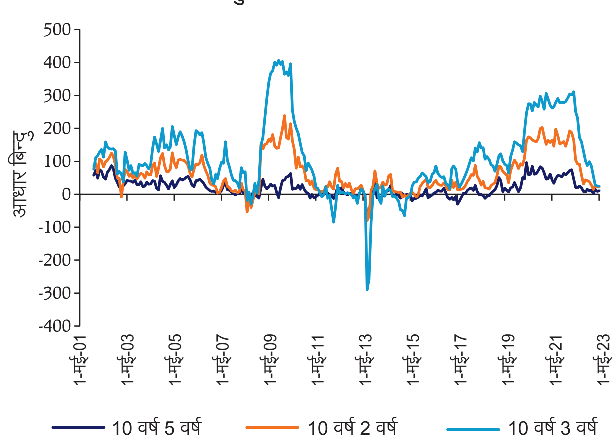

स्रोत: रिफाइनिटिव।

यह घटना एक बहु-वर्षीय आवृत्ति पर होती है, उदाहरण के लिए, यूरो ऋण संकट के दौरान; टेंपर टैंट्रम; और 2008 के उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय संकट के बीच।

प्रतिफल वक्र के (बियर फ्लैटेनिंग) के रूप में संदर्भित , यह प्रतिफल वक्र व्यवस्थाओं के बीच संक्रमण से जुड़ा हुआ है जो आम तौर पर नीति दर चक्रों के अनुरूप होता है (चार्ट 3)।

हालिया अभिसरण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों के संगम, वैश्विक मौद्रिक नीति के घटनाक्रमों से स्पिलओवर, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और सुरक्षित निवेश उड़ानों को दर्शाता है। घरेलू ड्राइवरों में लंबी अवधि के निवेशकों,

चार्ट 1: जी-सेक प्रतिफल और नीतिगत दर

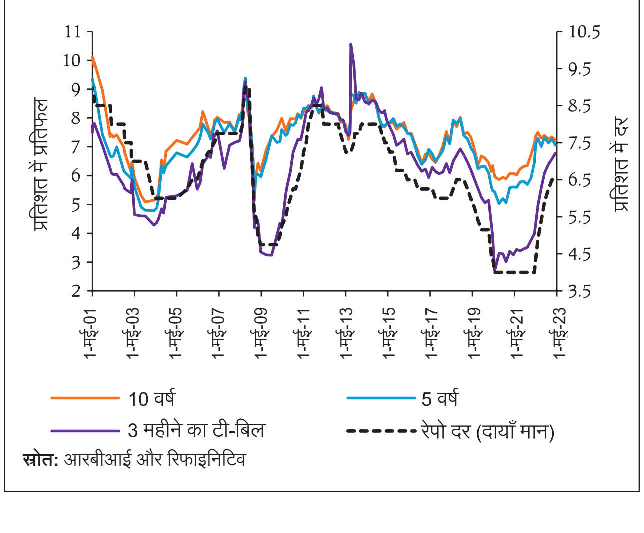

स्रोत: आरबीआई और रिफाइनिटिव

चार्ट 3: प्रतिफल वक्र में परिवर्तन

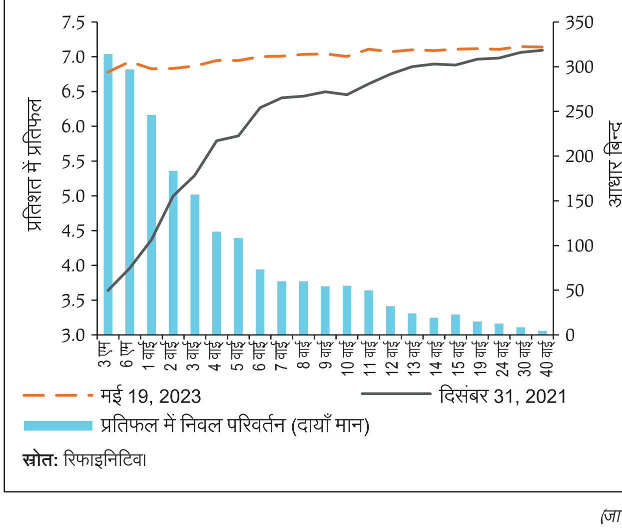

स्रोत: रिफाइनिटिव।

(जारी)

[17] इस प्रसार की गणना 12 मई, 2023 को 91-दिवसीय टी-बिल के लिए नवीनतम उपलब्ध नीलामी कट-ऑफ प्रतिफल का उपयोग करके की जाती है , जो 10 मई, 2023 को 6.9482 प्रतिशत थी (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55655).

[18] बियर फ़्लैटनिंग एक ऐसी घटना है जहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक ब्याज दरें लंबी अवधि की दरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं, जिससे प्रतिफल वक्र समतल हो जाता है।

मुख्य रूप से बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और भविष्य निधि से मजबूत मांग शामिल है। मार्च 2023 से, कुछ न्यायालयों में बैंकिंग संकट का जोरदार समाधान, मौद्रिक नीति कार्यों में कमी या ठहराव और भावनाओं से जोखिम की वापसी प्रतिफल अभिसरण के अतिरिक्त चालक हैं। असममित जमा संग्रहण और बैंकों द्वारा अपनाई जा रही अलग-अलग तरलता और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, रबी फसल परिचालन से संबंधित मुद्रा की मांग में वृद्धि, सरकारी खर्च में कमी और कर बहिर्वाह के कारण बाजार भागीदारों के बीच तरलता के असमान वितरण के कारण घरेलू तरलता की स्थिति में छिटपुट सख्ती के कारण अल्पकालिक प्रतिफल में वृद्धि हुई है।

एक नीतिगत दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है: क्या यह एक अज्ञात विकास है, या यह व्यापक आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में बाजार की अपेक्षाओं का संकेत दे रहा है? इस स्तर पर, वास्तविक परिणामों को परिभाषित करने वाले डेटा बिंदुओं की कमी को देखते हुए, केवल संयोजन पूर्वानुमान का प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले, सर्वेक्षण-आधारित साक्ष्य[19] के संयोजन के साथ पढ़ने वाले प्रतिफल वक्र के चपटेपन से पता चलता है कि 2022 के दौरान कई और अतिव्यापी झटकों का सामना करने के बाद मुद्रास्फीति की उम्मीदें फिर से कम हो रही हैं। दूसरा, यह एक साल पहले की तुलना में 2023-24 में धीमी वृद्धि की आम सहमति की उम्मीदों को दर्शाता है - आरबीआई को उम्मीद है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2022-23 में 7.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.5 प्रतिशत हो जाएगी, जिसमें जोखिम इस आधारभूत प्रक्षेपण के आसपास समान रूप से संतुलित होंगे। तीसरा, यह संकेत दे सकता है कि ऋण बाजारों में वित्तीय स्थितियां - जिसके लिए जी-सेक प्रतिफल वक्र एक बेंचमार्क है - तटस्थ हैं और इसलिए, दीर्घकालिक संसाधन जुटाने की तलाश करने वाले व्यवसायों के लिए एक बाधा नहीं है। यह निजी पूंजीगत व्यय निर्णयों की संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत की तरह लगता है, जो प्रतिफल वक्र के 20 के 'बुल स्टीपरिंग' को उत्प्रेरित कर सकता है जो यह संकेत देता है कि मुद्रास्फीति समाप्त हो गई है और भारत एक ऐसे विकास पथ पर खड़ा है जो इसकी आकांक्षाओं के अनुरूप है।

जी-सेक प्रतिफल से संकेत लेते हुए, अप्रैल 2023 की दूसरी छमाही के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आई, जबकि बॉन्ड बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (5-वर्षीय ए माइनस 5 साल जी-सेक) इसी अवधि के दौरान काफी हद तक अपरिवर्तित रहा (सारणी 3)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 12 मई, 2023 (एक साल पहले 9.1 प्रतिशत) तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरएम का सबसे बड़ा घटक मुद्रा प्रचलन (सीआईसी) में सालाना आधार पर 7.6 फीसदी की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले 9.6 फीसदी थी, जो आंशिक रूप से भुगतान के डिजिटल तरीकों को तेजी से अपनाने को दर्शाता है।

2023-24 के दौरान अब तक (12 मई, 2023 तक) आरएम में विस्तार मुख्य रूप से शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) द्वारा संचालित था, जो लगभग 100.7 प्रतिशत का योगदान देता था,

सारणी 3: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 मार्च 2023- 13 अप्रैल 2023	17 अप्रैल 2023- 15 मई 2023	भिन्नता (बीपीएस में)	16 मार्च 2023- 13 अप्रैल 2023	17 अप्रैल 2023- 15 मई 2023	भिन्नता (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.97	7.71	-26	68	60	-8
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.98	7.81	-16	74	73	0
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.97	7.73	-22	68	61	-7
(iv) एए (3-वर्ष)	8.67	8.51	-15	143	143	1
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.32	12.16	-15	508	508	1

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।

19 परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21755 ; और व्यवसाय मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (बीआईईएस) (https://www.iima.ac .in/faculty-research/centers/Misra-Centre-for-Financial-Markets-and-Economy/BIES)।

20 तेजी का बढ़ना एक ऐसी घटना है जिसमें अल्पकालिक ब्याज दरें दीर्घकालिक दरों की तुलना में तेजी से गिरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप दो दरों के बीच अधिक प्रसार होता है और प्रतिफल वक्र में तेजी आती है।

चार्ट 42 : सकल मौद्रिक और ऋण राशियाँ

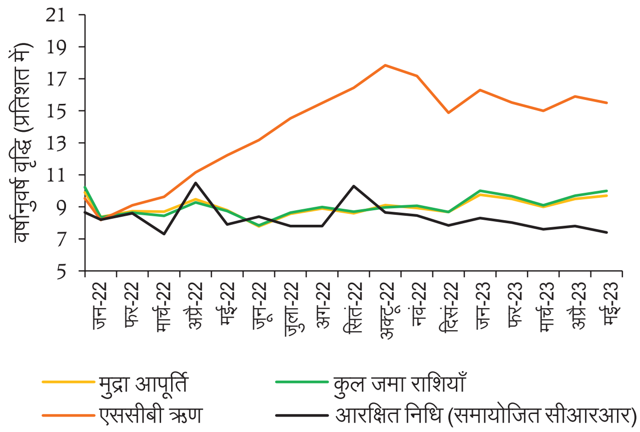

नोट: 1. ये आंकड़े मुद्रा आपूर्ति, सकल जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबन्धित हैं; और आरक्षित निधि के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार से संबन्धित हैं।
2. तथापि, आरक्षित निधि से संबन्धित आंकड़े 12 मई 2023; जबकि धन आपूर्ति की 05 मई 2023 की स्थिति के अनुसार हैं।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 43: रिज़र्व बैंक के एनडीए और एनएफए (साप्ताहिक परिवर्तन)

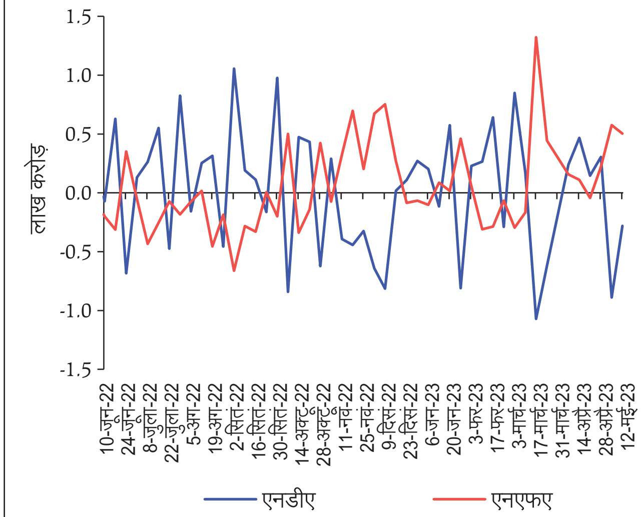

स्रोत: आरबीआई

जो बदले में, विदेशी मुद्रा बाजारों में रिज़र्व बैंक के संचालन में भिन्नताओं को ट्रैक करता है (चार्ट 43)।

मुद्रा आपूर्ति (एम3) 5 मई, 2023 को एक साल पहले की तरह ही 9.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो मुख्य रूप से इसके सबसे बड़े घटक - बैंकों के साथ कुल जमा से प्रेरित थी। प्रतिकूल आधार प्रभाव और औद्योगिक क्षेत्र को ऋण वृद्धि में कमी के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 5 मई, 2023 तक 15.5 प्रतिशत पर मजबूत बनी रही, हालांकि अक्टूबर 2022 में दर्ज 17.8 प्रतिशत के शिखर से नीचे है। इसके अलावा, एससीबी की जमा और ऋण के लिए 3 साल की मौसमी समायोजित वार्षिक वृद्धि [21], जो महामारी के दौरान अलग-अलग रुझान दिखाती है, अक्टूबर 2022 से एक-दूसरे के साथ तालमेल में चली गई, जो महामारी के बाद की अवधि में ऋण मांग की स्थिति में बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है (चार्ट 44)। वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात, जो नवंबर 2022 में बढ़कर 142.2 प्रतिशत हो गया था, 21 अप्रैल, 2023 को घटकर 112.6 हो गया।

मई 2022 से रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के जवाब में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क दरों को उसी परिमाण से ऊपर की ओर संशोधित किया है। इसके अलावा, मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान नई जमा और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 245

चार्ट 44: एससीबी की और बैंक ऋण - 3 साल की वार्षिक वृद्धि दर (मौसमी रूप से समायोजित)

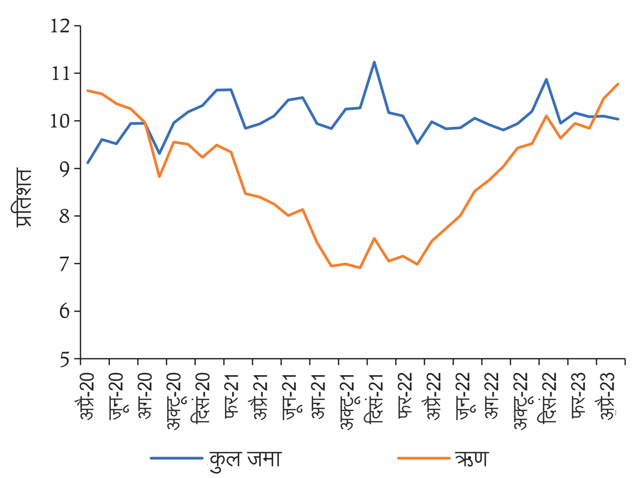

नोट: डेटा हर महीने के अंतिम पखवाड़े से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

21 मौसमी आधार पर, हटाने के बाद 3 वर्षों के वार्षिक औसत पर आधारित।

सारणी 4: रिपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार बिन्दुओं में परिवर्तन)

अवधि	रिपो दर (बीपीएस)	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डबल्यूएडीटीडीआर		ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	नया रुपया उधार	बकाया रुपया उधार
		खुदरा जमा	खुदरा और एकमुश्त जमा				
-1	**-2**	**-4**	**-5**	**-6**	-7	-8	-9
ढील वाली अवधि फरवरी 2019- मार्च 2022	-250	-259	-188	-	-155	-232	-150
सख़्ती वाली अवधि मई -22 से मार्च 2023	250	245	113	250	140	181	100
मई 2022 से अप्रैल 2023	250	-	-	250	145	-	-

नोट: 31 घरेलू बैंकों ने अप्रैल 2023 के अंत तक अपने ईबीएलआर में 250 बीपीएस की वृद्धि की है। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।
स्रोत: आरबीआई।

बीपीएस और 113 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी 4)। मई 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान, एससीबी ने अपनी औसत 1 साल की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 145 बीपीएस की बढ़ोतरी की। नतीजतन, मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान नए रुपये के ऋण और बकाया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 181 बीपीएस और 100 बीपीएस की वृद्धि हुई।

मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान, बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में नए रुपये की जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर और नए रुपये के ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि अधिक थी, जबकि बकाया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर और बकाया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर निजी बैंकों के लिए अधिक था (चार्ट 45)।

उपलब्ध परिणामों के आधार पर 2022-23 की चौथी तिमाही के दौरान कॉर्पोरेट प्रदर्शन से पता चलता है कि भले ही कुल बिक्री वृद्धि में कमी आई है, लेकिन कंपनियों ने अपने परिचालन लाभ का विस्तार किया है क्योंकि व्यय वृद्धि भी धीमी हो गई है (चार्ट 46)। अन्य आय, जो ट्रेजरी प्रबंधन जैसे गैर-

चार्ट 45: बैंक-समूहों में संचरण (मई 2022 से मार्च 2023)

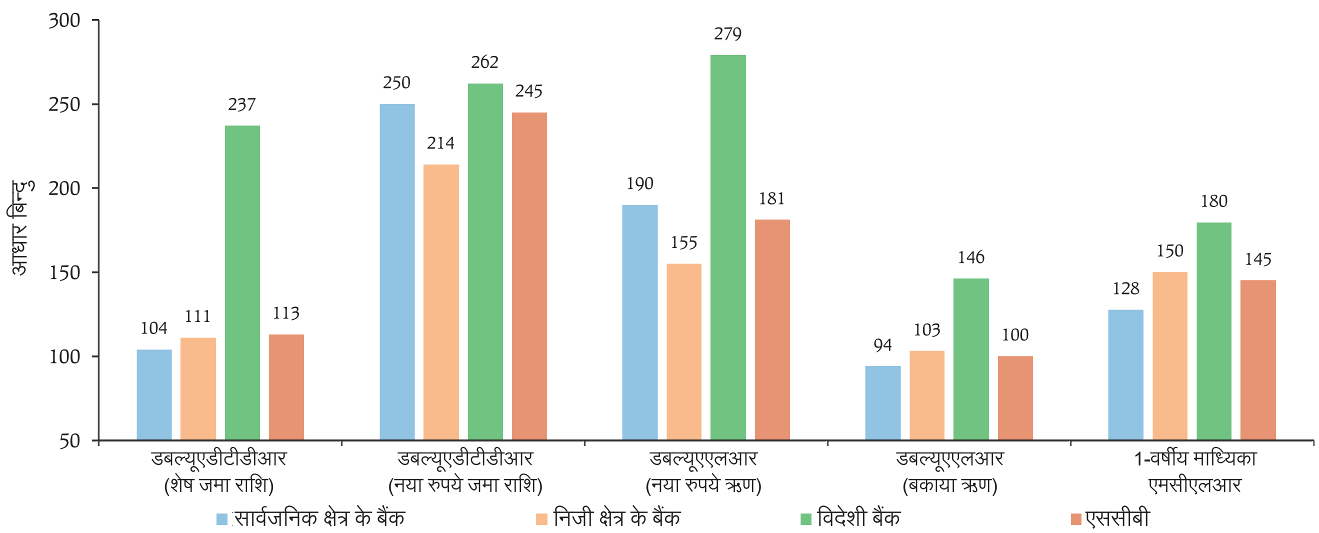

नोट: 1 साल के औसत एमसीएलआर पर आंकड़े मई 2022 से अप्रैल 2023 की अवधि से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

[22] 549 कंपनियों पर आधारित, जो सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 56 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है।

चार्ट 46: सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

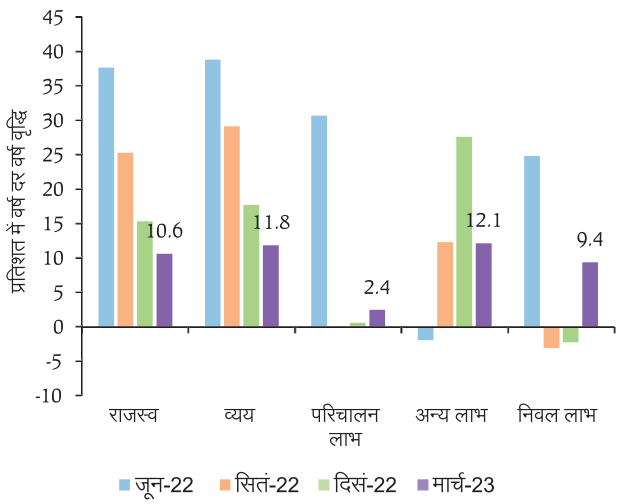

स्रोत: सीएमआईई कौशल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 47: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

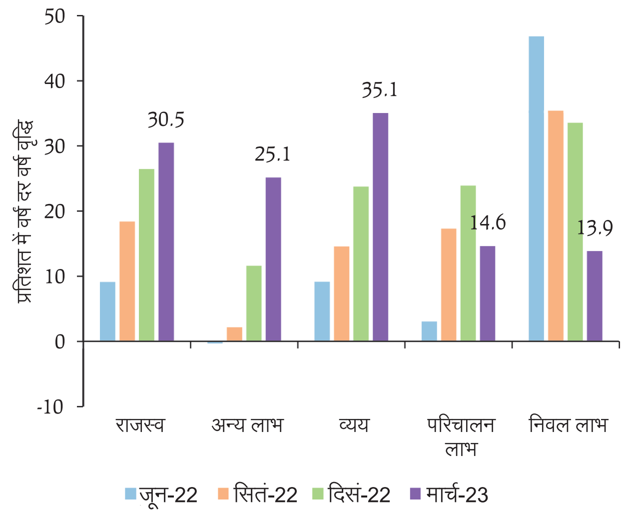

स्रोत: सीएमआईई कौशल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों से आय को मापता है, तिमाही के दौरान भी बढ़ी। कुल मिलाकर, लगातार दो तिमाहियों के संकुचन के बाद शुद्ध लाभ वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में लौट आई।

बैंकिंग और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने 2022-23 की चौथी तिमाही में अपनी राजस्व वृद्धि में तेजी दर्ज की, लेकिन व्यय में वृद्धि के कारण उनकी लाभप्रदता वृद्धि कम हो गई (चार्ट 47)।[24] अन्य आय जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतियों, शुल्कों और कमीशन के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को दर्शाती है, ने भी अच्छी वृद्धि दर्ज की है। धन की बढ़ती लागत के अलावा, कर्मचारी लागत में भी तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि कई कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। प्रावधान संबंधी व्यय में मामूली वृद्धि हुई है। शुद्ध लाभ वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में बनी रही, हालांकि यह पिछली तिमाहियों से कम हो गई।

वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए कंपनियों के उम्मीद से बेहतर नतीजों के जारी होने के बाद अप्रैल और मई की शुरुआत में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। घरेलू विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के अप्रैल 2023 के आंकड़ों ने

चार्ट 48: अप्रैल- 11 मई, 2023 के दौरान वैश्विक इक्विटी बाजारों का प्रदर्शन

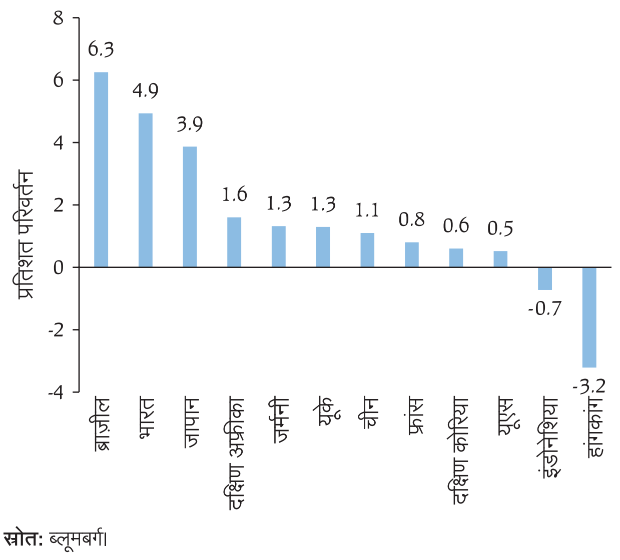

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

---

23 इसमें निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा की गई एकमुश्त अधिग्रहण संबंधी लागत भी शामिल है।

24 169 कंपनियों पर आधारित, जो सभी सूचीबद्ध वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 62 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है।

चार्ट 49 : भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह

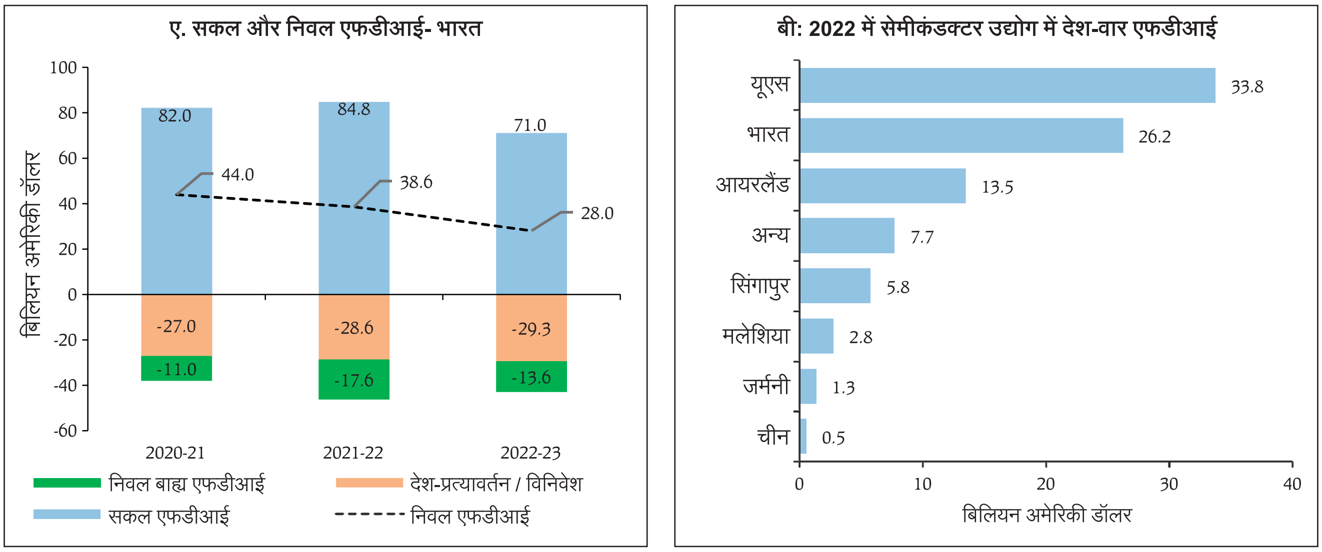

स्रोत: आरबीआई और एफडीआई आसूचना।

सकारात्मक धारणा की पुष्टि की। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि चक्र में संभावित ठहराव और अमेरिकी सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी के संकेत के परिणामस्वरूप जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2023-24 के दौरान अब तक 4.6 प्रतिशत बढ़कर 19 मई, 2023 को 61,730 पर बंद हुआ, जो अधिकांश वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है।

सकल आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2022-23 में 71.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है (चार्ट 49ए)। निवल एफडीआई एक साल पहले के 38.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 में घटकर 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसका मुख्य कारण सकल एफडीआई प्रवाह में कमी और प्रत्यावर्तन में वृद्धि है। विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं और संचार सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई प्रवाह में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान प्रवाह में गिरावट के लिए प्रमुख योगदानकर्ता अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मॉरीशस थे। एफडीआई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2022 के लिए अर्धचालक उद्योग में एफडीआई (यूएस $ 26.2 बिलियन) का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जो अमेरिका (यूएस $ 33.8 बिलियन) के बाद दूसरा था। उद्योग को विकसित करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप, पूंजी-गहन चिप एफडीआई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश चल रहा है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अप्रैल (चार्ट 50) में घरेलू वित्तीय बाजारों में शुद्ध खरीदार बन गए, मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट (यूएस $ 1.9 बिलियन) में, जो ऋण खंड (यूएस $ 0.2 बिलियन) में प्रवाह से पूरक था। वित्तीय सेवाओं, पूंजीगत वस्तुओं और तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन में 16-30 अप्रैल, 2023 के दौरान सबसे अधिक शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश देखा गया। मई में (15 तारीख तक) एफपीआई की निवल खरीद 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर थी।

बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) पंजीकरण जो 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान धीरे-धीरे बढ़ा था, चौथी तिमाही में कम हो गया। बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों और घरेलू ऋण वृद्धि में अधिक वृद्धि के बीच, ईसीबी पंजीकरण 2022-23 के दौरान एक तिहाई घटकर 26.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2022-23 के दौरान 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर ईसीबी अंतर्वाह बहिर्वाह की तुलना में मामूली रूप से अधिक था, जिसमें मामूली शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया (चार्ट 51)।

चार्ट 50 : निवल पोर्टफोलियो निवेश

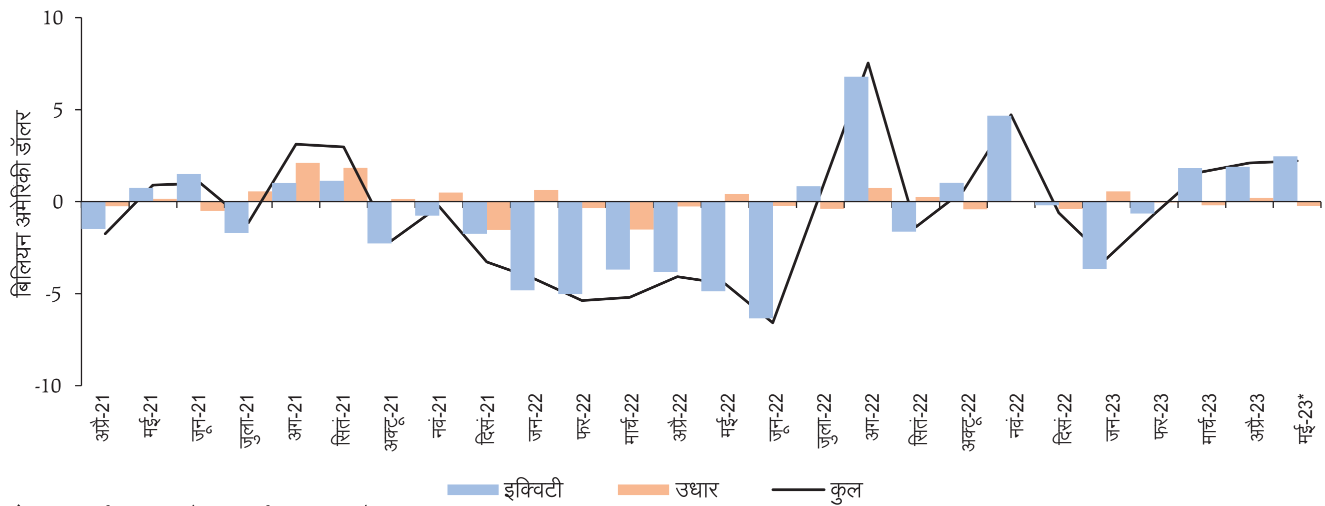

नोट: 1. *: मई 2023 का डेटा 15 मई, 2023 तक है।

2. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)।

पुनर्वित्त को विस्थापित करने वाले ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग में वृद्धि के अलावा, 2022-23 के दौरान उठाए गए ईसीबी स्पष्ट रूप से आधुनिकीकरण, नई और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और पूंजीगत वस्तुओं की स्थानीय सोर्सिंग के वित्तपोषण के लिए थे (चार्ट 52)।

सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ बेंचमार्क दरों में सहवर्ती वृद्धि के साथ, ईसीबी ऋणों की कुल लागत मार्च 2022 और मार्च 2023 के बीच 516 बीपीएस तक बढ़ गई। 6 जुलाई और 31 दिसंबर, 2022 के बीच ऑल-इन-कॉस्ट सीमाओं में अस्थायी नीतिगत वृद्धि के बावजूद, भारित

चार्ट 51: ईसीबी - पंजीकरण, अंतर्वाह और बहिर्वाह

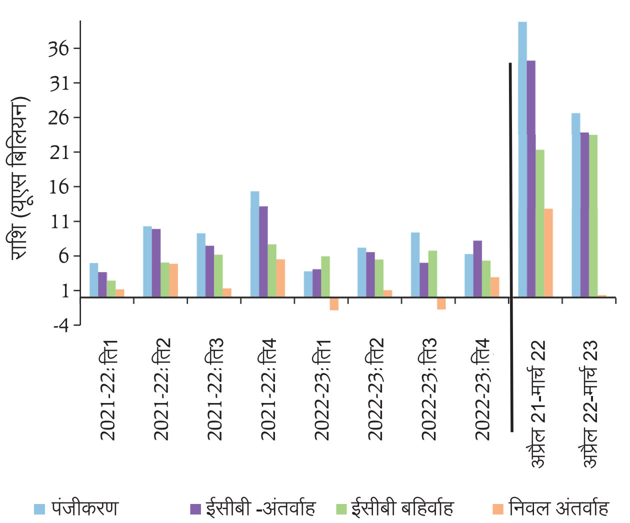

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 52: पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग (अप्रैल-मार्च)

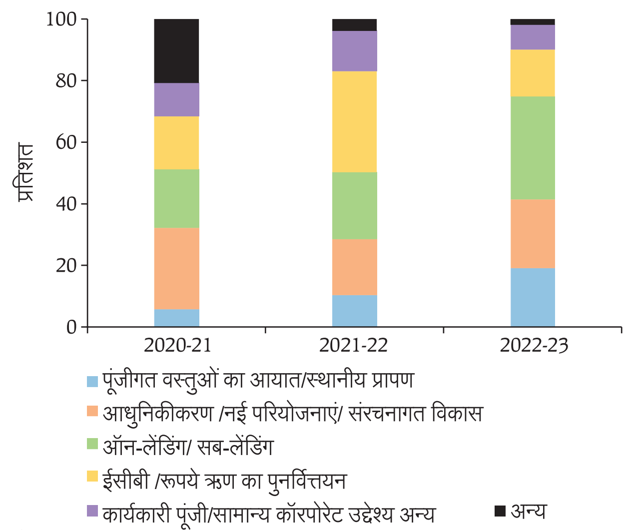

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 53 ईसीबी का समग्र मूल्य

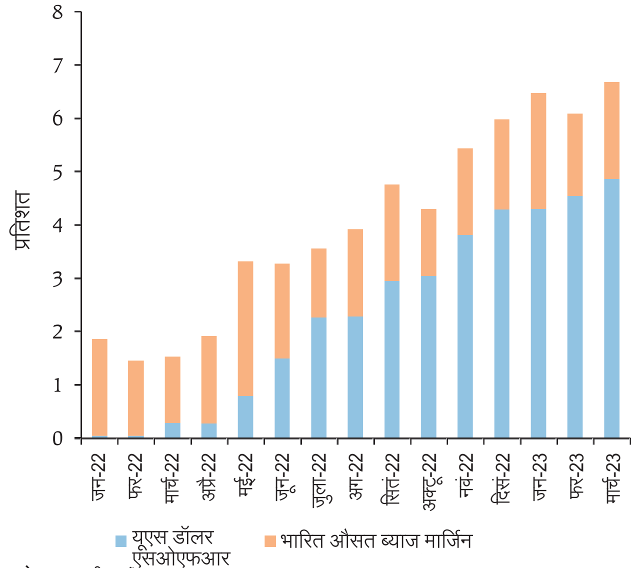

स्रोत: आरबीआई

औसत ब्याज मार्जिन (डब्ल्यूएआईएम) सीमित सीमा में बना रहा (चार्ट 53)। ईसीबी समझौते की लगभग 72 प्रतिशत राशि स्पष्ट रूप से हेज की गई थी या विदेशी पैरेंट से रुपये में अंकित ऋण और ऋण थे (चार्ट 54)।

अनिवासी जमाओं में निवल अभिवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसमें अनिवासी साधारण (एनआरओ), विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर (बी)] खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों [एनआर (ई)ए] में शुद्ध प्रवाह शामिल है।

विदेशी मुद्रा भंडार में 21 अक्टूबर, 2022 से 75.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और 12 मई, 2023 को यह 599.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022-23 के लिए अनुमानित आयात के 10.0 महीनों और कुल विदेशी ऋण के 97.8 प्रतिशत को कवर करने के लिए पर्याप्त है (चार्ट 55ए)। कोविड-19 की शुरुआत के बाद से, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 100.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च 2020 के अंत की तुलना में मार्च 2023 के अंत) की वृद्धि हुई है। यह विदेशी मुद्रा भंडार धारिताओं (चार्ट 55 बी) द्वारा रैंक किए गए शीर्ष दस देशों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है।

चार्ट 54: ईसीबी समझौते - हेजिंग स्थिति

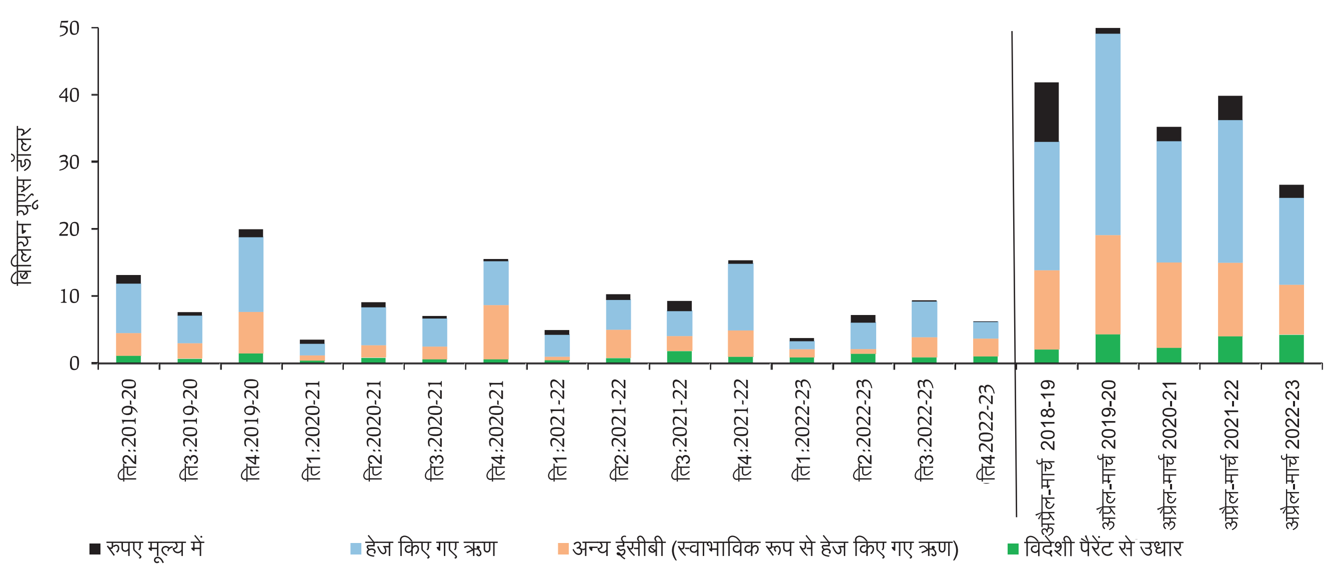

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 55: विदेशी मुद्रा भंडार

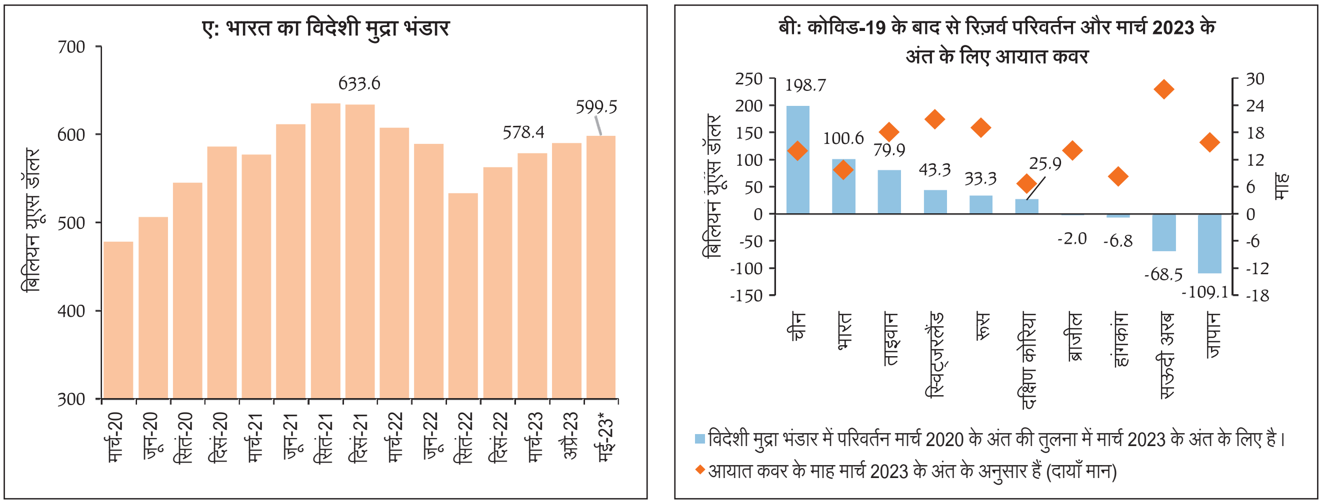

नोट: 1. रूस के लिए आयात कवर के महीनों का विवरण जनवरी 2023 के अंत तक है और सऊदी अरब दिसंबर 2022 के अंत के लिए है।
2. *: मई 2023 के आंकड़े 12 मई, 2023 तक के हैं।
स्रोत: आरबीआई; सीईआईसी; और संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

अप्रैल 2023 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया (आरएनआर) 0.3 प्रतिशत (एम-ओ-एम) मजबूत हुआ और प्रमुख मुद्राओं में सबसे कम अस्थिर में से एक रहा (चार्ट 56)।

अप्रैल 2023 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में रुपये में 1.8 प्रतिशत (एम-ओ-एम) की गिरावट आई (चार्ट 57)।

भुगतान प्रणाली

खातों के वार्षिक समापन के कारण मार्च 2023 में मजबूत विस्तार के बाद, डिजिटल भुगतान ने अप्रैल में विभिन्न तरीकों से स्थिर वृद्धि बनाए रखी है (सारणी 4)। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल ऋण के पुनर्भुगतान के लिए दूसरे सबसे पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है, जो राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) से काफी

चार्ट 56: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (अप्रैल 2023, माह दर माह)

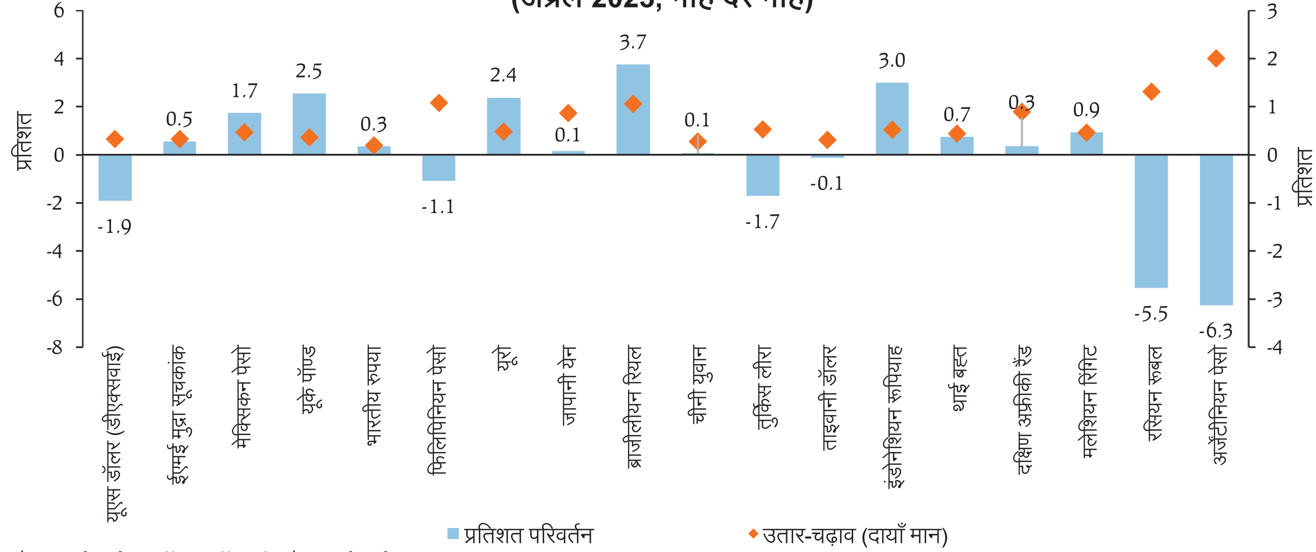

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 57: 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में परिवर्तन

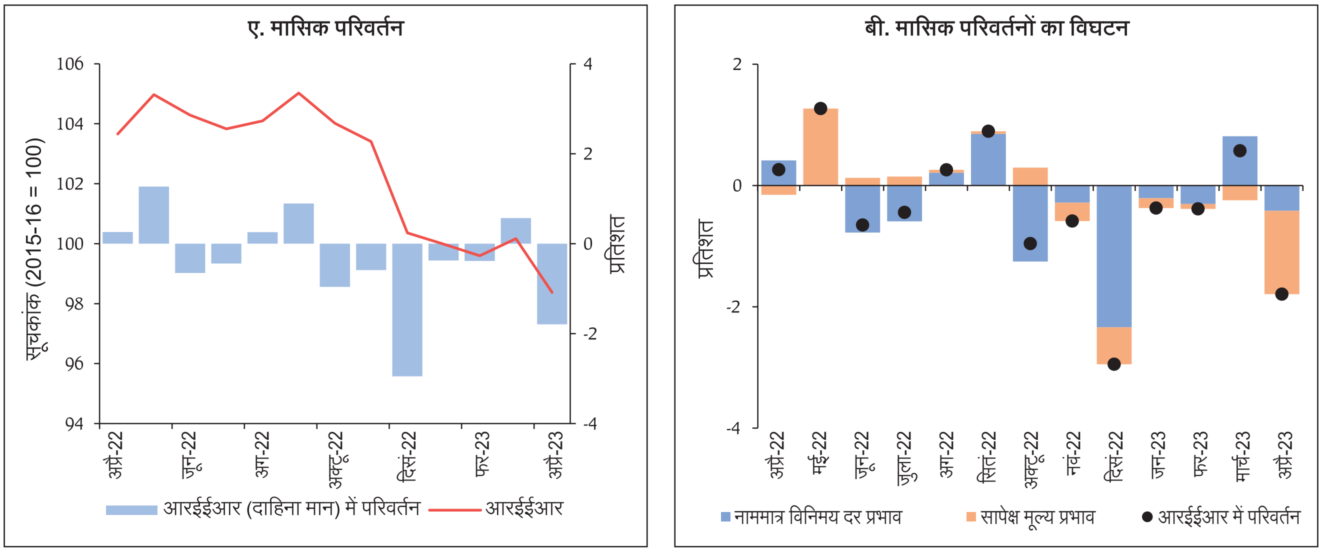

स्रोत: आरबीआई

पीछे है।[25] बैंक क्रेडिट द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म के उपयोग की अनुमति देने से डिजिटल अपटेक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जबकि साथ ही साथ अधिक अभिनव और समावेशी ऋण वितरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड खर्च में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो मार्च 2023 में 1.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2022-23 में 47 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की समग्र वृद्धि का संकेत देता है। अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड ने अप्रैल में उच्च वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रोफाइल बनाए रखी (32 प्रतिशत)। ई-कॉमर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन को अपनाने से खर्च में इस वृद्धि को बढ़ावा मिला है।

भारत ने 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवक प्रेषण का मील का पत्थर पार कर लिया। सीमा पार भुगतान रेलों का डिजिटलीकरण इन प्रवाहों की आसानी और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ाकर इस विकास गति का उपयोग कर सकता है। अन्य तीव्रभुगतान प्रणालियों के साथ यूपीआई की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देने और दुनिया भर में यूपीआई

सारणी 4 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मात्रा			
	मार्च-22	मार्च-23	अप्रै-22	अप्रै-23	मार्च-22	मार्च-23	अप्रै-22	अप्रै-23
आरटीजीएस	13.7	7.8	28.9	3.2	11.4	11.5	26.1	7.0
एनईएफ़टी	23.9	26.8	30.6	29.1	14.6	7.4	22.1	10.5
यूपीआई	97.9	60.0	111.4	58.7	90.3	46.3	99.2	43.9
आईएमपीएस	35.5	1.0	46.0	5.1	41.3	18.2	48.4	17.2
एनएसीएच	7.5	29.8	19.0	-3.7	-6.3	35.1	14.3	18.4
एनईटीसी	39.9	13.3	61.5	14.9	32.7	23.7	51.9	22.1
बीबीपीएस	102.4	56.5	110.9	33.5	120.7	61.6	117.7	51.2

स्रोत : आरबीआई

[25] https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/upi-payments-second-most-preferred-by-millennials-for-digital-loans-cashe/article66710999.ece

[26] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55473

चार्ट 58: भारतीय भुगतान मोड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन

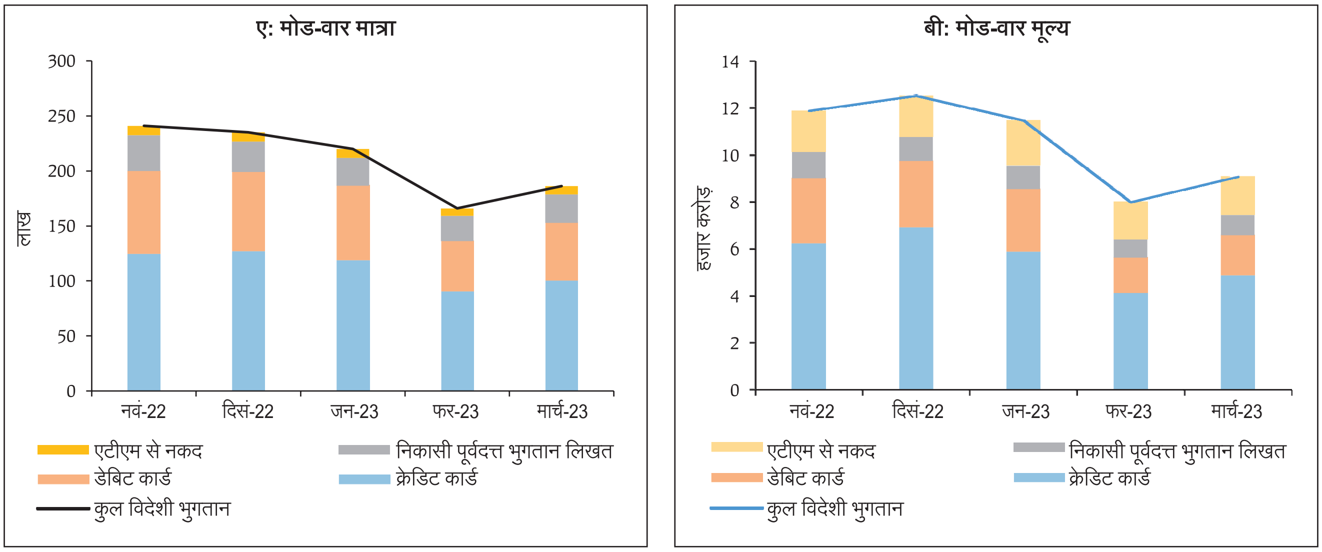

स्रोत: आरबीआई

और रुपे कार्डों की स्वीकार्यता का विस्तार करने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान सुविधाप्रदाताओं के साथ भागीदारी करने के लिए चल रहे प्रयासों से स्थानीय भुगतान मोड को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों की श्रृंखला में वृद्धि होगी। इन पहलों के प्रतीक, घरेलू भुगतान चैनलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन ने मार्च 2023 में क्रमिक वृद्धि दिखाई है। कार्ड भुगतान (डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में इन भुगतानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, इसके बाद प्रीपेड भुगतान उपकरण (चार्ट 58) हैं।

50 प्रतिशत से अधिक भारतीय (यानी, 759 मिलियन) वर्तमान में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ते एकीकरण का प्रदर्शन करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार 900 मिलियन तक बढ़ जाएगा, जो ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं की गहराई से उत्साहित है। फिनटेक क्षेत्र में, वित्त पोषण जनवरी-मार्च 2023 में दर्ज 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ बदलाव के शुरुआती संकेत दिखाता है, जो पिछली तिमाही के 523 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर की तुलना में 126 प्रतिशत की तेज वृद्धि है। हालांकि, जुटाई गई धनराशि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 55 प्रतिशत कम रही। इस मंदी को "अन्यथा दीर्घकालिक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र में अल्पकालिक सुधार" के रूप में वर्णित करते हुए, भारत को 2030 तक विश्व स्तर पर सबसे बड़े फिनटेक बाजारों में से एक के रूप में देखा जाता है, जो वित्तीय समावेशन संभावनाओं और जनसांख्यिकीय लाभ से प्रेरित है।[31]

निष्कर्ष

इस पृष्ठभूमि में, 2023-24 की पहली तिमाही के संदर्भ में निकट भविष्य कैसा दिखता है? अप्रैल 2023-32 में जारी आरबीआई के अनुमानों से संकेत मिलता है कि वास्तविक जीडीपी साल-दर-साल 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जो अपने पूर्व-महामारी स्तर (2019-20 की इसी तिमाही) से 13.7 प्रतिशत ऊपर है। यह अनुमान मौसमी रूप से समायोजित तिमाही-दर-तिमाही (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर नकारात्मक

[27] https://www.livemint.com/news/india/india-russia-explore-possibility-of-accepting-rupay-mir-cards-11682855523924.html

[28] एनपीसीआई परिपत्र। 27 अप्रैल 2023.

[29] आईएएमएआई और केएएनटीएआर। मई 2023। 759 मिलियन भारतीय सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता, 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंच जाएंगे

[30] https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/indian-fintech-start-ups-raise-12-billion-in-q1-2023-tracxn/article66733593.ece

[31] बीसीजी और क्यूईडी निवेशक। मई 2023। ग्लोबल फिनटेक 2023: वित्त के भविष्य की पुनर्कल्पना।

[32] द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-2024: 06 अप्रैल, 2023।

गति [(-) 1.7 प्रतिशत] को एम्बेड करता है। यह पहली तिमाही के उतार-चढ़ाव की विशेषता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि नकारात्मक गति का परिमाण पिछले दो वर्षों की पहली तिमाहियों की तुलना में कम है।[33] इस प्रकार, महामारी और युद्ध से प्रभावित होने का धीरे-धीरे सामान्यीकरण हो रहा है।

2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि निजी खपत से प्रेरित होने की उम्मीद है, जो 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र और 2023-24 के रबी विपणन सत्र दोनों में उत्साहजनक घटनाक्रमों, सेवाओं, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों में निरंतर उछाल और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के कारण ग्रामीण मांग में पुनरुद्धार से समर्थित है। सार्वजनिक खर्च में पूंजीगत व्यय पर जोर और जिंस कीमतों में नरमी से निवेश गतिविधियों में भी सुधार होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, विनिर्माण में क्षमता उपयोग प्रवृत्ति के स्तर पर और कुछ उद्योगों में इससे ऊपर है, मांग बढ़ने के साथ अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिए निजी पूंजी खर्च को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इनपुट लागत के दबाव में नरमी से पूरे विनिर्माण क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि सेवा निर्यात अपने हालिया उच्च प्रोफ़ाइल को बनाए रखता है, तो शुद्ध बाहरी मांग से दबाव अप्रैल-जून 2023 तक कम हो सकता है। घरेलू सेवा क्षेत्र की गतिविधि संपर्क-गहन सेवाओं में वापसी और निर्माण गतिविधि में लचीलापन के नेतृत्व में जारी रहेगी।

अर्थव्यवस्था की स्थिति के इस संस्करण को सकारात्मक रूप से समाप्त करने के लिए, अप्रैल 2023 के मौद्रिक नीति दस्तावेजों ने 2023-24 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 5.1 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है, जो पिछली तिमाही में 6.2 प्रतिशत था। हालांकि तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन, या गति, पिछली तिमाही की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है - मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में मौसमी वृद्धि के कारण - यूक्रेन युद्ध के बाद एक साल पहले उच्च मुद्रास्फीति के कारण बड़े अनुकूल आधार प्रभावों से इसे संतुलित करने और हेडलाइन मुद्रास्फीति में अनुमानित कमी आने की उम्मीद है।

अप्रैल 2023 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट इंगित करता है कि गेहूं की कीमतों में गिरावट, तेल और वसा की कीमतों में लगातार पांचवीं मासिक गिरावट और अंडे की कीमतों में लगातार तीसरी मासिक गिरावट के कारण गति अनुमान से नरम हो रही है। सब्जियों और फलों की कीमतें भी गर्मियों की गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर रही हैं और उनकी गति वर्ष के इस समय के लिए उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कम है। केरोसिन की कीमतों में गिरावट आ रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य मुद्रास्फीति - खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई - पिछले 10 महीनों में लगातार वृद्धि के सापेक्ष नरम गति (मौसमी रूप से समायोजित) पर चल रही है। अगर बफर स्टॉक से बिक्री की जाती है, जो मानक से तीन गुना अधिक है, तो चावल की कीमतों में महत्वपूर्ण सुधार देखा जा सकता है। अप्रैल में अपस्फीति में थोक मूल्य उतार-चढ़ाव का दौर भी आगे चलकर खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी लाने में योगदान दे सकता है।

संक्षेप में, नीतिगत ढांचे को आगे की ओर देखने वाला होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों में नीतिगत आवेगों के संचरण में अंतराल है। पूर्वानुमान इन रूपरेखाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे भविष्य की एक झलक प्रदान करते हैं, जो आज हम जो कुछ भी जानते हैं और हमारे सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर हैं, और मध्यवर्ती चर की भूमिका निभाते हैं - वे लक्ष्य चर के प्रतिबिंब को पकड़ते हैं। अक्सर ये प्रतिबिंब धुंधले हो सकते हैं, अनिश्चितताओं और अज्ञातताओं से अस्पष्ट हो सकते हैं और जब ऐसा होता है, तो यह पूर्वानुमानों को बदनाम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्री एज़्रा सुलैमान ने एक बार टिप्पणी की थी कि "आर्थिक पूर्वानुमान का एकमात्र कार्य ज्योतिष को सम्मानजनक बनाना है। [34] आर्थिक पूर्वानुमान एक अचूक विज्ञान है, लेकिन इसकी आलोचना को इस बात की समझ से प्रभावित किया जाना चाहिए कि पूर्वानुमान वास्तव में क्या दर्शाते हैं। वे समय के किसी विशेष बिंदु पर सभी उपलब्ध जानकारी के सर्वोत्तम गंध परीक्षण पर वातानुकूलित हैं। जैसे ही नई जानकारी आती है, निर्णय को फिर से व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसा कि जॉन

[33] (-) 4.1 प्रतिशत और 2021-22 की पहली तिमाही में (-) 11.9 प्रतिशत।

[34] रीडर्स डाइजेस्ट, 1975।

मेनार्ड कीन्स को यह कहने का श्रेय दिया जाता है: "जब तथ्य बदलते हैं, तो मैं अपना मन बदल देता हूं। सर, आप क्या करते हैं?[35] 2020 के बाद से, अर्थशास्त्रियों को अपने पूर्वानुमान बनाने के लिए महामारी विज्ञान, सैन्य परिदृश्यों, आपूर्ति श्रृंखला, रसद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्थिति लेनी पड़ी है। फिर भी एक बात निश्चित है - महामारी और युद्ध से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक हो रही है। फिर भी आत्मसंतोष के लिए कोई जगह नहीं है। इस वसूली की नींव और लचीलापन को मजबूत करने के लिए कम और स्थिर कीमतों का वातावरण आवश्यक है। कार्य करने की तत्परता के साथ शाश्वत सतर्कता इसकी कीमत है। इस पर, शब्द[36] के काव्यात्मक अर्थ में एक अंतिम 'परहेज' - हम गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास[37] के शब्दों को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं: "हम मूल्य स्थिरता की अपनी खोज में दृढ़ और दृढ़ बने हुए हैं जो टिकाऊ विकास के लिए सबसे अच्छी गारंटी है"।

[35] बौद्धिक विनम्रता क्यों मायने रखती है? फाइनेंशियल टाइम्स, 1 सितंबर, 2022।

[36] रिफ्रेन एक कविता (या गीत) का एक छोटा छंद है जिसे प्रत्येक लंबे भाग के अंत में दोहराया जाता है - कैम्ब्रिज डिक्शनरी।

[37] गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 6 अप्रैल, 2023। https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55471

*निर्यात समानता सूचकांकों के माध्यम से भारत की निर्यात क्षमता का पता लगाना**

देब प्रसाद रथ, अभिलाषा, मोनिका सेठी और राशिका अरोड़ा^ द्वारा

यह आलेख महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्यों, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भागीदारों और अब तक कम उपयोग किए गए निर्यात बाजारों को कवर करने वाले प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में, निर्यात समानता सूचकांक (ईएसआई) को विनियोजित करते हुए भारत की निर्यात क्षमता की जांच करता है। ईएसआई के विकास से पता चलता है कि भारत की निर्यात संरचना तेजी से औसत विश्व मांग के साथ स्वयं को संरेखित कर रही है। इसके अलावा, भारत का पण्य और सेवा निर्यात, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान से उबर गया है और ईएसआई, व्यापार भागीदारों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और वस्तुओं और सेवाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रभावी साधन हो सकता है जो वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।

भूमिका

वर्ष 2022 में, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंच गया और उसी वर्ष भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो बाद के वर्ष में बेहतर हो गया है। आर्थिक आकार के मामले में भारत से आगे चार देश दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। यह स्वीकार करते हुए कि विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए व्यापार - वृद्धि का एक अनिवार्य वाहक है, सरकार ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं में से प्रत्येक के निर्यात को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हालांकि भारत का निर्यात 2022 की पहली छमाही तक उत्साहजनक रहा, लेकिन मौद्रिक सख्ती की तीव्र गति से बाहरी मांग में कमी आई है जो व्यापार में वृद्धि के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अपनी निर्यात मांग का विस्तार करने के लिए भारत द्वारा चुने गए तरीकों में से एक, प्रमुख आर्थिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को साकार करना है। यह उम्मीद की जाती है कि एफटीए के माध्यम से तालमेल - व्यापार, वृद्धि और कल्याण में तेजी लाने का आधार होगा। उदाहरण के लिए, 18वें भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग[1] के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरक प्रकृति, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश प्रदान करती है। एक अन्य तरीका भारत के निर्यात स्थलों में विविधता लाना रहा है। चूंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में वर्तमान आर्थिक मंदी अधिक स्पष्ट है और ये भारत के प्रमुख निर्यात बाजार हैं, अफ्रीका "अवसरों का एक नया महाद्वीप"[2] हो सकता है। अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान अफ्रीका के लिए भारत का निर्यात 46.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था[3], जो 2021-22 में इस क्षेत्र के लिए कुल निर्यात की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है। हाल ही में शुरू किया गया अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता (एएफसीएफटीए) – विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें 55 देश शामिल हैं – भारत के लिए विशाल निर्यात संभाव्यता प्रदान करता है।

इस संदर्भ में, यह हमारी जानकारी में अपने प्रकार का पहला आलेख है जो निर्यात समानता सूचकांक (ईएसआई) की गणना करके, 21वीं सदी में दुनिया और चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में भारत के निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता के बदलते स्वरूप की जांच करता है। सूचकांक, जिसकी दो देशों या देशों के समूहों के लिए गणना की जाती है, इस बात का आकलन करता है कि क्या दोनों की निर्यात संरचना प्रतिस्पर्धी है, यानी, क्या निर्यात संरचनाओं के अभिसरण पर विशेषज्ञता की गुंजाइश है और इस प्रकार समान-समान व्यापार के लाभों का लाभ उठाते हैं (क्रुगमैन,

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। ये विचार लेखकों के निजी विचार हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। लेखक, डॉ. हरेंद्र बेहेरा के बहुमूल्य सुझावों के लिए उनके आभारी हैं।

[1] https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1906076 (March, 2023).

[2] https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/this-time-for-africa-for-indian-exporters-a-new-continent-of-opportunities-as-demand-wanes-in-europe-us/articleshow/94316341.cms?from=mdr

[3] वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त किया गया है जहां अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश, पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

2008)। दूसरी ओर, निम्न समानता, पूरकता या व्यापार निर्माण के लिए तुलनात्मक लाभ की गुंजाइश को दर्शाती है।

कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दो वर्षों की मंदी के बाद, निर्यात में मजबूत पुनरुत्थान ने 2021-22 में जीडीपी वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने महामारी के कारण उभरे पण्य और सेवा व्यापार अंतराल, दोनों को पहले ही पाट दिया है। महामारी ने व्यापार की संरचना में एक बड़ा बदलाव भी किया, जैसा कि ओईसीडी व्यापार नीति पत्र में उल्लेख किया गया है (एरिओला और अन्य, 2023)। इस अध्ययन में पाया गया है कि महामारी के कारण भारत के निर्यात ढांचे में जो उतार-चढ़ाव आया है, वह दो साल बाद भी बना हुआ है। हालांकि पिछले दो दशकों में, भारत की आर्थिक संरचना दुनिया के साथ संरेखित हो रही है, जो अर्थव्यवस्था में जगह बना रही विशेषज्ञता को दर्शाती है।

शेष आलेख निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है: खंड II में ईएसआई पर चर्चा करने वाले साहित्य, इसके महत्व और संबंधित अवधारणाओं की समीक्षा संक्षेप में शामिल की गई है। खंड III आलेख में ईएसआई की गणना करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले डेटा और कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। भारतीय ईएसआई और इसके विकास, महामारी के संबंध में ईएसआई और भारत के प्रमुख एफटीए भागीदारों के संबंध में ईएसआई और अफ्रीकी बाजार में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के संबंध में ईएसआई की जांच खंड IV में की गई है। विश्व की धीमी मांग के मद्देनजर भारत के निर्यातों के लिए शक्तियों और नीति के प्रभावों को समापन खंड V में दर्शाया गया है।

II. साहित्यिक समीक्षा

फिंगर और क्रिनिन (1979) [एफके] ने देशों द्वारा निर्यात की समानता और उनके बीच अधिमान्य व्यापार समझौतों के व्यापार निर्माण/ अपवर्ती (डायवर्टिंग) प्रभाव के बीच संबंधों को समझने के लिए निर्यात समानता का एक सूचकांक प्रस्तुत किया। इस सूचकांक का उपयोग देशों की आर्थिक संरचना में अभिसरण/ विचलन का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है। साहित्य में कई अध्ययनों ने अन्य देशों की तुलना में देशों की निर्यात संरचनाओं के विकास का विश्लेषण करने के लिए एफके समानता सूचकांक का उपयोग किया है (स्कॉट, 2008; स्कॉट, 2008) एर्लाट और एकमेन, 2009; चाउ, 2012; वांग और लियू, 2015; गुयेन और अन्य, 2017)। कुछ अध्ययनों ने अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए देशों के बीच निर्यात की असमानता (समानता के विपरीत) का पता लगाया है (एमेबल, 2000; पार्टेका और ताम्बरी, 2013; बर्नटोनिट, 2015)[4]। साहित्य का एक विस्तृत सारांश अनुबंध - I में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान अध्ययन में फिंगर और क्रिनिन (एफके) के ईएसआई का उपयोग भारत के निर्यात पैटर्न के विकास, विशेष रूप से कुछ प्रमुख एफटीए और संभावित नए बाजारों के संदर्भ में विशेषज्ञता की गुंजाइश, और निर्यात संरचना पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया गया है।

III. डेटा स्रोत और कार्यप्रणाली

फिंगर और क्रिनिन (1979) द्वारा प्रस्तावित[5] और इस आलेख में प्रयुक्त निर्यात समानता सूचकांक (ईएसआई) की गणना इस प्रकार की गई है:

$$S(ab,c) = \sum_{i} Minimum[X_i(ac), X_i(bc)]$$

जहां, सूचकांक $S(ab,c)$, देश/ देश समूह *a* और *b* से देश/ देश समूह *c* के निर्यात पैटर्न की समानता को मापता है। $X_i(ac)$, *a* के *c* को निर्यात में पण्य *'i'* का हिस्सा है और *Xi (bc), b* के *c* को निर्यात में पण्य *'i'* का हिस्सा है। यदि a से c और b से c के निर्यात का ढांचा या संरचना समान है, यानी, प्रत्येक i के लिए $X_i(ac) = X_i(bc)$, सूचकांक का मान 1 होगा। यदि a और b से c के निर्यात में कोई ओवरलैप नहीं है, अर्थात, प्रत्येक 'i' के लिए, X; (ac) > 0 और Xi (bc) = 0 या इसके विलोमतः, सूचकांक का मान 0 होगा। इस प्रकार, S दूसरे देश/ क्षेत्र/ दुनिया के संबंध में दो देशों/ क्षेत्रों की निर्यात संरचनाओं की समानता में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इस आलेख में, सभी ईएसआई गणनाओं के लिए, 'c' विश्व बाजार है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

---

4 कुछ अध्ययन अन्य समानता सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उत्पाद समानता सूचकांक (पीएसआई) और मूल्य (या गुणवत्ता) समानता सूचकांक (एंटीमियानी और हेन्के, 2007; एर्लाट और एकमेन, 2009)। जबकि ईएसआई केवल पण्य व्यापार प्रवाह की संरचना को संदर्भित करता है क्योंकि यह निर्यात के अनुपात पर विचार करता है, पीएसआई पूर्ण निर्यात मूल्यों पर विचार करता है, व्यापार प्रवाह के आयामों का पता लगाता है। मूल्य समानता सूचकांक देशों के निर्यात मूल्यों की तुलना करता है, जिसमें उच्च कीमतें उत्पाद की उच्च गुणवत्ता का संकेत देती हैं।

5 फिंगर और क्रिनिन (1979) ने सूचकांक को 100 के साथ गुणा किया था, इस प्रकार उस शोध में ईएसआई की सीमा 0-100 थी।

भारत के ईएसआई के आकलन के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) ट्रेड मैप डेटाबेस से पण्य व्यापार डेटा पर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन[6] (एचएस) का उपयोग किया जाता है। भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम 6) के छठे संस्करण के आधार पर सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) डेटाबेस का उपयोग, सेवा व्यापार डेटा के लिए किया जाता है। पण्य के लिए भारत के ईएसआई को एचएस दो-अंकीय स्तर पर अनुमानित किया गया है। पण्य व्यापार के लिए ईएसआई का विश्लेषण वर्ष 2002 के बाद से किया जाता है, जबकि सेवाओं के लिए अध्ययन 2005 से शुरू होता है, यानी जिस वर्ष से डेटा उपलब्ध होता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए नवीनतम अवधि वर्ष 2021 है।

भारत की निर्यात संरचना के विकास की तुलना बदलते विश्व निर्यात ढांचे के साथ-साथ जी-7 देशों के साथ की गई है। जी-7 के साथ भारत के निर्यात पैटर्न में अभिसरण को मापने के लिए एचएस 2-अंकीय और 6-अंकों पर एक वस्तु-वार विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, निर्यात संरचना में कोविड-19 के कारण आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, आलेख में भारत के ईएसआई के साथ-साथ इसके पांच मौजूदा एफटीए भागीदारों अर्थात आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, अफ्रीकी बाजार में भारत के व्यापारिक निर्यात स्वरूप की तुलना इसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ की जाती है और एचएस 4-अंकीय वस्तुओं की पहचान ओवरलैप वाली वस्तुओं और भारत के लिए निर्यात क्षमता प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए की गई है।

IV. भारतीय संदर्भ में

IV.1 भारत की बदलती निर्यात संरचना

मौजूदा साहित्य से पता चलता है कि यह केवल निर्यात वृद्धि नहीं है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है, बल्कि विशेषज्ञता का स्वरूप, यानी, निर्यात की संरचना भी है जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में निर्यात की क्षमता का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए, खुलेपन के माध्यम से लाई गई विशेषज्ञता जो किसी देश को अनुसंधान और/ या प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों से दूर करती है, एक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र (औटारकी) (एमेबल, 2000) की तुलना में निम्न उत्पादन वृद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए, किसी देश की निर्यात संरचना का विश्लेषण करना प्रासंगिक हो जाता है।

लिंडर (1961) ने परिकल्पना की कि समान मांग संरचनाओं वाले देशों के बीच मजबूत व्यापार मौजूद है। वृद्धि के लिए व्यापार फायदेमंद है, जब कोई देश उन उद्योगों में माहिर होता है जहां विश्व मांग मजबूत होती है (एमेबल, 2000 और बर्नटोनिट, 2015)। विश्व की मांग के साथ भारत की निर्यात संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की निर्यात संरचना, विश्व व्यापार के औसत पैटर्न की ओर बढ़ रही है, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में ईएसआई में वृद्धि से देखा गया है (चार्ट 1)। इससे पता चलता है कि भारत उन उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल कर रहा है जिनकी अंतरराष्ट्रीय मांग अपेक्षाकृत अधिक है।

भारत की बदलती निर्यात संरचना पण्य स्तर पर भी दिखाई दे रही है; भारत के समग्र निर्यात समूह में इंजीनियरिंग सामान, रसायन, दवाएं और फार्मा, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी

चार्ट 1: भारत के निर्यात समानता सूचकांक का विकास

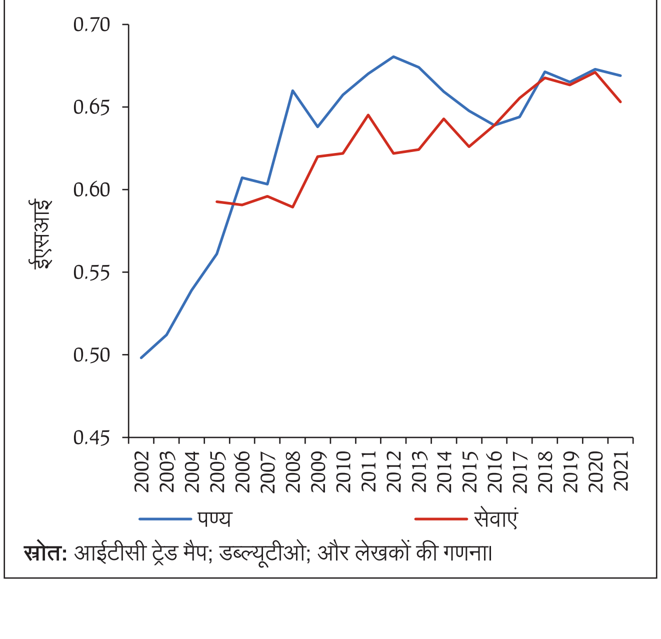

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; डब्ल्यूटीओ; और लेखकों की गणना।

[6] एचएस प्रणाली व्यापार उत्पादों को वर्गीकृत करने की एक मानकीकृत संख्यात्मक विधि है जहां वस्तुओं को 2-अंकीय स्तर एचएस पर अध्यायों (1 से 99) में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे बाद में 4-अंकीय एचएस स्तर पर लगभग 1200 शीर्षकों में विभाजित किया जाता है, इन्हें 6-अंकीय एचएस स्तर पर लगभग 5600 उपशीर्षकों में विभाजित किया जाता है।

चार्ट 2: भारत के निर्यात समूह में संरचनात्मक परिवर्तन

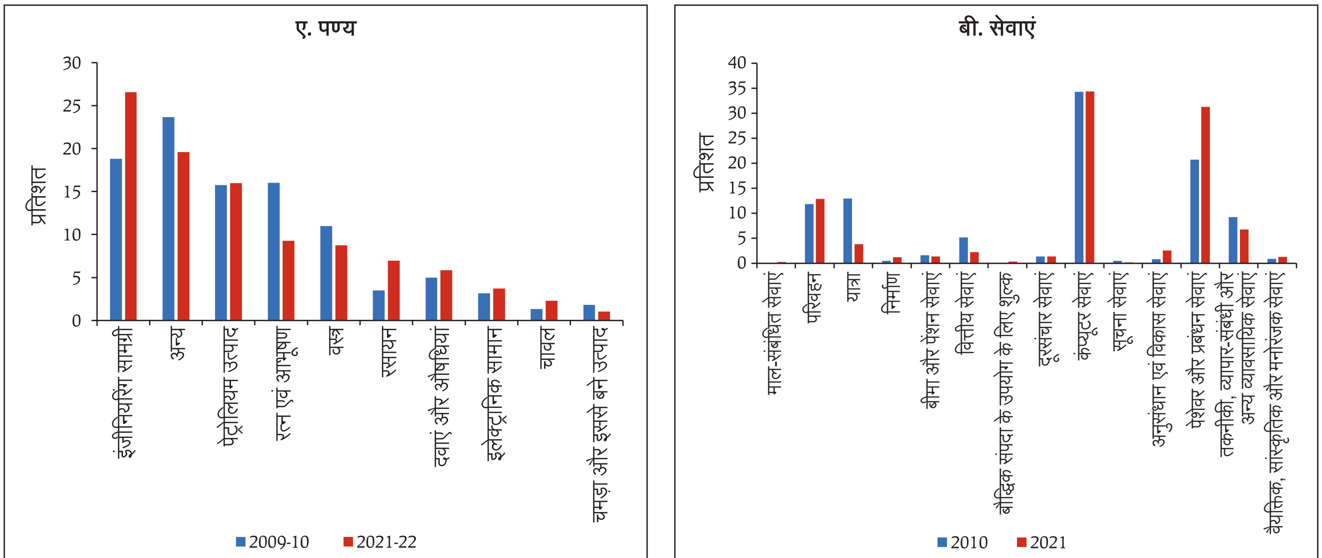

स्रोत: डीजीसीआईएस।

स्रोत: डब्ल्यूटीओ।

प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। दूसरी ओर, रत्न और आभूषण और अन्य श्रम-गहन वस्तुओं जैसे कपड़ा, चमड़ा और चमड़े से बने उत्पादों जैसी वस्तुओं की हिस्सेदारी में पिछले दशक में गिरावट आई है (चार्ट 2ए)। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलाव के पैटर्न के अनुरूप है, जिसकी विशेषज्ञता दशकों से वस्त्रों और कपड़ों तथा चमड़े और खाल के शेयरों में धीरे-धीरे गिरावट है।

सेवाओं के मामले में भी, ईएसआई पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने से भारत का निर्यात ढांचा विश्व के साथ अभिसरण कर रहा है। अलग-अलग स्तर पर, वर्ष 2010 और 2021 के बीच पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट 2बी)। विश्व निर्यात संरचना के साथ समानता की सीमा हाल के वर्षों में वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए लगभग समान स्तर पर है। हालांकि, निर्यात संरचना पर कोविड-19 का प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं, दोनों के लिए दिखाई देता है, जिसका विश्लेषण बाद के उप-खंड में किया जाएगा।

IV.2 जी7 निर्यात संरचना के साथ अभिसरण

यदि समय के साथ दोनों देशों/ क्षेत्रों के बीच ईएसआई बढ़ता है, तो यह दोनों देशों/ क्षेत्रों की अभिसरण निर्यात संरचना को दर्शाता है और यदि यह अभिसरण एई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच है, तो ईएसआई में वृद्धि दर्शाती है कि दोनों की आर्थिक संरचनाएं करीब आ रही हैं और इसलिए यह ईएमई में तेजी से आर्थिक वृद्धि का संकेत देता है (फिंगर और क्रिनिन, 1979 तथा वांग और लियू, 2015)। इसके अलावा, एईएस के साथ किसी देश के निर्यात समूह की समानता को देश के निर्यात के सापेक्ष परिष्कार का एक उपाय माना जाता है (स्कॉट, 2008)।

जी-7 देशों के साथ भारत की पण्य निर्यात संरचना, जैसा कि बढ़ते ईएसआई में परिलक्षित होता है, यह दर्शाता है कि भारत विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने की राह में सही रास्ते पर है, क्योंकि एई के साथ ईएमई के निर्यात समूह में अधिक ओवरलैप, बढ़ते निर्यात परिष्कार को दर्शाता है। वर्तमान में, भारत के निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा जी-7 के समान है और इसमें अभिसरण की और गुंजाइश मौजूद है (चार्ट 3)। देश-वार, समग्र स्तर पर भारत की व्यापारिक निर्यात संरचना, अमेरिका (0.64) के साथ सबसे अधिक मिलती है, इसके बाद यूके (0.62) का स्थान है [चार्ट 4]।

चार्ट 3: जी7 की तुलना में भारत की निर्यात संरचना

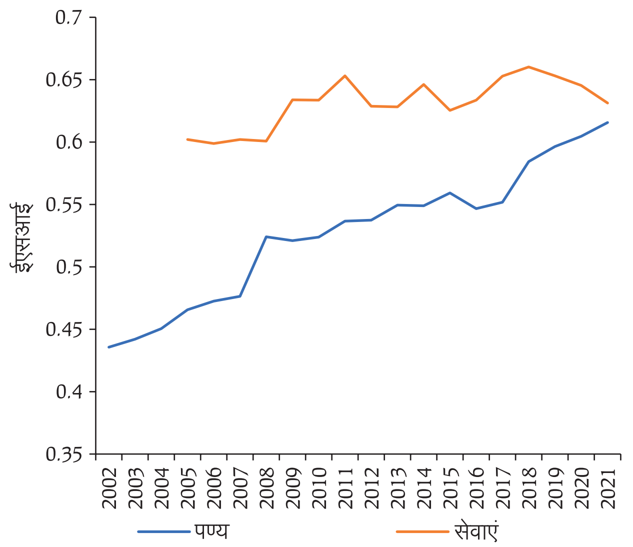

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखकों की गणना।

चार्ट 4: जी7 देशों के साथ भारत के व्यापारिक निर्यात का ईएसआई

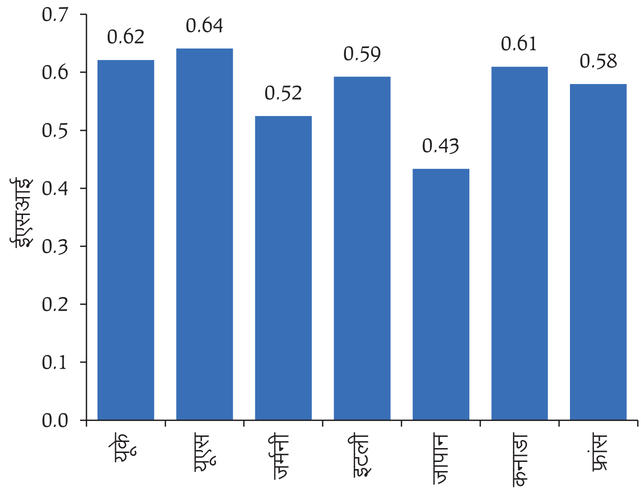

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखकों की गणना।

भारत का सेवा निर्यात काफी हद तक जी-7 सेवा निर्यात पैटर्न के समान रहा है क्योंकि समीक्षाधीन अवधि में इसका ईएसआई मान 0.6-0.65 के आसपास रहा है, जिसमें कोविड-19 के बाद से हाल की अवधि में गिरावट देखी गई है, जब सेवा निर्यात में गिरावट आई थी। सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के कारण भारत के कुल निर्यात में उनकी हिस्सेदारी उच्च स्तर तक बढ़ गई है, यहां तक कि एई में औसत हिस्सेदारी से भी अधिक है (आनंद, कोचर और मिश्रा, 2015) [चार्ट 5]।

इसके अलावा, दुनिया के साथ जी-7 देशों में से प्रत्येक की निर्यात संरचना की तुलना करने पर, यह स्पष्ट है कि जी-7 देशों के पण्य और सेवाओं दोनों की निर्यात संरचना बाकी विश्व के समान है क्योंकि 2021 में कनाडा और जापान (पण्य

चार्ट 5: निर्यात की संरचना

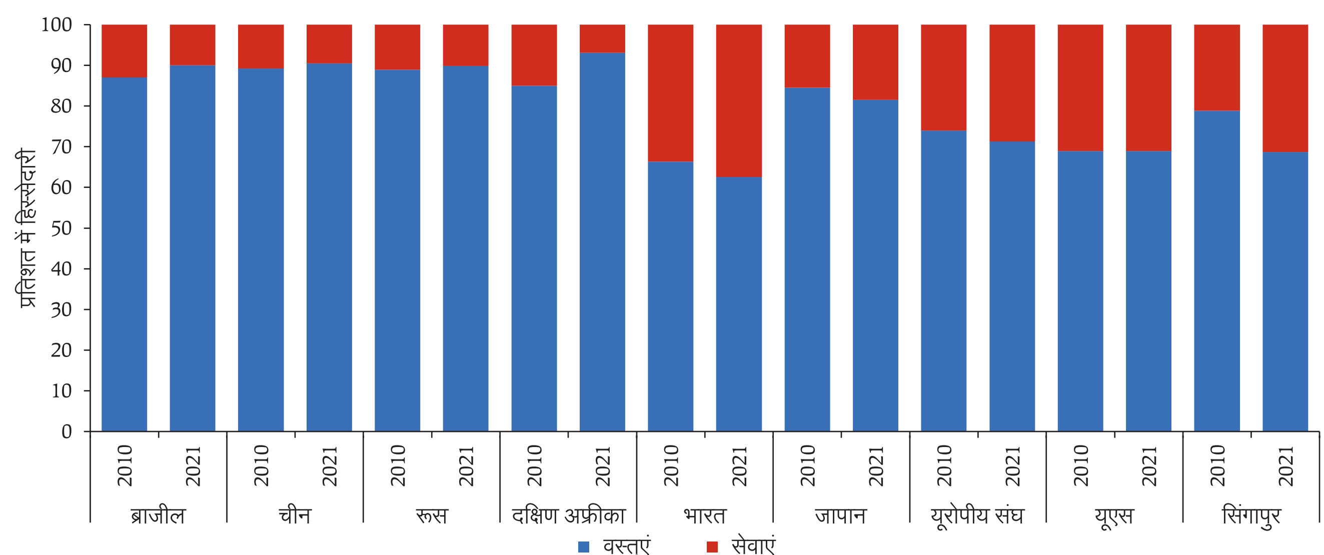

स्रोत: आईएमई।

चार्ट 6: विश्व की तुलना में भारत और जी7 देशों का ईएसआई

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; डब्ल्यूटीओ; और लेखकों की गणना।

के लिए) को छोड़कर ईएसआई 0.7 से ऊपर है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है क्योंकि इसका सूचकांक मूल्य 2002 में 0.50 से सुधरकर 0.67 (पण्य) हो गया है तथा 2005 में 0.6 से बढ़कर 2021 में 0.65 (सेवाएं) हो गया है; हालाँकि यह अभी भी कई जी-7 देशों के स्तर से नीचे है (चार्ट 6)।

जी-7 के साथ भारत का उच्च ईएसआई - ईंधन, मशीनरी, फार्मास्युटिकल उत्पादों और वाहनों आदि जैसी वस्तुओं के लिए दिखाई देता है (चार्ट 7)। 6 अंकीय एचएस के और अधिक अलग-अलग स्तर पर, जैसे कि दवाएं, तेल और बनाने की प्रक्रिया, भारी वाहनों, मोटर कारों आदि के लिए पुर्जे और सहायक सामग्री - ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारत और जी-7 की निर्यात संरचनाओं को समान बनाते हैं।

चार्ट 7: भारत और जी7 के शीर्ष ईएसआई पण्य - 2021

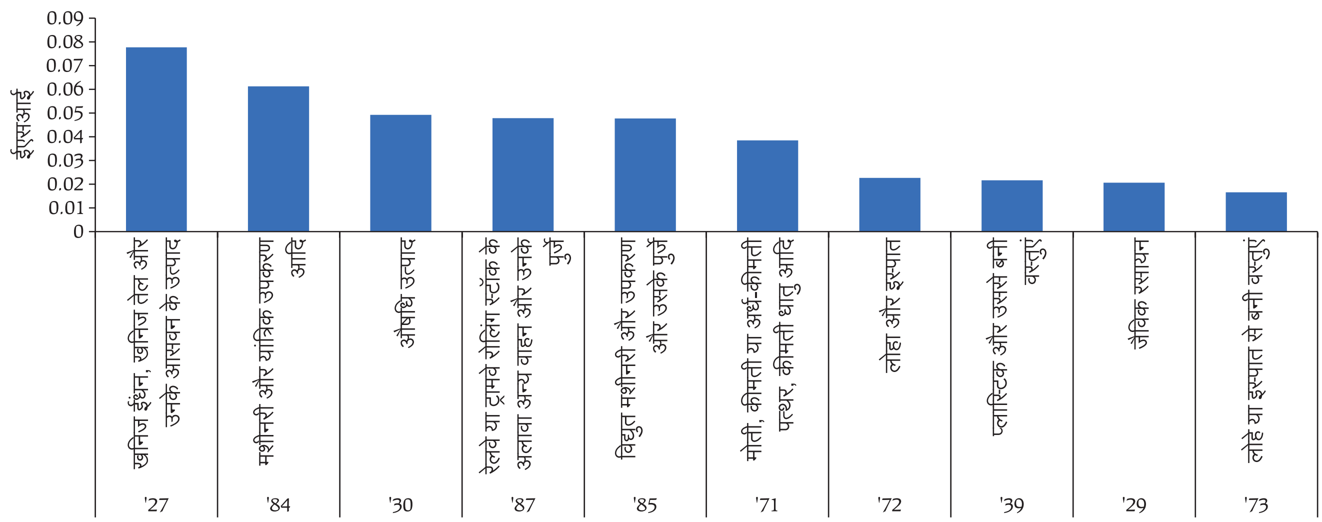

टिप्पणी: पण्य विवरण के नीचे दिए गए नंबर, संबंधित 2-अंकीय एचएस कोड दर्शाते हैं।
स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखकों की गणना।

IV.3 कोविड के बाद की अवधि में सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन

महामारी के आघातों के कारण, 2020 की शुरुआत में दुनिया और जी-7 देशों की तुलना में भारत के व्यापारिक निर्यात में भारी गिरावट देखी गई (चार्ट 8ए)। इस अध्ययन में व्यापार अंतराल की गणना एरिओला और अन्य, 2023 के बाद की गई है, जो कि महामारी-पूर्व स्तरों (दिसंबर 2019 तक) के आधार पर जनवरी 2020 से शुरू होने वाली अवधि के लिए वास्तविक व्यापार प्राप्तियों और निर्यात के अनुमानित मूल्यों के बीच का अंतर है। अनुमानित निर्यात मूल्य सीजनल ऑटो-रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (एसएआरआईएमए) मॉडल से प्राप्त होते हैं। मॉडल का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

विश्व व्यापारिक निर्यात ने भारत की तुलना में एक धनात्मक व्यापार अंतराल शीघ्र प्राप्त किया - वास्तविक निर्यात मूल्य, अनुमानित निर्यात मूल्यों से अधिक रहा। बदले में, भारत का निर्यात अंतराल जी-7 देशों की तुलना में शीघ्र धनात्मक हो गया। हाल के महीनों में, भारत के व्यापारिक निर्यात ने जी-7 और वैश्विक पण्य निर्यात दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

जी-7 सेवा व्यापार अंतराल (निर्यात) ऋणात्मक बना हुआ है, जो महामारी से पहले की प्रवृत्ति से भी नीचे बना हुआ है। दूसरी ओर, भारत का सेवा निर्यात अंतराल 2021 की चौथी तिमाही में धनात्मक हो गया (चार्ट 8 बी)। एरिओला और अन्य (2023) के अनुसार, सेवाओं में डिजिटल रूप से वितरित किया जा सकने वाला व्यापार, महामारी से ऋणात्मक रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। संपर्क-गहन सेवाओं के विपरीत, भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं एवं पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए (चार्ट 2 बी देखें), इसने भारत को सेवा व्यापार अंतराल को तेजी से पाटने में सक्षम बनाया।

कोविड-19 महामारी ने वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार की संरचना में बड़ा बदलाव किया। एरिओला और अन्य (2023) ने जी-7 और चीन के संदर्भ में उल्लेख किया है कि एक ही वर्ष में कोविड-19 के कारण व्यापारिक व्यापार संरचना में बदलाव उन परिवर्तनों के समान परिमाण का है जो आमतौर पर पांच से सात वर्षों की अवधि में देखे जाते हैं। सेवा व्यापार की संरचना में परिवर्तन और भी बड़े हैं। वैश्विक रुझान के अनुरूप, कोविड-19 के बाद की अवधि में भारत की निर्यात संरचना भी 2019 की तुलना में काफी भिन्न है। हालांकि, पण्य व्यापार के

चार्ट 8: संचित कोविड-19 व्यापार अंतराल

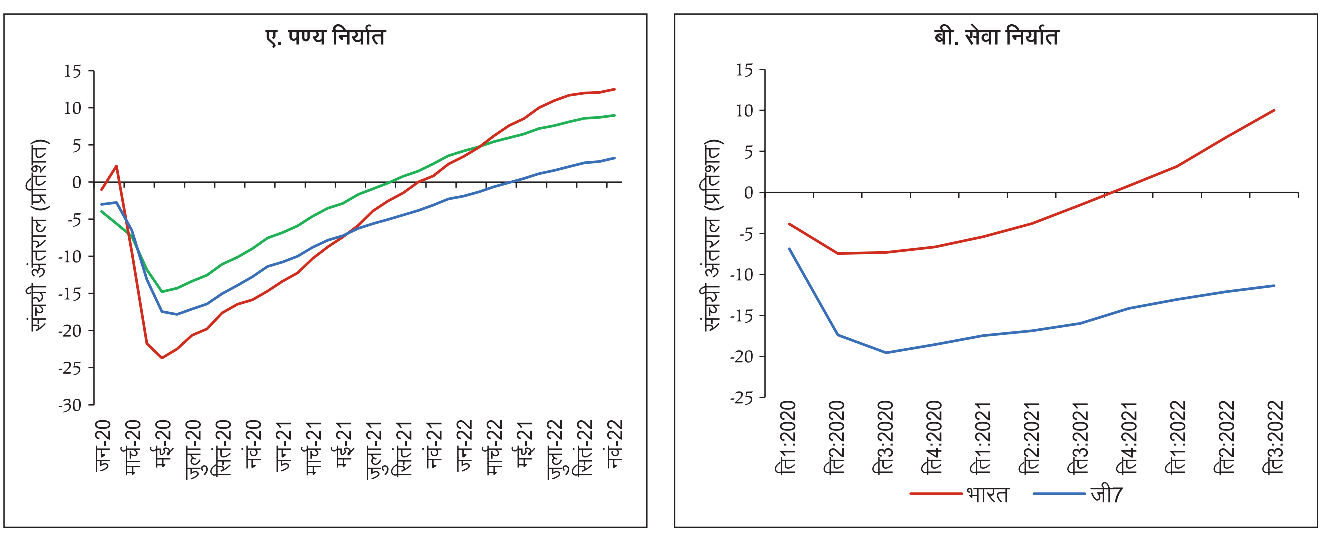

टिप्पणी: संचित व्यापार अंतराल महामारी-पूर्व स्तरों (दिसंबर 2019 तक) के आधार पर, जनवरी 2020 से शुरू होने वाली अवधि के लिए एसएआरआईएमए मॉडल से वास्तविक व्यापार प्राप्तियों और अनुमानित निर्यात मान के बीच का अंतर है।
स्रोत: डब्ल्यूटीओ; और लेखकों की गणना।

चार्ट 9: कोविड के बाद निर्यात संरचना में बदलाव

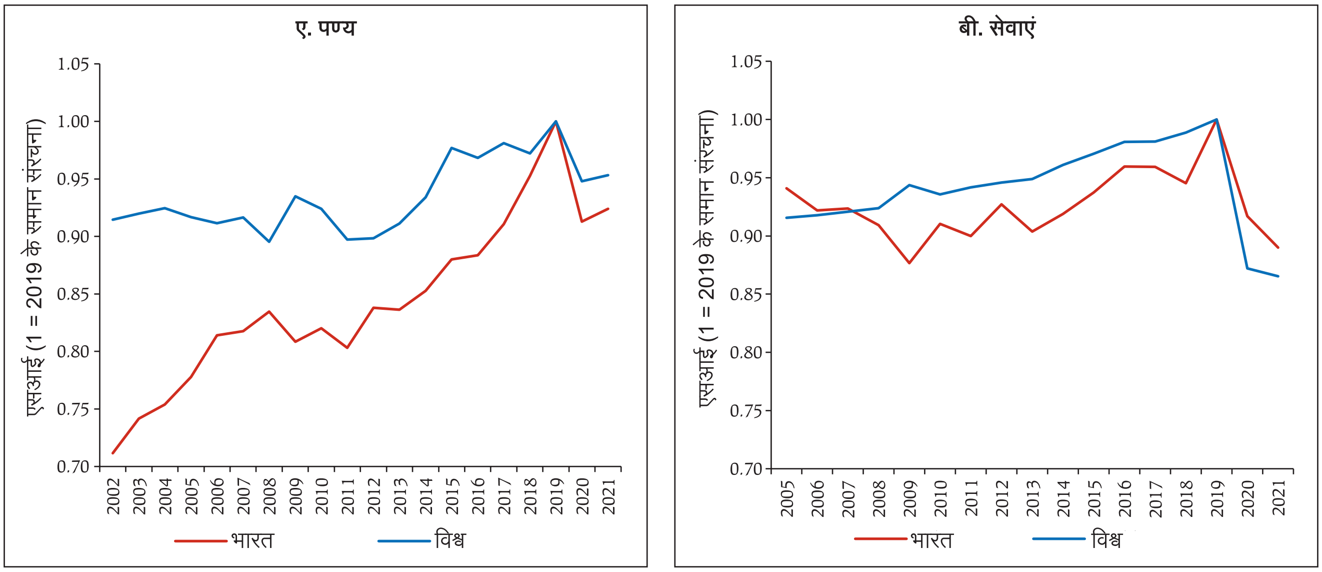

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; विश्व व्यापार संगठन; और लेखकों की गणना।

लिए इसके प्रभाव पलटने लगे हैं। कोविड-19 के बाद के सेवा निर्यात ढांचे की तुलना 2019 के आंकड़ों से करें, तो विश्व के औसत मांग स्वरूप की तुलना में भारत के सेवा निर्यात समूह में कम तेज संरचनात्मक बदलाव आया है (चार्ट 9)। ऐसा भारत के सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात के प्राबल्य के कारण होने की संभावना है, यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे महामारी के दौरान मांग में कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

IV.4 पांच एफटीए भागीदारों के साथ भारत के ईएसआई का विश्लेषण

भारत ने नए एफटीए पर हस्ताक्षर करके और मौजूदा एफटीए को ठीक करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाकर अपनी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दी है। विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार समझौतों का उद्देश्य भारत की निर्यात बाजार विविधीकरण रणनीति को गति देना है। एफटीए में, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ समय की अवधि में भागीदार देशों की निर्यात संरचना की समानता बढ़ जाती है। एफटीए करते समय यदि संभावित एफटीए भागीदार देश/देशों की निर्यात संरचना में उच्च समानता है, तो एफटीए अंतर-उद्योग व्यापार के संदर्भ में ज्यादा लाभ नहीं दे सकता है क्योंकि भागीदार देशों के पास निर्यात पूरकता नहीं है (प्लमर, चेओंग और हमानाका, 2010)। रिकार्डियन /हेक्शेर-ओलिन मॉडल के अनुसार, व्यापार केवल उद्योगों - अंतर-उद्योग व्यापार के बीच होता है। कोई देश ऐसे माल के उत्पादन में विशेषज्ञ होता है जिसमें उसे अपने कारक विन्यास से प्राप्त तुलनात्मक लाभ हासिल होता है और उत्पाद को दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करता है। तुलनात्मक लाभ के आधार पर, यदि एफटीए का एक भागीदार देश किसी विशेष उद्योग के उत्पादों का उत्पादन और निर्यात करता है जो अन्य भागीदार देश द्वारा आयात किए जाते हैं, तो दोनों के बीच व्यापार प्रकृति में पूरक है। इस मामले में, एफटीए भागीदार देशों के बीच अंतर-उद्योग व्यापार में वृद्धि के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होता है या जिसे व्यापार निर्माण के रूप में जाना जाता है।

दूसरी ओर, साहित्य यह भी तर्क देता है कि निर्यात समानता के माध्यम से, अंतः उद्योग व्यापार से एफटीए देशों के अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है (हपसारी और मंगुनसोंग, 2006)। अंतः उद्योग व्यापार तब होता है जब देश उन उत्पादों में व्यापार करते हैं जो एक ही उद्योग से संबंधित हैं जैसे, ब्रांडेड ऑटोमोबाइल में व्यापार। अंतः उद्योग व्यापार विभेदित उत्पादों के कारण उत्पन्न होता है और लाभ पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर दोहन से प्राप्त किया जाता है। उत्पादन प्रक्रियाओं के बढ़ते अंतरराष्ट्रीयकरण के साथ, अंतः उद्योग व्यापार वर्षों से बढ़ रहा है। एफटीए देशों की निर्यात संरचना में

समानता का अर्थ है - अंतः उद्योग व्यापार के लिए अधिक संभावना का होना। इसके अलावा, एफटीए का उनके हब-एंड-स्पोक प्रकृति के माध्यम से व्यापार पर अतिरिक्त सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (अल्बा, हूर और पार्क, 2010)।

भारत ने अब तक अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 14 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, इसने 6 सीमित कवरेज अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें मॉरीशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में (2021 में मॉरीशस के साथ और 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ) समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह उप-खंड अपने पांच बड़े एफटीए भागीदारों अर्थात् आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की निर्यात संरचना की समानता का विश्लेषण करता है।

आसियान के साथ भारत के एफटीए में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में समझौते शामिल हैं। आसियान के साथ भारत के समझौते 2010 में माल व्यापार के लिए और 2014 में सेवाओं और निवेश के लिए लागू हुए थे। आसियान की निर्यात समानता के बारे में एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए, आसियान क्षेत्र के निर्यात के संबंध में अलग-अलग आसियान देशों के ईएसआई की गणना की गई है। ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ को छोड़कर, अन्य सदस्य देशों में निर्यात संरचनाएं आसियान निर्यात संरचना के समान हैं। इसके अलावा, आसियान के भीतर, मलेशिया उच्चतम ईएसआई मूल्य के साथ सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी देश है जो आसियान निर्यात संरचना के साथ मलेशियाई निर्यात संरचना की उच्च समानता प्रदर्शित करता है। इन वर्षों में, वियतनाम की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी है जैसा कि इसके बढ़ते ईएसआई मूल्यों में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, विश्व एफटीए हब के रूप में वियतनाम की प्रगति इसे अन्य सदस्य देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे रही है। भारत के निर्यात समूह का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा आसियान क्षेत्र के समान है और निर्यात समानता पिछले कुछ वर्षों में यह बहुत अधिक नहीं बदली है (चार्ट 10)।

कुछ एशियाई देशों के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत ने 2009 में दक्षिण कोरिया के साथ और 2011 में जापान के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीईपीए और 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतों ने इन देशों के साथ भारत के अधिकांश व्यापार पर शुल्क को समाप्त कर दिया।

चार्ट 10: भारत और आसियान देशों के व्यापारिक निर्यात की आसियान क्षेत्र के साथ समानता

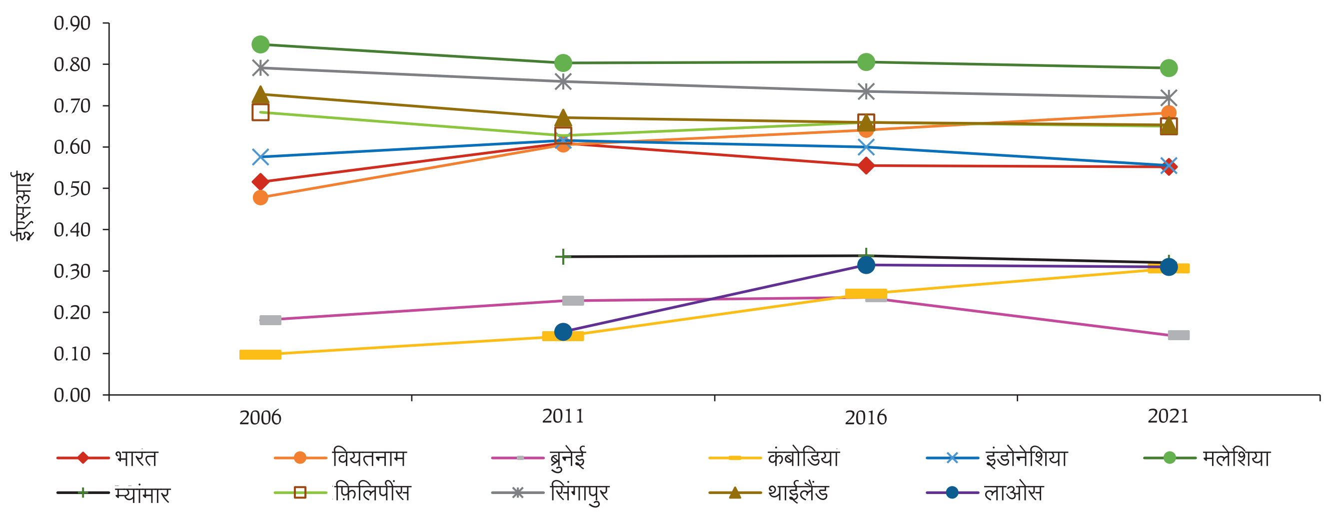

टिप्पणियाँ: 1. ये विश्व भर में निर्यात के लिए समग्र आसियान क्षेत्र के साथ एक देश के द्विपक्षीय ईएसआईएस हैं।
2. लाओस और म्यांमार के लिए डेटा केवल वर्ष 2011 से उपलब्ध है।

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखकों की गणना।

[7] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1814151; https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/

चार्ट 11: भारत के पण्य निर्यात पैटर्न की उसके एफटीए भागीदारों के साथ समानता

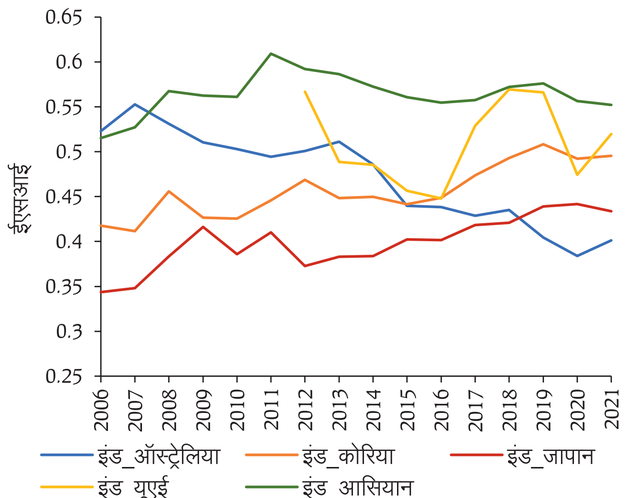

टिप्पणी: संयुक्त अरब अमीरात के लिए डेटा केवल वर्ष 2012 से लगातार उपलब्ध है।
स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखक की गणना।

चार्ट 12: अपने एफटीए भागीदारों के साथ भारत के सेवा निर्यात पैटर्न की समानता

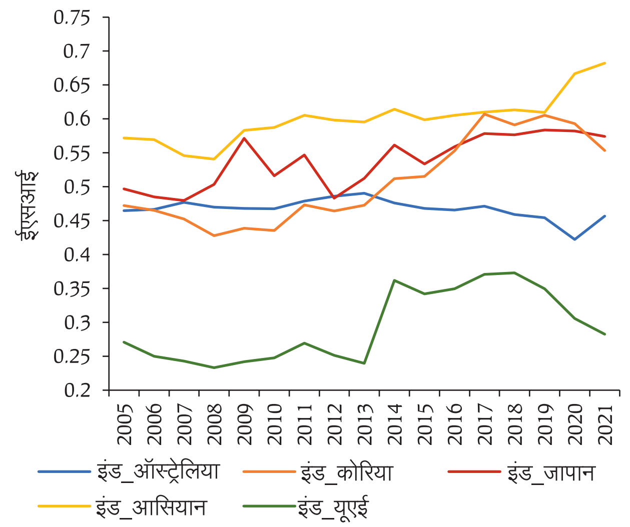

स्रोत: डब्ल्यूटीओ; और लेखकों की गणना।

परिकलित ईएसआई मूल्यों के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की निर्यात संरचनाएं भारत से काफी भिन्न हैं और इसलिए, इन देशों के साथ भारत के लिए अंतर-उद्योग व्यापार विस्तार की बहुत अधिक संभावना है। भारत का निर्यात तेजी से दक्षिण कोरिया के समान हो रहा है; हालांकि, अभी भी दोनों देशों के सूचकांक मूल्य उनके निर्यात में पूरकता दिखाते हैं। दूसरी ओर, चयनित एफटीए देशों में आसियान के साथ भारत का निर्यात पैटर्न सबसे अधिक समान है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में समानता में गिरावट आई है। इसके अलावा, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते के मामले में भारत द्वारा अंतर-उद्योग व्यापार के विस्तार की संभावना अधिक है (चार्ट 11)। संयुक्त अरब अमीरात मुख्य रूप से एक ईंधन निर्यातक देश है, जिसके आधे निर्यात में 'खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन आदि के उत्पाद' शामिल हैं। वैश्विक तेल मांग में उतार-चढ़ाव इसके निर्यात को काफी प्रभावित करता है और इसलिए, इसकी निर्यात संरचना में अस्थिरता दिखाई दे रही है। इसके बावजूद, भारत की संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापारिक निर्यात में दूसरी सबसे बड़ी समानता है, जो संभवतः पेट्रोलियम उत्पादों और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के कारण समानता को दर्शाती है। सेवाओं के मामले में अपने एफटीए भागीदारों की तुलना में भारत के ईएसआई इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत के निर्यात पैटर्न में आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अधिक समानता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ निर्यात पैटर्न में समानता पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई है, नवीनतम अवधि को छोड़कर। ऑस्ट्रेलिया के साथ, हालांकि, माल जैसी सेवाओं के लिए पूरकता मौजूद है (चार्ट 12)। संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूरकता सबसे अधिक है और बढ़ रही है, जो संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा और परिवहन के उच्च हिस्से को दर्शाती है, जबकि भारत का स्थान दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में है।

IV.5 अफ्रीकी बाजार में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ भारत के ईएसआई का विश्लेषण

अफ्रीका निर्यात करने वाले देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संभावित बाजार है। भारत अफ्रीका के साथ तेजी से जुड़ रहा है और महाद्वीप के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत कर रहा है - अफ्रीका के आयात में इसकी हिस्सेदारी 2017 में लगभग 4 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 6 प्रतिशत हो गई।

साहित्य में, ईएसआई को किसी विशेष बाजार में किसी देश के समक्ष प्रतिस्पर्धा की सीमा को मापने के लिए लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, ईएसआई पद्धति ने पाया कि तुर्की को यूरोपीय संघ के बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धा का सामना करना

चार्ट 13: अफ्रीकी बाजार में भारत की निर्यात समानता (2021)

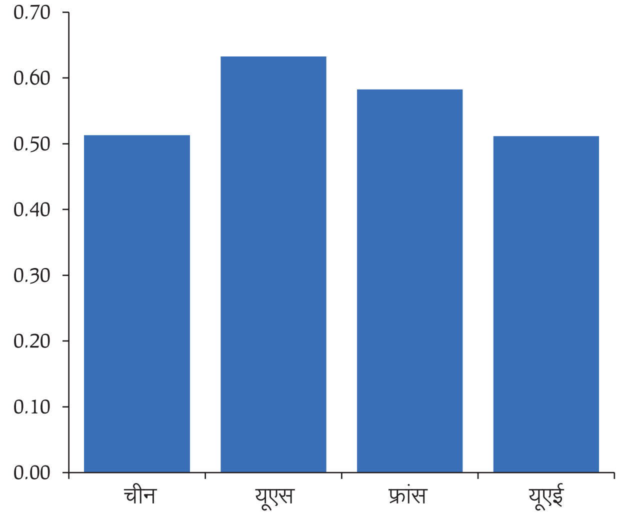

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप; और लेखकों की गणना।

पड़ता है, विशेष रूप से श्रम-गहन वस्तुओं में (एर्लाट और एकमेन, 2009)। अफ्रीका को अन्य प्रमुख वस्तुओं[8] के निर्यातकों के साथ भारत के ईएसआई के आकलन से पता चलता है कि अफ्रीका के लिए भारत का निर्यात अधिकांशतः अमेरिका और फ्रांस के समान है (चार्ट 13)। गहन गांच करते हुए, 4-अंकीय एचएस के स्तर पर ईएसआई इंगित करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर कार और व्यक्तियों के परिवहन के लिए अन्य वाहन, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन एवं चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों के लिए रक्त - ऐसे प्रमुख पण्य हैं जिनमें उच्चतम समानता है, जहां भारत को चीन, अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अफ्रीकी आयात समूह में महत्वपूर्ण शेयरों के साथ 4-अंकीय एचएस वस्तुओं में, जिनके लिए ईएसआई मान कम हैं, जो भारत के लिए व्यापार निर्माण करने वाली निर्यात क्षमता को दर्शाता है, जिसमें पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों, अपरिष्कृत सामग्री से प्राप्त तेल; टेलीफोन सेट; चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद; ट्रैक्टर के लिए पुर्जों और सहायक उपकरण; स्वचालित डेटा-प्रसंस्करण मशीनें और उनकी इकाइयां; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर; और दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन शामिल हैं।

V. नीति के प्रभाव और निष्कर्ष

यह आलेख संभवतः वस्तु और सेवा निर्यात दोनों में भारत के निर्यात समानता सूचकांकों, वर्षों के साथ इसके विकास तथा प्रमुख एई और प्रमुख एफटीए भागीदारों के साथ तुलना की व्यापक जांच करने वाला पहला आलेख है। यह बड़े अफ्रीकी बाजार और उन वस्तुओं में विस्तार की संभावना की भी पड़ताल करता है जो विस्तार को बढ़ा सकते हैं। ईएसआई भारत के निर्यात पैटर्न की ताकत और विकास का एक दृश्य प्रतिनिधित्व देता है। हाल के वर्षों में विश्व निर्यात के साथ भारत के व्यापारिक निर्यात पैटर्न के तेजी से संरेखण से पता चलता है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने से भारत को दुनिया के लिए 'मेड इन इंडिया' के रूप में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने में भी मदद मिल रही है। बढ़ती विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा भारत के लिए आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए अच्छा संकेत है। जी-7 देशों में वस्तु निर्यात के लिए भारत का ईएसआई 0.64 है, जो अमेरिका के साथ सबसे अधिक है, और यह भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य भी है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उन्नति के लिए एक वांछनीय प्रोत्साहन है।

दो प्रतिवाद क्रमबद्ध हैं। पहली, विश्लेषण को पण्य वर्गीकरण के 2-अंकीय स्तर पर किया जाता है, जिससे उच्च स्तर के सूचकांक प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि पण्य एकत्रीकरण का स्तर जितना अधिक होता है, उतना अधिक अंतः उद्योग व्यापार समाप्त हो जाता है। तथापि, व्यापक रुझान भारत को 2030 तक निर्यात के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डालर के स्तर तक ले जाने के लिए नीतिगत प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। दूसरी, भले ही ईएसआई मोटे तौर पर आर्थिक रुझानों के अनुरूप है, यह प्रतिस्पर्धा की सीमा को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकता है क्योंकि यह गुणवत्ता और उत्पाद परिष्कार में अंतर पर विचार नहीं करता है (आईएमएफ, 2011)।

साथ ही, ईएसआई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है - अलग-अलग पण्य स्तर पर ईएसआई में वृद्धि यह संकेत दे सकती है कि स्केल और विशेषज्ञता में बढ़ते रिटर्न के लाभों को प्राप्त करने के लिए निवेश और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को कहां निर्देशित करने की आवश्यकता है। अलग-अलग स्तर पर हमारे

[8] अफ्रीका में देश-वार सेवाओं के आयात पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण सेवाओं के लिए यह विश्लेषण नहीं किया जा सका।

विश्लेषण से पता चलता है कि दवाएं, तेल और बनाने की प्रक्रिया, भारी वाहनों, मोटर कारों आदि के लिए पुर्जों और सहायक उपकरण जैसी वस्तुओं के लिए उच्च प्रतिस्पर्धा है। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हैं जिन्हें मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उच्चतम परिव्यय है, और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए चौथा उच्चतम परिव्यय है[9]। यह इन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, विशेषज्ञता और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है।

महामारी के बाद की अवधि में सेवाओं में, भले ही भारत ने जी-7 देशों की तुलना में व्यापार अंतराल को तेजी से पाट दिया है, विश्व के संबंध में इसकी सेवा ईएसआई सभी जी-7 देशों की तुलना में कम है और नवीनतम वर्ष में भी इसमें गिरावट आई है। यह सॉफ्टवेयर और पेशेवर सेवाओं से परे क्षेत्रों में विविधता लाने और अनुकूल स्थान हासिल करने की आवश्यकता को दर्शाता है। जबकि महामारी के समय भारत की मुख्य सेवाओं के निर्यात की स्थिति ठीक थी, आगे चलकर, भारत को परिवहन और यात्रा में दक्षता हासिल करनी होगी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तत्वावधान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने से इस उद्देश्य में मदद मिलनी चाहिए, जिसमें देश में रसद लागत को मौजूदा 13-14 प्रतिशत से जीडीपी के 10 प्रतिशत से कम करने की परिकल्पना की गई है।

भारत के मुख्य एफटीए व्यापारिक भागीदारों के साथ ईएसआई के विश्लेषण से पता चलता है कि आसियान क्षेत्र में भारत का व्यापारिक ईएसआई, बिग-5 आसियान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है और इसमें गिरावट आ रही है। वियतनाम, जो एक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है, ने पिछले दो दशकों में अपने ईएसआई मान में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। इससे पता चलता है कि भारत के पास आसियान देशों की तुलना में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण गुंजाइश है। एफटीए के प्रभाव में आने के बाद से जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ईएसआई में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो उन्नत एशियाई प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप भारत के निर्यात की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईएसआई का मौजूदा अपेक्षाकृत निम्नतर स्तर पूरकता के माध्यम से निर्यात का विस्तार करने की गुंजाइश प्रदान करता है, जबकि धीरे-धीरे भारत के एफटीए भागीदारों की सूची में नवीनतम प्रविष्टि के साथ व्यापार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता प्रदान करता है। अफ्रीकी बाजार में प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों के साथ ईएसआई विश्लेषण, उन वस्तुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जहां हमारे पास बढ़त है और जहां हमें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है।

जबकि इस आलेख ने चुनिंदा एफटीए भागीदारों के साथ ईएसआई का अवलोकन किया है, निर्यात समानता सूचकांक - इसकी अवधारणा की सादगी और इसके महत्व की व्यापकता के साथ - जब इसकी विस्तृत डेटा और विशिष्ट बाजारों के लिए गणना की जाती है, तो भविष्य के एफटीए में सौदों, समझौतों और रियायतों पर बातचीत के लिए रुझानों के एक संकेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

संदर्भ

Alba, J. M., Hur, J., and Park, D. (2010). Do Hub-and-Spoke Free Trade Agreements Increase Trade? A Panel Data Analysis. *ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration*, No. 46, Asian Development Bank.

Amable, B. (2000). International Specialisation and Growth. *Structural Change and Economic Dynamics*, 11(4), 413-431.

Anand, R., Kochhar, M. K., and Mishra, M. S. (2015). Make in India: Which Exports Can Drive the Next Wave of Growth?. *International Monetary Fund.*

Antimiani, A., & Henke, R. (2007). Old and new partners: Similarity and competition in the EU foreign agri-food trade. *Acta Agriculturae Scand Section C*, 4(3), 129-138.

Arriola, C., Cadestin C., Kowalski P., Guilhoto J.J.M, Miroudot S. and Frank van Tongeren (2023), Challenges to International Trade and the Global Economy: Recovery from COVID-19 and Russia's War of Aggression against Ukraine, *OECD Trade Policy Papers*, No. 265, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5c561274-en.

9 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1671912

Bernatonytė, D. (2015). Estimation of Export Specialization: Lithuanian Case. *Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 10(3), 129-138.

Chandran, D. (2011). Trade Complementarity and Similarity between India and ASEAN Countries in the Context of the RTA. *Available at SSRN* 1763299.

Chow, P. C. (2012). Trade Similarity Index and the Level of Development. In Trade and Industrial Development in East Asia. *Edward Elgar Publishing.*

Erlat, G., and Ekmen, S. (2009). Export Similarity and Competitiveness: The Case of Turkey in the EU Market. In *Proc. Anadolu International Conference in Economics.*

Finger, J. M., and Kreinin, M. E. (1979). A Measure of Export Similarity and its Possible Uses. *The Economic Journal*, 89(356), 905-912.

Hapsari, I. M., and Mangunsong, C. (2006). Determinants of AFTA Members' Trade Flows and Potential for Trade Diversion. *ARTNeT Working Paper Series*, No. 21, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT).

Hasan, M. D. (2007). Measuring Export Competitiveness in South Asia: Export Similarity Index Approach. accessed at

https://www.academia.edu/22528741/Measuring_Export_Competitiveness_in_South_Asia_Export_Similarity_Index_Approach

Hyndman, R. J., and Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice. OTexts.

IMF. (2011). Asia and Pacific, Managing the Next Phase of Growth. Regional Economic Outlook, World Economic and Financial Surveys. April.

Kanupriya. (2020). Export Similarity Index as a Barometer of Indian Textiles Exports Competitiveness. *The Indian Economic Journal*, 68(3), 457-464.

Krugman, P. (2008). The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography. Nobel Prize Lecture, December 8

Linder, S. B. (1961). An essay on trade and transformation (pp. 82-109). Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Nguyen, T. N. A., Pham, T. H. H., and Vallée, T. (2017). Similarity in Trade Structure: Evidence from ASEAN+ 3. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 26(8), 1000-1024.

Parteka, A., and Tamberi, M. (2013). Product Diversification, Relative Specialisation and Economic Development: Import–Export Analysis. *Journal of Macroeconomics*, 38, 121-135.

Plummer, M. G., Cheong D., and Hamanaka, S. (2010). Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements. Asian Development Bank.

Schott, P. K. (2008). The Relative Sophistication of Chinese Exports. *Economic Policy*, 23(53), 6-49.

Vlasenko, L. (2020). Evaluation of the Composite Export Similarity Index on the Example of China. REICE: *Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas 8, No. 16*: 135-149.

Wang, P. Z., and Liu, X. J. (2015). Comparative Analysis of Export Similarity Index between China and EU. *International Conference on Management Science and Management Innovation* (pp. 222-227). Atlantis Press. August.

अनुबंध I: निर्यात समानता सूचकांक की साहित्य समीक्षा

संदर्भ	अवधि/ भूगोल	तरीका	प्रमुख निष्कर्ष/ परिणाम
फिंगर और क्रेनिन (1979)	380 श्रेणियों को कवर करते हुए मानक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (एसआईटीसी) डेटा का उपयोग करके विनिर्मित निर्यात के समानता पैटर्न की गणना की गई। 1960 से 1974 तक का डेटा। कवर किए गए देशों में अमेरिका, जापान, पुराने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (छह देश) और बाकी औद्योगिक पश्चिमी यूरोप, कम विकसित देशों (एलडीसी) के तीन समूह - अर्ध-औद्योगिक, निम्न विकसित और अन्य शामिल हैं।	निर्यात समानता का सूचकांक पेश किया गया। अध्ययन का उद्देश्य है: (i) किसी विशेष देश (देशों) को दिए गए अधिमान्य उपचार के संभावित व्यापार मोड़ या व्यापार निर्माण प्रभावों को समझना (ii) उस स्तर का आकलन करना जिससे दो देशों या देशों के समूहों की आर्थिक संरचना का अभिसरण/ विचलन होती है।	1. प्रमुख औद्योगिक देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और पुराने यूरोपीय आर्थिक समुदाय) की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) के कारण होने वाले व्यापार परिवर्तन से ज्यादातर सात अर्ध-औद्योगिक एलडीसी को लाभ होगा। 2. प्रशुल्क (टैरिफ) और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) के तहत औद्योगिक देशों द्वारा आदान-प्रदान की गई टैरिफ रियायतें संभवतः अर्ध-औद्योगिक एलडीसी के निर्यात को बढ़ाने में सहायक रही हैं, लेकिन अन्य एलडीसी के निर्यात में ऐसा नहीं हुआ। 3. जब तक एलडीसी जीएटीटी वार्ता में गैर-पारस्परिक भूमिका निभाने पर जोर देते हैं, व्यापार बाधाओं में और कमी की संभावना कम हो जाती है। 4. यूरोप में मुक्त व्यापार क्षेत्र के गठन से एलडीसी के पक्ष में अधिकांश प्राथमिकताएँ समाप्त हो गई हैं।
एमेबल (2000)	1965-1990 के दौरान 39 देशों की आर्थिक वृद्धि पर अंतर-उद्योग विशेषज्ञता और व्यापार असमानता का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञता के प्रभावों की जांच की गई।	विदेशी व्यापार के तीन संकेतक माने जाते हैं - (i) अंतर-उद्योग विशेषज्ञता (ii) व्यापार असमानता का सूचकांक, और (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स में तुलनात्मक लाभ।	व्यापार असमानता सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश का व्यापार पैटर्न अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप है या नहीं। क्षणों की सामान्यीकृत पद्धति का उपयोग करते हुए, शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व व्यापार से भिन्न व्यापार संरचना, वृद्धि को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है।

अनुबंध I: निर्यात समानता सूचकांक की साहित्य समीक्षा *(जारी...)*

संदर्भ	अवधि/ भूगोल	तरीका	प्रमुख निष्कर्ष/ परिणाम
स्कॉट (2008)	1972-2001 की अवधि के लिए चीन के निर्यात के सापेक्ष "परिष्कार" की जांच की गई।	गणना की गई- (i) बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद की पहुँच (ii) एफके का एसआई, और (iii) कीमत तुलना	1. अध्ययन का निष्कर्ष है कि चीन का निर्यात समूह तेजी से दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ ओवरलैप हो रहा है। 2. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) से निकलने वाले निर्यात की तुलना में चीन का निर्यात पर्याप्त और बढ़ती छूट पर बिकता है।
एर्लाट और एकमेन (2009)	1996-2007 की अवधि के लिए सापेक्ष परिष्कार के उपाय के रूप में ईयू-15 समूह के अन्य प्रमुख निर्यातकों के साथ तुर्की निर्यात की समानता और विकसित देशों के निर्यात का विश्लेषण किया गया।	गणना की गई- (i) एफके का निर्यात एसआई, (ii) उत्पाद एसआई, और (iii) कीमत एसआई।	1. तुर्की को यूरोपीय संघ के बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देशों और क्षेत्रों के संबंध में प्रतिस्पर्धा का स्तर बदलता रहता है। 2. उत्पाद के लिहाज से, तुर्की को श्रम-गहन वस्तुओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 3. हालांकि, विकसित देशों के साथ तुर्की की निर्यात समानता बढ़ रही है, पर कुछ विकसित देशों के साथ कम बनी हुई है।
चाउ (2012)	पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार समानता सूचकांक का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया कि क्या विकासशील पूर्वी एशियाई देश आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और 1962-2000 की अवधि के लिए निर्यात समानता सूचकांक और आर्थिक विकास के स्तर के बीच संबंधों की पड़ताल करते हैं।	एफके के एसआई की गणना की गई।	विश्लेषण से पता चला है कि जैसे-जैसे जापान और आसियान देशों के बीच आय का अंतर कम हुआ, विश्व बाजार में जापान के साथ निर्यात वस्तुओं के बीच ओवरलैप बढ़ गया, यह दर्शाता है कि निर्यात वस्तुओं के बीच अधिक ओवरलैप के कुछ सबूत हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अंतर कम हो जाता है।

अनुबंध I: निर्यात समानता सूचकांक की साहित्य समीक्षा *(जारी...)*

संदर्भ	अवधि/ भूगोल	तरीका	प्रमुख निष्कर्ष/ परिणाम
पार्टेका और ताम्बेरी (2013)	1988-2010 की अवधि के लिए 163 देशों के लिए दुनिया की तुलना में देशों के निर्यात और आयात के सापेक्ष विशेषज्ञता पैटर्न का आकलन किया।	गणना की गई- (i) सापेक्ष थील सूचकांक, (ii) सापेक्ष गिनी सूचकांक, और (iii) असमानता सूचकांक।	अध्ययन का निष्कर्ष है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, निर्यात और आयात समूह में विशेषज्ञता में गिरावट देखी जाती है और अधिक विविध हो जाती है तथा आयात और निर्यात संरचनाओं के बीच समानता में वृद्धि होती है।
बर्नटोनित (2015)	2007-2013 की अवधि के लिए एसआईटीसी डेटा का उपयोग करके लिथुआनिया में निर्यात विशेषज्ञता की प्रकृति और पैटर्न की जांच की।	गणना की गई- (i) निर्यात विशेषज्ञता सूचकांक (संशोधित आरसीए सूचकांक), (ii) व्यापार असमानता सूचकांक।	1. यूरोपीय संघ में लिथुआनिया के एकीकरण ने इसकी निर्यात विशेषज्ञता को प्रभावित किया है। लिथुआनिया की व्यापार संरचना यूरोपीय संघ के समान है। 2. लिथुआनिया से यूरोपीय संघ में सबसे बड़ा प्रवाह भोजन, पेय-पदार्थ और तंबाकू में है; कच्चे माल; खनिज ईंधन, ल्यूब्रिकैंट और संबंधित सामग्री।
वांग और लियू (2015)	विश्व बाजार, अमेरिकी बाजार और भारतीय बाजार में चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच निर्यात समानता का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 2007-2013 से 1-अंकीय डेटा एसआईटीसी का उपयोग किया गया है।	विभिन्न बाजारों में चीन और यूरोपीय संघ के लिए एफके के एसआई की गणना की गई।	1. चीन और यूरोपीय संघ में विकसित देशों के बाजार में उच्च निर्यात समानता है और इसलिए, भीषण प्रतिस्पर्धा है। 2. चीन और यूरोपीय संघ विकासशील देशों के बाजार में व्यापार पूरकता रखते हैं।
गुयेन और अन्य (2017)	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) + 3 सदस्यों के लिए 1 से 4 अंकीय एसआईटीसी डेटा पर निर्यात समानता सूचकांक की गणना की गई। इसकी तुलना, तुलनात्मक लाभ सूचकांक से की गई है। आसियान+3 में निर्यात समुदायों (सबसे समान	1. प्रत्येक सदस्य देश के लिए फिंगर एंड क्रिनिन (एफके) के समानता सूचकांक (एसआई) की गणना की गई। 2. नेटवर्क विश्लेषण में स्यूडो-एल्गोरिदम के माध्यम से एसआई परिणामों के आधार पर सामुदायिक पहचान।	1. आसियान + 3 की निर्यात संरचना में समानता, ब्रुनेई और कंबोडिया के साथ सदस्यों के बीच भिन्न होती है, जिसमें एसआई का स्तर निम्न होता है जबकि चीन, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया उच्च निर्यात समानता का अनुभव करते हैं।

अनुबंध I: निर्यात समानता सूचकांक की साहित्य समीक्षा *(समाप्त)*

संदर्भ	अवधि/ भूगोल	तरीका	प्रमुख निष्कर्ष/ परिणाम
	या सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी) का पता लगाया गया। 1990-2014 के आंकड़े। इसमें आसियान और चीन, जापान और कोरिया शामिल हैं।		2. जापान, सिंगापुर, चीन, मलेशिया और कोरिया, उच्चतम एसआई के साथ, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोसर्किट और कार्यालय की मशीनों के कुछ हिस्सों में एक निर्यात समुदाय बनाते हैं। 3. निर्यात समानता धनात्मक रूप से और महत्वपूर्ण रूप से प्रकट तुलनात्मक लाभ (आरसीए) के साथ जुड़ी हुई है।
व्लासेंको (2020)	1. प्रस्तावित समग्र निर्यात समानता सूचकांक। 2001-18 के लिए हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम (एचएस) 2-अंकीय वस्तुओं में 40 देशों के पैनल डेटा का उपयोग किया गया है। 2. चीन के निर्यात पोर्टफोलियो की तुलना 40 अन्य प्रमुख वैश्विक निर्यातकों के साथ की जाती है जो 246 गंतव्यों के लिए डेटा को कवर करते हैं।	वस्तुओं के निर्यात समानता सूचकांक और गंतव्यों के निर्यात समानता सूचकांक को एकीकृत करके गणना की गई समग्र निर्यात समानता सूचकांक।	चीन के सबसे संभावित प्रतियोगी - वियतनाम, कोरिया गणराज्य, जापान, मलेशिया और सिंगापुर थे; कुवैत, सऊदी अरब और ईरान की तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाएं अल्पतम संभावित प्रतिस्पर्धी थीं, जिनके निर्यात में कोई ओवरलैप नहीं था।
कनुप्रिया (2020)	ईएसआई ने प्रत्येक उत्पाद के लिए पांच प्रमुख बाजारों के लिए 2013 से 2017 की अवधि के लिए एचएस 6-अंकीय स्तर (56 से 60 तक एचएस 2-अंकीय स्तर के तहत) पर पांच प्रमुख उत्पादों के लिए गणना की।	ईएसआई की गणना भागीदार देश (पहचाने गए शीर्ष पांच बाजारों में से प्रत्येक) को भारतीय वस्त्र निर्यात के अनुपात को उन देशों को सभी उत्पादों के कुल निर्यात से भागीदार के वस्त्र निर्यात और भारत को सभी उत्पादों के कुल निर्यात के अनुपात से विभाजित करके की जाती है।	भारतीय वस्त्र निर्यात ईएसआई के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी नहीं है।

अनुबंध II: निर्यात पूर्वानुमानों के माध्यम से व्यापार अंतराल की गणना

ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (एआरआईएमए) मॉडल रैखिक मॉडल का एक प्रकार है जो भविष्य के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक मूल्यों का उपयोग करता है। एक ऑटोरेग्रेशन (एआर) मॉडल में, हम उस चर के पिछले मूल्यों के रैखिक संयोजन का उपयोग करके ब्याज के चर का पूर्वानुमान लगाते हैं। इंटीग्रेटेड किसी भी भिन्नता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे डेटा को स्थिर बनाने के लिए लागू किया जाना चाहिए। मूविंग एवरेज मॉडल भविष्य के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रतिगमन-जैसे मॉडल में पिछले मूल्यों के बजाय पिछली पूर्वानुमान त्रुटियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, एक विशिष्ट मॉडल इस प्रकार होता है:

$ARIMA\ (p, d, q)$

जहाँ p: आश्रित चर के अंतरालों की संख्या (एआर पद),

d: शृंखला को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक अंतरों की संख्या, और

q: एरर टर्म (एमए पद) के विलंबित पदों की संख्या।

सीज़नल ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज

(एसएआरआईएमए या सीजनल एआरआईएमए), एआरआईएमए का एक विस्तार है जो मौसमी घटक के साथ यूनीवेरिएट टाइम सीरीज़ डेटा का समर्थन करता है। शृंखला के मौसमी घटक के लिए ऑटोरेग्रेशन (एआर), डिफरेंसिंग (आई) और चल औसत (एमए) को निर्दिष्ट करने के लिए तीन नए मापदंड, साथ ही मौसमी की अवधि के लिए एक अतिरिक्त मापदंड जोड़ा गया है। एसएआरआईएमए मॉडल इस प्रकार है:

$SARIMA\ (p, d, q)\ (P, D, Q)m$

जहां, *m* मौसमी अवधि है (उदाहरण के लिए, प्रति वर्ष प्रेक्षणों की संख्या), एकल मौसमी अवधि के लिए समय चरणों की संख्या

'लोअरकेस नोटेशन' का उपयोग मॉडल के ट्रेंड (गैर-मौसमी) भाग के लिए किया जाता है, जबकि 'अपरकेस नोटेशन' का उपयोग मॉडल के मौसमी भागों के लिए किया जाता है।

आलेख में, महामारी से पहले के आंकड़ों के आधार पर पण्य व्यापार की भविष्यवाणी के लिए, मासिक आवृत्ति वाले एक मॉडल का उपयोग किया जाता है। मॉडल की विशिष्टता निम्न है:

$SARIMA\ (1,1,1)\ (0,1,1)12$

त्रैमासिक आवृत्ति के साथ, महामारी-पूर्व डेटा के आधार पर सेवा व्यापार के पूर्वानुमान के लिए, मॉडल इस प्रकार है:

$SARIMA\ (1,1,1)\ (0,1,1)4$

भारत की स्थिर साम्य मुद्रास्फीति: पुनर्मूल्यांकन

आर. के. सिन्हा^ द्वारा

यह लेख 2014 से 2022 की अवधि में मुद्रास्फीति के स्टोकेस्टिक संक्रमण को ट्रैक करता है, जो 2016 में अपनी औपचारिक संस्था के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य को वास्तविक रूप से अपनाने और उसके बाद के अनुभव के साथ मेल खाता है। इसमें पाया गया है कि महामारी से पहले के आंकड़ों के आधार पर मुद्रास्फीति का दीर्घकालिक स्थिर राज्य संतुलन स्तर लगभग 4.3 प्रतिशत हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि महामारी की अवधि में इसमें मामूली वृद्धि हुई है, जो क्षणिक होने की संभावना है और वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक स्थितियों के सामान्य होने के बाद आने वाले समय में निचले स्तर पर पहुंच सकती है।

परिचय

मुद्रास्फीति के स्वीकार्य और वांछनीय स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में, जबकि रिज़र्व बैंक का नीतिगत रुख सबसे प्रमुख और मार्गदर्शक कारक रहा है, अन्य घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक कारक भी हैं, जो मुद्रास्फीति पथ को प्रभावित कर रहे हैं। बार-बार लगने वाले झटके मुद्रास्फीति को उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति से दूर ले जाते हैं और लघु से मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र की सहजता को बिगाड़ देते हैं। ये झटके सकारात्मक (अनुकूल) के साथ-साथ नकारात्मक (प्रतिकूल) भी होते हैं। सकारात्मक झटके (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट) ने कई बार हेडलाइन मुद्रास्फीति को नीचे लाने में सहायता की है, जबकि प्रतिकूल झटके (जैसे चुनिंदा खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से अनाज और सब्जियों की कीमतों में अचानक और अभूतपूर्व वृद्धि, और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल), अल्पावधि में मुद्रास्फीति को सामान्य प्रक्षेपवक्र से बाहर निकालते हैं। आपूर्ति के इन झटकों की संवेदनशीलता के बावजूद, रिज़र्व बैंक के नीतिगत रुख के माध्यम से निरंतर प्रयास ने कोविड-पूर्व अवधि के दौरान मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के निशान तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,जिससे लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई।

विभिन्न आघातों की उपस्थिति में, यह हमेशा एक प्रासंगिक प्रश्न रहा है कि एफआईटी के बाद की अवधि में भारत में मुद्रास्फीतिकी प्रवृत्ति क्या रही है, और यह एक स्थिर राज्य संतुलन के तहत लंबे समय तक कहां मंडराएगी। इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की संभावित केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रारंभिक कवायद से पता चला कि मुद्रास्फीति का दीर्घकालिक स्थिर संतुलन स्तर ऊपर की ओर झुकाव के साथ लगभग 4 प्रतिशत तक स्थिर हो सकता है (आरबीआई, 2017)। अध्ययन ने उपलब्ध सीमित आंकड़ों का उपयोग करके उपयुक्त संक्रमण संभाव्यता मैट्रिक्स (टीपीएम) के माध्यम से मार्कोव श्रृंखलाओं के माध्यम से मुद्रास्फीति के संक्रमण को ट्रैक किया। इस पर एक अपडेट का भी विश्लेषण किया गया और बाद में चर्चा की गई, जिसने पहले के अध्ययन (सिन्हा, 2018) के निष्कर्षों की पुष्टि की।

बेहरा और पात्र (2020) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 2007 से 2020 (कोविड महामारी के उभरने से पहले) तक देखी गई मुद्रास्फीति की लंबी श्रृंखला का उपयोग करके न्यू केनेसियन फिलिप्स कर्व (एनकेपीसी) के माध्यम से प्रवृत्ति मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है। शासन के पूर्व-विनिर्देश के साथ एनकेपीसी मॉडल का अनुमान लगाने से पहले, मुद्रास्फीति के वर्तमान शासन को समझने के लिए अज्ञात शासनों के साथ मार्कोव स्विचिंग प्रतिगमन का अनुमान लगाया गया था। प्रमुख निष्कर्षों ने भारत के हालिया मुद्रास्फीति इतिहास में दो व्यवस्थाओं का संकेत दिया - 2007-2014 के दौरान 9.4 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति व्यवस्था और 2015-2020 के दौरान 4.0 प्रतिशत की निम्न मुद्रास्फीति व्यवस्था (कोविड से पहले)। बाद की व्यवस्था में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति का संभाव्यता भारित अनुमान 4.2 प्रतिशत अनुमानित किया गया

^ लेखक मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) से हैं। लेखक इस लेख को तैयार करने में उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए डॉ. माइकल देबब्रत पात्र के आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] कोविड-19 महामारी के उभरने और उसके बाद यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित दुनिया भर में मुद्रास्फीति लक्ष्य बिंदु से बहुत दूर हो गई।

[2] प्रवृत्ति मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का स्थायी या अंतर्निहित घटक है जिसमें वास्तविक मुद्रास्फीति एक झटके के बाद अभिसरण करती है। वैकल्पिक रूप से, इसे स्थिर राज्य मुद्रास्फीति (एस्करी और स्बोर्डोन, 2014) के रूप में जाना जाता है। इस लेख में, हम प्रवृत्ति मुद्रास्फीति और स्थिर स्थिति (या स्थिर राज्य संतुलन) मुद्रास्फीति का परस्पर उपयोग करते हैं।

था। 2019 की पहली तिमाही में वास्तविक समय फ़िल्टर और चिकना पश्चवर्ती अनुमान-आधारित भारित औसत प्रवृत्ति मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत अनुमानित थी। यह पाया गया कि प्रवृत्ति मुद्रास्फीति के सहज संभाव्यता भारित अनुमान 2009 से लगातार कम होकर 2020 की पहली तिमाही में 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गए।

अब लंबी श्रृंखला के सीपीआई-सी आधारित मुद्रास्फीति आंकड़ों की उपलब्धता के साथ, हम मुद्रास्फीति के स्थिर राज्य संतुलन पर फिर से विचार करते हैं और पहले के प्रारंभिक अध्ययन (आरबीआई, 2017) का विस्तार करते हैं और पूर्व-कोविड से लेकर कोविड के बाद की अवधि तक मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र में क्षणिक परिवर्तनों की जांच करते हैं। हम पाते हैं कि कोविड-19 से पहले के दौर में मुद्रास्फीति का स्थिर राज्य संतुलन मोटे तौर पर बेहरा और पात्र (2020) के निष्कर्षों के अनुरूप है, जिसमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया गया था। डेटा के दोनों सेटों (कोविड से पहले और बाद के) के लिए दीर्घकालिक संतुलन संबंधित अवधि में दर्ज किए गए संबंधित देखे गए आंकड़ों की तुलना में 20-40 बीपीएस कम स्तर का संकेत देता है।

लेख को चार खंडों में विभाजित किया गया है। परिचयात्मक खंड के बाद, दूसरे खंड में शैलीबद्ध तथ्यों को शामिल किया गया है। तीसरे खंड में अध्ययन में अपनाई गई पद्धति को शामिल किया गया है। अंतिम खंड अध्ययन से कुछ प्रमुख टेकअवे के साथ लेख का समापन करता है।

II. मुख्य तथ्य

सीपीआई-सी आधारित मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष) में 2014 के मध्य से गिरावट देखी गई, जिसमें व्यापक आधार पर मूल्य दबाव कम होने से सहायता मिली। मुद्रास्फीति पिछले वर्ष 2013 के कई दोहरे अंकों से सितंबर 2014 में 6 प्रतिशत से नीचे आ गई, और नवंबर 2019 तक लक्ष्य सीमा के भीतर रही, 63 महीनों की लंबी अवधि के दौरान केवल तीन मौकों पर 3 को पार किया (चार्ट 1)।

[3] मुद्रास्फीति दो बार (जून 2017 में 1.46 प्रतिशत और जनवरी 2019 में 1.97 प्रतिशत) और एक बार ऊपरी सीमा (जुलाई 2016 में 6.07 प्रतिशत) को पार कर गई। उल्लेखनीय रूप से, इन तीन उल्लंघनों में से, दो मामूली (सिर्फ 3 और 7 आधार अंक) थे।

चार्ट 1: सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की समय - शृंखला

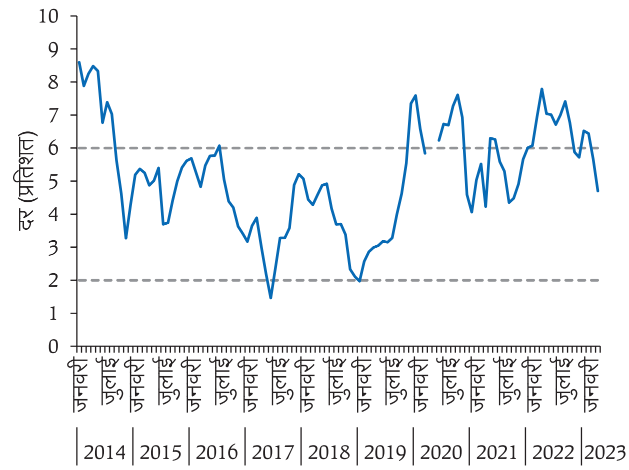

नोट: अप्रैल और मई 2020 के मुद्रास्फीति संबंधी प्रिंट सम्मिलित नहीं हैं। महामारी – के कारण उत्पन्न सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर लगाए गए लॉकडाउन्स जिन्हें बाद में खत्म कर दिया गया था उनके कारण एमओएसपीआई द्वारा नियमित रूप से इन्हें प्रकाशित नहीं किया गया था।
स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)।

यूक्रेन युद्ध के बाद कोविड महामारी के उभरने के बाद कई महीनों तक विकसित देशों सहित कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही। भारत अपनी मुद्रास्फीति को 7.79 प्रतिशत (अप्रैल 2022) के उच्चतम रिकॉर्ड के साथ एकल-अंक के स्तर पर सीमित रख सकता है। महामारी की शुरुआत के बाद से उल्लंघन के मामले में ऊपरी सीमा का औसत ओवरशूट अपेक्षाकृत कम (79 आधार अंक) रहा है। कोविड-19 के बाद की

चार्ट 2: सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का आवृत्ति वितरण

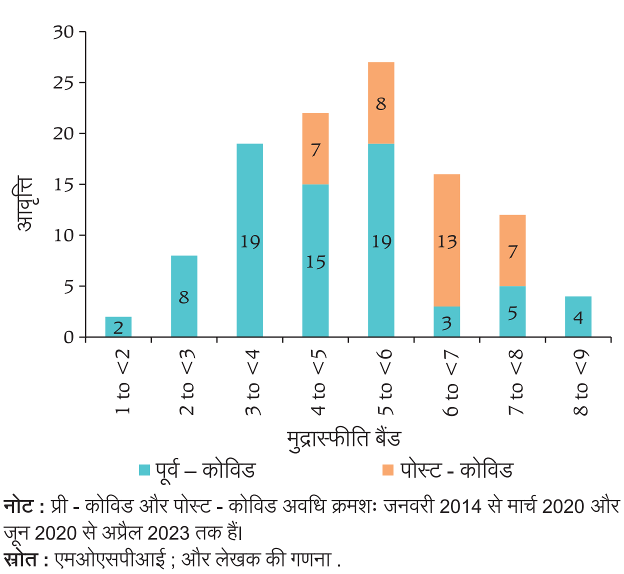

नोट : प्री - कोविड और पोस्ट - कोविड अवधि क्रमशः जनवरी 2014 से मार्च 2020 और जून 2020 से अप्रैल 2023 तक हैं।
स्रोत : एमओएसपीआई ; और लेखक की गणना .

चार्ट 3: सीपीआईसी-सी घटकों का सीएजीआर (2014-2022)

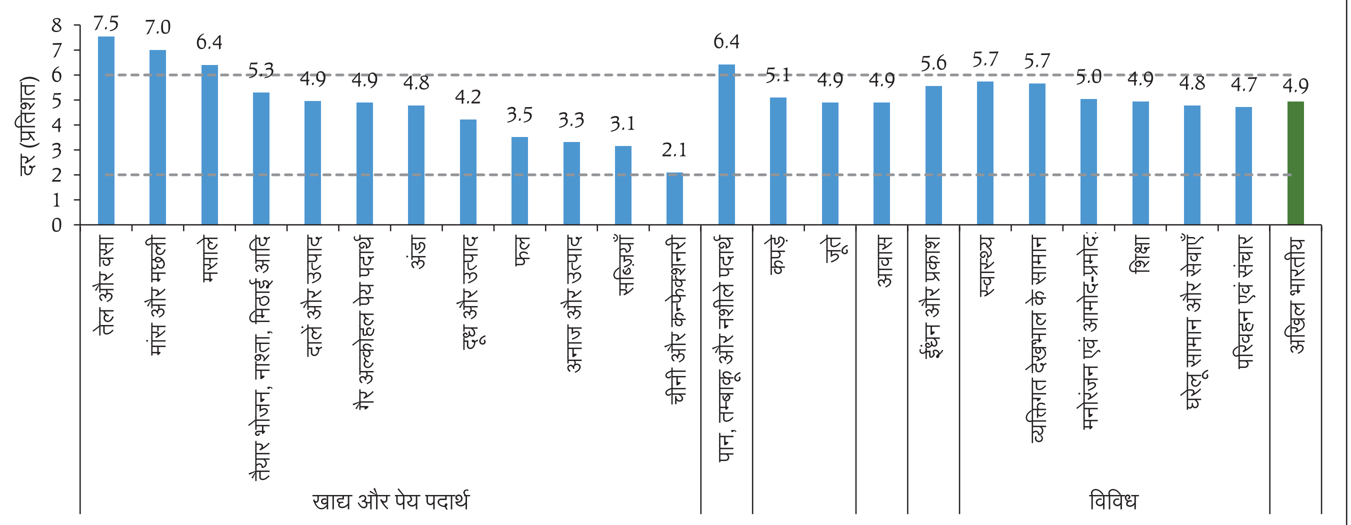

नोट : सीजीआर की गणना आठ वर्षों में बढ़ोतरी के रूप में की जाती है (कैलेंडर वर्ष 2014 में औसत सूचकांक की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2022 में औसत सूचकांक को शामिल करते हुए)।
स्रोत : लेखक की गणना

अवधि में सबसे कम मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 4.06 प्रतिशत दर्ज की गई है (चार्ट 1 और चार्ट 2)।

सीपीआई-सी के घटकों में लंबी अवधि अर्थात 2014 से 2022 तक की औसत मुद्रास्फीति कुछ उत्पाद उप-समूहों, विशेष रूप से 'खाद्य और पेय' जैसे 'मांस और मछली', 'तेल और वसा' और 'मसालों' में 6 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ उच्च पक्ष में बड़े अंतर को दर्शाती है। इसके विपरीत, 'चीनी और कन्फेक्शनरी' की सीएजीआर सबसे कम रही, 2 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर (चार्ट 3)।

उप-उत्पादों के सीएजीआर में भिन्नता इन उत्पादों की सापेक्ष मांग और आपूर्ति को प्रतिबिंबित करती है और उनके अंतर-वर्षीय और अंतर-वर्षीय भिन्नताएं अर्थव्यवस्था में कई सामान्य और विशिष्ट झटकों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में मुद्रास्फीति के सीएजीआर इस अवधि के दौरान अधिक तालमेल में रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों का भारांश (हिस्सा) शीर्ष कुछ राज्यों में केंद्रित है, उदाहरण के लिए, शीर्ष छह राज्य, सामूहिक रूप से सीपीआई-सी बास्केट में 50 प्रतिशत से अधिक वजन को कवर करते हैं (चार्ट 4)।

एमओएसपीआई बड़े 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति के अलग-अलग आंकड़ों के उच्च स्तर प्रकाशित करता है। इनमें क्षेत्र (ग्रामीण और शहरी), उत्पाद समूहों (जैसे 6 समूह - 'खाद्य और पेय पदार्थ', 'पान और तंबाकू', 'कपड़े और जूते', 'आवास', 'ईंधन और प्रकाश' और 'विविध') और उत्पाद उप-समूहों (कुल 23 उप-समूह) द्वारा ग्रैन्यूलिटी को शामिल किया गया है। छोटे 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास, जिनका व्यक्तिगत भारांक 025 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, उनके पास उत्पाद उप-समूह स्तरों पर जानकारी नहीं है। दानेदार स्तर के वजन सीएसओ (2015) से लिए गए हैं। 22 बड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कुल सीपीआई-सी का प्रॉक्सी माना जा सकता है, क्योंकि वे भारत के कुल सीपीआई-सी का 98.30 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह देखा गया है कि समग्र मुद्रास्फीति के संकलन में कार्यप्रणाली/एकत्रीकरण मुद्दों (दास और जॉर्ज, 2023) के कारण प्रकाशित सकल मुद्रास्फीति प्रिंट के साथ कुछ अंतर हो सकता है।

इस खंड और बाद के खंडों में शेष विश्लेषण 22 बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डेटासेट पर आधारित है। इसके अलावा, विश्लेषण में एक सारणी (अनुबंध सारणी ए 1) को छोड़कर सारणी

चार्ट 4: सीपीआई-सी समूह में राज्य / केन्द्रशासित का सापेक्ष भार

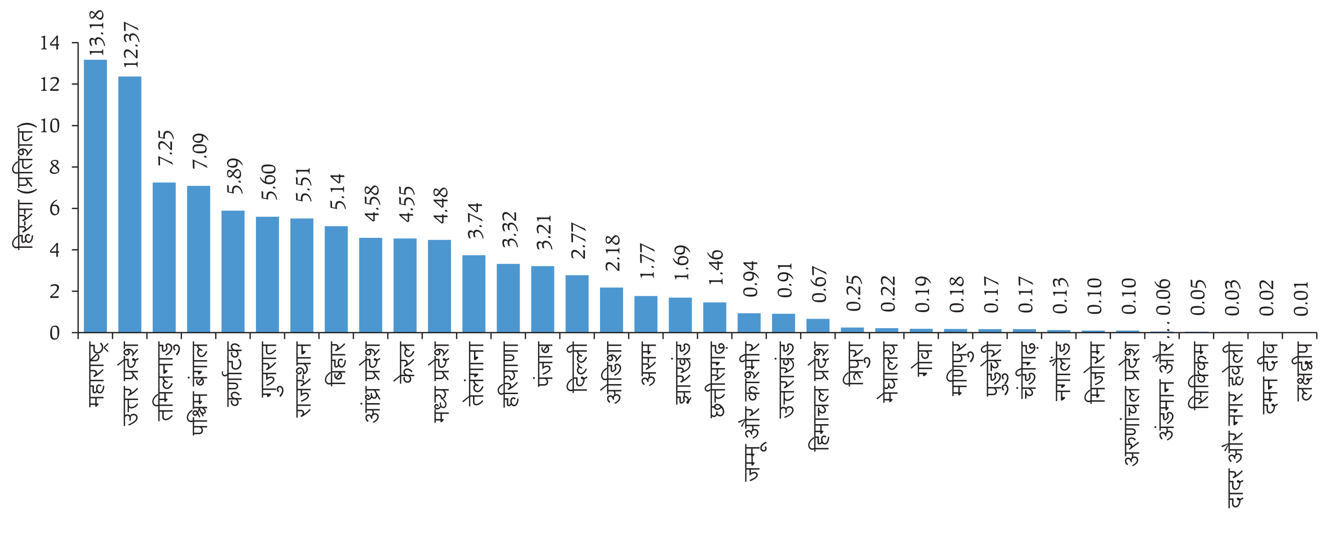

स्रोत: एमओएसपीआई; और लेखक की गणना।

ओं और चार्टों में प्रदर्शित गणनाओं में उपयुक्त संभाव्यता-भारित वितरण शामिल है, जो संक्रमणों की अभारित गणना का एक सरल प्रदर्शन है।

चूंकि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सबसे बारीक स्तर[4] पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर वार्षिक मुद्रास्फीति के मासिक संक्रमण को ट्रैक करना है, इसलिए बड़े राज्यों के बारीक स्तर के मुद्रास्फीति आंकड़ों पर विचार किया जाता है। आंकड़ों के इस अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर, 2017 के मध्य तक उच्च मुद्रास्फीति (6 प्रतिशत से अधिक) वाले उत्पादों की हिस्सेदारी 5 में क्रमिक गिरावट, जो जून 2017 में 13.75 प्रतिशत के गर्त को छू गई, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को नीचे लाने और इसे आसानी से वांछित गलियारे में रोकने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता प्रतीत होती है। दिलचस्प बात यह है कि 2 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के बीच मुद्रास्फीति वाले उत्पादों का हिस्सा इस अवधि के दौरान लगभग 58 प्रतिशत (मई 2017 में 58.87 प्रतिशत और जून 2017 में 57.18 प्रतिशत) पर पहुंच गया।

मुद्रास्फीति आम तौर पर महीनों में उच्च मुद्रास्फीति वाले उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ बढ़ी है। हालांकि, संबंध रैखिक प्रतीत नहीं होता है और बल्कि एक लॉग-रैखिक संबंध एक बेहतर संबंध प्रदर्शित करता है (चार्ट 6)।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च और निम्न मुद्रास्फीति बैंड में उत्पादों की सापेक्ष हिस्सेदारी कुछ हद तक एक-दूसरे की भरपाई करने की उम्मीद है, इसके अलावा 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के मध्यम बैंड में उत्पादों की मुद्रास्फीति प्रोफाइल के साथ उनके संयुक्त प्रभाव के अलावा। महत्वपूर्ण मूल्य वास्तव में सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि इन स्तरों में सशर्त वितरण है।

सशर्त माध्य, यानी, औसत मूल्य यह दिया गया है कि यह एक विशेष बैंड में है, दोनों पूंछों के लिए बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि ये असहज हैं। एक उदाहरण के रूप में, दिसंबर 2019 में दर्ज 7.35 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बैंड (6 प्रतिशत से ऊपर मुद्रास्फीति) के बहुत अधिक सशर्त औसत से प्रेरित थी, यानी, सही पूंछ। यह 21.98 प्रतिशत है, जो 2014 से 2022 के महीनों के दौरान अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हैरानी की बात

[4] एमओएसपीआई सभी 299 वस्तुओं के लिए आइटम-स्तरीय मुद्रास्फीति भी प्रकाशित करता है, जैसा कि सीपीआई-सी के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, यह क्षेत्र अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। तदनुसार, बड़े राज्यों की समग्र ग्रैन्यूलैरिटी 990 (=2*22*23-22) डेटा बिंदुओं को कवर करते हुए बहुत अधिक है। उप-समूह आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है और तदनुसार, यह न तो राज्यों के लिए और न ही समग्र सीपीआई-सी के लिए उपलब्ध है और तदनुसार उपलब्ध नहीं है।

[5] सीपीआई-सी को संकलित करने के तरीके का प्रतिनिधित्व करने के लिए शेयर में संबंधित उत्पाद उप-समूहों के उचित भार शामिल हैं, न कि केवल सरल औसत।

चार्ट 5: सीपीआई -सी के विखंडित डेटा का वितरण (2014-2022)

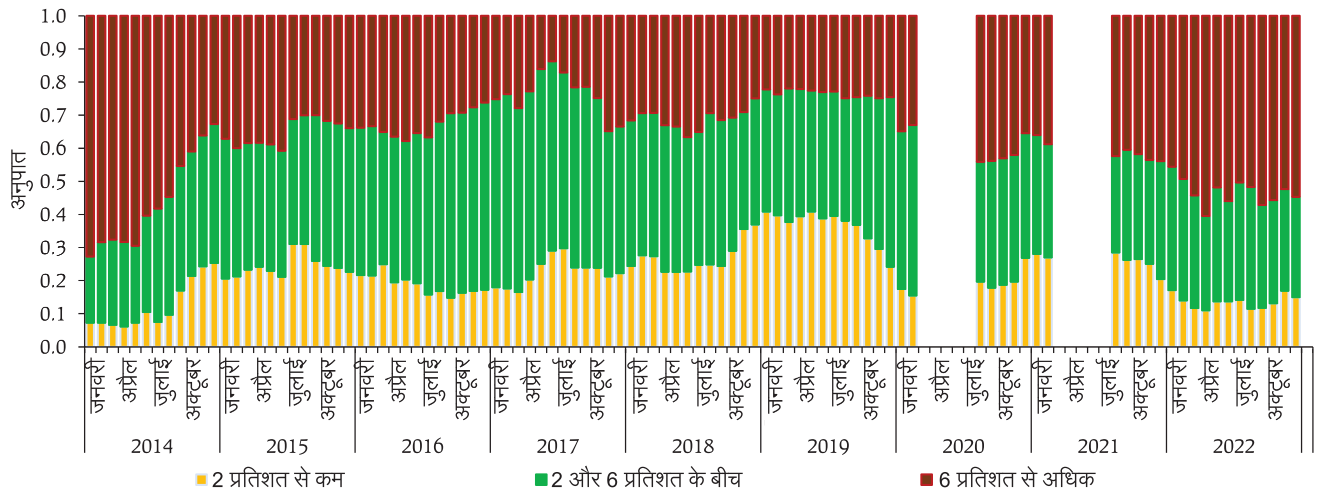

नोट : कोविड की प्रथम और दूसरी लहर के कारण मार्च 2020 से जुलाई 2020 मार्च 2021 से जुलाई 2021 तक डेटा की ग्रैन्यूलैरिटी (या तो सूचकांक या दर या दोनों) उपलब्ध हैं। तदनुसार इन अपूर्ण डेटा बिन्दुओं को बाद में आने वाले सभी चार्ट / सारणियों जहां कहीं भी लागू हो से हटा दिया गया।
स्रोत : लेखक की गणना।

यह है कि दिसंबर 2019 में बाएं पूंछ (24.18 प्रतिशत) और दाईं पूंछ (24.55 प्रतिशत) की हिस्सेदारी के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक झटके एक-दूसरे की भरपाई करने में सक्षम थे, लेकिन उनके सशर्त साधनों का प्रसार 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अलग था। यह अन्यथा अन्य महीनों के औसत प्रोफ़ाइल 7 (चार्ट 7) से भी काफी अलग था।

चार्ट 6: सीपीआई-सी मुद्रास्फीति और टेल - स्कैटर खंड

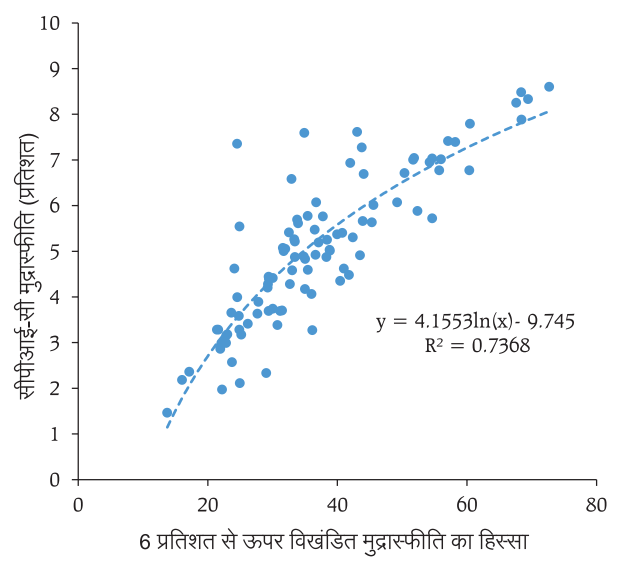

स्रोत : लेखक की गणना।

चार्ट 7: सीपीआई-सी मुद्रास्फीति – मीन एंड टेल्स

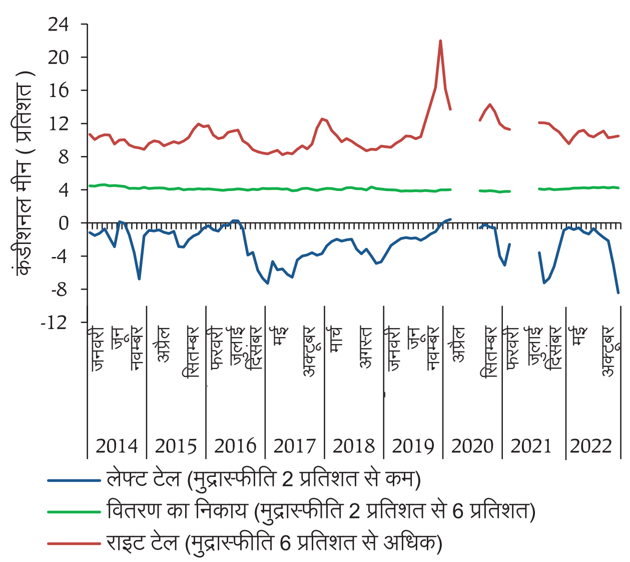

स्रोत : लेखक की गणना।

[6] दिसंबर 2019 में 4 प्रतिशत से दायें सिरे के सशर्त औसत का प्रसार (दूरी) 17.98 प्रतिशत था, जबकि बाएँ सिरे के लिए यह केवल -4.24 प्रतिशत था, जिसका सशर्त औसत -0.24 प्रतिशत था।

[7] अध्ययन अवधि के तहत देखे गए 98 महीनों के साधारण औसत के आधार पर, बाएँ सिरे और दायें सिरे के सशर्त साधनों की गणना क्रमशः -2.50 प्रतिशत और 10.61 प्रतिशत के रूप में की जाती है, जबकि वितरण के शरीर के लिए यह 4.10 प्रतिशत है।

चार्ट 8: सीपीआई - सी मुद्रास्फीति – एक्सट्रीम टेल्स का माध्य

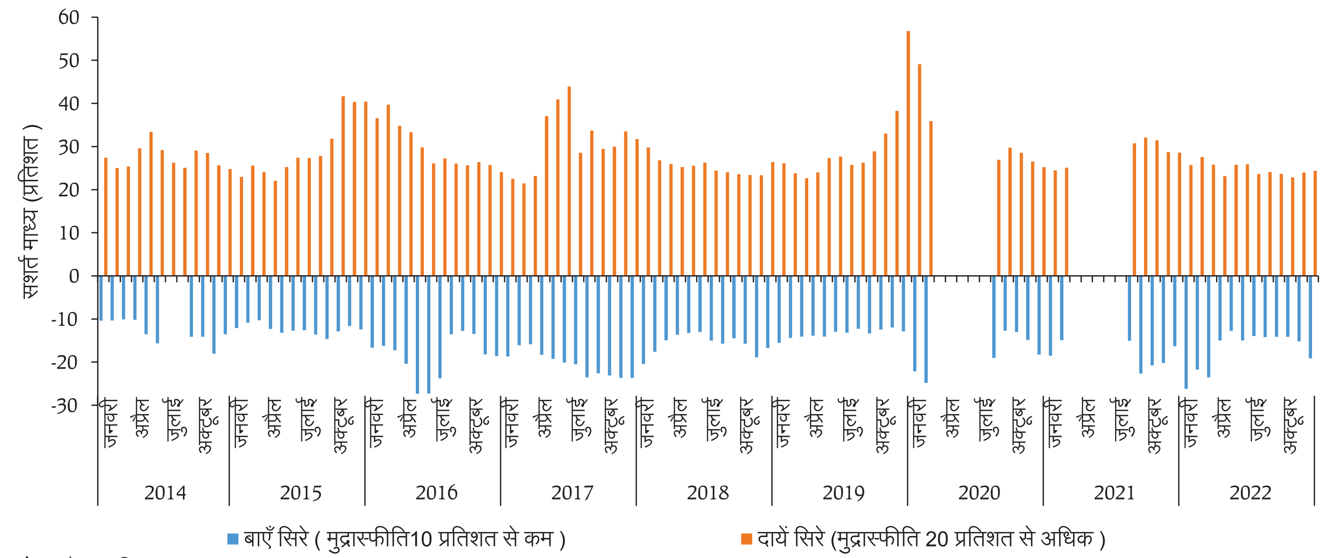

स्रोत : लेखक की गणना।

मुद्रास्फीति के अलग-अलग आंकड़ों में पूंछ के उच्च महत्व के कारण, उनके चरम मूल्यों की भी जांच की गई थी। ये चरम पूंछ मुद्रास्फीति प्रिंट की भेद्यता को प्रदर्शित करती है जब सकारात्मक और नकारात्मक झटके सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के अंतिम एकल प्रिंट को आकार देने में उनके विघटित असममित योगदान के संदर्भ में एक-दूसरे की भरपाई करने में विफल रहते हैं (चार्ट 8)।

III. पद्धति

एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया एक परिवार या आदेशित यादृच्छिक चर का सेट है। यह एक समय-निर्भर यादृच्छिक घटना के लिए एक मॉडल है। यह यादृच्छिक चर $X(t)$ का एक संग्रह है, जो कुछ सेट जे में हर बार टी के लिए एक है। इसे $\{X(t)\}$ के रूप में निरूपित किया जाता है. मानों का वह सेट जो यादृच्छिक चर $X(t)$ लेने में सक्षम है, उसे प्रक्रिया का राज्य स्थान कहा जाता है। एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया को स्थिर या कड़ाई से स्थिर कहा जाता है, यदि $X(t_1), X(t_2), X(t_3), \ldots\ldots, X(t_n)$ और $X(t_1), X(t_2), X(t_3), \ldots\ldots, X(t_n)$ and $X(k+t_1), X(k+t_2), X(k+t_3), \ldots\ldots, X(k+t_n)$ के संयुक्त वितरण सभी $t_1, t_2, t_3, \ldots\ldots, t_n$ और $k+t_1, k+t_2, k+t_3, \ldots\ldots, k+t_n$ J में और सभी पूर्णांक n के लिए। यह कहना है कि प्रक्रिया के सांख्यिकीय गुण समय बीतने के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। सांख्यिकीय गुण संभावनाओं, अपेक्षित मूल्यों, विचरण आदि से संबंधित हैं। इनमें से किसी भी स्थिति को पकड़ने में विफलता का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि प्रक्रिया स्थिर नहीं है।

एक सतत स्टोकेस्टिक प्रक्रिया $\{X(t), t \geq 0\}$ को प्रथम-क्रम मार्कोव प्रक्रिया कहा जाता है, यदि समय बिंदुओं के एक सेट के लिए $t_0 < t_1 < t_2 \ldots < t_n$, यादृच्छिक चर $X(t_n)$ के सशर्त वितरण को केवल $X(t_{n-1})$ के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। यही है, समय से पहले प्रक्रिया का इतिहास t_{n-1} को समय t_n पर चर द्वारा लिए गए मूल्य के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। औपचारिक रूप से, स्टोकेस्टिक प्रक्रिया $\{X(t)\}$ एक मार्कोव है, यदि सभी समय के लिए $t_0 < t_1 < t_2 \ldots < t_n$ नहीं,

$$\text{Prob.}\,[\,X(t_n) \le x_n \mid X(t_k) \le x_k\,;\, k = 0, 1, 2, 3, \ldots, n-1]$$

$$= P\,[\,X(t_n) \le x_n \mid X(t_{n-1}) \le x_{n-1}]$$

जहां, Prob. प्रायिकता है, $x_0, x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_n$ वास्तविक संख्याओं के एक समूह से संबंधित है।

असतत अवस्था स्थान के साथ यादृच्छिक चर $X(t)$, $t = 0, 1, 2, 3, \ldots$, के अनुक्रम द्वारा वर्णित एक असतत-समय प्रथम-क्रम मार्कोव प्रक्रिया को प्रथम-क्रम मार्कोव श्रृंखला या बस मार्कोव श्रृंखला के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हम संक्रमण संभाव्यता मैट्रिक्स पी के साथ मार्कोव श्रृंखला के स्थिर संभाव्यता वितरण को परिभाषित करते हैं यदि एस में सभी जे के लिए निम्नलिखित स्थितियां हैं:

1. $\pi_j = \sum \pi_i \, p_{ij}$

2. $\pi_j \geq 0$

3. $_{j\in S}\sum \pi_j = 1$

इन तीन स्थितियों को एक साथ मैट्रिक्स समीकरण में दर्शाया जा सकता है, $\pi P = \pi$।

जहां, π एक पंक्ति वेक्टर है, इस प्रकार, $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \ldots.. \pi_n)$

इसका अर्थ यह है कि यदि हम π को हमारे प्रारंभिक संभाव्यता वितरण के रूप में लेते हैं, अर्थात्,

$P [X_0 = i] = \pi_i$

फिर, समय 1 पर वितरण फिर से π द्वारा दिया जाता है:

$P [X_1 = j] = {}_{i\in S}\sum P [X_1 = j / X_0 = i] P[X_0 = i]$

$= {}_{i\in S}\sum p_{ij} \, \pi_i = \pi_j$

यह सभी समय के लिए मान्य है। π का संभाव्यता वितरण अपरिवर्तनीय है। यदि श्रृंखला कभी भी किसी समय वितरण π तक पहुंच जाती है, तो कहें, एन, अर्थात, $P [X_n = i] = \pi_i$ के सभी मानों के लिए X_t का वितरण बाद के सभी समय के लिए π होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संक्रमण मैट्रिक्स अपरिवर्तित रहेगा। इसके साथ, प्रक्रिया के सांख्यिकीय गुण समय के साथ नहीं बदलेंगे और मार्कोव श्रृंखला में एक स्थिर प्रक्रिया होगी।

मार्कोव श्रृंखला में स्थिर संभाव्यता वितरण हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा, यदि इसमें एक स्थिर संभाव्यता वितरण है, तो यह आवश्यक रूप से अद्वितीय नहीं हो सकता है। हालांकि, यदि किसी श्रृंखला में एक परिमित स्थान है, तो इसमें कम से कम एक स्थिर वितरण का अस्तित्व होना चाहिए। व्यवहार में, संक्रमण की संभावनाएं (p_{ij}, सभी i और j के लिए एक चरण में ih अवस्था से jth अवस्था में संक्रमण की संभावना) उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, अनुभवजन्य आंकड़ों से इनका अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि$x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_N$ अनुभवजन्य डेटा से उपलब्ध अवलोकन हैं। छोड़ देना

n_{ij} = t की संख्या $(1 \leq t \leq N\text{-}1)$ इस प्रकार है कि $x_t = i$ और $x_{t+1} = j$

$n_{i.}$ = t की संख्या $(1 \leq t \leq N\text{-}1)$ इस प्रकार है कि $x_t = i$

वास्तव में , nij वह संख्या है जिसे i स्थिति से j स्थिति से परिवर्तित होते हुए देखा गया है और ni स्थिति वह है जहां I स्थिति से उत्पन्न होने वाले संक्रमणों की कुल संख्या को देखा अगया है।

इसके साथ, संक्रमण संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है:

Est. $p_{ij} = n_{ij} / n_{i.} = n_{ij} / \sum n_{ij}$ (summation over j)

उपर्युक्त पद्धति के विस्तार के रूप में, हम सीपीआई-सी बास्केट में अलग-अलग भार वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और क्षेत्रों (ग्रामीण/शहरी) में किसी विशेष उत्पाद उप-समूह के संक्रमण को अलग करने के लिए एक भारित गणना अवधारणा विकसित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बारीक डेटा के माध्यम से संक्रमण कुल मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार, अब हम इसे परिभाषित करते हैं:

मान लीजिए कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (कुल 22) में एक चरणीय श्रेणी - ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के जीवें उत्पाद-समूह (कुल 23) के लिए एक चरणीय अवधि (एक मुद्रास्फीति बैंड) से सातवें राज्य (मुद्रास्फीति बैंड) तक की चालों की भारित संख्या (भारित) है।

पीआईजे को संबंधित (भारित) संभावना होने दें, जिसे बराबर करके अनुमान लगाया जा सकता है:

$p_{ij} = w_{g,s,a} * n_{ij} / {}_j\sum (w_{g,s,a} * n_{ij})$, जहां भाजक ih स्थिति (एक मुद्रास्फीति बैंड) में शब्दों (पंक्ति सीमांत योग) का योग है।

इसके अलावा, किसी भी स्थिति के लिए j:3,pij = 1।

मान लीजिए कि $P = \{p_{ij}\}$ ऐसी संभावनाओं का मैट्रिक्स है और π $1 \times i$ का पंक्ति वेक्टर होने दें । यह P को एक स्थिर समाधान में परिवर्तित कर देगा, जिसे P = P के समीकरण को हल करके प्राप्त π जा सकता है।

वर्तमान लेख परिचयात्मक खंड में चर्चा किए गए अवलोकन (अनुभवजन्य) डेटा का उपयोग करके सीपीआई-सी के संक्रमण के लिए एक सरल स्टोकेस्टिक प्रक्रिया बनाने का प्रयास करता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक स्थिर स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के माध्यम से बारीक स्तर पर मुद्रास्फीति के संक्रमण का विश्लेषण किया जाता है। अध्ययन

अभ्यास करने के लिए मार्कोव चेन (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है) का उपयोग करता है। मार्कोव श्रृंखलाएं असतत राज्य स्थान और असतत समय ग्रहण करती हैं। सीपीआई-सी मुद्रास्फीति डेटा की आवृत्ति के अनुरूप असतत-समय रिक्त स्थान को "महीने" माना जाता है। असतत राज्य रिक्त स्थान को विभिन्न मुद्रास्फीति बैंड के रूप में माना जाता है।

जैसा कि दूसरे खंड में चर्चा की गई है, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारीक डेटासेट का उपयोग प्रत्येक संक्रमण की जांच करने के लिए किया जाता है। एक संक्रमण के लिए लगातार दो महीनों के लिए जोड़ी-वार मुद्रास्फीति डेटा की आवश्यकता होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी विशेष महीने के डेटा का उपयोग दो बार किया जाता है, एक गंतव्य (पिछले महीने से वर्तमान महीने) और दूसरा उत्पत्ति (वर्तमान महीने से अगले महीने) के लिए। हालांकि, प्रत्येक वर्ष 2020 और 2021 के मार्च से जुलाई तक पूर्ण डेटा की अनुपलब्धता के कारण समय श्रृंखला में संरचनात्मक ब्रेक के कारण, लगातार महीनों के कुछ जोड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए अध्ययन से हटा दिए गए हैं। इस तरह, कुछ महीनों का उपयोग केवल एक बार किया जाता है (जैसे कि फरवरी 2020 का उपयोग केवल एक गंतव्य के रूप में संक्रमण के लिए किया जाता है), जबकि कुछ अन्य (जैसे मार्च 2020) को छोड़ दिया जाता है।

अब हम अपने राज्यों (जैसे सीपीआई-सी मुद्रास्फीति बैंड) को पांच व्यापक श्रेणियों में परिभाषित करते हैं, अत्यधिक निम्न (ईएल), निम्न (एल), मध्यम (एम), उच्च (एच) और अत्यधिक उच्च (ईएच) निम्न, मध्यम और उच्च बैंड के लिए 10 बैंड के उप-स्तर के साथ। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के लिए 32 बैंड होते हैं (सारणी 1)।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपर्युक्त वर्गीकरण में रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति के लिए सहिष्णुता बैंड 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत है, अर्थात बैंड एम03, एम04, एम05 और एम06। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह सीपीआई-सी अखिल भारतीय (समग्र) मुद्रास्फीति के लिए है न कि इसके घटकों/विवरणों के लिए। फिर भी, दानेदार डेटा के लिए ये बैंड नीति विश्लेषण के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

बैंड के वर्गीकरण के आधार पर, हम उन्हें सौंपे गए उचित भार के साथ दानेदार स्तर पर वार्षिक मुद्रास्फीति के मासिक संक्रमण को ट्रैक करते हैं। एक बार दानेदार-स्तर के डेटा की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक बैंड से दूसरे बैंड में संक्रमण संकलित होने के बाद, आकार 32-बाय-32 के संक्रमण संभाव्यता मैट्रिक्स (टीपीएम) का निर्माण किया जाता है। ऐसा ही प्री-कोविड, पोस्ट-कोविड और संयुक्त अवधि के लिए लगातार[8] महीनों की वैध जोड़ी

सारणी 1: सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए बैंड

मुद्रास्फीति (जे) (व्यापक स्तर)	बैंड कोड (उप-स्तर)	राज्य संख्या
अत्यधिक निम्न (ईएल)	ईएल (जे < -10)	1
निम्न (एल)	एल01 (-10 ≤ जे < -9)	2
	एल02 (-9 ≤ जे < -8)	3
	एल03 (-8 ≤ जे < -7)	4
	एल04 (-7 ≤ जे < -6)	5
	एल05 (-6 ≤ जे < -5)	6
	एल06 (-5 ≤ जे < -4)	7
	एल07 (-4 ≤ जे < -3)	8
	एल08 (-3 ≤ जे < -2)	9
	एल09 (-2 ≤ जे < -1)	10
	एल10 (-1 ≤ जे < 0)	11
मध्य (एम)	एम01 (0 ≤ जे < 1)	12
	एम02 (1 ≤ जे < 2)	13
	एम03 (2 ≤ जे < 3)	14
	एम04 (3 ≤ जे < 4)	15
	एम05 (4 ≤ जे < 5)	16
	एम06 (5 ≤ जे < 6)	17
	एम07 (6 ≤ जे < 7)	18
	एम08 (7 ≤ जे < 8)	19
	एम09 (8 ≤ जे < 9)	20
	एम10 (9 ≤ जे < 10)	21
उच्च (एच)	एच01 (10 ≤ जे < 11)	22
	एच02 (11 ≤ जे < 12)	23
	एच03 (12 ≤ जे < 13)	24
	एच04 (13 ≤ जे < 14)	25
	एच05 (14 ≤ जे < 15)	26
	एच06 (15 ≤ जे < 16)	27
	एच07 (16 ≤ जे < 17)	28
	एच08 (17 ≤ जे < 18)	29
	एच09 (18 ≤ जे < 19)	30
	एच10 (19 ≤ जे < 20)	31
अत्यधिक उच्च (ईएच)	ईएच (जे ≥ 20)	32

[8] जनवरी 2014 से दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों में लगातार दो महीनों के 95 वैध जोड़े हैं, जिनके लिए बारीक डेटा उपलब्ध है। इसमें कोविड-पूर्व अवधि के लिए 73 जोड़े और पोस्ट-कोविड अवधि के लिए 22 जोड़े शामिल हैं।

के लिए किया जाता है। सीपीआई-सी एग्रीगेट डेटा (सारणी 2) के अनुरूप, इस बारीक स्तर के देखे गए डेटा की सांख्यिकीय विशेषताएं पूर्व-कोविड और पोस्ट-कोविड अवधि में स्पष्ट अंतर प्रदर्शित करती हैं।

देखे गए आंकड़े कोविड महामारी के उभरने और उसके बाद यूक्रेन युद्ध के बाद मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र में बदलाव को उजागर करते हैं। 2014 के बाद से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के संभाव्यता घनत्व समारोह का विकास अनुबंध में प्रदान किया गया है, जो दर्शाता है कि प्रत्येक 6-मासिक नए (वृद्धिशील) डेटा के आने के बाद घनत्व को फिर से आकार दिया जाता है - दोनों कोविड-पूर्व और पोस्ट-कोविड अवधि के दौरान। मुद्रास्फीति को कम करने के साथ-साथ 2014 और 2015 के दौरान इनक्रेमेंटल डेटासेट के

सारणी 2: प्रेक्षित डेटा की संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन (पीडीएफ)।

बैंड	कोविड-पूर्व		कोविड के बाद		संयुक्त	
	मध्य-बिंदु	पीडीएफ	मध्य-बिंदु	पीडीएफ	मध्य-बिंदु	पीडीएफ
ईएल (जे < -10)	-16.787	0.02483	-18.451	0.02483	-17.198	0.02483
एल01 (-10 ≤ जे < -9)	-9.518	0.00382	-9.504	0.00250	-9.515	0.00349
एल02 (-9 ≤ जे < -8)	-8.541	0.00379	-8.450	0.00146	-8.531	0.00322
एल03 (-8 ≤ जे < -7)	-7.453	0.00376	-7.491	0.00272	-7.461	0.00350
एल04 (-7 ≤ जे < -6)	-6.480	0.00463	-6.510	0.00278	-6.485	0.00417
एल05 (-6 ≤ जे < -5)	-5.465	0.00568	-5.494	0.00401	-5.470	0.00527
एल06 (-5 ≤ जे < -4)	-4.471	0.00701	-4.506	0.00622	-4.479	0.00681
एल07 (-4 ≤ जे < -3)	-3.492	0.00941	-3.418	0.00517	-3.481	0.00836
एल08 (-3 ≤ जे < -2)	-2.489	0.01397	-2.501	0.01143	-2.492	0.01334
एल09 (-2 ≤ जे < -1)	-1.496	0.02006	-1.515	0.01620	-1.500	0.01911
एल10 (-1 ≤ जे < 0)	-0.507	0.02832	-0.494	0.02004	-0.505	0.02628
एम01 (0 ≤ जे < 1)	0.500	0.04658	0.544	0.04165	0.510	0.04537
एम02 (1 ≤ जे < 2)	1.536	0.06263	1.520	0.04727	1.533	0.05883
एम03 (2 ≤ जे < 3)	2.524	0.08532	2.531	0.07453	2.526	0.08265
एम04 (3 ≤ जे < 4)	3.510	0.11637	3.510	0.08650	3.510	0.10899
एम05 (4 ≤ जे < 5)	4.499	0.11660	4.488	0.09480	4.497	0.11122
एम06 (5 ≤ जे < 6)	5.491	0.10950	5.498	0.08463	5.492	0.10335
एम07 (6 ≤ जे < 7)	6.474	0.08870	6.492	0.08567	6.478	0.08795
एम08 (7 ≤ जे < 8)	7.473	0.06270	7.476	0.07198	7.474	0.06499
एम09 (8 ≤ जे < 9)	8.467	0.04859	8.467	0.05997	8.467	0.05140
एम10 (9 ≤ जे < 10)	9.475	0.03373	9.474	0.04677	9.475	0.03695
एच01 (10 ≤ जे < 11)	10.473	0.02480	10.471	0.03839	10.472	0.02816
एच02 (11 ≤ जे < 12)	11.478	0.01608	11.473	0.02800	11.476	0.01903
एच03 (12 ≤ जे < 13)	12.461	0.01049	12.479	0.02443	12.469	0.01394
एच04 (13 ≤ जे < 14)	13.489	0.00813	13.461	0.01844	13.477	0.01067
एच05 (14 ≤ जे < 15)	14.485	0.00586	14.518	0.01588	14.501	0.00834
एच06 (15 ≤ जे < 16)	15.486	0.00492	15.468	0.01238	15.478	0.00676
एच07 (16 ≤ जे < 17)	16.481	0.00442	16.438	0.00935	16.463	0.00564
एच08 (17 ≤ जे < 18)	17.401	0.00379	17.476	0.00871	17.434	0.00501
एच09 (18 ≤ जे < 19)	18.465	0.00260	18.416	0.01041	18.437	0.00453
एच10 (19 ≤ जे < 20)	19.451	0.00254	19.467	0.00723	19.459	0.00370
ईएच (जे ≥ 20)	32.003	0.02035	26.962	0.03564	30.164	0.02413
माध्य (प्रतिशत)		**4.66**		**6.16**		**5.03**

नोट: अलग-अलग और समग्र मुद्रास्फीति डेटा की संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन अलग-अलग होगी, हालांकि इन दो डेटासेट से प्राप्त केंद्रीय प्रवृत्ति समान या तुलनीय होगी। हालाँकि, डेटा के अन्य सांख्यिकीय क्षण (जैसे मानक विचलन, तिरछापन और कर्टोसिस) काफी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दानेदार डेटा का मानक विचलन समग्र डेटा की तुलना में अधिक होगा।

स्रोत: लेखक की गणना.

घनत्व समारोह की तिरछीता लगातार कम हो गई। वितरण बाद में (2016 और 2017 की पहली छमाही के दौरान) अधिक चरम (लेप्टोकुर्टिक) हो गया, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास अधिक केंद्रित मूल्य थे और प्रत्येक छोर पर आम तौर पर कम चरम मूल्य थे। 2018 की दूसरी छमाही में अत्यधिक कम मूल्यों की आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई, जिसने समग्र मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की। कोविड के उद्भव से पहले 2020 की पहली छमाही में उच्च चरम मूल्यों की आवृत्ति में वृद्धि हुई। कोविड के बाद की अवधि में, मुद्रास्फीति वितरण में समग्र दक्षिणपंथी बदलाव लगातार विभिन्न तीव्रता के साथ देखा गया है, साथ ही चरम छोर पर घनत्व में उल्लेखनीय परिवर्तन (अनुबंध चार्ट ए 1)।

दीर्घकालिक स्थिर वितरण (एलआरएसडी) प्राप्त करने के लिए, डेटासेट में बड़ी संख्या में टिप्पणियों की उपलब्धता के कारण एक बड़े आकार के मैट्रिक्स का कार्यान्वयन संभव था क्योंकि हमने ग्रैन्यूलैरिटी के उच्चतम क्रम को चुना, जिससे मैट्रिक्स में 1,024 (= 32 * 32) कोशिकाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारे पास अवलोकनों के प्रत्येक वैध जोड़े के लिए 990 अवलोकन हैं, जिससे 94,042 अवलोकन 9 हो गए हैं। संयुक्त अवधि के लिए इन प्रेक्षणों (सरल/भारित गणना) के लिए संक्रमण मैट्रिक्स प्रदान किया गया है (अनुलग्नक सारणी ए1)) ताकि आसान प्रदर्शन के लिए तैयार संदर्भ मिल सके।

यह देखना दिलचस्प (और तार्किक) है कि एक महीने में एक चरम बैंड (जैसे, ईएल) से दूसरे चरम बैंड (जैसे, ईएच) तक की संभावना बहुत कम है। इसके विपरीत भी सच है।

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, ऐसे मामलों के अवलोकन की संख्या बहुत कम है। तदनुसार, एक महीने की छोटी अवधि में, मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) में या तो वृद्धि या भारी गिरावट की संभावना नहीं है।

संक्रमण को बेहतर ढंग से देखने के लिए, हम 32-बाय-32 मैट्रिक्स को बहुत छोटे मैट्रिक्स (3-बाय-3) में ध्वस्त कर देते हैं। यह देखा गया है कि निम्न और मध्यम मुद्रास्फीति के मामले में कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में कोविड के बाद की अवधि में मुद्रास्फीति की निरंतरता में कमी आई है, जबकि यह उच्च स्तर पर बढ़ी है। इसके अलावा, कोविड के बाद के चरण में संक्रमण में चरम बदलाव यानी बैंड ए से बैंड सी और बैंड सी से बैंड ए में भी वृद्धि हुई है (सारणी 3)।

आंकड़ों में मुद्रास्फीति बैंड के उपरोक्त स्थिरता स्तरों का उपयोग करते हुए, उच्च मुद्रास्फीति बैंड (बैंड सी) का दीर्घकालिक (स्थिर अवस्था) औसत प्रत्यावर्तन समय कोविड-पूर्व अवधि (3.20 महीने) से पोस्ट-कोविड अवधि (2.05 महीने) तक काफी कम हो गया है, जिसकी भरपाई अन्य दो बैंड ों के लिए उसी में वृद्धि से की जाती है। पोस्ट-कोविड के लिए औसत प्रत्यावर्तन समय इंगित करता है कि यदि कोई संक्रमण बैंड सी (या तो बैंड ए या बैंड बी) से बाहर निकलता है, तो यह इस बैंड (यानी बैंड सी) में तेजी से (लगभग दो महीने में) फिर से आने की उम्मीद है, जो कि पूर्व-कोविड युग के लिए 3.20 महीने था (सारणी 4)।

संक्रमण मैट्रिक्स [पी] के आधार पर, हम पी = π समीकरणों के सेट को हल करके एक स्थिर वितरण (स्थिर राज्य संतुलन) प्राप्त कर सकते हैं, जो इन संक्रमणों के बाद दीर्घकालिक स्थिर वितरण

सारणी 3: मुद्रास्फीति की निरंतरता (संक्रमण संभावना मैट्रिक्स)

कोविड-पूर्व				कोविड के बाद			
बैंड	ए	बी	सी	बैंड	ए	बी	सी
ए	0.8456	0.1365	0.0179	ए	0.8058	0.1723	0.0220
बी	0.0760	0.8322	0.0918	बी	0.0719	0.7938	0.1343
सी	0.0143	0.1298	0.8559	सी	0.0190	0.0822	0.8988

स्रोत: लेखक की गणना.

ए: मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से नीचे बी: मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच सी: मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर

9 ग्रेन्यूलर डेटासेट में टिप्पणियों के आठ जोड़े गायब थे, और तदनुसार, अध्ययन से हटा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 94,050 के बजाय 94,042 अवलोकन थे।

सारणी 4: औसत प्रत्यावर्तन समय (महीनों में)

बैंड	कोविड-पूर्व	कोविड के बाद
ए	4.0607	5.7720
बी	2.2642	2.9483
सी	3.2043	2.0510

स्रोत: लेखक की गणना.
ए: मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से नीचे
बी: मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच
सी: मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर

(एलआरएसडी) π, जहां π एक 1 * 32 पंक्ति वेक्टर है और पी एक 32 * 32 मैट्रिक्स है। इन तीन डेटासेट के लिए पंक्ति वेक्टर π का पारगमन एलआरएसडी (सारणी 5) का प्रतिनिधित्व करता है।

सारणी 5: एलआरएसडी का पूर्वानुमानित संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन (पीडीएफ)।

बैंड	प्री कोविड	पोस्ट कोविड	एकीकृत
ईएल (जे < -10)	0.02456	0.03079	0.02595
एल01 (-10 ≤ जे < -9)	0.00388	0.00297	0.00369
एल02 (-9 ≤ जे < -8)	0.00384	0.00153	0.00337
एल03 (-8 ≤ जे < -7)	0.00378	0.00309	0.00357
एल04 (-7 ≤ जे < -6)	0.00473	0.00276	0.00425
एल05 (-6 ≤ जे < -5)	0.00583	0.00385	0.00538
एल06 (-5 ≤ जे < -4)	0.00717	0.00629	0.00694
एल07 (-4 ≤ जे < -3)	0.00968	0.00458	0.00848
एल08 (-3 ≤ जे < -2)	0.01480	0.01086	0.01373
एल09 (-2 ≤ जे < -1)	0.02141	0.01340	0.01938
एल10 (-1 ≤ जे < 0)	0.03081	0.01723	0.02723
एम01 (0 ≤ जे < 1)	0.05126	0.03703	0.04769
एम02 (1 ≤ जे < 2)	0.06911	0.04334	0.06261
एम03 (2 ≤ जे < 3)	0.09392	0.07076	0.08870
एम04 (3 ≤ जे < 4)	0.12582	0.08444	0.11649
एम05 (4 ≤ जे < 5)	0.12225	0.09583	0.11694
एम06 (5 ≤ जे < 6)	0.10993	0.08949	0.10631
एम07 (6 ≤ जे < 7)	0.08454	0.09243	0.08725
एम08 (7 ≤ जे < 8)	0.05633	0.07810	0.06158
एम09 (8 ≤ जे < 9)	0.04218	0.06471	0.04740
एम10 (9 ≤ जे < 10)	0.02783	0.04917	0.03273
एच01 (10 ≤ जे < 11)	0.01962	0.03995	0.02416
एच02 (11 ≤ जे < 12)	0.01275	0.02832	0.01610
एच03 (12 ≤ जे < 13)	0.00846	0.02502	0.01195
एच04 (13 ≤ जे < 14)	0.00662	0.01757	0.00898
एच05 (14 ≤ जे < 15)	0.00485	0.01477	0.00700
एच06 (15 ≤ जे < 16)	0.00381	0.01191	0.00559
एच07 (16 ≤ जे < 17)	0.00370	0.00830	0.00472
एच08 (17 ≤ जे < 18)	0.00314	0.00788	0.00417
एच09 (18 ≤ जे < 19)	0.00230	0.00944	0.00390
एच10 (19 ≤ जे < 20)	0.00222	0.00625	0.00314
Eएच (जे ≥ 20)	0.01888	0.02793	0.02059
अनुमानित माध्य (प्रतिशत)	**4.31**	**5.92**	**4.67**

स्रोत: लेखक की गणना.

सारणी 2 और सारणी 5 से, हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का दीर्घकालिक स्थिर-राज्य स्तर संभवतः देखे गए स्तरों से कम होगा, जैसा कि डेटासेट में लगातार देखा जाता है। यह संकेत देता है कि स्थिर स्थिति आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्य मुद्रास्फीति के करीब है, अवलोकन किए गए आंकड़ों की तुलना में।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्री-कोविड डेटासेट श्रृंखला में लंबा होने के कारण अधिक मजबूत होने की उम्मीद है और कोविड और युद्ध जैसी गंभीर घटनाओं के एक-एक एपिसोड को कवर नहीं करता है। फिर भी, हम मुद्रास्फीति दर में 20-40 आधार अंकों की गिरावट देखते हैं यदि वर्तमान और पिछले बदलाव जारी रहते हैं और अन्य अंतर्निहित धारणाएं और स्थितियां बनी रहती हैं।

देखे गए से एलआरएसडी तक संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन में बदलाव (परिवर्तन) की प्रकृति भी जांच के योग्य है। उदाहरण के लिए, प्री-कोविड डेटासेट के मामले में, हालांकि, बदलाव परिमाण में छोटा है, जैसे कि पूर्ण (संयुक्त) डेटासेट (चार्ट 9) में, केंद्रीय मूल्य (चार्ट 10) की ओर बढ़ने वाले संक्रमण का संकेत है।

एलआरएसडी की पूर्वानुमानित संभाव्यता घनत्व इंगित करता है कि प्रेक्षणों की आवृत्ति प्रेक्षित दानेदार आंकड़ों से केंद्रीय प्रवृत्ति (मुद्रास्फीति 0 प्रतिशत से 6 प्रतिशत) के आसपास थोड़ी

चार्ट 9: अवलोकन किया गया और एलआरएसडी का पीडीएफ

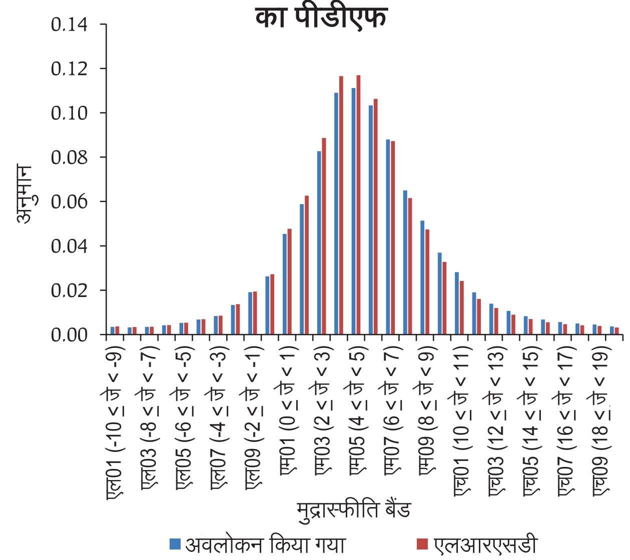

स्रोत : लेखक की गणना।

चार्ट 10: पीडीएफ में शिफ्ट (परिवर्तन)

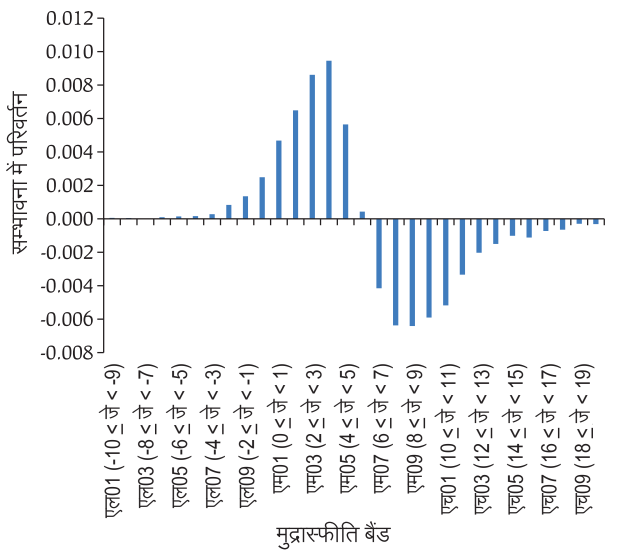

स्रोत : लेखक की गणना।

अधिक हो सकती है, जिसकी भरपाई उच्च मुद्रास्फीति बैंड में कम टिप्पणियों से की जा सकती है।

IV. निष्कर्ष

कोविड महामारी और उसके बाद यूक्रेन युद्ध के उभरने के बाद से भारत में मुद्रास्फीति बढ़ी और यह एक प्रमुख नीतिगत चिंता बन गई। महामारी के प्रभाव में कमी आने और आपूर्ति श्रृंखला ओं में नरमी आने के साथ, हालांकि, सूक्ष्म-स्तर के आंकड़ों पर स्टोकेस्टिक संक्रमण का उपयोग करके मुद्रास्फीति के लिए दीर्घकालिक स्थिर राज्य स्तर मुद्रास्फीति की अपने केंद्रीय मूल्य की ओर धीरे-धीरे चलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि महामारी से पहले के डेटासेट के आधार पर मुद्रास्फीति दीर्घकालिक स्थिर राज्य संतुलन स्तर लगभग 4.3 प्रतिशत हो सकता है। महामारी की अवधि के दौरान स्थिर राज्य मुद्रास्फीति में देखी गई मामूली वृद्धि क्षणिक होने की संभावना है और स्थिर राज्य मुद्रास्फीति आगे चलकर निचले पथ पर वापस आ सकती है। उभरती परिरिस्थितियों के साथ व्यावसायिक स्थितियों के सुधार और सामान्यीकरण की सटीक गति यह तय कर सकती है कि मुद्रास्फीति कितनी और कितनी जल्दी कम प्रक्षेपवक्र पर जाती है।

संदर्भ

Ascari, G. and Sbordone, A. M. (2014), "The Macroeconomics of Trend Inflation", *Journal of Economic Literature*, Vol. 52(3), 679–739.

Behera, H. K. and Patra, M. D. (2020), "Measuring Trend Inflation in India", *Reserve Bank of India Working Paper Series*, WPS (DEPR): 15/2020.

Central Statistics Office (2015), "Consumer Price Index: Changes in the Revised Series (Base Year 2012 = 100)", National Accounts Division, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Das, P. and George, A. T. (2023), "Consumer Price Index: The Aggregation Method Matters", *Monthly Bulletin*, Reserve Bank of India, March.

RBI (2017), "Distribution of Inflation in India", Box II.3, *Annual Report 2016-17*, Reserve Bank of India, August.

Sinha, R. K. (2018), "Tracking the Stochastic Transition of Inflation in India", 12th Statistics Day Conference, Reserve Bank of India, 23rd July (Press release – "RBI discusses Measurement and Management of Macro-Economic and Financial Sector Risks at its Twelfth Statistics Day Conference (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2024E74E1ABAEC3426FA7A028611DD7F0EB.PDF).

अनुबंध

अनुलग्नक सारणी ए 1: संक्रमण संभाव्यता मैट्रिक्स (गणना-वार) - संयुक्त अवधि

चालू माह से / अगले महीने तक	ईएल	एल01	एल02	एल03	एल04	एल05	एल06	एल07	एल08	एल09	एल10	एम01	एम02	एम03	एम04	एम05	एम06	एम07	एम08	एम09	एम10	एच01	एच02	एच03	एच04	एच05	एच06	एच07	एच08	एच09	एच10	एह	कुल
बैंड																																	
ईएल	1785	121	87	64	49	33	34	20	27	14	10	10	12	10	5	6	7	8	3	1		4		3	2	2			1			2	**2320**
एल01	120	54	43	33	30	20	17	12	7	4	2	4	2	2	1	3		2	2		1										1	1	**361**
एल02	88	50	60	38	33	33	17	15	10	5	7	3	4	2	7	3	2	3															**380**
एल03	66	28	36	67	66	49	30	23	10	9	9	4	4	6	2	6	3		1			1			1			1	1				**423**
एल04	53	27	38	45	76	77	60	37	32	11	18	6	8	7	7	7	3	1	2		1	2				1		1	1				**521**
एल05	40	14	30	43	63	105	108	61	54	32	16	21	11	8	8	3	8	3	2	3	2			1	2							1	**639**
एल06	32	14	15	33	47	97	144	136	99	55	34	22	18	21	8	12	5	4		4	1	2	1	1						1		3	**809**
एल07	23	10	14	18	36	61	108	205	193	115	75	49	24	22	19	12	8	2	5	2	3		2	1	1	1		1	1				**1011**
एल08	20	5	10	15	33	45	91	176	363	303	180	115	63	48	14	16	14	9	7	2	4	1	2	1	1		1				2	2	**1543**
एल09	16	2	6	8	18	27	53	108	286	508	416	184	114	55	46	24	16	14	8	6	4	4	5	5	2	1	2	1	2				**1941**
एल10	14	8	7	7	12	15	36	65	166	372	724	651	270	107	64	39	27	19	12	9	2	3	1	3	4	1	1				2	1	**2642**
एम01	14	6	5	6	10	15	28	40	100	218	633	1609	960	397	164	93	48	24	11	12	12	2	7	3	2	1	2	1	1		2		**4426**
एम02	9	3	6	8	6	13	21	34	65	125	249	972	2564	1318	483	171	101	47	18	16	13	6	5	5	2	2	2	1		2		4	**6271**
एम03	8	4	2	1	7	6	9	13	38	47	119	365	1346	3292	1560	478	222	95	60	27	24	9	10	4	2	2	1	4	1	1	2	2	**7761**
एम04	5	2	5	4	8	4	8	11	16	37	59	183	476	1592	3801	1758	522	223	92	43	28	28	15	12	2	4	8	3	1	1		9	**8960**
एम05	5	1	2	6	5	8	2	12	13	27	28	89	201	547	1804	3791	1738	528	203	85	40	30	12	15	5	6	6	5	2		2	7	**9225**
एम06	9	1	3	2	1	2	7	8	7	19	19	55	99	215	551	1821	3379	1570	521	169	82	61	17	18	11	8	7	8	1	3	2	9	**8685**
एम07	6	2	3	2	1	2	8	10	8	9	10	36	54	81	207	541	1629	2741	1284	448	155	62	41	22	10	10	7	7	6	4	3	11	**7420**
एम08	7	1		3	1	2	2	4	5	7	14	23	26	43	97	219	557	1346	2097	1029	342	141	52	34	26	21	10	4	3	3	2	8	**6129**
एम09	3	1	1		2	3	3	2	4	13	10	17	10	35	56	114	209	429	1044	1531	711	297	100	45	51	19	10	7	4	8	5	12	**4756**
एम10	3	2		1	2	1	4	2	1		6	10	11	8	29	42	70	154	393	792	1066	555	231	95	49	25	15	9	7	3	3	12	**3601**
एच01	6		1	2	1	3	5	3	8	2	3	6	14	10	12	31	45	73	159	276	604	752	411	187	83	42	23	11	10	11	3	13	**2810**
एच02	6	2	1		2	2		1	4	5	6	2	9	10	17	15	30	38	91	122	217	433	500	288	123	72	24	24	14	8	6	26	**2098**
एच03	2			1		2		2	3	4	1	2	3	4	10	12	20	26	36	51	99	182	291	321	203	101	68	26	26	9	5	29	**1539**
एच04				3		1	1	1	1	2	1	2	6	3	6	8	11	20	21	30	50	81	137	221	240	167	83	47	29	21	15	24	**1232**
एच05	1		1				2	4	1	3	1	3	4	6	5	8	8	7	12	15	31	34	70	100	174	185	136	82	32	26	18	39	**1008**
एच06							2	1	1		4		1		4	2	4	2	11	11	17	21	42	49	85	117	143	106	47	39	23	43	**775**
एच07				2			1	1	1	1	1	1	4	2	2	3	2	3	9	6	11	13	29	36	53	77	70	88	84	46	29	64	**639**
एच08	1				1		1	1	1				5	3		4	4	4	7	9	12	10	16	9	29	38	59	60	81	65	40	75	**535**
एच09	2		1		1			2	2		1	1	2		3	3	1	5	3	8	10	11	16	13	16	20	28	37	52	58	43	107	**446**
एच10			1		2							2	1	1	3	4	5	2	3	5	10	5	12	6	11	22	16	29	46	45	49	119	**399**
एह	1	1					2	2	1	3	3	2	4	4	2	5	13	15	8	10	13	26	24	34	36	41	34	65	70	90	135	2093	**2737**
कुल	**2345**	**359**	**378**	**412**	**513**	**626**	**804**	**1012**	**1527**	**1950**	**2659**	**4449**	**6330**	**7859**	**8997**	**9254**	**8711**	**7417**	**6125**	**4722**	**3565**	**2776**	**2049**	**1532**	**1226**	**986**	**756**	**628**	**523**	**444**	**392**	**2716**	**94042**

चार्ट ए1: प्रत्येक अर्ध-वार्षिक वृद्धिशील डेटा के आगमन के साथ संभाव्यता घनत्व कार्य का विकास और स्थिरीकरण (2014-2022)
कोविड-पूर्व

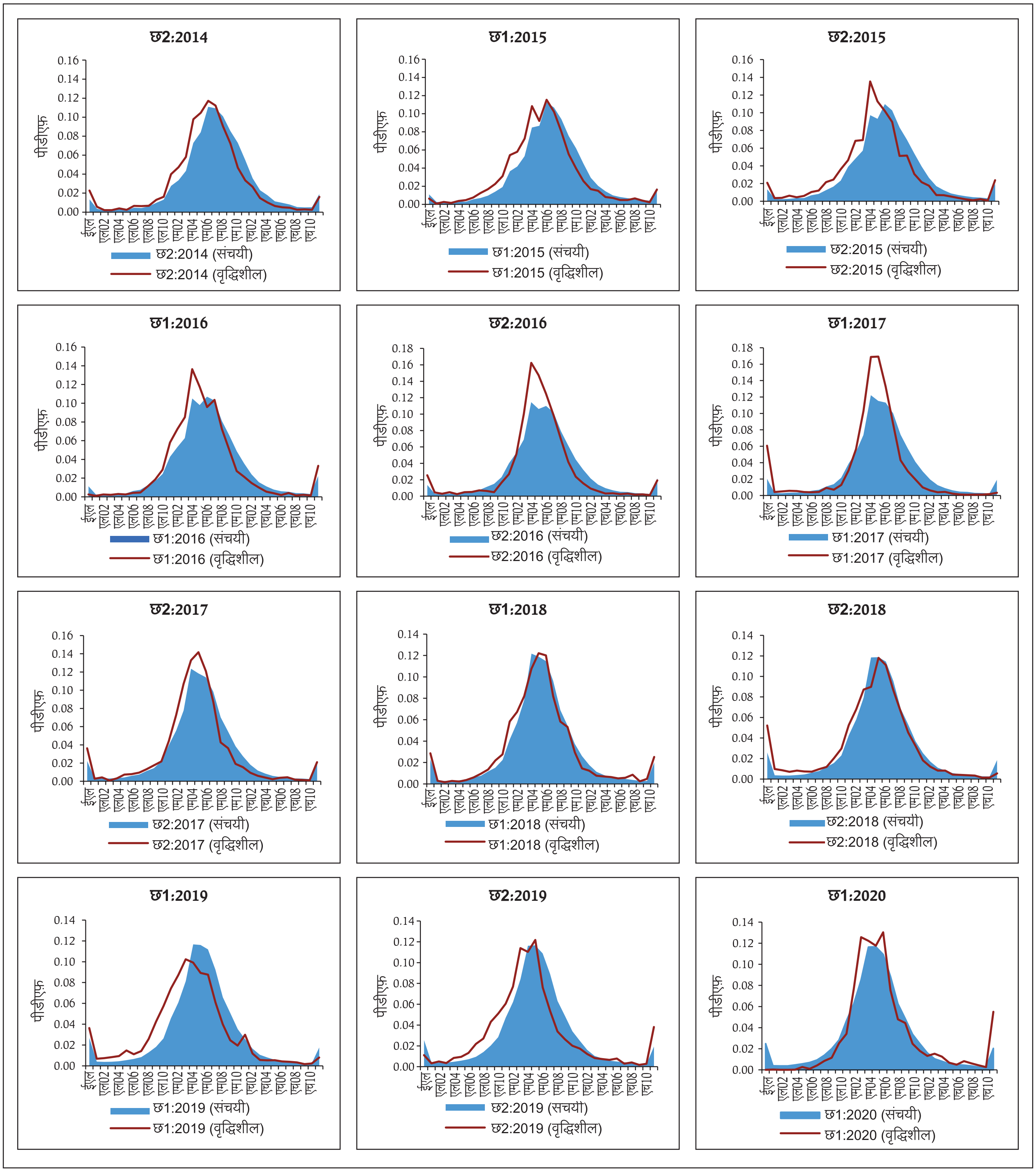

कोविड के बाद

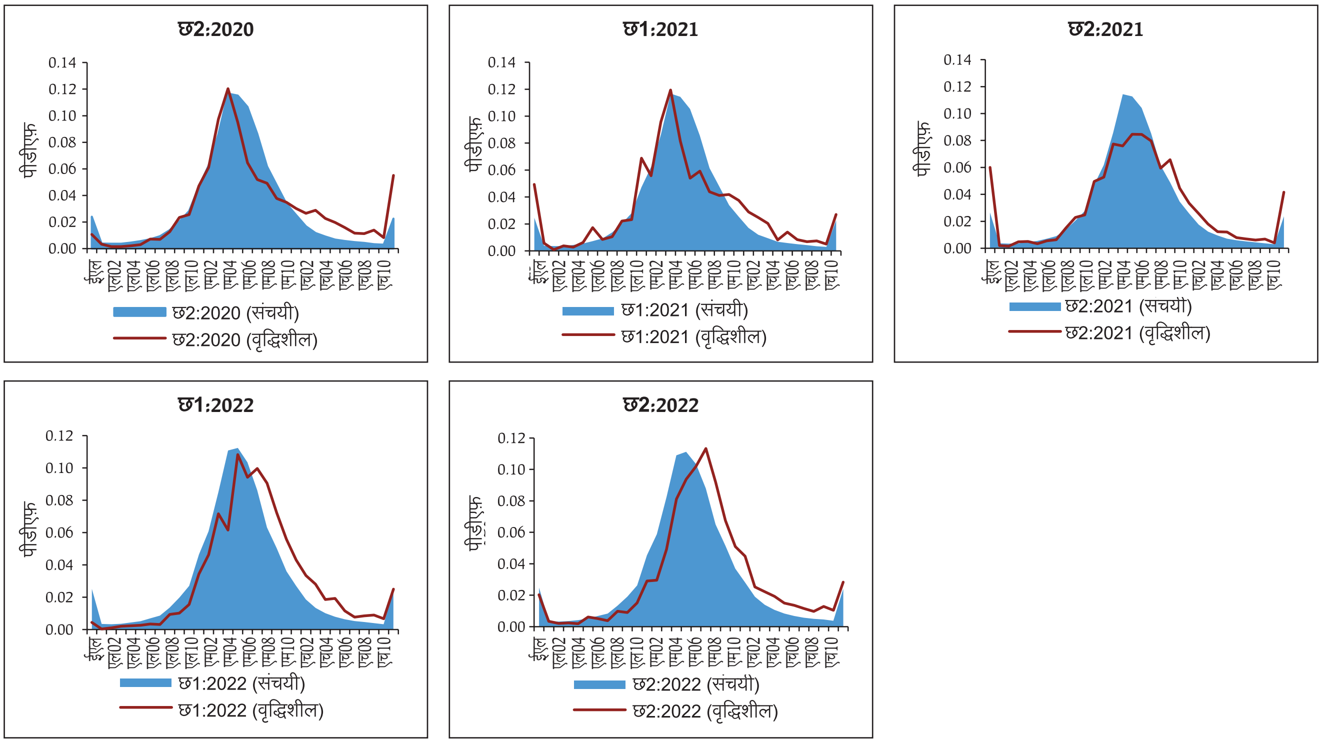

नोट : छ1:2020 और छ1:2021 सम्बंधित वर्ष के केवल जनवरी और फ़रवरी को शामिल करता है। छ2:2020 और छ2:2021 सम्बंधित वर्ष के जुलाई को शामिल नहीं करता है।

स्रोत : लेखक की गणना .

भारत और सीओपी-26 प्रतिबद्धताएं: खनन क्षेत्र के लिए चुनौतियां

वी. धन्या, गौतम और अर्जित शिवहरे ^ द्वारा

स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर टिकी हुई है, हालांकि, मध्यम अवधि में, कोयले की प्रमुख भूमिका बनी रहने की संभावना है। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में, देश ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा पारगमन ने खनन क्षेत्र में गतिकी को बदल दिया है और कोयले से क्रमिक बदलाव हो कर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की ओर धीरे-धीरे झुकाव बढ़ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में हालिया वैश्विक आपूर्ति शृंखला की बाधाएं एक लागत-प्रभावी धारणीय और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

भूमिका

खनन क्षेत्र, किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है, जिसके लाभ सभी देशों में अलग-अलग होते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया और बोत्सवाना जैसे कुछ संसाधन-संपन्न देशों को अपने समृद्ध संसाधनों से लाभ हुआ, कई देश ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण 'संसाधन अभिशाप' शब्द का निर्माण हुआ। इसके लिए कई कारण बताए गए, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वास्तविक विनिमय दर का अधिमूल्यन है जिसे 'डच डिसीज सिंड्रोम' के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) (सीओपी26[1]) के बाद धारणीय संसाधनों और वृद्धि में नई रुचि ने प्राकृतिक संसाधनों को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। चूंकि प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, दोनों का आधार बनते हैं, इसलिए धारणीयता संबंधी विचारों के मामले में खनिज संसाधनों का महत्व बढ़ने की संभावना है। इसके विपरीत, कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक तनाव के बाद आपूर्ति में व्यवधान के कारण विवैश्वीकरण हुआ और दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई। इसके साथ-साथ, इसने कई आवश्यक खनिजों पर सीमित संख्या में देशों के एकाधिकार के बारे में भी चिंता पैदा कर दी है। इस संदर्भ में, विशेष रूप से धारणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए दुनिया की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, निविष्टि के रूप में प्राकृतिक संसाधन किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्व रखते हैं। भारत का शुद्ध शून्य (नेट जीरो) उत्सर्जन में पारगमन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर निर्भर है, हालांकि देश की विकासात्मक जरूरतों को देखते हुए मध्यम अवधि में कोयला एक प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का धारणीय विकास, नवीकरणीय संसाधनों के उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस अध्ययन में, हम सीओपी26 के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पृष्ठभूमि में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के मार्ग और व्यापक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खनन क्षेत्र पर इसके प्रभाव की जांच करते हैं।

आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है: खंड II सीओपी26 की प्रमुख विशेषताओं और भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) की स्थिति की जांच करता है। यह सीओपी26 के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं की भी व्याख्या करता है। खंड III शुद्ध शून्य उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत की रणनीति की पड़ताल करता है। यह खंड उत्सर्जन कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण भी करेगा। खंड IV ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताओं के समग्र ढांचे में खनन क्षेत्र की भूमिका की जांच करता है। और खंड V का समापन प्रमुख प्रेक्षणों के साथ होता है।

II. सीओपी26: प्रतिबद्धताएं और स्थिति

सीओपी26 शिखर सम्मेलन में विश्व जीडीपी में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले लगभग 140 देश नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में एक साथ आए, जिनमें से भारत

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक, अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियों के लिए श्री राजीब दास और रिग्जेन यांगडोल के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] "पक्षों का सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीस)" या 'सीओपी', संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 2021 की बैठक सीओपी का 26वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, जिससे इसे सीओपी26 नाम दिया गया है।

भी एक था। सम्मेलन ने उन कार्यों के माध्यम से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए 'नए मूलभूत अंग' प्रस्तुत किए जो विश्व को अधिक धारणीय, निम्न कार्बन मार्ग पर ले जा सकते हैं[2]। यह कोयले के उपयोग को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध पहला जलवायु समझौता था। संधि ने "वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और तापमान वृद्धि को औद्योगिक-पूर्व स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर पेरिस समझौते की पुष्टि की" और "माना कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से, गहन और निरंतर कटौती की आवश्यकता है, जिसमें वर्ष 2010 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना और शताब्दी के मध्य के आसपास नेट जीरो तक कम करना शामिल है, साथ ही अन्य ग्रीनहाउस गैसों में गहरी कटौती भी शामिल है।"[3] कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) की ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में लगभग तीन-चौथाई हिस्सेदारी है और इसलिए शिखर सम्मेलन द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्राथमिकता दी गई थी। (आईपीसीसी, 2015) के अनुसार, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन और औद्योगिक प्रक्रियाओं से सीओ2 उत्सर्जन ने वर्ष 1970 से 2010 तक कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन वृद्धि में लगभग 78 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि वर्ष 2000-2010 की अवधि के लिए समान प्रतिशत योगदान है।

शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता जताई। सीओपी26 के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार, देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की आकांक्षा रखता है। सीओपी26 में भारत की प्रमुख घोषणाओं में निम्न शामिल हैं[4]:

- भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने की दिशा में प्रगति करेगा
- भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा
- भारत 2030 तक अपने पूर्वानुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा
- भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम कर देगा।
- भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा

विभिन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में, ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2018 में दुनिया में कुल ग्रीनहाउस उत्सर्जन में अकेले ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 74.5 प्रतिशत था, जिसमें बिजली और ऊष्मा का हिस्सा 31.9 प्रतिशत था[5]। इसलिए, उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धता का ऊर्जा क्षेत्र पर सीधा असर पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा और 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा के अतिरिक्त कोयले के लिए ईंधन की आवश्यकता को 20 प्रतिशत और गैस को 32 प्रतिशत तक कम करने और अंततः सीओ2 उत्सर्जन को 280 मिलियन टन तक कम करने का अनुमान है (भारत सरकार, 2017)। इस प्रकार नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए यह पूर्वापेक्षा, स्वच्छ ऊर्जा पारगमन की ओर एक कदम है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की स्थिति

परंपरागत रूप से, विकसित देश ग्रीनहाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक रहे हैं, औद्योगीकरण ने आर्थिक समृद्धि के साथ ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाई है। चीन और भारत जैसे विकासशील देश भी सीओ2 के प्रमुख उत्सर्जक के रूप में उभरे हैं (कारस्टेंसन और अन्य., 2020)। 2021 तक, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बाद भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो सालाना 2.7 बिलियन टन सीओ2 उत्सर्जित करता है। दूसरी ओर, प्रति व्यक्ति के संदर्भ में वर्ष 2021 में भारत का जीएचजी उत्सर्जन 1.9 टन सीओ2 प्रति व्यक्ति है, जो 2021 में 4.7 टन सीओ2 प्रति व्यक्ति के वैश्विक औसत से काफी कम है (चार्ट 1)।

प्रति व्यक्ति सीओ2 उत्सर्जन के समान, भारत की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, जिसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रति डॉलर

[2] https://www.un.org/en/climatechange/cop26

[3] ग्लासगो जलवायु संधि

[4] पत्र सूचना कार्यालय(pib.gov.in)

[5] world-greenhouse-gas-emissions-sankey-chart-2021-02(1)_0.png (1575×1047) (wri.org)

चार्ट 1: सीओ2 उत्सर्जन

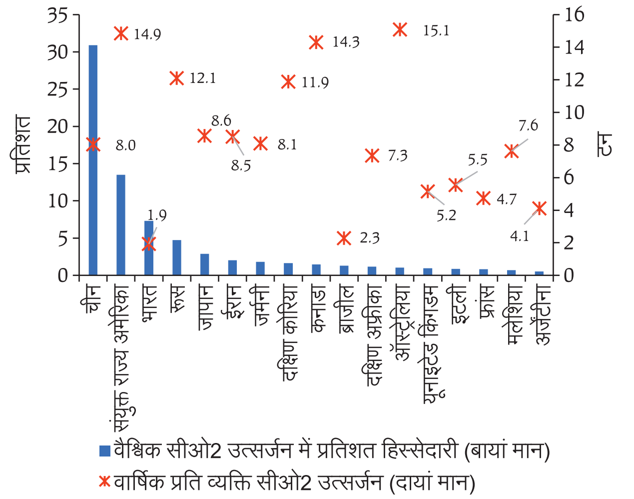

टिप्पणी: जीवाश्म ईंधन और उद्योग से सीओ$_2$ उत्सर्जन। भूमि उपयोग परिवर्तन शामिल नहीं है।

स्रोत: वैश्विक कार्बन परियोजना 2022।

उत्सर्जित सीओ2 के किलोग्राम के रूप में मापा जाता है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम में से एक है (चार्ट 2)। विकसित देशों ने, हालांकि ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार किया है, उनका उच्च वृद्धि चरण उच्च ऊर्जा तीव्रता के साथ मेल खाता है। औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में लाभ, ऊर्जा तीव्रता में गिरावट का मुख्य कारण है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र की भारी मशीनरी ऊर्जा गहन हैं। इसके अलावा, जीडीपी के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रहे सेवा क्षेत्र ने भी उत्सर्जन तीव्रता में गिरावट में योगदान दिया है। हालांकि भारत की उत्सर्जन तीव्रता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन यह अधिकांश देशों की तुलना में कम है और हाल के वर्षों में तीव्रता में भी गिरावट आ रही है (चार्ट 2)।

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र, जीएचजी का प्रमुख उत्सर्जक है। वैश्विक ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल से पूरा होता है जिसमें से कोयले की बड़ी हिस्सेदारी होती है। इसके साथ ही, उत्सर्जन के मामले में भी कोयला प्रमुख स्रोत रहा है, जो वैश्विक सीओ2 उत्सर्जन का 40 प्रतिशत हिस्सा है। वैश्विक औसत की तुलना में, कोयले पर भारत की निर्भरता और कोयले से उत्सर्जन अधिक है (चार्ट 3ए और 3बी)। भारत के कुल सीओ2 उत्सर्जन में कोयले का उत्सर्जन 65 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत से 25 प्रतिशत अधिक है।

अधिकांश देशों में पिछले कुछ वर्षों में कोयले के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है। चीन और भारत की प्राथमिक ऊर्जा समूह में कोयले की हिस्सेदारी अधिक है, चीन ने समय के साथ अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। इसकी तुलना में भारत में कुल ऊर्जा

चार्ट 2: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता

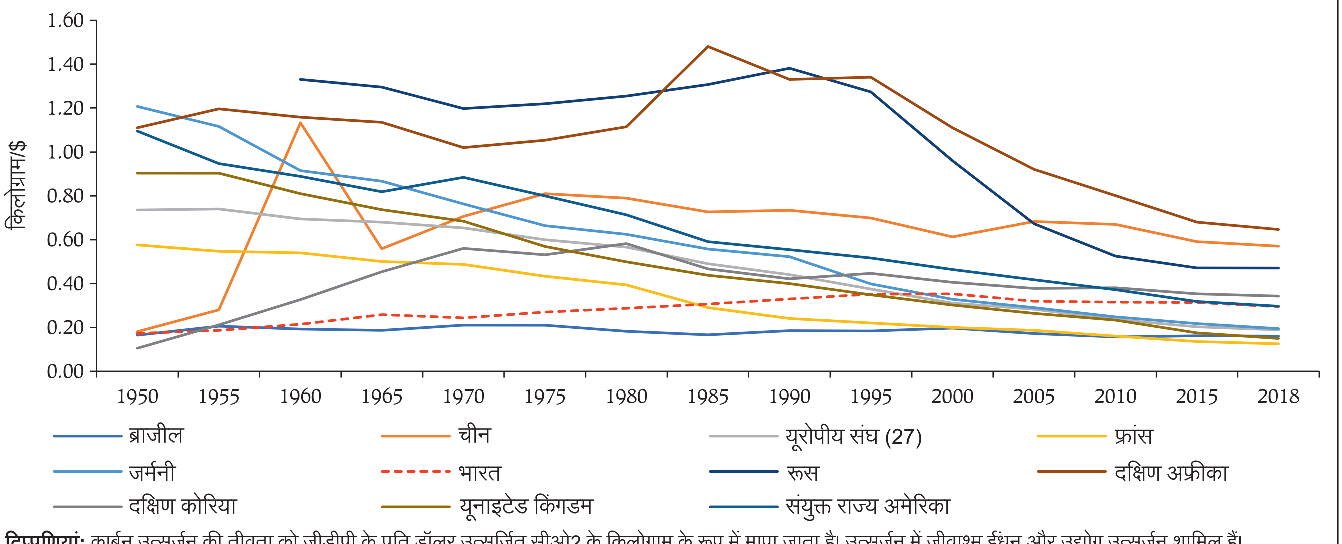

टिप्पणियां: कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को जीडीपी के प्रति डॉलर उत्सर्जित सीओ2 के किलोग्राम के रूप में मापा जाता है। उत्सर्जन में जीवाश्म ईंधन और उद्योग उत्सर्जन शामिल हैं।

स्रोत: वैश्विक कार्बन परियोजना 2021; और अवर वर्ल्ड इन डेटा।

चार्ट 3ए: क्षेत्रवार सीओ2 उत्सर्जन - विश्व

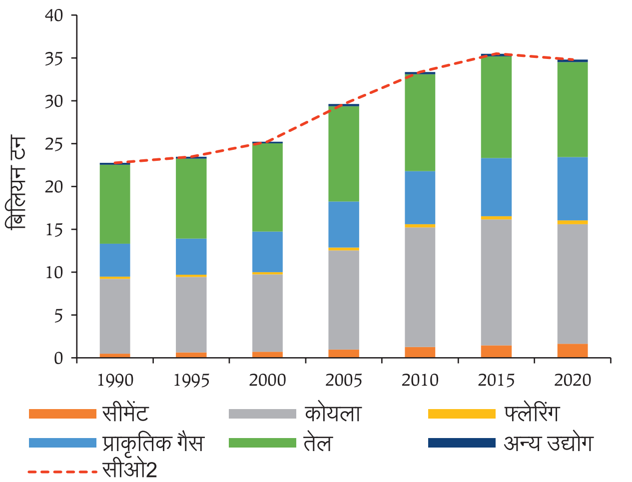

चार्ट 3बी: क्षेत्रवार सीओ2 उत्सर्जन - भारत

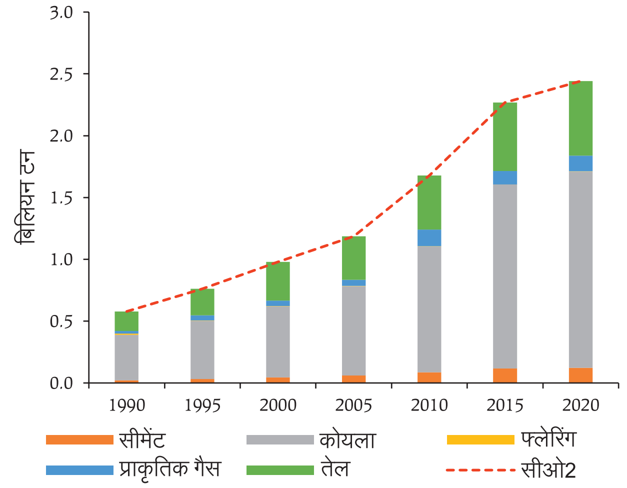

स्रोत: वैश्विक कार्बन परियोजना 2021; और अवर वर्ल्ड इन डेटा।

खपत में कोयले की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि देखी गई (चार्ट 4)। भारत में कोयला सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, यह भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 55 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है जो विश्व की तुलना में लगभग दोगुना है।

कुल प्राथमिक खपत में कोयले की घटती हिस्सेदारी के बावजूद, चीन, कोयले के उपयोग से जीएचजी का प्रमुख उत्सर्जक बना हुआ है और 2001 में डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बनने और विश्व विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद, कोयले से इसका उत्सर्जन बढ़ गया। कोयले से भारत का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है और यह विकसित और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से अधिक है [चार्ट 5]।

चार्ट 4: प्राथमिक ऊर्जा खपत में कोयले की हिस्सेदारी

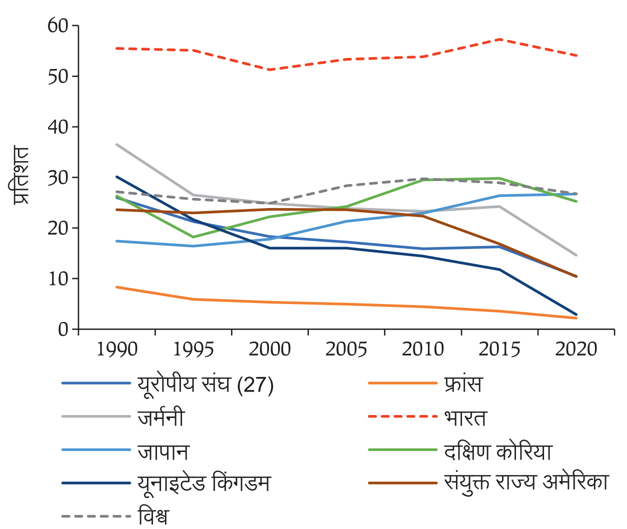

स्रोत: विश्व ऊर्जा 2022 की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा; और अवर वर्ल्ड इन डेटा।

चार्ट 5: कोयले के उपयोग से उत्सर्जन - 1960 से 2020

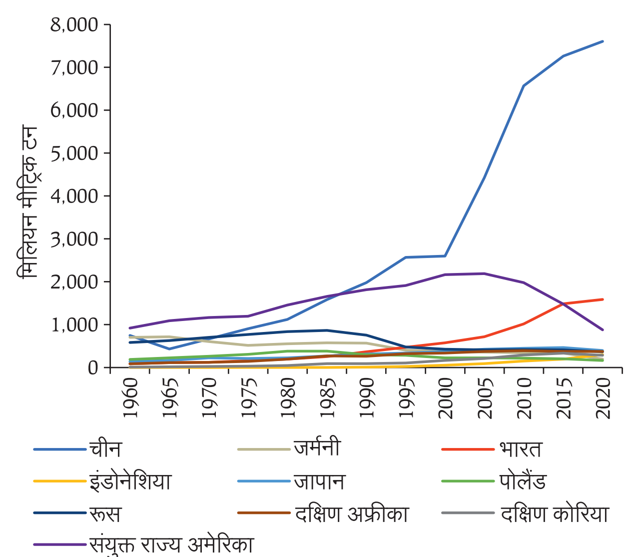

स्रोत: वैश्विक कार्बन परियोजना, 2021।

प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा

जीएचजी उत्सर्जन नियंत्रण की वैश्विक लड़ाई में नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीओपी26 शिखर सम्मेलन में लगभग सभी देशों ने कोयले के उपयोग में उल्लेखनीय कमी के साथ जीवाश्म ईंधन की कमी और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर होने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं (चार्ट 6)। हालांकि, नवीकरणीय संक्रमण विभिन्न देशों में भिन्न है, क्योंकि यह भौगोलिक स्थिति, खनिज भंडार, तकनीकी प्रगति, आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए - ब्राजील और कनाडा में नवीकरणीय पारगमन का नेतृत्व जलविद्युत ऊर्जा, फ्रांस (परमाणु, और जलविद्युत), यूके और जर्मनी (पवन और सौर), अमेरिका (सौर और पवन), इटली (सौर), और ऑस्ट्रेलिया (सौर और पवन) कर रहे हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक निवेश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश से कहीं अधिक है। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार, विश्व ऊर्जा निवेश 2022 में 8 प्रतिशत से अधिक बढ़कर कुल 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो कि कोविड-पूर्व अवधि से काफी अधिक है (आईईए, 2022ए)। 2022 में स्वच्छ ऊर्जा निवेश 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जो कुल ऊर्जा निवेश में लगभग तीन-चौथाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। दूसरी ओर, पारंपरिक स्रोतों में निवेश कोविड-पूर्व स्तरों से कम रहा और 2015 के बाद से इसमें गिरावट का रुझान जारी रहा। भारत में भी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश 2021-22 में दोगुने से अधिक होकर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया[6]। जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध ने इस रास्ते पर कुछ खतरे पैदा किए, साथ ही कई यूरोपीय देशों ने कई बंद कोयला संयंत्र चालू किए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निरंतर निवेश वैश्विक उत्सर्जन कटौती योजनाओं के लिए आशा प्रदान करता है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार, जीवाश्म ईंधन की वैश्विक मांग में 2020 के दशक के मध्य से हर वर्ष औसतन लगभग 2 एक्साजूल (ईजे) (प्रति दिन 1 मिलियन बैरल तेल [एमबीओई/डी] के बराबर) (आईईए, 2022बी) तक की लगातार गिरावट का अनुमान है। अगले कुछ वर्षों में कोयले की मांग चरम पर पहुंचने और 2030 के दशक के मध्य के बाद तेल की मांग में कमी आने का पूर्वानुमान है। तदनुसार, कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा आपूर्ति के तीन-चौथाई से कम और 2050 तक मौजूदा 84 प्रतिशत से घटकर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगी। सौर पीवी की घटती लागत, प्रौद्योगिकीय विकास से लाभ ने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर कदम को नई शक्ति प्रदान की। आईईए (2022) के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के पिछले पांच वर्षों की तुलना में 85 प्रतिशत

चार्ट 6: नवीकरणीय ऊर्जा पथ: दुनिया में

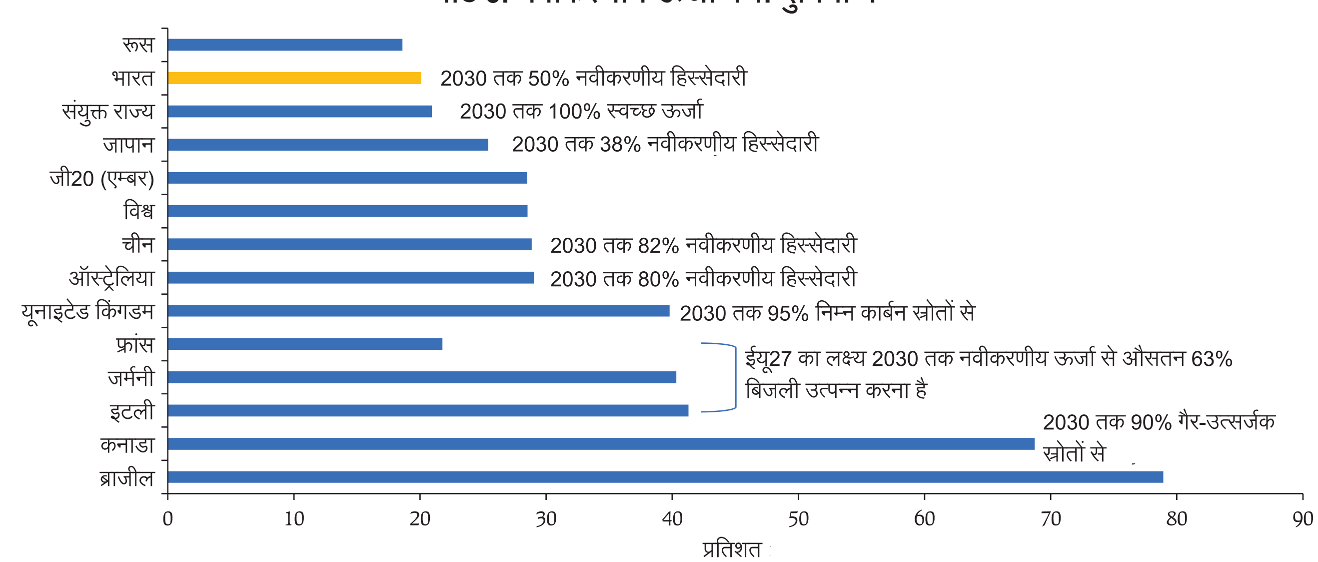

स्रोत: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण; स्टैटिस्टा; फ़ाइनेंशियल टाइम्स; और आईईए।

[6] 'इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसियल एनालिसिस' के अनुसार।

की त्वरित दर से बढ़ने की उम्मीद है। नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना, आरईपॉवरईयू योजना, अमेरिकी मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम और नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत के जोर को इस वृद्धि के मुख्य चालकों के रूप में उद्धृत किया गया है।

III. उत्सर्जन नियंत्रण के लिए रणनीतियां

जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा पारगमन प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के संयुक्त प्रयासों और एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए वैश्विक रास्ते ऊर्जा दक्षता उपायों, व्यवहार परिवर्तन, विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन-आधारित ईंधन, बायोएनर्जी और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करते हैं [आईईए, 2021]। इस प्रकार, कार्बन उत्सर्जित जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा से दूर जाने के अलावा, आमूलचूल परिवर्तन ऊर्जा-दक्ष तकनीकी प्रगति के साथ-साथ उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव पर जोर देते हुए ऊर्जा के उपयोग को कम करने पर भी निर्भर करता है। भारत में भी, उत्सर्जन कटौती रणनीतियों ने बड़े पैमाने पर उसी प्रतिमान का पालन किया है। भारत का निम्न उत्सर्जन की ओर दीर्घकालिक पारगमन निम्न कार्बन वाली बिजली, परिवहन और औद्योगिक प्रणाली, ऊर्जा-दक्ष शहरी डिजाइन, कार्बन निवारण नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, वन आवरण को बढ़ाने और कम लागत वाले जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाले सात स्तंभों पर आधारित है (जीओआई, 2022)।

विकसित देशों की तुलना में, जहां पहले से ही कोयले के उपयोग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, भारत की प्रतिबद्धताओं की सफलता के लिए कम-से-कम अल्प से मध्यम अवधि में ताप-विद्युत (थर्मल) स्रोतों के कुशल उपयोग की भी आवश्यकता होगी। भारत का ऊर्जा खपत समूह, विश्व स्तर पर अधिक वैविध्य की तुलना में कोयले की ओर बहुत अधिक झुकी हुई है, जो आंशिक रूप से घरेलू उपलब्धता और ताप-विद्युत ऊर्जा में बड़े निवेश को दर्शाती है। वैश्विक स्तर पर, कुल ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है, जबकि भारत में यह 55 प्रतिशत है। विकसित देशों ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस और तेल की ओर रुख करके कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अमेरिका में प्राथमिक ऊर्जा खपत में गैस की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई और यूरोपीय संघ में एक-चौथाई है। हालांकि, भारत के खपत समूह में थोड़ा बदलाव देखा गया और कोयले की हिस्सेदारी 1990 के बाद से 55 प्रतिशत के आसपास स्थिर रही। भारत में प्राकृतिक गैस की खपत वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है और दुनिया में सबसे कम खपत में से एक है - निम्न प्राकृतिक गैस भंडार के कारण प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में केवल 6.5 प्रतिशत है।

निम्न उत्सर्जन वाले स्रोत वैश्विक बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं, जिसमें 30 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से और 10 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है (आईईए, 2022)। आने वाले वर्षों में, विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन से बिजली उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। जबकि भारत मुख्य रूप से उत्सर्जन नियंत्रण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को लक्षित करता है, 2070 तक नेट जीरो की उपलब्धि काफी हद तक पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जन को कम करने पर निर्भर करेगी। भारत ने मार्च 2023 में कुल स्थापित क्षमता में अपनी हिस्सेदारी 41.3 प्रतिशत (बड़े जल-विद्युत सहित) के साथ स्थापित नवीकरणीय क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति की है[7] (चार्ट 7)। हालांकि, बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 22.8 प्रतिशत पर कम है।

चार्ट 7: स्रोत द्वारा कुल स्थापित क्षमता
(प्रतिशत में हिस्सेदारी)

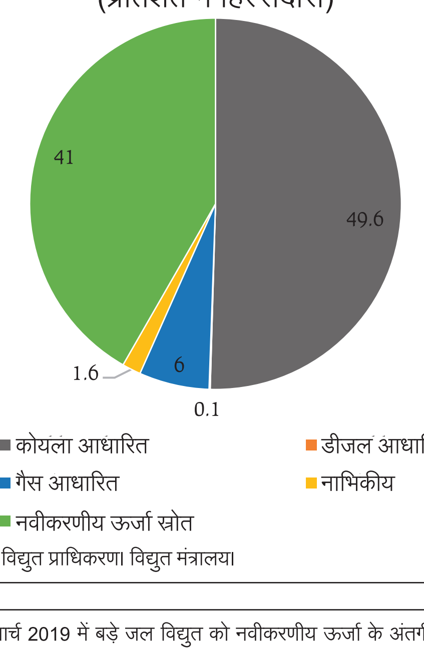

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। विद्युत मंत्रालय।

[7] सरकार ने मार्च 2019 में बड़े जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल किया। इससे पहले केवल 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं को ही नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत माना जाता था।

चार्ट 8: वर्ष 2022 और 2047 में अधिकतम स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा मार्ग के मामले में कुल ऊर्जा आपूर्ति में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

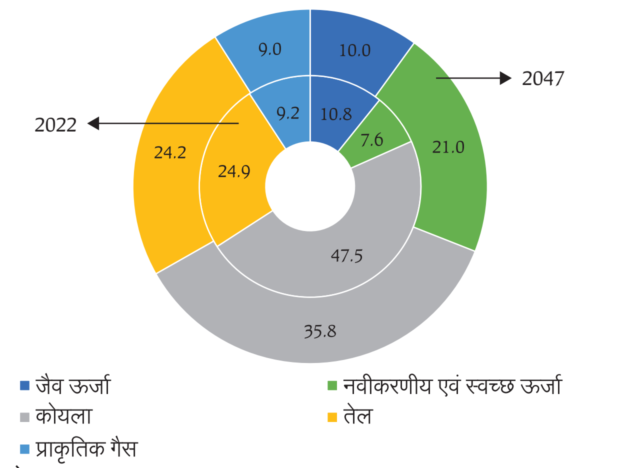

स्रोत: iess2047.gov.in.

जबकि ग्रिड कनेक्टिविटी और आपूर्ति विसंगतियों को सुचारू करने की दिशा में पहल की जा रही है, अल्प से मध्यम अवधि में पारंपरिक स्रोत एक प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे। ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य[8] के अनुसार, अधिकतम स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा मार्ग में भी कुल ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी अधिक रहेगी, जो 2047 में कुल ऊर्जा आपूर्ति का 35.8 प्रतिशत होगी (चार्ट 8)।

तदनुसार, भारत की उत्सर्जन नियंत्रण रणनीति काफी हद तक तकनीकी प्रगति के माध्यम से कोयले के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर निर्भर करती है। इस प्रकार रणनीतियाँ, पारंपरिक ऊर्जा खंड में उत्सर्जन कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित हैं (चित्र 1)।

भारत के व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से ताप-विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग की आवश्यकता है, जहां भारत को प्राकृतिक लाभ प्राप्त है। भारत के पास वैश्विक कोयला भंडार का लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा है और उपयोग की वर्तमान दर के साथ, भारत के पास इतना भंडार है जो एक शताब्दी से अधिक समय तक चल सकता है (वेदाचलम, रामदास, और आत्मानंद, 2020)। कोयले के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के समय होने वाले दहन के दौरान सीओ2 का उत्सर्जन होता है। एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) तकनीक जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, जहां कोयले को ईंधन गैस में परिवर्तित किया जाता है, सीओ2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पारंपरिक कोयला आधारित थर्मल पावर सिस्टम की तुलना में आईजीसीसी सिस्टम बिजली उत्पादन दक्षता में लगभग 15 प्रतिशत सुधार कर सकता है और सीओ2 को कम कर सकता है। हालांकि आईजीसीसी सिस्टम को अपनाने की पहल 2000 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाना बाकी है। भारत वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन गैसीकृत कोयले का लक्ष्य रख रहा है।

चित्र 1: भारत का स्वच्छ ऊर्जा मार्ग

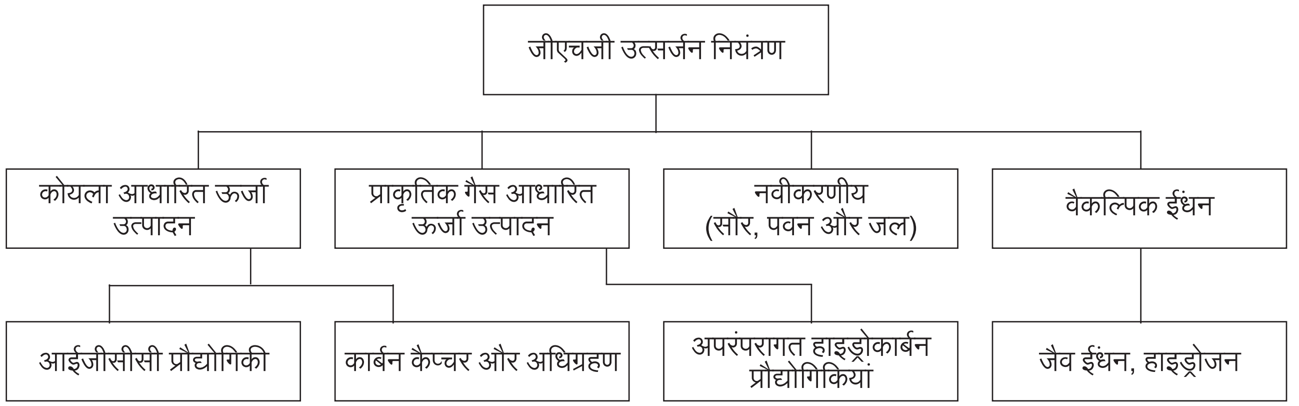

स्रोत: वेदाचलम और अन्य, 2020 से रूपांतरित।

8 iess2047.gov.in

9 मित्सुबिशी पावर | ऊर्जा संयंत्र: एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) ऊर्जा संयंत्र (mhi.com)

परिणामी ईंधन गैस से हाइड्रोजन, मेथनॉल और इथेनॉल जैसे गैसीय ईंधन प्राप्त हो सकते हैं। एक और स्वच्छ कोयला तकनीक जिसकी खोज की जा रही है, वह कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन (सीसीएस) है जो सीओ2 एकत्र करती है और इसे गहरे भूमिगत रूप में संग्रहीत करती है। सरकार ने जून 2025 से पहले चालू होने वाली ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय संचारण शुल्क माफ कर दिया है। सरकार उद्योग के सामने आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण नीति पर भी काम कर रही है।

उच्च उत्सर्जन वाली बिजली का एक विकल्प जैव ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कम उत्सर्जन वाले ईंधन हैं। भारत में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि नेट जीरो उद्देश्य को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अकेले ग्रीन हाइड्रोजन वर्ष 2050 तक 400 मिलियन टन सीओ2 को कम करने की क्षमता रखता है (बिरोल और अन्य, 2022)। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की काफी संभावना है क्योंकि नवीकरणीय बैटरी और अन्य अल्प कार्बन उपयोग आधारित तकनीक के साथ ग्रीन हाइड्रोजन वर्ष 2030 तक भारत में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का बाजार बना सकता है[10]। अकेले भारत की रिफाइनरियां और उर्वरक क्षेत्र 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन की मांग पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 28 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का दोहन करने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। अप्रैल 2022 में, 'रीन्यू पावर' (एक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर) ने समयबद्ध तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और लार्सन एंड टर्बो (इंजीनियरिंग और निर्माण अग्रणी) के साथ अपने संयुक्त उद्यम की घोषणा की। एसीएमई (भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर) और कर्नाटक सरकार के बीच एकीकृत सौर से ग्रीन हाइड्रोजन से हरित अमोनिया सुविधा के माध्यम से वर्ष 2027 तक प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जबकि ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जा रही है, शुद्ध शून्य उपलब्धि के लिए भारत का मार्ग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है।

सारणी 1: स्थापित क्षमता में अनुमान

ऊर्जा स्रोत	गीगावाट में स्थापित क्षमता		स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी		पूर्वानुमानित वार्षिक वृद्धि
	फ़र-23	2030	फ़र-23	2031-32	
जीवाश्म ईंधन	**230**	**292**	**55.8**	**35.7**	**3.4**
जिसमें से					
कोयला	204	244	49.5	29.9	**2.3**
गैर-जीवाश्म ईंधन	**176**	**525**	**42.7**	**64.3**	**16.9**
जिसमें से					
हाइड्रो सहित नवीकरणीय	169	500	41.0	61.2	**16.8**
कुल स्थापित क्षमता	412	817	100	100	**10.3**

स्रोत: सीईए डेटा पर आधारित लेखक की गणना।

सीईए के पूर्वानुमानों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा को वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट क्षमता तक पहुंचने के लिए शेष सात वर्षों में 16.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ना चाहिए। यह देखते हुए कि बड़ा जलविद्युत खंड ठहराव के बिंदु पर पहुंच गया है, नवीकरणीय खंड में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भावी वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछले पाँच वर्षों में महामारी तक यानी, 2019-2020[11] तक, नवीकरणीय क्षेत्र (जल-विद्युत को छोड़कर) में 23.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत क्षमता वृद्धि देखी गई है जो आवश्यक वृद्धि के अनुरूप है। फिर भी, जबकि कोयले की हिस्सेदारी में कमी आ रही है, यह देश की विकास आवश्यकताओं को देखते हुए एक प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखेगा (सारणी 1)।

निम्नलिखित खंड में हम यह पता लगाएंगे कि भारत का खनन क्षेत्र, बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कैसे अनुकूल है।

IV. खनन क्षेत्र पर प्रभाव

भारत में खनन क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक जीवीए में 10.4 प्रतिशत का योगदान दिया और 2020-21 में लगभग 1.10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया। भारत के पास दुनिया में धात्विक, अधात्विक, ईंधन और गौण खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। भारत के पास विश्व में कोयला और लौह अयस्क का पांचवां सबसे बड़ा भंडार है। कुल खनन उत्पादन में, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित ईंधन खनिजों का कुल उत्पादन में 53.8

[10] पूर्वोक्त।

[11] यह 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि को संदर्भित करता है।

प्रतिशत योगदान था, इसके बाद धात्विक और गैर-धात्विक खनिजों का 28.2 प्रतिशत योगदान था तथा गौण खनिजों का खनन उत्पादन में केवल 18 प्रतिशत का योगदान था। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का खनन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ता है – पहला, कोयला खनन पर इसके प्रभाव और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की मांग के कारण। नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, बिजली उत्पादन क्षमता की एक नई इकाई के लिए आवश्यक खनिजों की औसत मात्रा में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (आईईए, 2022)।

पवन और सौर से एक टेरावाट-प्रति घंटे बिजली पैदा करने से गैस आधारित बिजली संयंत्र की तुलना में धातुओं की खपत क्रमशः दो गुना और तीन गुना अधिक हो सकती है (अज़ेवेदो और अन्य, 2022)। उदाहरण के लिए, एक तटवर्ती पवन संयंत्र को गैस से चलने वाले संयंत्र की तुलना में नौ गुना अधिक खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है (आईईए, 2022)। इसी प्रकार, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर पीवी में खनिजों की आवश्यकता अधिक है। पवन टर्बाइनों के लिए, जिंक, मैंगनीज, दुर्लभ-पृथ्वी तत्व महत्वपूर्ण हैं (बलराम, 2019)। सौर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल के लिए तांबा और जिंक के अलावा सिलिकॉन एक महत्वपूर्ण खनिज है (चार्ट 9ए)। इसलिए, पारंपरिक कार की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन चार गुना से भी अधिक खनिज गहन होते हैं (चार्ट 9बी)। एक इलेक्ट्रिक कार के लिए अधिक खनिजों जैसे लिथियम, निकल, ग्रेफाइट, मैंगनीज, कोबाल्ट, दुर्लभ-पृथ्वी सामग्री आदि की आवश्यकता होती है। ईवी और बैटरी भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य की आवश्यकताओं से वर्ष 2040 तक लिथियम की मांग 40 गुना से अधिक तथा ग्रेफाइट, कोबाल्ट और निकल की मांग के लगभग 25-30 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे ईंधन सेल से प्लैटिनम समूह की सामग्रियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है; हाइड्रोजन के लिए निकल की मांग बढ़ने की उम्मीद है और इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए ज़िरकोनियम की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

(आईईए, 2022) के अनुसार, 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए खनिज आवश्यकताओं में दो से चार गुना वृद्धि होगी और लिथियम की मांग 40 गुना बढ़ जाएगी, निकल और कोबाल्ट की मांग में 20-25 गुना इजाफा होगा एवं धारणीय विकास परिदृश्य[11] (एसडीएस) में मैंगनीज और दुर्लभ पृथ्वी

चार्ट 9ए: स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रयुक्त खनिज (किलोग्राम/मेगावाट)

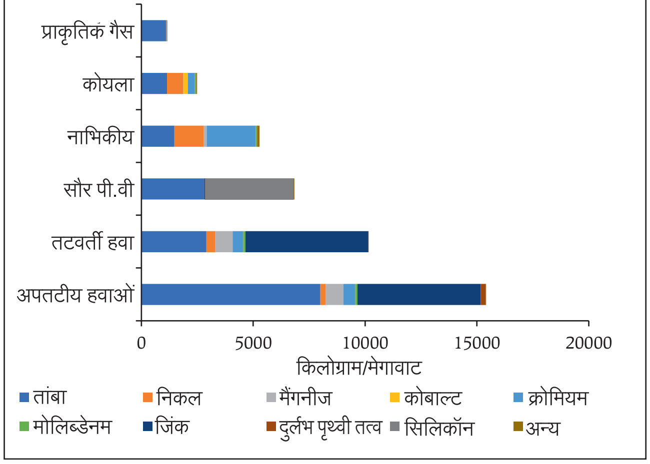

चार्ट 9बी: स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रयुक्त खनिज (किलोग्राम/वाहन)

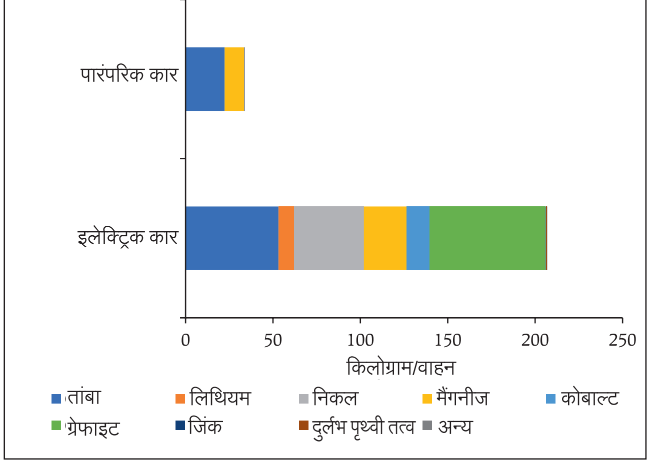

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, 2022।

[12] आईईए का धारणीय विकास परिदृश्य (एसडीएस) यह दर्शाता है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुरूपी मार्ग में क्या आवश्यक होगा। घोषित नीति परिदृश्य (स्टेप्स), क्षेत्र-दर-क्षेत्र विश्लेषण के आधार पर ऊर्जा प्रणाली कहां जा रही है, इसका संकेत आज की नीतियों और नीति घोषणा के अनुसार प्रदान करता है।

चार्ट 10: चुनिंदा खनिजों के लिए पूर्वानुमानित वृद्धि: वर्ष 2020 के सापेक्ष 2040 में

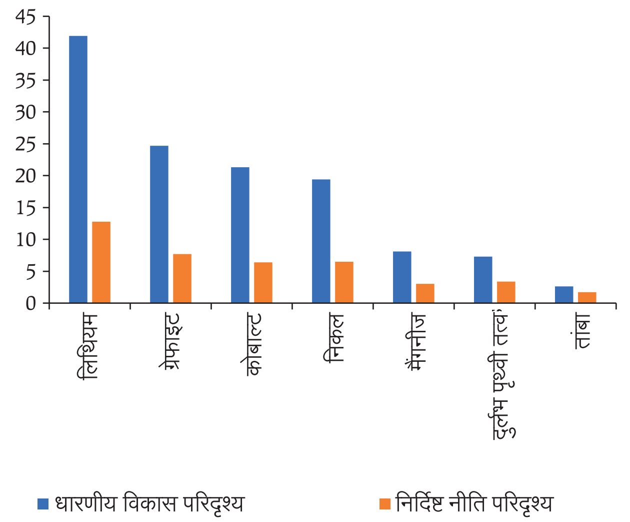

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, 2022।

सामग्री 5-10 गुना की गति से बढ़ेगी (चार्ट 10)। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता एक कदम, खनन क्षेत्र के महत्व को कम नहीं करता है। वास्तव में, इससे क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि हुई और इस प्रकार यह और अधिक विविध हो गया। गौण खनिज, जिनका भारत के खनन उत्पादन में केवल 18 प्रतिशत योगदान था, आने वाले वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे।

हालांकि भारत के पास प्रचुर कोयला भंडार होने के बावजूद, स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के लिए आवश्यक खनिजों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुल उत्पादन में आरई की हिस्सेदारी बढ़ने, ईवी की ओर संक्रमण से महत्वपूर्ण खनिजों की बैटरी भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत इनमें से कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की तुलना में ये महत्वपूर्ण खनिज भौगोलिक रूप से कुछ ही स्थानों पर केंद्रित हैं। वैश्विक भंडार के संदर्भ में, शीर्ष तीन देश इन महत्वपूर्ण खनिजों के कुल वैश्विक भंडार का आधे से अधिक हिस्सा साझा करते हैं (परिशिष्ट सारणी 1)। उच्च पूंजीगत व्यय और आवश्यक जटिल प्रौद्योगिकी के कारण, इन महत्वपूर्ण खनिजों की उत्पादन हिस्सेदारी कुछ देशों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है (चार्ट 11)। तीन-चौथाई से अधिक लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ-पृथ्वी तत्व - शीर्ष तीन उत्पादक देशों में केंद्रित हैं। इसके अलावा, इन खनिजों के शोधन और प्रसंस्करण के लिए भारी पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है, जहां चीन को शीघ्र शुरुआत का लाभ मिलता है। शोधन/प्रसंस्करण में चीन की हिस्सेदारी दुर्लभ पृथ्वी सामग्री के लिए लगभग 90 प्रतिशत, लिथियम और कोबाल्ट के लिए 50-70 प्रतिशत, तांबे के लिए 40 प्रतिशत और निकल के लिए लगभग 35 प्रतिशत है। भारत फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के आयात के लिए

चार्ट 11: चुनिंदा खनिजों और जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण में शीर्ष उत्पादक देशों की हिस्सेदारी, 2019

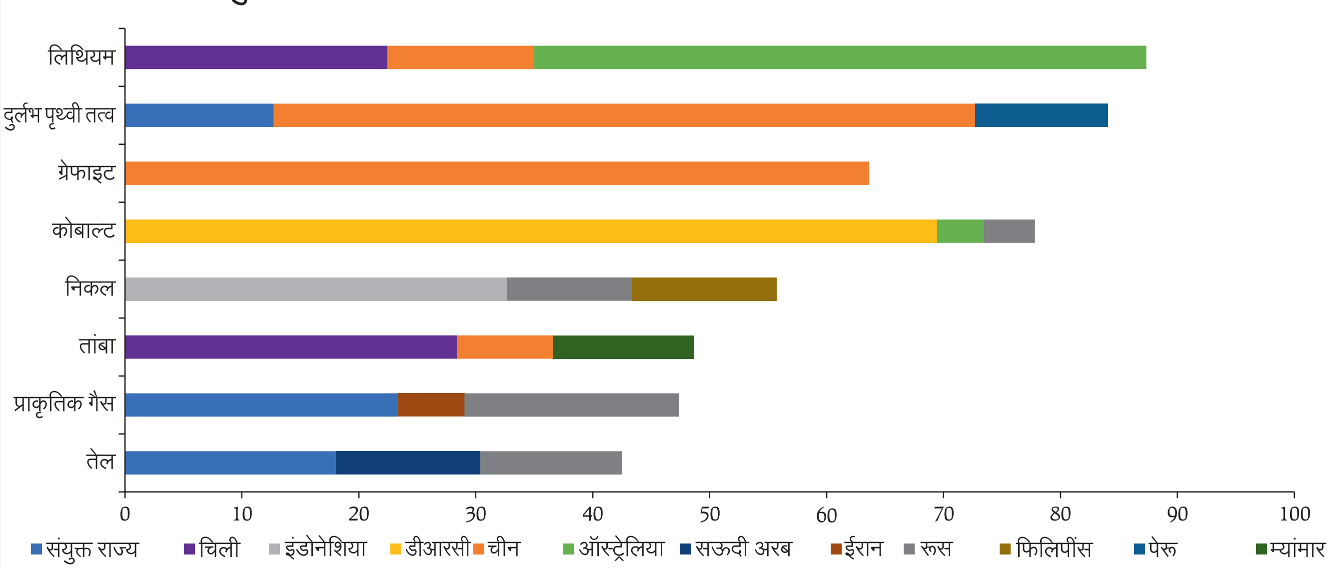

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, 2022।

चार्ट 12: 2018-19 में, प्रमुख खनिजों और धातुओं में आत्मनिर्भरता का स्तर

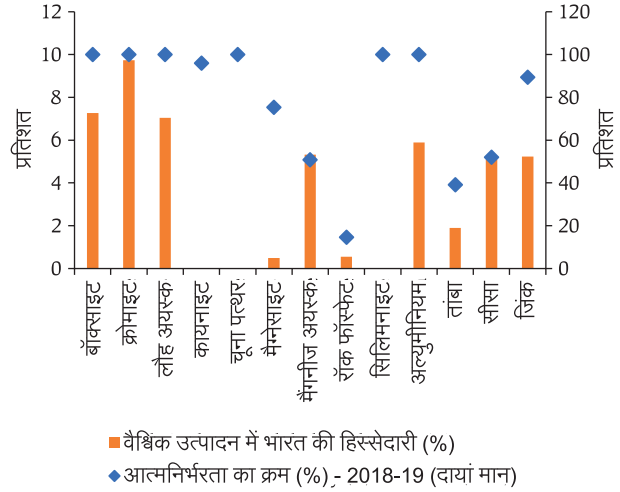

स्रोत: राष्ट्रीय खनिज परिदृश्य: खान मंत्रालय; खनिज पण्य सारांश 2022; और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।

चीन पर निर्भर है। वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक सौर पैनल और मॉड्यूल मुख्य रूप से चीन से आयात किए जाते हैं। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक लिथियम उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा साझा किया है और दक्षिण अफ्रीका वैश्विक क्रोमियम उत्पादन का 43 प्रतिशत साझा किया है (परिशिष्ट सारणी 1)।

इन महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक भंडार में क्रोमियम (17.5 प्रतिशत) और सिलिकॉन (प्रचुर मात्रा में) को छोड़कर, भारत की हिस्सेदारी कम है। भारत में वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी सामग्री भंडार का लगभग 5-6 प्रतिशत, जस्ता भंडार का 3.64 प्रतिशत एवं वैश्विक तांबा और मैंगनीज भंडार का लगभग 2-3 प्रतिशत हिस्सा है। वर्तमान मांग स्तर पर, भारत बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, एल्यूमीनियम, जस्ता और तांबे जैसे खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के करीब है। हालांकि भारत में मैंगनीज अयस्क, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी सामग्री, लिथियम, कायनाइट आदि की कमी है, जिसके चलते आयात पर निर्भरता अपरिहार्य है। यहां तक कि खनिजों में भी आत्मनिर्भरता हासिल होने के करीब है, स्वच्छ ऊर्जा पर प्रोत्साहन बढ़ने से भविष्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए भारी पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उभरती मांग को पूरा करने के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन खनिजों का रणनीतिक अधिग्रहण भी किए जाने की आवश्यकता है (चार्ट 12 और परिशिष्ट सारणी 2)।

V. सारांश और निष्कर्ष

स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर टिकी हुई है, हालांकि मध्यम अवधि में, कोयले की भूमिका प्रमुख बने रहने की संभावना है। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में, देश ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए खनन क्षेत्र पर भारत की निर्भरता को कोयले से हटाकर अन्य आवश्यक खनिजों पर स्थानांतरित करना होगा।

वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ खनिज गहन हैं, जिनकी आपूर्ति कुछ देशों में केंद्रित है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता पर चिंताएं बढ़ा दीं। सरकार, खनिज-संपन्न देशों के साथ विभिन्न रणनीतिक गठबंधन बनाने की प्रक्रिया में है। भारत अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे लिथियम और कोबाल्ट उत्पादक देशों के साथ काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, इसने लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्तियों की पहचान के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की चतुष्क गुटबंदी (क्वाड ग्रुपिंग) ने एक "क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी" कार्य दल पेश किया है जो महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति शृंखला सुरक्षा पर केंद्रित है। भारत और जापान ने दुर्लभ पृथ्वी सामग्री विकसित करने के लिए एक समझौता किया है, जिसका उपयोग कई उच्च-तकनीकी वस्तुओं (भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2019) के विनिर्माण में किया जाता है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आवश्यक समैरियम-कोबाल्ट मैग्नेट के निर्माण के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) संयंत्र पर काम कर रहा है।

दूसरा दृष्टिकोण इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम करना है। तदनुसार, विभिन्न कंपनियाँ उन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही हैं जिनके लिए इन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आवश्यकता नहीं है। बैटरी रसायन का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है जो कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, एल्यूमीनियम आयन आदि जैसे सस्ते, प्रचुर और टिकाऊ खनिजों का उपयोग करता है। हाइड्रोजन फ्युल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल (एफसीईवी) में भी भार की प्रति इकाई अपनी उच्च ऊर्जा के कारण, भविष्य में अधिक उपयोग की संभावना है। बैटरी प्रौद्योगिकियों में उन्नति से गैर-जीवाश्म ईंधन की ओर अधिक धारणीय तरीके से कदम बढ़ाने की उम्मीद है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफएएमई) योजना की शुरूआत, 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्स छूट जैसी पहलों का उद्देश्य प्रमुख निविष्टियों पर आयात निर्भरता को कम करना है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए, मध्यम अवधि में कोयला खनन महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, दीर्घावधि में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होना वांछनीय है, जहाँ तकनीकी नवोन्मेषों को बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं और डिज़ाइनों द्वारा सहायता मिलती है और जिनमें कम या किसी महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए संयुक्त राज्य की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी-एनर्जी (एआरपीए-ई) की तरह विश्व स्तर पर प्रयास किए गए हैं, जिसने रेयर अर्थ अल्टरनेटिव्स इन क्रिटिकल मैटेरियल्स (रिएक्ट) कार्यक्रम की शुरुआत की (ग्रेंजर, 2022)। इसके अलावा, सीओपी-26 प्रतिबद्धताओं की उपलब्धि काफी हद तक ऊर्जा उपयोग में व्यवहारिक परिवर्तनों के बाद ऊर्जा-दक्ष तंत्र अपनाने पर निर्भर करती है। हालिया आपूर्ति शृंखला की बाधा ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को सामने ला दिया है। यह एक लागत-प्रभावी धारणीय ऊर्जा पारगमन और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

संदर्भ

Azevedo, M., Baczynska, M., Bingoto, P., Callawa, G., Hoffman, K., & Ramsbottom, O. (2022). "The raw-materials challenge: How the metals and mining sector will be at the core of enabling the energy transition".

Balaram, V. (2019). "Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact". Geoscience Frontiers, 10(4), 1285–1303.

Birol, F., & Kant, A. (2022). "India's clean energy transition is rapidly underway, benefiting the entire world". International Energy Agency.

BP (2022). "BP Statistical Review of World Energy 2022".

GOI, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2022). "India's Long-Term Low-Carbon Development Strategy". Government of India.

GOI, Central Electricity Authority (2020). "Report on Optimal generation capacity mix for 2029-30". Government of India.

Grainger T. (2022). "The rare earth problem must be solved by innovating, not just playing catch up".

Ritchie, H., Roser, M., & Rosado, P., (2020). "CO_2 and Greenhouse Gas Emissions". OurWorldInData.org.

GOI (2017)."Greening the Grid". National Renewable Energy Laboratory & Ministry of Power.

IEA (2021). "Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector". International Energy Agency.

IEA (2022a). "World Energy Investment Report 2022". International Energy Agency.

IEA (2022b). "World Energy Outlook 2022". International Energy Agency.

IPCC (2015). "Summary for Policymakers. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Working

Group III Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report" (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415416.005

Karstensen, J., Roy, J., Pal, B. D., Peters, G., & Andrew, R. (2020). "Key Drivers of Indian Greenhouse Gas Emissions". Economic & Political Weekly, 46-53.

USGS(2022). "Mineral Commodity Summaries 2022". United States Geological Survey.

IPCC (2021). "Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change".

Vedachalam, N., Ramadass, G., & Atmanand, M. (2020). "Review on the Role of Hydrocarbon Resources in India's Energy Security and Climate Goals". Geological Society of India, 95, 561-565.

परिशिष्ट सारणी 1: चुनिंदा खनिजों के भंडार और उत्पादन वाले शीर्ष देश
(वैश्विक भंडार और उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी)

कोयला				कोबाल्ट			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
संयुक्त राज्य	23	चीन	50.8	डीआर कांगो	48.2	कांगो (किंशासा)	68.4
रूस	15	इंडोनेशिया	9.0	ऑस्ट्रेलिया	18.1	इंडोनेशिया	5.3
ऑस्ट्रेलिया	14	भारत	8.0	इंडोनेशिया	7.2	रूस	4.7
चीन	13	ऑस्ट्रेलिया	7.4	क्यूबा	6.0	ऑस्ट्रेलिया	3.1
भारत	10	संयुक्त राज्य	7.0	फिलिपींस	3.1	कनाडा	2.1
प्राकृतिक गैस				सीसा			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
रूस	25.5	संयुक्त राज्य	23.6	तुर्की	27.3	चीन	65.4
ईरान	21.9	रूस	17.7	ब्राजील	22.4	मोज़ाम्बिक	13.1
कतर	16.9	ईरान	6.5	चीन	15.8	मेडागास्कर	8.5
तुर्कमेनिस्तान	9.3	चीन	5.3	मेडागास्कर	7.9	ब्राजील	6.7
संयुक्त राज्य	8.6	कतर	4.5	मोज़ाम्बिक	7.6	कोरिया गणराज्य	1.3
लिथियम				दुर्लभ पृथ्वी तत्व			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
चिली	35.8	ऑस्ट्रेलिया	46.9	चीन	33.8	चीन	70.0
ऑस्ट्रेलिया	23.8	चिली	30.0	वियतनाम	16.9	संयुक्त राज्य	14.3
अन्य देश 8	12.7	चीन	14.6	ब्राजील	16.2	ऑस्ट्रेलिया	6.0
अर्जेंटीना	10.4	अर्जेंटीना	4.8	रूस	16.2	बर्मा	4.0
चीन	7.7	ब्राजील	1.7	भारत	5.3	थाईलैंड	2.4
तांबा				क्रोमियम			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
चिली	21.3	चिली	23.6	कजाखस्तान	41.1	दक्षिण अफ्रीका	43.9
ऑस्ट्रेलिया	10.9	डीआर कांगो	10.0	दक्षिण अफ्रीका	35.7	तुर्की	16.8
पेरू	9.1	पेरू	10.0	भारत	17.9	कजाखस्तान	15.9
रूस	7.0	चीन	8.6	तुर्की	4.6	भारत	10.2
मेक्सिको	6.0	संयुक्त राज्य	5.9	फिनलैंड	1.5	फिनलैंड	5.6
निकल				जस्ता			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
ऑस्ट्रेलिया	21	इंडोनेशिया	48.5	ऑस्ट्रेलिया	27.5	चीन	38.7
इंडोनेशिया	21	फिलिपींस	10.0	चीन	17.5	पेरू	14.7
ब्राजील	16	रूस	6.7	रूस	8.8	ऑस्ट्रेलिया	12.0
रूस	7.5	न्यू कैलेडोनिया 9	5.8	मेक्सिको	7.6	भारत	7.5
संयुक्त राज्य	7.37	ऑस्ट्रेलिया	4.8	पेरू	7.6	संयुक्त राज्य	6.8
मैंगनीज				सिलिकॉन			
भंडार		उत्पादन		भंडार		उत्पादन	
दक्षिण अफ्रीका	37.6	दक्षिण अफ्रीका	36.0	चीन	68.2		
चीन	16.5	गैबॉन	23.0	रूस	7.3		
ऑस्ट्रेलिया	15.9	ऑस्ट्रेलिया	16.5	ब्राजील	4.5	प्रचुर	
ब्राजील	15.9	चीन	5.0	नॉर्वे	4.1		
यूक्रेन, संकेंद्रित	8.2	घाना	4.7	संयुक्त राज्य	3.5		

स्रोत: खनिज वस्तु सारांश 2023, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण; और विश्व ऊर्जा 2022 की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा।

परिशिष्ट सारणी 2: वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी और महत्वपूर्ण खनिजों का वैश्विक भंडार

(प्रतिशत में)

	उत्पादन हिस्सेदारी (2021)	आरक्षित शेयर
क्रोमियम	7.3	17.5
तांबा	2.28	2.0
सीसा	0.65	2.5
मैंगनीज	3.0	2.3
दुर्लभ पृथ्वी तत्व	1.0	5.8
सिलिकॉन	0.7	प्रचुर
जस्ता	6.2	3.64

स्रोत: राष्ट्रीय खनिज परिदृश्य; खान मंत्रालय; और खनिज वस्तु सारांश 2022, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।

अंतिम पड़ाव पर बुनियादी और डिजिटल वित्तीय साक्षरता: ग्रामीण पश्चिम बंगाल की एक झलक

साक्षी अवस्थी ^ , राखे बालचंद्रन#, बरखा गुप्ता ^ ,राजस सरौए ^ , आशीष खोब्रागडे ^ , गुणवीर सिंह, रेखा मिश्र ^ , सरत चंद्र धल ^ द्वारा*

आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने हेतु वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। यह लेख घरेलू वित्तीय निर्णय निर्माताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है जिन्हें अभी तक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों (एफएलपी) में शामिल नहीं किया गया था। वित्तीय साक्षरता वित्तीय पहलुओं और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में विषम है। उच्च वित्तीय साक्षरता उन व्यक्तियों से जुड़ी है जो आर्थिक रूप से संपन्न, शिक्षित, युवा हैं और स्मार्टफोन तक पहुंच रखते हैं। यद्यपि बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को यथोचित रूप से समझा जाता है, तथापि, डिजिटल पहलुओं, शिकायत अग्रेषण तंत्र और समग्र रूप से व्यापक वित्तीय ज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने की गुंजाइश है।

परिचय

वित्तीय साक्षरता को वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो ठोस वित्तीय निर्णय लेने और व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है (ओईसीडी, 2012; ओईसीडी, 2012) आरबीआई, 2021)। एक सामान्यीकृत परिप्रेक्ष्य से, वित्तीय साक्षरता में तीन घटक शामिल हैं; (ए) वित्तीय उत्पादों और संस्थानों के बारे में वित्तीय जागरूकता और ज्ञान (कार्पेना एवं अन्य, 2011); (बी) धन प्रबंधन और वित्तीय नियोजन (जू और ज़िया, 2012) से जुड़ी वित्तीय क्षमता, और (सी) ब्याज चक्रण, मुद्रास्फीति और जोखिम विविधीकरण जैसी जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक वित्तीय कौशल (लुसार्डी और मिशेल, 2014)। जटिल उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता के साथ, उपभोक्ताओं को वित्तीय क्षेत्र में चौंकाने वाले विकल्पों का सामना करना पड़ता है। आवश्यक वित्तीय साक्षरता के बिना, उपभोक्ता अक्सर इन उत्पादों से जुड़े अधोगामी जोखिमों से चूक जाते हैं और वित्तीय नुकसान झेलते हैं। इसके अलावा, वित्तीय शिक्षा विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक जागरूकता और पहुंच को सक्षम करके मांग-पक्ष प्रतिक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; जिससे परिवारों के वित्तीय आघात सहनीयता को मजबूत किया जा सके (दास, 2020; 2021)। इस प्रकार, वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन के लिए एक पूर्व अपेक्षित शर्त और आर्थिक कल्याण के लिए एक आवश्यक शर्त है। वित्तीय साक्षरता का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय पहलुओं और जनसंख्या के उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जो लक्षित नीतिगत ध्यान देने योग्य हैं। इस परिप्रेक्ष्य से प्रेरित, यह लेख सुदूरवर्ती गांवों से संबंधित ग्रामीण जनता की वित्तीय साक्षरता से जुड़ी तथ्यों को प्रस्तुत करता है।

भारत में, वित्तीय साक्षरता सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक एजेंडा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय रूप से जागरूक भारत बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं जिनमें, अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के सहयोग से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) की स्थापना, वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) परियोजना - सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय शिक्षा प्रदान करने का एक अभिनव तरीका और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाते हुए, एनसीएफई ने 2020-2025 के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं

लेखक अंतरराष्ट्रीय विभाग से हैं

* लेखक भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग से हैं

लेखक श्री प्रत्यूष अमित, सहायक प्रबंधक, आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद और श्री अवि दास, वरिष्ठ सहायक, आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण के लिए उत्कृष्ट लॉजिस्टिक सहयोग को स्वीकार करते हैं। लेखक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के अधिकारियों, सरकारी अधिकारी, पश्चिम मेदिनीपुर जिला; अग्रणी जिला प्रबंधक, पश्चिम मेदिनीपुर; और वित्तीय साक्षरता केंद्र, पश्चिम मेदिनीपुर के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग को भी स्वीकार करते हैं।

इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(एनएसएफई) तैयार की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को विकसित करना और जोखिमों का प्रबंधन करते हुए डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ाना है।

वित्तीय साक्षरता का जायजा लेने के लिए, यादृच्छिक रूप से चयनित 2000 से कम आबादी वाले पश्चिम बंगाल के आठ गांवों में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें वित्तीय जागरूकता और वित्तीय अवधारणाओं / उत्पादों / संस्थानों के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चूंकि चयनित नमूना 2.5 लाख से अधिक गांवों (साक्षरता के दृष्टिकोण से) का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्ययन के निष्कर्ष सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए मौजूदा नीतियों को ठीक करने में उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, उत्तरदाताओं को इस सर्वेक्षण के समय आरबीआई या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या सीएफएल से कोई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (एफएलपी) प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, इस अध्ययन में सामने आई वित्तीय साक्षरता की सीमा किसी भी तरह से एफएलपी की प्रभावशीलता को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

एक उच्च साक्षर अर्थव्यवस्था में, वित्तीय साक्षरता को नकारात्मक विषमता अर्थात अधिकांश प्रतिभा वितरण के दाहिने छोर पर वितरित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, इस अध्ययन में उजागर थोड़ा सकारात्मक विषम वित्तीय साक्षरता वक्र यह इंगित करता है कि सुदूरवर्ती गांवों में वित्तीय साक्षरता में सुधार की गुंजाइश है। बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं पर जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत पर्याप्त है, हालांकि, डिजिटल पहलुओं, शिकायत वृद्धि तंत्र और समग्र व्यापक वित्तीय ज्ञान पर कम है। बीटा प्रतिगमन और रैखिक मॉडल का उपयोग करके अनुभवजन्य विश्लेषण आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, शिक्षा और व्यवसाय जैसे वित्तीय साक्षरता के जनसांख्यिकीय संवाहकों के महत्व को रेखांकित करता है। संक्षेप में, एफएलपी के तहत विभिन्न जनसांख्यिकीय घटकों और वित्तीय पहलुओं को शामिल करने के क्षैतिज विस्तार के साथ, विस्तृत वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में ऊर्ध्वाधर गहराई भी आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय साक्षरता को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्ययन के शेष भाग को सात खंडों में प्रस्तुत किया गया है: साहित्य की समीक्षा (II), प्रश्नावली की विशेषताएं (III), अध्ययन क्षेत्र और नमूना चयन (IV) वित्तीय साक्षरता सूचकांक का विवरण (V) सर्वेक्षण का निष्कर्ष (VI) वित्तीय साक्षरता के सहचरों के लिए प्रतिगमन परिणाम (VII) और (VIII) निष्कर्ष।

II. साहित्य की समीक्षा

साहित्य में वित्तीय साक्षरता की भूमिका के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा गया है। एक परिवार की भलाई और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, वित्तीय साक्षरता को विकास बढ़ाने वाले कारक के रूप में पहचाना गया है (हस्टन, 2010; बेकमैन, 2013)। वित्तीय साक्षरता के उच्च स्तर वाले परिवारों को सेवानिवृत्ति की योजना बनाने (बैंक एवं अन्य 2010), अधिक परिष्कृत निवेश दृष्टिकोण के साथ वित्तीय बाजारों में भाग लेने (क्रिस्टलिस एवं अन्य, 2010) और अधिक धन जमा करने की अधिक संभावना है (बेहरमैन एवं अन्य, 2010)। दूसरी ओर, आवश्यक वित्तीय ज्ञान की अनुपस्थिति अर्थव्यवस्थाओं के लिए महंगी उधार और उच्च ऋण भार से जुड़ी हुई है (क्लैपर और पैनोस, 2011)। अनुसंधान से पता चला है कि वित्तीय गलतियाँ अक्सर कम वित्तीय ज्ञान और अविकसित संज्ञानात्मक क्षमता का एक परिणाम होती हैं, जिससे वित्तीय कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है (अग्रवाल एवं अन्य, 2009)

वित्तीय साक्षरता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में, आयु, शिक्षा, लिंग, व्यावसायिक स्थिति और आय ने साहित्य में प्रमुखता प्राप्त की है (मॉर्गन और ट्रिन, 2017)। अधिकांश देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास वित्तीय ज्ञान का स्तर कम है, जबकि युवा और वृद्ध दोनों आबादी ने अपने मध्यम आयु वर्ग के समकक्षों की तुलना में कम वित्तीय जानकारी का प्रदर्शन किया है। आय और वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ शिक्षा और वित्तीय ज्ञान (सिंगला और मलिक, 2021) के बीच एक सकारात्मक संबंध है। इसके अलावा, अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि सेवानिवृत्त या स्व-नियोजित व्यक्तियों में उनके वेतनभोगी समकक्षों (चौधरी और कंबोज, 2017) की तुलना में कम वित्तीय साक्षरता होती है। इसके अलावा, शहरी लोगों के पास ग्रामीण आबादी की तुलना में उच्च वित्तीय साक्षरता है (क्लैपर और

पैनोस, 2011)। सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं में इस तरह की भिन्नताओं का दृष्टिकोण, विश्वास, आत्मविश्वास स्तर और वित्तीय अवधारणाओं को सीखने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा पर भी असर पड़ता है (ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग, 2011)।

साहित्य के एक खंड ने उन मार्गों का भी आकलन किया है जिनके माध्यम से एफएलपी वित्तीय व्यवहार, आर्थिक प्रदर्शन और परिवारों के सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि प्रासंगिक साहित्य विशाल है, आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करने में एफएलपी के प्रभाव पर मिश्रित साक्ष्य मिलते हैं। सर्वेक्षण डेटा-आधारित विश्लेषण एफएलपी और व्यवहार के बीच सकारात्मक सहसंबंध इंगित करता है, हालांकि, स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने वाले कारण प्रयोगात्मक विश्लेषण की कमी मौजूद है (कार्पेना एवं अन्य, 2015)। कुछ अध्ययनों में वित्तीय व्यवहार (फर्नांडीस एवं अन्य, 2014) पर एफएलपी के मामूली प्रभाव और प्रभावों का त्वरित अपव्यय (ब्रुन एवं अन्य, 2014) का निष्कर्ष निकला है। एफएलपी की प्रभावशीलता पर आम सहमति की कमी को अध्ययनों में वित्तीय साक्षरता उपायों में विविधता और संभावित विलोपित परिवर्तनीय पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो तुलना को मुश्किल बनाते हैं (फर्नांडीस एवं अन्य, 2014)। इसलिए, एक-आकार-समायोजित-सभी नीति के बजाय लक्ष्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों को व्यक्तिगत व्यवहार में आधारभूत अंतर के लिए लेखांकन में बेहतर माना जाता है।

III. सर्वेक्षण डिजाइन और प्रश्नावली

यह अध्ययन वित्तीय साक्षरता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग करता है, जिसे 'डिजिटल बैंकिंग और शिकायत वृद्धि तंत्र सहित बैंकिंग अवधारणाओं / उत्पादों / संस्थानों के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सूचित, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग निर्णय लेने और वित्तीय धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए आवश्यक हैं। प्रश्नावली को डिजाइन करने के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी), आरबीआई की वित्तीय साक्षरता सामग्री का उपयोग किया गया था। प्रश्नों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, और धोखाधड़ी पर साक्षरता और शिकायत वृद्धि तंत्र पर वर्गों में विभाजित किया गया था।

प्रारंभ में, उत्तरदाताओं को सर्वेक्षण का उद्देश्य समझाया गया था। सर्वेक्षण में भागीदारी वैकल्पिक थी और प्रतिभागियों को पुरस्कृत नहीं किया गया था। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले प्रतिभागियों को गोपनीयता वक्तव्य दिया गया था कि 'सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र की गई व्यक्तिगत विशिष्ट जानकारी का उपयोग केवल अनुसंधान और नीति उद्देश्यों के लिए किया जाएगा'। टैबलेट का उपयोग करके सर्वेक्षण के लिए कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) आयोजित किए गए थे ताकि एकत्र किए गए डेटा को तुरंत एक सर्वर पर सहेजा जा सके, इस प्रकार, संभावित मैनुअल डेटा एंट्री गलतियों से बचा जा सके।

जांचकर्ता-प्रेरित पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रत्येक प्रश्न का उद्देश्य, प्रश्नों को प्रस्तुत करने के तरीके के साथ बताया गया था। सर्वेक्षण की निगरानी संबन्धित क्षेत्र में की गई ताकि गणनाकारों में पूछताछ पद्धति की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके, उत्तरदाताओं से किसी भी उत्तर को प्रेरित करने से बचा जा सके और उत्तरदाताओं के साथ किसी भी अतिरिक्त जानकारी को साझा करने से रोका जा सके।

इसके अलावा, प्रश्नावली-प्रेरित पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे, जिसमें पायलट परीक्षण के माध्यम से सर्वेक्षण प्रश्नावली का पूर्व-परीक्षण करना और प्रश्नावली का स्थानीय भाषा (बंगाली) में अनुवाद करना शामिल था। डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को आसान बनाने के लिए सभी प्रश्नों को क्लोज-एंड किया गया था, और प्रतिभागियों पर किसी भी दिए गए उत्तर को थोपने से बचने के लिए 'पता नहीं' विकल्प था। यह वित्तीय साक्षरता को मापने के दौरान एक गलत उत्तर और 'पता नहीं' के बीच वैचारिक रूप से अंतर करने में मदद करता है। इसी तरह, सभी बहु वैकल्पिक प्रश्नों (एमसीक्यू) में 'अन्य' का विकल्प था, ताकि उत्तरदाता प्रश्नावली में प्रदान किए गए सीमित विकल्पों से विवश न हो। इसके अलावा, एमसीक्यू के सभी विकल्पों को प्रतिभागियों के सामने उसी क्रम में प्रस्तुत किया गया था ताकि प्रतिक्रियाओं में पूर्वाग्रह से बचा जा सके जो उत्तरदाताओं की विचार प्रक्रिया पर अलग-अलग प्रभाव से उत्पन्न हो सकते हैं।

उपभोग व्यय का उपयोग आय के प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तरदाताओं को पायलट परीक्षण में आय पर

सवालों को दरकिनार करते हुए देखा गया था। हालांकि, मासिक उपभोग व्यय के आंकड़े में स्मरण त्रुटि की समस्या पाई गई । जबकि साप्ताहिक उपभोग व्यय डेटा आमतौर पर स्मरण त्रुटि से मुक्त होता है, इन आंकड़ों को मासिक स्तर पर लाना वैचारिक रूप से अच्छा नहीं है क्योंकि यह एक महीने के हफ्तों में एक समान खपत पैटर्न मानता है। पायलट सर्वेक्षण में, यह देखा गया कि अधिकांश परिवारों ने एक स्थानीय किराने की दुकान (किराना दुकान) से मासिक किराने का सामान खरीदा, और ये वस्तुएं विभिन्न गांवों की दुकानों में एक समान थीं। यह भी देखा गया कि प्रतिभागी विशिष्ट वस्तुओं पर व्यय की जानकारी प्रदान करने की तुलना में अपने मासिक किराने के व्यय का विवरण प्रदान करने के बारे में अधिक आश्वस्त थे। इसलिए, मुख्य सर्वेक्षण में, मासिक किराने के व्यय पर एक प्रश्न अनुमानित उपभोग व्यय में शामिल किया गया था।

उपभोग व्यय पर डेटा के पूरक के लिए, आवास की स्थिति और घरेलू आस्तियों पर जानकारी एकत्र की गई थी। आवास की स्थिति पर डेटा में बेडरूम की संख्या, क्या एक अलग रसोई और रहने / भोजन कक्ष उपलब्ध है, और घर की छत, दीवार और फर्श के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री संबंधी विवरण शामिल था। घरेलू आस्तियों पर डेटा में फ्रिज, टेलीविजन, साइकिल आदि जैसी विभिन्न संपत्तियों के होने के बारे में जानकारी एकत्र की गई। प्रश्नावली में परिवारों की जनसांख्यिकीय और सामाजिक विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी भी एकत्र की गई थी।

उत्तरदाता प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययनों में कई तरीकों से पूर्वाग्रह को प्रेरित कर सकते हैं। बैंकिंग चैनलों के उपयोग पर निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, यह सुनिश्चित किया गया था कि केवल घर के मुख्य वित्तीय निर्णय लेने वाले का साक्षात्कार हो । यदि सर्वेक्षण के समय मुख्य उत्तरदाता उपलब्ध नहीं था, तो एक सदस्य जो घर के सभी प्रमुख वित्तीय निर्णयों से अवगत था, का साक्षात्कार लिया गया था। इसके अलावा, जब कुछ उत्तरदाता सर्वेक्षण में रुचि नहीं रखते हैं और एमसीक्यू में एक विशिष्ट विकल्प का जवाब देने का निर्णय लेते हैं (उदाहरण के लिए, वित्तीय साक्षरता पहलू के बावजूद सभी प्रश्नों के लिए पहला विकल्प या तीसरा विकल्प), तो यह वित्तीय साक्षरता के सही अनुमान (अर्थात या तो कम आंका गया या अत्यधिक) को विकृत करता है। इसका समाधान करने के लिए, सभी एमसीक्यू में यादृच्छिक रूप से सही उत्तर रखे गए थे, ताकि औसत अनुमान प्रभावित न हों। इसके अलावा, प्रतिभागी एमसीक्यू में एक से अधिक उत्तरों का चयन कर सकते थे ताकि उत्तरों का अनुमान लगाने वाले तथा स्पष्ट ज्ञान वाले प्रतिभागियों के बीच अंतर किया जा सके, इस प्रकार, उत्तरदाता-प्रेरित पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता था ।

वित्तीय साक्षरता के सही स्तर का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक वित्तीय पहलू पर सत्यापन प्रश्नों पर एक खंड भी शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए, बुनियादी वित्तीय साक्षरता खंड में, यह प्रश्न किया गया था कि क्या उत्तरदाता को बचत/ चालू खाते के बारे में पता है। सत्यापन खंड में, यह भी पूछा गया कि क्या प्रतिवादी को पता है कि किस प्रकार का खाता (बचत / चालू) ब्याज प्रदान करता है। इन सत्यापन प्रश्नों को अन्य वित्तीय साक्षरता वर्गों में उत्तरों के बावजूद जानबूझकर सर्वेक्षण के अंत में रखा गया था ताकि इन प्रश्नों के निष्पक्ष उत्तर सुनिश्चित किए जा सकें।

IV. अध्ययन क्षेत्र और नमूना चयन

पश्चिम बंगाल से नमूना जिले के चयन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जिलों की साक्षरता दर और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पर जनगणना 2011 से शामिल किया गया था। सबसे पहले, विश्लेषणात्मक सुविधा के लिए, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले की साक्षरता दर और एलएफपीआर को अखिल भारतीय स्तर पर इन दो चरों के औसत और मानक विचलन के औसत का उपयोग करके मानकीकृत किया गया था। इसके बाद, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले के लिए मानकीकृत साक्षरता दर (60 प्रतिशत) और एलएफपीआर (40 प्रतिशत) के भारित अंकगणितीय माध्यों की गणना की गई। अंत में, पश्चिम बंगाल के छह जिलों में से, जिनका भारित माध्य 0±0.2 की सीमा के भीतर था, पश्चिम मेदिनीपुर को सर्वेक्षण संचालन पर विचार करने के बाद चुना गया था।

पश्चिम मेदिनीपुर से ब्लॉकों के चयन के लिए, जिले की औसत साक्षरता दर और एलएफपीआर से प्रत्येक ब्लॉक की दूरी की गणना की गई थी। खड़गपुर II साक्षरता (60 प्रतिशत) और श्रम भागीदारी दर (40 प्रतिशत) के मामले में जिले के

औसत के करीब है। इसके बाद, इन मानदंडों पर खड़गपुर II से अन्य ब्लॉकों की दूरी की गणना की गई। खड़गपुर II के करीब विभिन्न ब्लॉकों में से, सर्वेक्षण संचालन पर विचार करने के बाद गरबेटा II का चयन किया गया था।

खड़गपुर II और गरबेटा II के 2000 से कम आबादी वाले चार-चार गांवों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। इन गांवों से घरों के यादृच्छिक चयन को सुनिश्चित करने के लिए, गांवों में विभिन्न पाराओं (बंगाली में 'घरों का समूह') की पहचान की गई थी। ग्राम-स्तर के पाराओं को अक्सर जाति या समुदाय द्वारा विभेदित किया जाता है। इसलिए, नमूना-प्रेरित पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, नमूना गांवों के प्रत्येक पाराओं से परिवारों का चयन किया गया था। पाराओं के भीतर, परिवारों का यादृच्छिक चयन सुनिश्चित करने के लिए, हर तीसरे घर को नमूने में शामिल किया गया था। यह एक विश्वसनीय ग्राम-स्तरीय घरेलू सूची की अनुपस्थिति में दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में किया गया था जिसे नमूना फ्रेम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आठ गांवों में कुल नमूना आकार 505 घरों का था और सर्वेक्षण सितंबर 2022 के अंतिम दो हफ्तों में संपादित किया गया था।

सर्वेक्षण के लिए पश्चिम बंगाल का चयन करने के लिए प्राथमिक विचार पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बैंकिंग पैठ और सर्वेक्षण संचालन था। यद्यपि नमूना गांव पश्चिम बंगाल के हैं, परिणामों की वैधता केवल राज्य तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, नमूना गांवों की औसत साक्षरता दर 0.70 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 2000 से कम आबादी वाले गांवों की औसत साक्षरता दर 0.57 है। लगभग 2,58,429 गांव ऐसे हैं जो इस औसत साक्षरता दर के ठीक नीचे आते हैं, अर्थात 0.57, और जिनकी औसत साक्षरता दर 0.68 है। इन दाहिनी छोर वाले गांवों का औसत एलएफपीआर 0.46 है, जो नमूना गांवों के 0.44 के करीब है। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता का एक अन्य महत्वपूर्ण सहचर, लिंग अनुपात, इन दाएं-छोर वाले गांवों (0.97) और नमूना गांवों (0.97) के बीच तुलनीय है। इसलिए, आठ यादृच्छिक गांवों पर इस सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर देश के 2.5 लाख से अधिक गांवों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

V. वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सूचकांकों का अनुमान

प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, प्रत्येक सर्वेक्षण प्रतिभागी के लिए वित्तीय साक्षरता सूचकांक की गणना की गई थी। ऐसा करते समय, सभी 'हां' या 'नहीं' (वाई / एन) प्रश्नों में सभी 'हां' वाले उत्तरों को एक अंक प्राप्त हुआ और सभी 'नहीं' उत्तरों को शून्य अंक मिला। 'हां', 'नहीं' और 'पता नहीं' (वाईएनडी) के विकल्पों वाले प्रश्नों में, जबकि सही उत्तर को एक अंक मिला, गलत उत्तर को माइनस एक अंक मिला और 'पता नहीं' को शून्य अंक मिला। इस प्रकार, एक आत्मविश्वास से भरे गलत उत्तर को 'पता नहीं' से अधिक दंडित किया जाता है। एमसीक्यू के लिए, केवल सही उत्तर को एक अंक मिला। यदि गलत उत्तर के साथ सही उत्तर का चयन किया गया था, तो एक अंक पर ऋणात्मक अंकन लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि कुल चार उत्तर विकल्प हैं, तो प्रत्येक गलत उत्तर को 0.25 का ऋणात्मक अंक प्रदान किया गया है, और गलत उत्तर के साथ सही उत्तर के चयन के परिणामस्वरूप एक अंक माइनस 0.25 का अंक और इसी तरह प्रदान किया जाता है। इसने आंशिक ज्ञान को सटीक रूप से मापने को शामिल किया।

इस प्रकार, हाँ/नहीं प्रश्नों पर आधारित सूचकांक शून्य से एक की सीमा में थे, जबकि वाईएनडी (हाँ/नहीं/पता नहीं) और एमसीक्यू पर आधारित सूचकांक माइनस एक से प्लस एक की सीमा में थे। बुनियादी वित्तीय साक्षरता (बीएफएल), डिजिटल वित्तीय साक्षरता (डीएफएल) और शिकायत एस्केलेशन प्रणाली (सीईएम) पर तीन संयुक्त सूचकांकों को तैयार करने के लिए वाईएनडी और एमसीक्यू पर आधारित सूचकांकों को शून्य से एक की सीमा के भीतर सामान्यीकृत किया गया था। प्रत्येक श्रेणी में प्रश्नों के प्रतिशत को इन तीन सूचकांकों (सारणी 1) में भारिता के रूप में उपयोग किया गया था। इसके बाद संयुक्त वित्तीय साक्षरता (सीएफएल) सूचकांक के तीन प्रकारों पर काम किया गया। सीएफएल-एसडी में, विश्व आर्थिक मंच {सारणी 2} के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक की पद्धति का पालन करते हुए, बीएफएल, डीएफएल और सीईएम के उप-सूचकांकों को संयोजित करने के लिए भारिता की गणना के लिए मानक विचलन का उपयोग किया गया था।

सारणी 1: संयुक्त वित्तीय साक्षरता सूचकांक (सीएफएल) के बीएफएल, डीएफएल और सीईएम उप-सूचकांकों का निर्माण - प्रश्न प्रकार के अनुसार

संयुक्त सूचकांक	बुनियादी वित्तीय साक्षरता (बीएफएल)	डिजिटल वित्तीय साक्षरता (डीएफएल)	शिकायत एस्केलेशन प्रणाली (सीईएम)
हाँ /कोई प्रश्न नहीं	0.41	0.40	0.10
हाँ/नहीं/पता नहीं का प्रश्न	0.37	0.55	0.60
बहु विकल्पीय प्रश्न	0.22	0.05	0.30

यह भारिता उच्च मानक विचलन के साथ उप-सूचकांक को कम भारिता प्रदान करेगा। सीएफएल-जीएम में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक की पद्धति का पालन करते हुए, अंतिम संयुक्त सूचकांक पर पहुंचने के लिए तीन उप-सूचकांकों के ज्यामितीय माध्य को लिया गया था। यह विधि अंतिम सूचकांक में तीन उप-सूचकांकों में स्थिरता को कम करती है। सीएफएल-पीसीए में, प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) नियोजित किया गया था और पहले घटक को अंतिम सूचकांक के रूप में लिया गया था। आर्थिक सूचकांक की गणना के लिए, आवास की स्थिति, घरेलू संपत्ति और खपत पैटर्न पर जानकारी को पीसीए का उपयोग करके शामिल किया गया था।

नमूना प्रोफ़ाइल

पश्चिम मेदिनीपुर जिले के आठ गांवों में फैले कुल 505 घरों में कुल नमूना आकार था। अध्ययन का नमूना 39 की औसत आयु और 12.8 के मानक विचलन के साथ अपेक्षाकृत युवा है। नमूने में साक्षरता दर अधिक होने के बावजूद मैट्रिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या कम है। नमूने के दो-तिहाई पुरुष हैं। नमूना विभिन्न जाति समूहों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व रखता है। सभी आर्थिक संकेतक नमूने में परिवारों की कम आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, आवास विशेषताओं के बीच, केवल 38 प्रतिशत के पास एक अलग रसोई है और 21 प्रतिशत के घरों में एक अलग रहने / भोजन हेतु कक्ष है। मासिक किराना व्यय धनात्मक रूप से विषम है, भले ही चार से अधिक सदस्यों वाले परिवारों का वितरण 1,000 रुपये से कम' को छोड़कर व्यय श्रेणियों में तुलनीय है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की खपत की आवृत्ति इंगित करती है कि फलों और माँस जैसे अपेक्षाकृत महंगे खाद्य पदार्थों का सेवन सब्जियों, मछली और अंडे जैसी अन्य वस्तुओं की खपत की आवृत्ति की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत द्वारा किया जाता है, यहां तक कि उन परिवारों के लिए समायोजित करने के बाद भी जो स्थायी रूप से इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को नहीं खाते हैं (अनुबंध I-ए, I-बी और I-सी)।

सारणी 2: सीएफएल-एसडी सूचकांक का निर्माण

	माध्य	मानक विचलन	0.01/मानक विचलन	सूचकांक में प्रदत्त भारिता
बीएफएल	0.53	0.13	0.073	(0.073/0.219) = 0.34
डीएफएल	0.46	0.16	0.062	(0.062/0.219) = 0.28
सीईएम	0.62	0.12	0.083	(0.083/0.219) = 0.38

VI. सर्वेक्षण के निष्कर्ष

नमूना गांवों का वित्तीय साक्षरता परिदृश्य एक मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित करता है। पसंदीदा सीएफएल-एसडी इंडेक्स 0.54 के औसत के साथ वितरित किया जाता है, जिसमें सबसे कम मूल्य 0.31 और उच्चतम मूल्य 0.93 होता है। चूंकि इस सूचकांक में, कम मानक विचलन के साथ उप-सूचकांक को अधिक महत्व दिया जाता है, साक्षरता में सामुदायिक निकटता को अधिक और इसके विपरीत महत्व दिया जाता है। इसलिए, सीईएम को इस सूचकांक में बीएफएल और डीएफएल के बाद सबसे अधिक महत्व मिला। सीएफएल-एसडी में, 364 अवलोकन (72.1 प्रतिशत) औसत के एक मानक विचलन के भीतर आते हैं।

सारणी 3: वर्णनात्मक सांख्यिकी - वित्तीय साक्षरता सूचकांक

चर	अवलोकन	माध्य	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
बीएफएल	505	0.53	0.14	0.22	0.86
डीएफएल	505	0.46	0.16	0.15	1
सीईएम	505	0.62	0.12	0.23	1
सीएफएल_एसडी	**505**	**0.54**	**0.11**	**0.31**	**0.93**
सीएफएल-पीसीए	505	-3.78e-09	1.40	-2.93	4.79
सीएफएल_जीएम	505	0.52	0.12	0.29	0.92

नोट: बीएफएल: बुनियादी वित्तीय साक्षरता सूचकांक; डीएफएल: डिजिटल वित्तीय साक्षरता सूचकांक; सीईएम: धोखाधड़ी और शिकायत वृद्धि तंत्र पर सूचकांक; सीएफएल-एसडी: भार के रूप में मानक विचलन के व्युत्क्रम का उपयोग करते हुए संयुक्त वित्तीय साक्षरता सूचकांक; सीएफएल-पीसीए: प्रधान घटक विश्लेषण से पहले घटक के रूप में संयुक्त वित्तीय साक्षरता सूचकांक; सीएफएल-जीएम: तीन उप-सूचकांकों के ज्यामितीय माध्य के रूप में संयुक्त वित्तीय साक्षरता सूचकांक।

फिर भी, समग्र वित्तीय साक्षरता पूरे नमूने में थोड़ी धनात्मक रूप से तिरछी है, जबकि एक अत्यधिक वित्तीय साक्षर अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक रूप से विषम वितरण की उम्मीद की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य सूचकांकों की तुलना में डीएफएल में धनात्मक तिरछापन अधिक प्रमुख है, जो कम डिजिटल वित्तीय साक्षरता (सारणी 3 और चार्ट 1) को दर्शाता है।

बैंक खातों और पासबुक में नामांकन के बारे में जागरूकता नमूने में बहुत अधिक है, खासकर इस बात पर कि पासबुक का नियमित अद्यतन क्यों महत्वपूर्ण है। चेक, विभिन्न प्रकार के बैंक खातों और ब्याज दरों पर जागरूकता कम देखी जाती है। चालू खातों (17.2 प्रतिशत) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत में उत्तरदाताओं को बचत खातों (51.0 प्रतिशत) के बारे में पता

चार्ट 1: वित्तीय साक्षरता सूचकांकों का वितरण

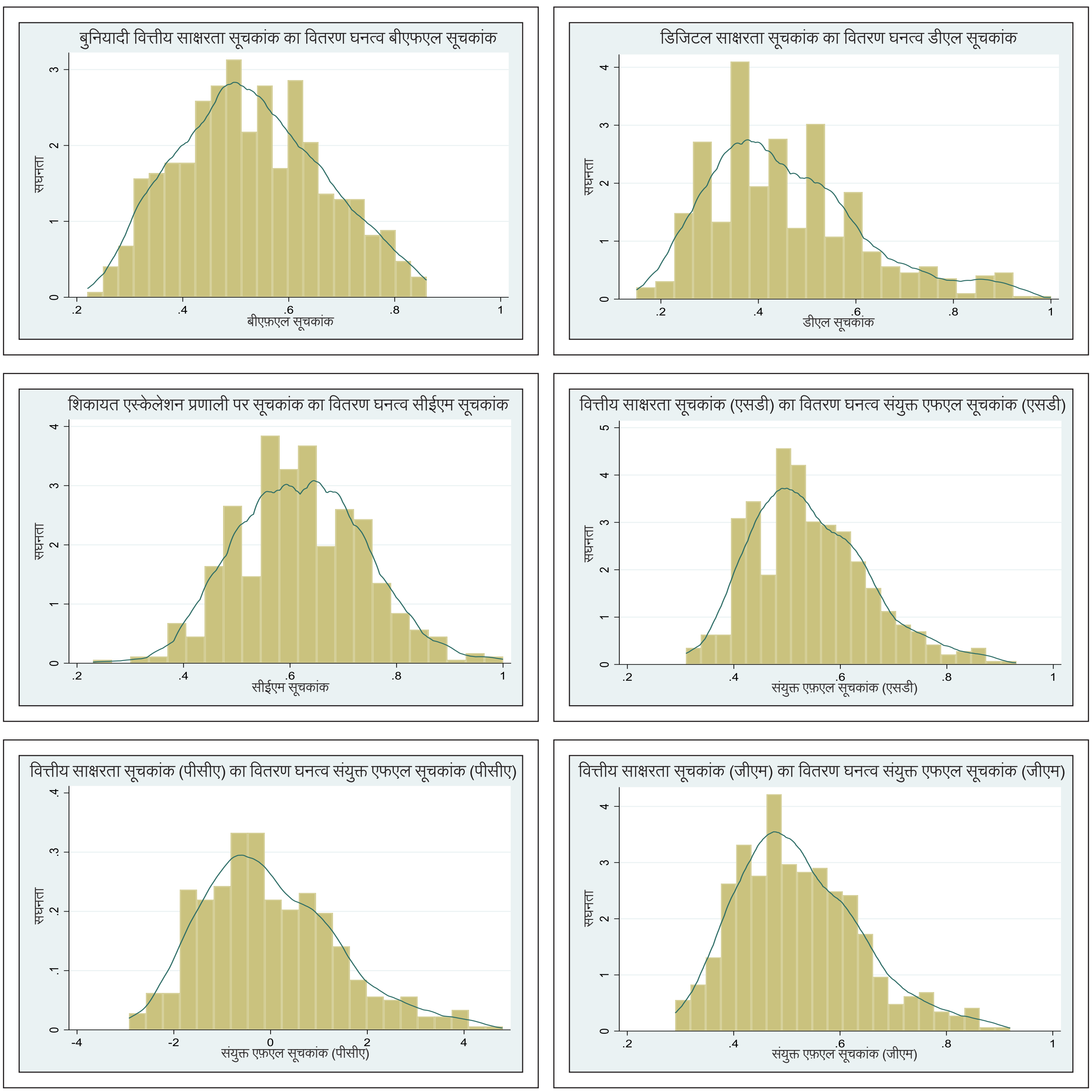

था। 41 प्रतिशत ने बताया कि वे जानते हैं कि ब्याज दर क्या है, हालांकि, केवल 38 प्रतिशत ने जवाब दिया कि जमा पर उच्च ब्याज दर लाभदायक है। जबकि 67 प्रतिशत ने चेक के बारे में सुना था, केवल 26.5 प्रतिशत जवाब दे सके कि 'चेक की समाप्ति तिथि होती है'। जबकि 10 प्रतिशत ने ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना था, उनमें से कोई भी ओवरड्राफ्ट की अवधारणा का सही जवाब नहीं दे सका (अनुबंध II)।

85 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एटीएम/डेबिट कार्ड के बारे में पता था, फिर भी केवल 63 प्रतिशत ने जवाब दिया कि वे एटीएम से सिक्के नहीं निकाल सकते हैं और केवल 34 प्रतिशत यह बता सकते हैं कि एटीएम से पैसे कैसे निकाले जाएं। सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) [28.7 प्रतिशत] की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अधिक लोकप्रिय (73.3 प्रतिशत) है। केवल 10.9 प्रतिशत लोग ही इस बात का जवाब दे सके कि कौन सा कार्ड केसीसी, जीसीसी और डेबिट कार्डों में से पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं देता है। वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के बारे में जागरूकता अपेक्षाकृत कम थी, जिसमें 47 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में सुना था, और केवल 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सही जवाब दिया कि 'आप ओटीपी कहां पा सकते हैं'। अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत उत्तरदाताओं (42.4 प्रतिशत) को पता था कि वे फीचर फोन (15.1 प्रतिशत) का उपयोग करने की तुलना में स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे इंटरनेट बैंकिंग जानते हैं, लेकिन केवल नौ प्रतिशत इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन करने के लिए आवश्यक जानकारी को सही ढंग से बता सकते हैं। जबकि 23 प्रतिशत ने बताया कि वे जानते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आईडी क्या है, जब उनसे पूछा गया कि यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने के लिए चार माध्यमों - आईएफएससी कोड, क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर में से कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो केवल नौ प्रतिशत सही जवाब दे सके (अनुबंध III)।

किसी के बैंक खाते को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए संभावित धोखाधड़ी और शिकायत एस्केलेशन प्रणाली पर साक्षरता आवश्यक है। अधिकांश उत्तरदाताओं को पता था कि उन्हें चेकबुक सौंपने सहित किसी और को अपने बैंक खाते का विवरण नहीं देना है। उत्तरदाताओं को यह भी पता था कि उन्हें बड़े उपहार / लॉटरी / नौकरी की पेशकश करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्राप्त किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हालांकि, मोटे तौर पर 42 प्रतिशत या तो भ्रमित थे या उनका मानना था कि बैंक/आरबीआई वास्तव में उन्हें सीधे फोन कर सकते हैं और बैंक की जानकारी मांग सकते हैं। शिकायत एस्केलेशन की व्यवस्था के बारे में, लगभग 76 प्रतिशत ने आत्मविश्वास से कहा कि यदि वे अपने बैंक खाते / एटीएम से पैसे खो देते हैं, तो उन्हें तुरंत अपनी बैंक शाखा को सूचित करना चाहिए, जबकि 25 प्रतिशत ने कहा कि शाखा को सूचित करने के साथ, वे पुलिस को भी सूचित करेंगे। हालांकि, केवल 23.5 प्रतिशत को पता था कि अगर बैंक तुरंत उनकी मदद नहीं कर रहा है तो वे बैंकिंग लोकपाल/लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, अधिकांश ने बताया कि बैंकिंग लोकपाल बैंक शाखा (अनुबंध IV) में उपलब्ध है।

VII. वित्तीय साक्षरता - महत्वपूर्ण सहचर

मौजूदा साहित्य के अनुरूप, प्रमुख सामाजिक-जनसांख्यिकीय-आर्थिक और वित्तीय चर को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है। मानक इकाई अंतराल (0,1) के भीतर परिणाम चर (सीएफएल सूचकांक) की सीमाबद्ध और निरंतर प्रकृति को देखते हुए, बीटा प्रतिगमन मॉडल (फेरारी और क्रिबरी-नेटो, 2004) को जनसांख्यिकीय विशेषताओं और वित्तीय साक्षरता स्तरों (मॉडल 1) के बीच संबंध का अनुभव पूर्वक अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन मामलों में, बीटा प्रतिगमन को साधारण न्यूनतम वर्गों (ओएलएस) से बेहतर माना जाता है क्योंकि उत्तरार्द्ध त्रुटियों की समविसरिता मानता है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसे सूचकांकों (स्कोर) की परिवर्तनशीलता जैसे-जैसे औसत सीमा तक पहुंचता है (किशनिक और मैककोलो, 2003) वह कम हो जाती है, जिससे पक्षपाती और सीमा से परे की भविष्यवाणियां होती हैं। मजबूती जांच के लिए, सीएफएल सूचकांक के दो अन्य रूपों को मॉडल किया जाता है, जैसा कि खंड V में विस्तार स बताया गया है, बीएफएल, डीएफएल और सीईएम उप-सूचकांकों पर (ए) ज्यामितीय माध्य (मॉडल 2) और (बी) प्रमुख घटक विश्लेषण (मॉडल 3) का उपयोग करके गणना

सारणी 4: शून्य-क्रम सहसंबंध मैट्रिक्स

चर	आयु	एचएच आकार	शिक्षा	पेशा	स्मार्टफोन	इको इंडेक्स
आयु	1.00					
एचएच आकार	-0.05	1.00				
शिक्षा	-0.22	0.05	1.00			
पेशा	-0.44	-0.04	0.22	1.00		
स्मार्टफोन	-0.45	0.09	0.42	0.27	1.00	
इको इंडेक्स	0.01	0.08	0.25	0.07	0.23	1.00

नोट: एचएच आकार - घरेलू आकार और इको इंडेक्स - आर्थिक सूचकांक

की जाती है। चूंकि पीसीए का उपयोग करके निर्मित सूचकांक (0,1) बाधा का उल्लंघन करता है, इसलिए इस मॉडल का अनुमान लगाने के लिए ओएलएस प्रतिगमन का उपयोग किया जाता है। समविसरिता के लिए, मॉडलों में मजबूत मानक त्रुटियों का उपयोग किया जाता है। सभी चर के साथ शून्य-क्रम सहसंबंध मैट्रिक्स सारणी 4 में प्रदान किया गया है।

वित्तीय साक्षरता का स्तर आबादी की सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल (जू और ज़िया, 2012) से काफी भिन्न होता है। परिणाम बताते हैं कि उच्च शिक्षा बेहतर वित्तीय साक्षरता से जुड़ी है (सारणी 5)। एक व्यवसाय के रूप में खेती की तुलना में, गृहिणी वित्तीय रूप से अपेक्षाकृत कम साक्षर हैं। नमूने में वित्तीय जागरूकता के साथ उम्र नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है, जो यह इंगित करता है कि युवा पीढ़ी वित्तीय अवधारणाओं से अधिक अच्छी तरह से परिचित है। आर्थिक मोर्चे पर, परिवार में बेहतर वित्तीय सुरक्षा वित्तीय साक्षरता के उच्च स्तर से जुड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि स्मार्टफोन साक्षरता के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरता है, जो यह दर्शाता है कि इंटरनेट-सक्षम हैंडसेट तक पहुंच वित्तीय ज्ञान में सुधार के लिए रास्ते खोल सकती है। परिवार का आकार वित्तीय साक्षरता अंक को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। ये निष्कर्ष मॉडल प्रकार और कार्यप्रणाली से परे शेष मॉडलों में विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार, ये परिणामों की मजबूती को मान्य करते हैं (सारणी 5)।

सारणी 5: वित्तीय साक्षरता के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों के लिए प्रतिगमन परिणाम

	(1) मॉडल 1	(2) मॉडल 2	(3) मॉडल 3
निर्भर चर	सीएफएल_ एसडी	सीएफएल_ जीएम	सीएफएल_ पीसीए
विधि	बीटा प्रतिगमन	बीटा प्रतिगमन	ओएलएस
आयु	-0.004*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.001*** (0.001)
पेशा			
श्रमिक	-0.061** (0.032)	-0.057* (0.034)	-0.018 (0.011)
स्व-रोजगार	0.040 (0.040)	0.058 (0.042)	0.021 (0.014)
वेतनभोगी वर्ग	0.098* (0.062)	0.113* (0.064)	0.037 (0.023)
गृहिणी	-0.111** (0.044)	-0.131*** (0.048)	-0.045*** (0.016)
बेरोजगार	-0.051 (0.045)	-0.056 (0.049)	-0.019 (0.017)
शिक्षा का स्तर	0.062*** (0.009)	0.068*** (0.009)	0.023*** (0.003)
आर्थिक सूचकांक^	0.062*** (0.009)	0.064*** (0.011)	0.023*** (0.003)
परिवार का आकार	0.009 (0.009)	0.009 (0.009)	0.003 (0.003)
स्मार्टफोन	0.085*** (0.031)	0.088*** (0.032)	0.029** (0.011)
अवरोधन	-0.341*** (0.072)	-0.398*** (0.075)	0.487*** (0.026)
अवलोकनों की संख्या	504	504	504
बीआईसी	-960.59	-913.32	-931.01
एआईसी	-1015.48	-968.21	-981.68
छद्म संभावना लॉग	520.74	497.11	-
वाल्ड ची-स्क्वायर (11)	326.18***	354.24***	-

नोट: (ए) कोष्ठक में सार्थकता स्तरों के साथ मजबूत मानक त्रुटियां: * पी <10 प्रतिशत, ** पी <5 प्रतिशत, और *** पी <1 प्रतिशत।

(बी) व्यवसाय के लिए संदर्भ श्रेणियां: खेती; स्मार्टफोन के लिए: कोई पहुंच नहीं।

(सी) शिक्षा का स्तर है -पैमाना 1 (कभी स्कूल नहीं गया और पढ़-लिख नहीं सकता), 2 (कभी स्कूल नहीं गया लेकिन पढ़-लिख सकता है), 3 (प्राथमिक), 4 (मैट्रिकुलेशन), 5 (उच्च माध्यमिक), 6 (डिप्लोमा पाठ्यक्रम), 7 (स्नातक), और 8 (स्नातकोत्तर)।

(डी) ^ आर्थिक सूचकांक का निर्माण तीन उप-सूचकांकों पर प्रधान घटक विश्लेषण (पीसीए) का उपयोग करके किया जाता है – आस्ति स्वामित्व, उपभोग व्यय, और आवास सुविधाएं।

(ई) मॉडल 1 और 2 के लिए मॉडल चयन मानदंड बताते हैं कि उपयुक्त लिंक फंक्शन न्यूनतम बायेसियन सूचना मानदंड (बीआईसी) के साथ पूरक लॉग-लॉग (सीलॉगलॉग) है।

VIII. निष्कर्ष

यह अध्ययन ग्रामीण पश्चिम बंगाल में वित्तीय साक्षरता की सीमा का एक झलक प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता का जायजा लेना अंतराल को प्रकट करने और एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाने में फायदेमंद होगा। यह देखते हुए कि चयनित नमूना 2.5 लाख से अधिक गांवों (साक्षरता के संदर्भ में) का प्रतिनिधित्व करता है, अध्ययन के निष्कर्ष सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए मौजूदा नीतियों को ठीक करने में उपयोगी हो सकते हैं। तथापि, इस अध्ययन से एफएलपी की प्रभावशीलता का पता नहीं चलता है क्योंकि नमूना गांवों को कोई साक्षरता कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ था।

एक विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग करते हुए जिसमें बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं / उत्पादों / संस्थानों, डिजिटल पहलुओं और शिकायत एस्केलेशन प्रणाली पर प्रश्न शामिल थे, यह पाया गया है कि नमूने में वित्तीय साक्षरता सूचकांक (सीएफएल) का वितरण एक बेहतर ऋणात्मक विषम वितरण की तुलना में थोड़ा धनात्मक रूप से विषम है। जबकि बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को यथोचित रूप से समझा जाता है, डिजिटल पहलुओं, शिकायत एस्केलेशन प्रणाली और समग्र रूप से, व्यापक वित्तीय ज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने की गुंजाइश है। यह डीएफएल की तुलना में अपेक्षाकृत सामान्य रूप से वितरित बीएफएल में स्पष्ट है। बीटा प्रतिगमन और रैखिक मॉडल का उपयोग करके अनुभवजन्य विश्लेषण वित्तीय साक्षरता के जनसांख्यिकीय संवाहकों को मान्य करता है और दिखाता है कि एफएलपी ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध आयु समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ सीमित शैक्षिक योग्यता और कम आय स्तर वाले व्यक्तियों को लक्षित करने से वे लाभान्वित हो सकते हैं। आगे चलकर, एफएलपी के अंतर्गत विभिन्न जनसांख्यिकीय क्षेत्रों और वित्तीय पहलुओं को शामिल करने के क्षैतिज विस्तार के साथ, विस्तृत वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना भी आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय साक्षरता को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

Agarwal, S., Driscoll, J. C., Gabaix, X., & Laibson, D. (2009). The age of reason: Financial decisions over the life cycle and implications for regulation. *Brookings papers on Economic Activity*, (2), 51-117.

Singla, A., & Mallik, G. (2021). Determinants of financial literacy: Empirical evidence from micro and small enterprises in India. *Asia Pacific Management Review*, *26*(4), 248-255.

Australian Securities and Investments Commission. (2011). Financial literacy and behavioural change. Research Report 230, Australian Securities and Investments Commission, Sydney. Retrieved from https://www.moneysmart.gov.au

Banks, J., o'Dea, C., & Oldfield, Z. (2010). Cognitive function, numeracy and retirement saving trajectories. *The Economic Journal*, *120*(548), F381-F410.

Beckmann, E. (2013). Financial literacy and household savings in Romania. *Numeracy*, *6*(2), 9.

Behrman, J. R., Mitchell, O. S., Soo, C. K., & Bravo, D. (2012). How financial literacy affects household wealth accumulation. *American Economic Review*, *102*(3), 300-304.

Carpena, F., Cole, S. A., Shapiro, J., & Zia, B. (2011). Unpacking the causal chain of financial literacy. *World Bank Policy Research Working Paper*, (5798).

Carpena, F., Cole, S., Shapiro, J., & Zia, B. (2015). The ABCs of financial education.

Choudhary, K., & Kamboj, S. (2017). A study of financial literacy and its determinants: Evidence from India. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, *10*(1), 52-72.

Das, Shaktikanta (2020), 'National Strategy on Financial Education 2020-25', RBI Bulletin, January.

Das, Shaktikanta (2021), 'Financial Inclusion – Past, Present and Future', RBI Bulletin, August.

Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and

downstream financial behaviors. *Management Science*, *60*(8), 1861-1883.

Ferrari, S., & Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. *Journal of applied statistics*, *31*(7), 799-815.

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of consumer affairs*, *44*(2), 296-316.

Kieschnick, R., & McCullough, B. D. (2003). Regression analysis of variates observed on (0, 1): percentages, proportions and fractions. *Statistical modelling*, *3* (3), 193-213.

Klapper, L., & Panos, G. A. (2011). Financial literacy and retirement planning: the Russian case. *Journal of Pension Economics & Finance*, *10*(4), 599-618.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). *Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing* (No. w17078). National Bureau of Economic Research.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of economic literature*, *52*(1), 5-44.

Morgan, P. J., & Trinh, L. Q. (2019). Determinants and impacts of financial literacy in Cambodia and Viet Nam. *Journal of Risk and Financial Management*, *12*(1), 19.

OECD. (2012). High-level Principles on National Strategy for Financial Education.

RBI (2021). National Strategy for Financial Education: 2020-2025

Xu, L., & Zia, B. (2012). Financial literacy around the world: an overview of the evidence with practical suggestions for the way forward. *World Bank Policy Research Working Paper*, (6107).

Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation. *Journal of Financial Economics*, *101*(2), 449-472.

अनुलग्नक I-ए: सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताएं

(प्रतिशत)

शिक्षा	अशिक्षित	साक्षर और प्राथमिक स्तर तक	माध्यमिक/मैट्रिकुलेशन (10वीं)	उच्च माध्यमिक	स्नातक/ स्नातकोत्तर
	5.9	32.3	35.5	15.1	10.3
लिंग	महिला	नर			
	33.3	66.7			
धर्म	हिंदू	उत्तर देना पसंद नहीं	अन्य		
	96.4	3.2	0.4		
जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आम	
	26.9	16.4	14.1	41.6	

अनुलग्नक I-बी: आवास की स्थिति

(प्रतिशत)

बेडरूम की संख्या	एक (35.8)	दो (44.4)	तीन (12.3)	तीन से अधिक (7.5)
अलग रसोई	हाँ (38.4)	नहीं (61.6)		
अलग बैठक/भोजन कक्ष	हाँ (21.0)	नहीं (79.0)		

अनुलग्नक I-सी: उपभोग पैटर्न

(प्रतिशत)

	₹1,000/- से कम	₹1,001/- से ₹2,000/-	₹2,001/- से रु. 3,000/-	₹3,001/- से अधिक	
मासिक किराने का खर्च	20.2	42.6	17.0	20.2	
4 से अधिक सदस्यों वाले एचएच का प्रतिशत	32.4	39.1	39.5	42.2	
	किसान	गृहिणी	अनौपचारिक श्रमिक	वेतनभोगी	
पेशा	37.4	22.2	13.3	5.9	
उपभोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	दैनिक	सप्ताह में दो से तीन बार	सप्ताह में एक बार	हम इसे नहीं खाते	सर्वेक्षण से ठीक पहले के सप्ताह में नहीं खाया
फल	4.2	23.0	12.9	5.0	55.5
केक, मिठाई	2.8	17.6	15.6	5.9	58.0
मुर्गा	0.8	14.5	35.5	2.6	46.7
मांस	0.2	1.4	5.2	13.9	79.4
सब्जियाँ	91.3	8.7	-	-	-
मछली	11.7	46.9	29.5	1.0	10.9
अंडे	6.5	36.8	30.5	3.4	22.8
दूध	30.9	19.2	6.7	10.7	32.5

अनुबंध II: बुनियादी वित्तीय साक्षरता

प्रश्न	उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने सही उत्तर दिया
दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की घटना के मामले में, आपके बैंक खाते में पैसा किसे मिलेगा? (नामित/बैंक/आरबीआई)	92.3
आपको पासबुक को नियमित रूप से अपडेट क्यों करना चाहिए?	85
क्या आपने पासबुक के बारे में सुना है?	85.2
क्या आपने चेक के बारे में सुना है?	67.3
क्या आप जानते हैं बचत खाता क्या है?	51.0
क्या आपने ब्याज दरों के बारे में सुना है?	40.8
क्या आपने चालू खाते के बारे में सुना है?	17.2
क्या आपने ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना है?	10.1
क्या आप जानते हैं कि बैंकों को आपको लोन देने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं?	4.9
क्या आप जानते हैं वित्तीय डायरी क्या है?	2.6
सत्यापन प्रश्न	
जमा पर अधिक ब्याज दर रखना फायदेमंद है ?	38.0
क्या चेक की कोई समाप्ति तिथि होती है?	26.5
वित्तीय डायरियाँ किसके लिए उपयोग की जाती हैं? (आय/व्यय/दोनों/बैंकिंग लेनदेन रिकॉर्ड करना)	4.2
क्या आप अपने बचत खाते में कुल जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकते हैं?	0.8

अनुबंध III: डिजिटल वित्तीय साक्षरता

प्रश्न	उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने सही उत्तर दिया
क्या आपने एटीएम/डेबिट कार्ड के बारे में सुना है?	84.6
क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है?	73.3
क्या आपने वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) के बारे में सुना है?	47.1
क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन कर सकते हैं?	42.4
क्या आपने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में सुना है?	35.5
क्या आपने सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (केसीसी नहीं) के बारे में सुना है?	28.7
क्या आपने यूपीआई आईडी के बारे में सुना है?	23.0
क्या आप जानते हैं कि आप अपने फीचर फोन का उपयोग करके अपने बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन कर सकते हैं?	15.1
सत्यापन प्रश्न	
क्या आप एटीएम से सिक्के निकाल सकते हैं?	63.0
क्या आप यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने के लिए यू-ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं?	47.7
आप वन टाइम पासवर्ड/ओटीपी कहां पा सकते हैं/प्राप्त कर सकते हैं? (डेबिट कार्ड, पासबुक, एसएमएस के पीछे)	35.1
आपको अपने एटीएम से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? (डेबिट कार्ड, पासबुक, पिन)	33.9
इनमें से कौन सा कार्ड (केसीसी/जीसीसी/डेबिट) आपको पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं देता है?	10.9
इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? (पासबुक, ओटीपी, ग्राहक आईडी, पासवर्ड, आधार कार्ड)	9.3
यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ? (आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी)	9.1

अनुबंध IV: धोखाधड़ी और शिकायत वृद्धि तंत्र पर साक्षरता

प्रश्न	उत्तरदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने सही उत्तर दिया
क्या आपको सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पासबुक किसी और को सौंपना चाहिए?	98.1
क्या आपको चेकबुक किसी और को सौंपनी चाहिए?	97.7
क्या आप किसी के साथ ओटीपी साझा करने पर भरोसा करते हैं?	96.2
क्या आप डेबिट कार्ड या पिन साझा करने के लिए अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य पर भरोसा करते हैं?	89.5
क्या आपने कभी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक किया है जो आपको एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े उपहार/लॉटरी/नौकरी की पेशकश की पेशकश करता है?	83.0
क्या आपको लगता है कि आपका बैंक सीधे आपको कॉल करके आपके बैंक खाते का विवरण मांग सकता है?	58.8
क्या आपको लगता है कि आरबीआई सीधे आपको कॉल करके आपके बैंक खाते का विवरण मांग सकता है?	58.6
यदि आपके बैंक खाते से पैसे खो जाएं तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए?	53.7
यदि एटीएम/बैंक खाते से पैसे खोने की स्थिति में बैंक आपकी तुरंत मदद नहीं कर रहा है, तो अगला कदम क्या है?	23.5
यदि आपके बैंक खाते से पैसे खो जाएं तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? (आंशिक ज्ञान वाले लोग)	22.3
आप बैंकिंग लोकपाल से कैसे संपर्क कर सकते हैं? (वह बैंक शाखा, टेलीफोन, पत्र/ईमेल/ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है)	11.5

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	121
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	122
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	123
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	124
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	125
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	125
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	126
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	127
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	128
9	कुल चलनिधि राशियां	128
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	129
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	129
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	130
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	130
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	131
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	132
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	133
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	134
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	135
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	135
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	135
21	थोक मूल्य सूचकांक	136
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	140
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	140
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	141
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	141
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	142
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	143
28	वाणिज्यिक पत्र	143
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	143
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	144

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	145
32	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां	145
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	145
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	146
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	146
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	147
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	148
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	149
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	150
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	151
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	152
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	153
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	154
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	156
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	157
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	158
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	159
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	160
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	161
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	162
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	165

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2022-23	2021-22		2022-23	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	9.3	4.7	5.5	4.6
1.1.1 कृषि	3.3	4.8	2.3	2.4	3.7
1.1.2 उद्योग	1.7	7.3	2.2	-2.3	0.3
1.1.3 सेवाएं	9.3	11.0	6.5	9.0	6.5
1.1ए अंतिम खपत व्यय	6.4	13.9	10.2	7.0	1.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	11.2	12.4	1.2	9.7	8.3

	2022-23	2022		2023	
		फर.	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.1	1.2	2.2	5.8	1.1
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	9.6	8.6	8.9	10.1	9.6
2.1.2 ऋण #	15.0	9.1	9.6	15.5	15.0
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण #	15.4	9.2	9.7	15.9	15.4
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	14.5	4.7	6.0	14.3	14.5
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	6.0	13.9	13.0	10.5	6.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.0	8.7	8.8	9.5	9.0
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	4.6	4.7	5.0	5.0
3.4 ऋण-जमा अनुपात	75.8	71.8	72.2	75.3	75.8
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात #	113.0	72.1	77.2	111.6	113.0
3.6 निवेश-जमा अनुपात	30.0	28.8	28.7	29.9	30.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	43.5	18.8	19.7	43.6	43.5
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.50	4.00	4.00	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	6.25	-	-	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.75	4.25	4.25	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	4.25	4.25	6.75	6.75
4.6 आधार दर	8.65/10.10	7.25/8.80	7.25/8.80	8.65/9.40	8.65/10.10
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.50/8.50	6.45/7.00	6.45/7.00	7.50/8.40	7.50/8.50
4.8 मीयादी जमा दर>1 वर्ष	6.00/7.25	5.00/5.60	5.00/5.60	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.78	3.30	3.34	6.62	6.78
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	-	3.70	3.84	6.82	-
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	7.28	4.19	4.27	7.18	7.28
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	7.31	4.52	4.58	7.26	7.31
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.31	6.78	6.86	7.43	7.31
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.22	75.28	76.18	82.74	82.22
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.61	84.38	84.01	87.70	89.61
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	2.41	4.30	5.67	2.10	2.41
3-माह (%)	2.19	4.41	4.46	2.56	2.19
6-माह (%)	2.31	4.20	4.10	2.30	2.31
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.7	6.1	7.0	6.4	5.7
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.1	5.0	5.4	6.2	5.8
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	9.6	13.4	14.6	3.9	1.3
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.3	13.9	15.9	3.6	2.4
6.3.2 ईंधन और पावर	29.4	30.8	31.8	14.0	9.0
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	5.7	10.2	11.3	1.9	-0.8
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	16.5	37.2	29.0	-4.9	-4.9
7.2 निर्यात	6.7	34.5	26.4	-0.4	-7.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2022-23	2022	2023				
		अप्रै.	मार्च 24	अप्रै. 7	अप्रै. 14	अप्रै. 21	अप्रै. 28
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3350412	3182321	3350412	3386555	3407973	3425118	3424801
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	13	13	13	13	13	12	15
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3350425**	**3182334**	**3350425**	**3386568**	**3407985**	**3425130**	**3424816**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	142136	123547	142136	144914	143223	143580	141580
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3207988	3058380	3207988	3241401	3264343	3281176	3282897
1.2.3 रुपया सिक्का	300	407	300	254	419	374	339
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1340653	1654833	1340653	1349531	1288282	1165283	1219180
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	101	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	43	43	42	43	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	809907	740234	809907	804493	842162	838212	890423
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7332	7650	7332	9089	7087	7273	7730
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4615	4156	4615	4982	5081	4777	4687
2.1.1.7 अन्य बैंक	45939	38403	45939	46406	47433	47317	48248
2.1.1.8 अन्य	379890	804385	379890	388818	293869	175307	200029
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	92826	59862	92826	95599	92507	92252	67920
2.1.2 अन्य देयताएं	1627193	1237355	1627193	1628168	1620781	1613011	1600038
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**2967845**	**2892188**	**2967845**	**2977699**	**2909063**	**2778293**	**2819218**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	13	13	13	13	13	13	15
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1023426	1040173	1023426	998865	991751	970129	995491
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	122394	114380	3145	4666
2.2.3.2 राज्य सरकारें	7625	4380	7625	11506	10259	3146	4538
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	165085	94306	165085	74997	31402	36550	73004
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	23010	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	18368	6498	18368	18987	17830	19728	19937
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	93236	59307	93236	95475	92071	91343	67357
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1407585	1464756	1407585	1414863	1413433	1415640	1418112
2.2.6 अन्य आस्तियां	252508	199745	252508	240599	237925	238598	236098
2.2.6.1 स्वर्ण	232981	194425	232981	237533	234762	235347	232068

*: डेटा अनंतिम है।

शुक्रवार, 31 मार्च 2023 के आंकड़े मई 2023 में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई के तुलन पत्र के हिस्से के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मार्च 1, 2023	-	-	-	-	3419	156869	-4897	-	-	-158347
मार्च 2, 2023	-	-	-	-	590	168206	-708	-	-	-168324
मार्च 3, 2023	-	-	-	-	597	147494	-	-	-	-146897
मार्च 4, 2023	-	-	-	-	5	44081	-	-	-	-44076
मार्च 5, 2023	-	-	-	-	20	8518	-	-	-	-8498
मार्च 6, 2023	-	-	-	-	632	139898	4150	-	-	-135116
मार्च 7, 2023	-	-	-	-	2933	23389	-	-	-	-20456
मार्च 8, 2023	-	-	-	-	1204	116209	-	-	-	-115005
मार्च 9, 2023	-	-	-	-	620	141408	165	-	-	-140623
मार्च 10, 2023	-	-	82650	-	1453	190802	-	-	-	-106699
मार्च 11, 2023	-	-	-	-	351	4712	-	-	-	-4361
मार्च 12, 2023	-	-	-	-	21	3574	-	-	-	-3553
मार्च 13, 2023	-	-	-	-	434	189447	-	-	-	-189013
मार्च 14, 2023	-	-	-	-	477	220883	–	-	-	-220406
मार्च 15, 2023	-	-	-	-	730	136008	245	-	-	-135033
मार्च 16, 2023	-	-	-	-	8664	83383	417	-	-	-74302
मार्च 17, 2023	-	-	-	-	3811	66641	1514	20	-	-61336
मार्च 18, 2023	-	-	-	-	799	24196	–	-	-	-23397
मार्च 19, 2023	-	-	-	-	47	6449	–	-	-	-6402
मार्च 20, 2023	-	-	-	-	505	108146	7	-	-	-107634
मार्च 21, 2023	-	-	-	-	5699	79416	-	-	-	-73717
मार्च 22, 2023	-	-	-	-	2634	39122	-	-	-	-36488
मार्च 23, 2023	-	-	-	-	519	142307	-14	-	-	-141802
मार्च 24, 2023	-	-	55885	-	28388	97952	-494	-	-	-14173
मार्च 25, 2023	-	-	-	-	527	9570	-	-	-	-9043
मार्च 26, 2023	-	-	-	-	146	3180	-	-	-	-3034
मार्च 27, 2023	-	-	-	-	900	103238	456	-	-	-101882
मार्च 28, 2023	-	-	-	-	623	162609	490	-	-	-161496
मार्च 29, 2023	-	-	-	-	23489	154737	1188	-	-	-130060
मार्च 30, 2023	-	-	-	-	9147	78265	-	-	-	-69118
मार्च 31, 2023	-	-	-	-	31995	233723	3900	-	-	-197828

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/ विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2021-22	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	-20101	254	750
1.1 क्रय (+)	113991	4315	4381	6906
1.2 विक्रय (-)	96679	24416	4127	6156
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	134629	-153010	1134	5883
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	17312	-26266	-25516
(₹ करोड़)	134629	134629	-223142	-217259
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	65791	20470	23600

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2021-22	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	570	0	0
1.2 विक्रय (-)	2370	570	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 मार्च 2023 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	4368	700	3668
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3545	0	3545
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	17633	1246	16387
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**25546**	**1946**	**23600**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2022-23	2022			2023			
		अप्रै. 22	नवं. 18	दिसं. 30	जन. 27	फर. 24	मार्च 24	अप्रै. 21
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	28388	140	3250	33224	27370	15233	28388	16945
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त	-							
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा	-							
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	2442	0	1801	2376	1675	2107	2442	3719
4. अन्य	-							
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	15900	31021	10850	15400	7500	8350	15900	15900
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	46730	31161	15901	51000	36545	25690	46730	36564

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार उपाय

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	3037622	3231824	3258093	3278334
1.1 संचलन में नोट	3105703	3107637	3301475	3343411	3350365
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	27270	29264	29264	29264
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	98028	99788	115461	102085
2 जनता की जमाराशियां	2271436	2265371	2356710	2323113	2385928
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	2212992	2292581	2258851	2320598
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	52379	64129	64262	65330
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**5302993**	**5588534**	**5581206**	**5664261**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	188433	188433	199087	200257	200257
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5495558**	**5491426**	**5787621**	**5781463**	**5864518**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	15186605	16513885	16642515	16668966
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**20489597**	**22102418**	**22223721**	**22333227**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1012241	1012241	1105137	1113230	1113230
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21505970**	**21501838**	**23207555**	**23336951**	**23446457**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**6204211**	**6854246**	**6979996**	**6916058**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1177178	1216525	1291301	1201651
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1490166	1407652	1396846	1413446
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1489496	1398137	1396111	1405821
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	670	9515	736	7625
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	312988	191127	105546	211795
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	312946	191085	105503	211752
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	43	43	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	5027033	5637721	5688696	5714407
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**12610042**	**14188368**	**14293532**	**14423483**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	16571	10092	12529	18719	20396
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	12599950	14175838	14274813	14403087
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	11891314	13450269	13548593	13675235
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	690201	708230	708673	710187
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	18435	17340	17546	17665
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4963083**	**4731899**	**4685656**	**4862273**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4551499	4476306	4430063	4606680
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4551740	4476568	4430325	4606942
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	241	262	262	262
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	411583	255593	255593	255593
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**28013**	**30007**	**30007**	**30007**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3315752**	**3702101**	**3765470**	**3898594**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1346960	1496402	1450510	1612360
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1968792	2205699	2314960	2286234
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**20489597**	**22102418**	**22223721**	**22333227**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	5302993	5588318	5581206	5664261
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	12076917	12947497	12998755	13092880
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	20630753	22408995	22515989	22617633
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	3037622	3231607	3258093	3278334
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	17266157	18646314	18742295	18828640
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	2212992	2292581	2258851	2320598
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	15053166	16353733	16483444	16508042
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6773925	7359180	7417550	7428619
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	176718	282944	288600	304088
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	8279241	8994553	9065894	9079423
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	52379	64129	64262	65330
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	274594	466945	451340	445329
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	19802620	22163277	22389278	22455037
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6204211	6854246	6979996	6916058
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1177178	1216525	1291301	1201651
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	5027033	5637721	5688696	5714407
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	13598408	15309031	15409282	15538979
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	39581	35020	12529	18719	20396
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	13563389	15296502	15390562	15518583
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	952181	1097846	1095365	1096267
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	28013	29791	30007	30007
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4814211	4607135	4554744	4721610
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4551499	4476306	4430063	4606680
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	262711	130829	124681	114930
2.4 पूंजी खाता	3021858	3112135	3487014	3488851	3507224
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	901956	904194	969188	1081797

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(₹ करोड़)

समुच्चय	2022-23	2022	2023		
		मार्च	जन.	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**22617633**	**20630753**	**22199020**	**22408995**	**22617633**
2 डाकघर जमाराशियां	651847	596588	651847	651847	651847
3 एल$_1$ (1 + 2)	**23269480**	**21227341**	**22850867**	**23060842**	**23269480**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	54724	49578	70232	49679	54724
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1692	1824	1133	1229	1692
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46407	39170	61870	41920	46407
4.3 सावधि जमाराशियां	6625	8584	7229	6530	6625
5 एल$_2$ (3 + 4)	**23324204**	**21276919**	**22921098**	**23110522**	**23324204**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	78061	70564	..	..	78061
7 एल$_3$ (5 + 6)	**23402265**	**21347483**	..	..	**23402265**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	3135649	3331396	3373554	3380418
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	732270	854816	868195	867793
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	683437	797986	810703	809907
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	52379	64129	64262	65330
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3920298	4250341	4306011	4313542
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	906895	687746	1240647	1296451	1289215
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1177178	1216525	1291301	1201651
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1176550	1207052	1290607	1194069
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1488978	1397648	1395732	1405521
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1488978	1397648	1395732	1405521
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	518	489	379	300
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	312946	191085	105503	211752
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	1624	628	9472	693	7582
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-583282	-524452	11593	-13569	67168
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-499524	11593	-13569	67168
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	39581	35020	12529	18719	20396
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	2107	767	2442
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	24927	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	28013	29791	30007	30007
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4551499	4476306	4430063	4606680
2.3.1 सोना	322213	329562	345484	343961	375117
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4221955	4130840	4086120	4231580
2.4 पूंजी खाता	1254092	1344369	1547974	1488064	1566088
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	2592	-51572	-37554	46272

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2022	2023				
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3920298	4250557	4305663	4306011	4331106	4313542
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	3135649	3331612	3345755	3373554	3372295	3380418
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	732270	854816	895594	868195	892921	867793
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	52379	64129	64314	64262	65890	65330
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1177178	1216525	1322880	1291301	1165442	1201651
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-499524	11593	-66072	-13569	112619	67168
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	10092	12529	14441	18719	20933	20396
2.4 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4551499	4476306	4446769	4430063	4562255	4606680
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	28013	30007	30007	30007	30007	30007
2.6 आरबीआई की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1346960	1496402	1442362	1450510	1560149	1612360

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2022-23	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	17882990	16331874	17701702	17799252	17882990
1.1.1 मांग जमाराशियां	2180431	2072747	2150731	2119152	2180431
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15702560	14259128	15550972	15680099	15702560
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	7066152	6416607	6997937	7056045	7066152
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	304088	176718	282944	288600	304088
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8636408	7842520	8553034	8624055	8636408
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	445329	274594	466945	451340	445329
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20197180	17575002	19899791	20042147	20197180
2.1.1 सरकार को ऋण	5414322	4728179	5336711	5385657	5414322
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14782858	12846823	14563080	14656490	14782858
2.1.2.1 बैंक ऋण	13675235	11891314	13450269	13548593	13675235
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13655330	11836304	13414992	13520315	13655330
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	19491	11522	23081	20648	19491
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	826	769	847	847	826
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1087305	943218	1088883	1086402	1087305
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	114930	262711	130829	124681	114930
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	353850	465464	357705	357758	353850
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	160923	133439	160152	159072	160923
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	77997	69314	66724	74005	77997
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	833002	1268887	874539	927918	833002
2.3.1 आरबीआई के पास शेष	809907	683437	797986	810703	809907
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90263	85926	88146	103646	90263
2.3.3 आरबीआई से ऋण और अग्रिम	67168	-499524	11593	-13569	67168
2.4 पूंजी खाता	1916966	1743595	1914869	1976616	1916966
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	899827	756537	821643	867538	899827
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	711654	571535	696225	734097	711654
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	44733	26533	44850	64765	44733

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	24 मार्च 2023 की स्थिति	2022	2023		
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	5415148	4728948	5337558	5386504	5415148
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	182265	-	182650	183012	182265
3 वाणिज्यिक पत्र	65058	55315	56361	60661	65058
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	9736	7642	9827	9763	9736
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	71099	73814	70826	70857	71099
4.3 अन्य	4500	5152	4783	4782	4500
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सरकारी उद्यम	92304	117860	90873	89398	92304
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	325040	326188	325654	324074	325040
5.3 अन्य	99409	148753	101399	101525	99409
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	48810	34404	56553	53458	48810
6.2 वित्तीय संस्थाएं	189085	174090	189957	188871	189085

'-' डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2022-23	2022	2023		2022-23	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचनां देने वाले बैंकों की संख्या	212	212	212	212	137	136	137	137
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**355252**	**262674**	**348005**	**355252**	**351843**	**258649**	**344778**	**351843**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	228517	194143	219565	228517	226119	190570	217311	226119
1.2 बैंकों से उधार राशि	67566	38369	68709	67566	67199	38317	68361	67199
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	59170	30162	59731	59170	58524	29762	59106	58524
2 अन्य के प्रति देयताएं	**19730120**	**17832517**	**19536672**	**19730120**	**19278894**	**17380755**	**19091309**	**19278894**
2.1 कुल जमाराशियां	18477283	16899634	18290021	18477283	18043914	16465313	17861854	18043914
2.1.1 मांग	2225373	2117513	2197095	2225373	2180431	2072747	2150731	2180431
2.1.2 मीयादी	16251910	14782121	16092927	16251910	15863483	14392567	15711123	15863483
2.2 उधार	449945	278985	471322	449945	445329	274594	466506	445329
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	802891	653898	775329	802891	789651	640848	762949	789651
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**165085**	**94299**	**109026**	**165085**	**165085**	**94299**	**109026**	**165085**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	165085	94299	109026	165085	165085	94299	109026	165085
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	920953	788725	915676	920953	900170	769363	895219	900170
4.1 उपलब्ध नकदी	92788	88732	99578	92788	90263	85926	97233	90263
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	828165	699993	816098	828165	809907	683437	797986	809907
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**397874**	**315282**	**388389**	**397874**	**326601**	**243637**	**323009**	**326601**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	232028	199434	234472	232028	193422	164240	195668	193422
5.1.1 चालू खाते में	18589	19733	30231	18589	15528	16691	27045	15528
5.1.2 अन्य खातों में	213440	179701	204241	213440	177894	147549	168623	177894
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	50013	36905	39007	50013	24864	6982	20448	24864
5.3 बैंकों को अग्रिम	45330	39340	44408	45330	41184	35802	39919	41184
5.4 अन्य आस्तियां	70503	39603	70501	70503	67130	36613	66974	67130
6 निवेश	**5560674**	**4874070**	**5483663**	**5560674**	**5415148**	**4728948**	**5337558**	**5415148**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	5553712	4867102	5477026	5553712	5414322	4728179	5336711	5414322
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6963	6968	6637	6963	826	769	847	826
7 बैंक ऋण	**14078360**	**12259048**	**13852868**	**14078360**	**13675235**	**11891314**	**13450269**	**13675235**
7ए खाद्यान्न ऋण	65622	90827	80994	65622	19906	55011	35276	19906
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	13824791	12016486	13611145	13824791	13424906	11651337	13212088	13424906
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	39446	36070	37032	39446	39435	36055	37020	39435
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	165428	155796	159300	165428	162910	154212	156351	162910
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19758	19537	17307	19758	19545	19157	17161	19545
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	28936	31160	28085	28936	28439	30554	27649	28439

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2022	2023		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 24	2022-23	2023
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**11891314**	**13450269**	**13675228**	**15.0**	**15.0**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**55011**	**35276**	**19906**	**-63.8**	**-63.8**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**11836304**	**13414993**	**13655322**	**15.4**	**15.4**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**1461719**	**1461719**	**1655938**	**1687191**	**15.4**	**15.4**
2. उद्योग	**3156067**	**3156067**	**3291205**	**3336722**	**5.7**	**5.7**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	532792	532792	587494	598390	12.3	12.3
2.2 मध्यम	213996	213996	234858	256023	19.6	19.6
2.3 बड़े	2409279	2409279	2468853	2482310	3.0	3.0
3. सेवाएं	**3011975**	**3011975**	**3523813**	**3608574**	**19.8**	**19.8**
3.1 परिवहन परिचालक	155352	155352	168735	176239	13.4	13.4
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	20899	20621	21559	3.2	3.2
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64378	64378	65234	66466	3.2	3.2
3.4 शिपिंग	8436	8436	6881	6677	-20.8	-20.8
3.5 नौवहन	23979	23979	27819	28330	18.1	18.1
3.6 पेशेवर सेवाएं	116742	116742	131443	134661	15.3	15.3
3.7 व्यापार	696301	696301	798032	819921	17.8	17.8
3.7.1 थोक व्यापार	351213	351213	389231	396631	12.9	12.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	345088	345088	408801	423291	22.7	22.7
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	291168	291168	312809	314579	8.0	8.0
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[1] जिसमें से	1022399	1022399	1309521	1331097	30.2	30.2
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	282048	282048	307870	314678	11.6	11.6
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	137084	137084	178651	175614	28.1	28.1
3.10 अन्य सेवाएं [2]	612320	612320	682720	709044	15.8	15.8
4 वैयक्तिक ऋण	**3386982**	**3386982**	**4013299**	**4085168**	**20.6**	**20.6**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27628	27628	37011	37323	35.1	35.1
4.2 आवास	1684424	1684424	1910531	1936428	15.0	15.0
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	83379	83379	113457	121897	46.2	46.2
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6261	6261	6937	6778	8.3	8.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	148416	148416	186856	194282	30.9	30.9
4.6 शिक्षा	82723	82723	96164	96847	17.1	17.1
4.7 वाहन ऋण	402689	402689	495922	502780	24.9	24.9
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	73960	73960	87822	88428	19.6	19.6
4.9 अन्य वैयक्तिक ऋण	877503	877503	1078599	1100404	25.4	25.4
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
(i) कृषि और संबद्ध गतिविधियां [3]	1484923	1484923	1686333	1708951	15.1	15.1
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम [4]	1377848	1377848	1562145	1570295	14.0	14.0
(iii) मध्यम उद्यम [5]	351900	351900	390714	399008	13.4	13.4
(iv) आवास	616814	616814	619039	621376	0.7	0.7
(v) शिक्षा ऋण	58118	58118	59362	58634	0.9	0.9
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	3842	3842	4642	4656	21.2	21.2
(vii) सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	2483	2449	2464	-0.8	-0.8
(viii) निर्यात ऋण	24177	24177	14396	15696	-35.1	-35.1
(ix) अन्य	37159	37159	50056	59659	60.5	60.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	1180928	1428627	1441513	22.1	22.1

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, के आधार पर है। जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल खाद्येतर ऋण के लगभग 93 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और वृद्धि दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: दिसंबर 2021 से चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंकों की ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
2. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
3. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
4. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
5. 'मध्यम उद्यमों' में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25 2022	2022	2023		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 25	फर. 24	मार्च 24	2022-23	2023
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3156067	3156067	3291205	3336722	5.7	5.7
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49135	49135	57348	58812	19.7	19.7
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173246	173246	177739	182878	5.6	5.6
2.2.1 चीनी	26307	26307	21171	22867	–13.1	–13.1
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	18246	19005	19737	8.2	8.2
2.2.3 चाय	5728	5728	5005	5162	–9.9	–9.9
2.2.4 अन्य	122965	122965	132558	135112	9.9	9.9
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	18176	22098	23362	28.5	28.5
2.4 वस्त्र	224026	224026	222372	227843	1.7	1.7
2.4.1 सूती वस्त्र	90384	90384	88073	91095	0.8	0.8
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	3509	4046	3867	10.2	10.2
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38371	38371	39624	40354	5.2	5.2
2.4.4 अन्य वस्त्र	91761	91761	90628	92527	0.8	0.8
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11573	11573	11480	11675	0.9	0.9
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16294	16294	19204	19963	22.5	22.5
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40565	40565	42608	43010	6.0	6.0
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107333	107333	146052	149363	39.2	39.2
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196363	196363	213080	216481	10.2	10.2
2.9.1 उवर्रक	33160	33160	33656	33805	1.9	1.9
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	61093	66686	67130	9.9	9.9
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	19622	20467	20661	5.3	5.3
2.9.4 अन्य	82486	82486	92271	94885	15.0	15.0
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	72013	72013	77492	79037	9.8	9.8
2.11 कांच और कांच के सामान	5952	5952	7934	8100	36.1	36.1
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47910	47910	54884	56592	18.1	18.1
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288531	288531	336959	343507	19.1	19.1
2.13.1 लोहा और स्टील	187584	187584	228316	228860	22.0	22.0
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100946	100946	108643	114646	13.6	13.6
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167966	167966	173395	175260	4.3	4.3
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38179	38179	41136	41781	9.4	9.4
2.14.2 अन्य	129787	129787	132260	133479	2.8	2.8
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89896	89896	97942	96603	7.5	7.5
2.16 रत्न और आभूषण	80512	80512	75547	77718	–3.5	–3.5
2.17 निर्माण	117724	117724	120428	122880	4.4	4.4
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1195027	1195027	1178969	1186248	–0.7	–0.7
2.18.1 पॉवर	611410	611410	604072	604691	–1.1	–1.1
2.18.2 दूरसंचार	130318	130318	111184	111334	–14.6	–14.6
2.18.3 सड़क	270395	270395	280012	284793	5.3	5.3
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	6646	9181	9492	42.8	42.8
2.18.5 बंदरगाह	8886	8886	8209	8175	–8.0	–8.0
2.18.6 रेलवे	10512	10512	10936	11169	6.3	6.3
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156860	156860	155376	156593	–0.2	–0.2
2.19 अन्य उद्योग	253823	253823	255674	257391	1.4	1.4

टिप्पणी : जनवरी 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2021-22	2022				2023			
		फर. 25	दिसं. 02	दिसं. 16	दिसं. 30	जन. 13	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	33	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**126746.8**	**126531.5**	**127292.9**	**128339.4**	**130835.1**	**132887.9**	**133539.0**	**134672.6**	**135950.9**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23533.1**	**24733.8**	**25574.4**	**26161.0**	**28819.3**	**27185.8**	**26514.9**	**26882.2**	**28527.7**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4281.2	5237.4	5822.7	5522.9	5201.5	6029.5	5760.8	5776.8	5720.7
2.1.1.2 अन्य	14,413.7	13918.4	14281.6	14807.4	15609.5	15866.7	15381.7	15061.6	17432.4
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	499.9	544.7	624.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4838.2	5078.1	4925.4	5206.1	7958.3	5289.6	5372.4	6043.8	5374.5
2.2 मीयादी देयताएं	**181808.1**	**177613.0**	**171447.3**	**172012.1**	**174159.8**	**175067.2**	**176298.1**	**177254.6**	**175896.3**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	66572.3	61880.2	54278.4	54295.2	55395.7	55338.6	55159.9	55278.0	54797.7
2.2.1.2 अन्य	112333.1	112613.1	113011.3	113532.1	115225.6	117021.2	118157.3	119611.0	118518.4
2.2.2 बैंकों से उधार	899.9	859.4	1715.3	1734.4	1074.3	1764.1	2032.1	1374.0	1604.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2002.7	2260.3	2442.3	2450.5	2464.2	943.3	948.7	991.5	976.1
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	58868.2	64466.5	74853.3	74975.2	79539.1	131532.1	78164.1	78883.6	77988.7
4.1 मांग	12625.5	12992.3	15914.2	15783.7	17875.0	17952.8	17966.9	16829.0	16530.5
4.2 मीयादी	46242.7	51474.2	58939.1	59191.5	61664.2	113579.2	60197.2	62054.5	61458.3
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8371.5**	**9228.6**	**10547.0**	**10820.3**	**11342.1**	**11647.2**	**11360.2**	**10954.8**	**10769.8**
5.1 उपलब्ध नकदी	602.2	743.8	846.0	856.4	893.9	1224.4	732.3	862.4	797.2
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7769.3	8484.8	9701.0	9963.9	10448.2	10422.8	10627.9	10092.4	9972.6
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**894.4**	**1310.3**	**1561.1**	**1555.0**	**1676.2**	**1641.3**	**1850.1**	**1788.9**	**2038.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**66350.1**	**71262.5**	**72326.1**	**72684.3**	**72306.1**	**72808.5**	**72775.3**	**72507.4**	**72892.1**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**25325.3**	**24875.8**	**17284.9**	**17449.4**	**23466.4**	**20920.3**	**21666.8**	**21894.1**	**21601.9**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**117228.4**	**111718.8**	**120965.0**	**121585.0**	**121588.2**	**122782.6**	**123897.1**	**123643.3**	**123225.6**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**117209.2**	**111698.2**	**120925.5**	**121543.5**	**121546.4**	**122742.4**	**123866.2**	**123616.7**	**123202.0**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	87632.4	106973.7	117687.7	118828.7	122854.5	124378.1	125739.6	128547.9	128522.2
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.2	20.6	39.5	41.5	41.7	40.3	30.9	26.6	23.6

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2022-23			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अप्रै'22	मार्च'23	अप्रै'23(अ)	अप्रै'22	मार्च'23	अप्रै'23(अ)	अप्रै'22	मार्च'23	अप्रै'23(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**173.9**	**179.7**	**176.0**	**168.6**	**174.8**	**175.5**	**174.5**	**180.8**	**182.2**	**170.8**	**177.0**	**178.0**
1.1 अनाज और उत्पाद	163.3	165.3	164.0	151.8	174.3	173.3	155.4	174.7	174.8	152.9	174.4	173.8
1.2 मांस और मछली	208.7	215.2	211.0	209.7	205.2	206.8	215.8	212.2	213.7	211.8	207.7	209.2
1.3 अंडा	174.7	177.1	175.6	164.5	173.9	167.9	164.6	177.2	172.4	164.5	175.2	169.6
1.4 दूध और उत्पाद	170.1	170.7	170.3	163.8	177.0	178.2	164.2	177.9	178.7	163.9	177.3	178.4
1.5 तेल और चर्बी	197.0	181.1	191.2	207.4	183.3	178.5	186.0	172.2	168.8	199.5	179.2	174.9
1.6 फल	164.1	169.6	166.7	169.7	167.2	173.6	175.9	172.1	179.2	172.6	169.5	176.2
1.7 सब्जी	160.8	198.7	173.6	153.6	140.9	142.7	190.7	175.9	180.1	166.2	152.8	155.4
1.8 दाल और उत्पाद	168.1	168.2	168.2	165.1	170.5	172.8	164.0	172.2	174.7	164.7	171.1	173.4
1.9 चीनी और उत्पाद	119.9	122.2	120.7	118.2	119.1	120.4	120.5	121.9	123.1	119.0	120.0	121.3
1.10 मसाले	199.4	193.5	197.5	182.9	212.1	215.4	178.0	204.8	207.8	181.3	209.7	212.9
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	175.4	161.3	169.6	172.4	177.6	178.3	157.5	164.9	165.5	166.2	172.3	173.0
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	185.1	190.4	187.6	178.9	189.9	190.5	183.3	196.6	197.0	180.9	193.0	193.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**195.0**	**199.9**	**196.3**	**192.8**	**198.4**	**199.5**	**197.1**	**202.7**	**203.5**	**193.9**	**199.5**	**200.6**
3 कपड़ा और जूते	**184.5**	**172.9**	**179.9**	**177.1**	**189.6**	**190.2**	**166.3**	**178.2**	**178.9**	**172.8**	**185.1**	**185.7**
3.1 कपड़ा	184.8	175.0	180.9	177.5	190.0	190.6	168.4	180.2	180.9	173.9	186.1	186.8
3.2 जूते	182.7	161.4	173.9	175.1	187.0	187.4	154.5	167.0	167.7	166.5	178.7	179.2
4 आवास	--	**170.0**	**170.0**	--	--	--	**167.0**	**173.5**	**175.2**	**167.0**	**173.5**	**175.2**
5 ईंधन और लाइट	**179.7**	**178.4**	**179.2**	**173.3**	**181.4**	**181.5**	**170.5**	**182.6**	**181.9**	**172.2**	**181.9**	**181.7**
6 विविध	**173.8**	**166.5**	**170.3**	**170.2**	**177.9**	**178.9**	**163.1**	**170.0**	**170.9**	**166.8**	**174.1**	**175.0**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	173.7	165.1	169.6	167.7	178.6	179.1	159.8	169.2	169.6	164.0	174.2	174.6
6.2 स्वास्थ्य	181.3	174.6	178.7	177.0	186.6	187.2	169.0	180.8	181.5	174.0	184.4	185.0
6.3 परिवहन और संचार	167.3	158.8	162.8	166.2	169.0	169.4	159.3	159.8	160.1	162.6	164.2	164.5
6.4 मनोरंजन	170.0	165.8	167.6	167.2	172.8	173.2	162.2	168.4	168.7	164.4	170.3	170.7
6.5 शिक्षा	175.6	169.7	172.2	170.9	178.5	179.5	164.0	172.5	174.2	166.9	175.0	176.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	173.2	173.4	173.3	169.0	180.7	183.8	168.4	181.5	184.4	168.8	181.0	184.0
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**175.8**	**173.5**	**174.7**	**170.8**	**178.0**	**178.8**	**169.2**	**176.3**	**177.4**	**170.1**	**177.2**	**178.1**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2022-23	2022	2023	
				मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	131.1	126	132.7	133.3
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1148	1098	1171	1175
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1160	1109	1182	1186

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	51750	56646	57514
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	68286	66402	66520

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2022-23	2022	2023			
			अप्रै.	जन.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
	1	2	3	4	5	6	7
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**152.2**	**152.3**	**150.7**	**150.9**	**150.9**	**150.9**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**176.9**	**174.5**	**174.3**	**173.6**	**175.0**	**177.3**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**179.4**	**175.3**	**176.6**	**176.9**	**178.9**	**181.5**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	178.5	171.2	187.0	185.4	183.0	183.6
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	200.9	198.0	171.2	173.0	180.9	192.0
1.1.1.3 दूध	4.440	167.3	163.3	172.9	174.1	175.3	174.9
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	170.9	169.6	170.0	169.8	171.9	170.9
1.1.1.5 मसाले	0.529	187.2	173.8	195.7	191.8	192.9	197.7
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	178.1	178.4	180.8	182.3	183.3	184.3
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**172.2**	**177.5**	**173.7**	**170.2**	**166.9**	**165.8**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	203.4	216.1	185.0	182.6	181.0	180.7
1.1.2.2 तिलहन	1.115	205.2	227.2	201.6	199.5	192.5	191.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	131.3	127.3	137.6	135.0	134.3	135.5
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	257.6	230.8	321.8	297.7	281.7	252.1
1.1.3 खनिज	**0.833**	**206.2**	**208.2**	**202.3**	**217.5**	**217.5**	**222.5**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	196.6	204.0	185.9	206.1	206.1	212.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	240.1	222.9	259.7	257.2	257.3	256.7
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**158.5**	**152.5**	**151.4**	**143.2**	**149.8**	**155.0**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**157.2**	**151.2**	**155.6**	**157.6**	**156.8**	**152.6**
1.2.1 कोल	**2.138**	**132.8**	**130.9**	**134.3**	**135.6**	**135.4**	**135.1**
1.2.1.1 कोकिंग कोल	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कोकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	257.6	212.6	294.3	324.4	320.3	312.6
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**170.4**	**167.9**	**160.9**	**165.5**	**165.1**	**159.6**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**139.9**	**122.2**	**156.7**	**152.4**	**149.9**	**146.6**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**142.5**	**144.7**	**141.4**	**141.6**	**141.2**	**141.2**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**165.3**	**169.9**	**163.1**	**161.9**	**160.8**	**160.3**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	143.6	143.3	142.8	142.7	143.7	146.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	145.2	147.4	141.7	144.4	142.4	139.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	125.6	123.6	126.9	126.8	125.7	127.4
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	182.8	210.7	166.1	162.9	159.3	156.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	166.2	159.4	171.9	174.7	174.9	175.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	161.5	151.4	171.0	168.8	168.4	166.1
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	158.3	156.6	159.2	157.3	157.8	156.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	162.5	155.0	166.0	166.3	166.4	165.0
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	126.7	125.4	127.1	127.1	126.7	129.1
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	136.1	134.5	137.4	138.0	137.3	137.2
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	156.5	160.6	154.6	153.7	154.4	150.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	177.7	178.7	166.7	165.2	169.0	181.0
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	176.1	168.8	181.1	178.1	180.2	180.1
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	140.9	142.6	141.2	141.3	141.1	141.9
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	173.8	181.0	181.1	178.7	179.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	209.2	213.7	209.6	207.8	207.2	207.3
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**128.9**	**127.7**	**129.8**	**130.3**	**130.4**	**130.9**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	129.4	126.2	130.9	132.0	132.0	132.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	134.6	133.6	134.4	134.5	134.4	134.2
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	123.5	125.0	124.3	124.4	124.7	125.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**164.9**	**164.6**	**165.9**	**166.5**	**166.7**	**168.7**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	164.9	164.6	165.9	166.5	166.7	168.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2022-23	2022	2023			
			अप्रै.	जन.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
	1	2	3	4	5	6	7
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**142.8**	**145.8**	**137.1**	**137.2**	**136.8**	**137.4**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	133.3	140.6	123.8	123.8	123.0	123.4
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	159.0	155.8	158.7	159.3	159.5	160.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	130.2	133.1	124.2	123.0	123.8	122.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	153.3	149.2	152.4	152.9	153.4	153.3
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	156.8	166.3	149.4	147.4	145.1	145.3
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	132.4	133.9	129.2	130.4	127.8	129.4
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**148.6**	**146.5**	**149.1**	**149.7**	**150.0**	**149.8**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर बुने हुए तैयार वस्त्र	0.593	147.1	145.3	147.9	148.4	148.4	148.9
1.3.5.2 बुने हुए और क्रौशे वस्त्र	0.221	152.4	149.7	152.3	153.2	154.2	152.4
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**122.4**	**121.0**	**121.2**	**122.2**	**123.1**	**122.3**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	106.1	106.7	102.2	106.4	107.9	104.2
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.4	142.5	140.4	140.1	140.7	141.7
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	125.1	122.3	125.2	125.1	125.7	125.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**144.1**	**146.0**	**143.1**	**142.6**	**143.2**	**143.1**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.5	134.9	138.6	137.7	138.5	138.8
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	143.1	147.7	141.2	140.7	141.3	141.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	204.1	201.5	203.2	203.2	204.6	204.6
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	137.4	134.1	137.6	137.6	137.9	138.0
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**151.7**	**153.7**	**148.3**	**148.0**	**147.0**	**146.6**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	157.8	156.9	157.3	157.2	156.2	155.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	147.9	150.0	145.1	143.1	143.1	141.4
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	145.8	152.5	137.1	138.2	136.5	137.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**171.1**	**167.6**	**180.7**	**180.4**	**177.6**	**178.6**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	171.1	167.6	180.7	180.4	177.6	178.6
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**145.2**	**145.7**	**143.3**	**142.8**	**142.3**	**140.9**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	159.2	162.7	152.5	150.7	150.1	148.3
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	143.6	137.6	147.4	146.7	145.4	144.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	143.5	153.5	138.0	140.4	139.1	137.2
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	143.2	142.3	141.6	140.7	141.0	137.6
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	144.8	141.6	146.3	145.5	146.1	145.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	140.4	136.0	141.6	141.3	141.3	140.7
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	142.2	142.9	139.8	138.3	138.9	137.6
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	110.8	115.8	105.4	106.3	106.2	107.1
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**140.8**	**139.6**	**142.2**	**142.4**	**141.8**	**142.5**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	140.8	139.6	142.2	142.4	141.8	142.5
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**129.6**	**131.7**	**128.6**	**128.7**	**128.2**	**128.4**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	111.7	107.2	113.8	113.7	113.1	114.2
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	106.5	105.7	105.8	106.3	106.1	106.2
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	141.8	147.3	139.3	139.4	138.9	138.8
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**133.6**	**130.5**	**135.3**	**135.3**	**134.7**	**134.9**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	158.3	150.9	165.3	164.0	163.4	163.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.0	118.9	118.7	118.8	118.5	119.3
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	135.3	135.5	132.9	130.0	129.2	133.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	118.0	116.2	118.7	119.2	119.4	120.1
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	136.9	133.4	138.9	138.9	138.0	137.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2022-23	2022	2023			
			अप्रै.	जन.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
	1	2	3	4	5	6	7
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	134.4	132.7	134.3	135.6	135.6	137.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	125.7	122.6	126.3	126.0	127.0	127.3
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	105.8	104.9	107.4	108.4	106.3	105.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**148.7**	**161.2**	**145.5**	**146.9**	**146.3**	**145.4**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	159.9	181.9	150.9	154.6	153.1	151.7
1.3.14.2 धात्विक लौह	0.653	164.1	178.4	158.9	160.8	158.0	157.6
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	127.1	134.5	124.9	124.8	125.8	123.3
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	149.7	159.1	148.3	148.4	147.6	145.7
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	155.2	179.1	144.1	150.5	150.9	150.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	147.4	156.8	145.8	144.8	144.9	144.4
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	151.9	173.1	148.6	146.8	144.8	146.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	174.2	183.1	175.3	175.2	174.3	172.5
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	146.1	156.2	146.6	147.7	147.8	147.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	129.9	125.7	134.7	133.8	132.5	133.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	172.3	166.9	173.8	175.7	175.5	172.9
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**139.0**	**138.8**	**137.9**	**139.1**	**139.3**	**138.7**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.6	131.1	131.8	131.5	131.8	131.4
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	161.3	168.5	155.4	159.7	160.6	160.9
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	99.9	97.0	103.7	102.4	103.7	101.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	135.5	129.4	136.7	138.3	137.8	138.2
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	112.1	112.2	110.8	110.6	110.6	110.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	144.9	143.7	145.9	146.9	146.5	144.6
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**116.8**	**116.4**	**117.1**	**116.8**	**116.8**	**117.5**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	0.402	115.5	113.2	115.4	114.8	114.7	114.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	134.8	135.0	135.1	135.1	135.1
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	129.5	128.2	129.8	130.5	130.5	130.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	99.9	101.0	100.6	99.5	99.9	102.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेटिंग और नियंत्रण उपकरण	0.181	112.8	112.3	113.0	113.0	113.0	113.0
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घड़ी	0.076	151.3	149.3	151.5	151.9	150.0	151.1
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	109.2	109.9	108.9	109.1	108.9	106.8
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	100.4	99.6	100.3	100.3	100.3	103.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**128.5**	**127.4**	**130.1**	**129.9**	**129.9**	**130.1**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	126.0	123.3	129.0	127.3	127.2	127.6
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	131.8	129.4	131.6	131.6	132.4	133.4
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	115.6	105.3	119.9	122.9	119.6	119.7
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	146.2	153.3	146.4	149.0	148.3	148.8
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	117.1	116.2	117.0	116.9	117.4	116.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.9	133.3	133.8	133.2	133.9	133.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	117.4	114.3	118.9	120.0	120.8	121.2
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**126.0**	**124.3**	**127.0**	**127.7**	**127.7**	**128.4**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	126.5	125.4	126.4	128.0	127.3	128.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	128.1	125.5	129.9	130.3	131.4	133.0
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	117.4	117.6	117.5	117.7	117.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	123.7	121.1	125.7	126.6	127.1	128.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	79.7	78.5	82.3	81.5	80.9	80.2
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	126.2	125.4	127.2	128.0	128.2	127.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2022-23	2022	2023			
			अप्रै.	जन.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
	1	2	3	4	5	6	7
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	142.9	143.6	144.2	145.7	143.1	144.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	136.9	133.5	139.4	139.4	140.0	140.8
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	120.2	118.1	121.2	121.6	122.5	122.5
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	84.4	80.3	86.1	86.6	86.7	86.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	127.9	131.0	124.7	124.6	124.7	124.4
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	130.1	127.9	131.1	130.9	132.3	136.0
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	140.3	136.6	142.1	143.6	143.7	144.0
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	69.0	67.8	69.7	69.7	70.2	71.1
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**127.6**	**126.1**	**127.1**	**127.1**	**127.6**	**127.9**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	126.2	124.6	125.7	125.8	126.5	126.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुर्जे और सहायक उपकरण	2.368	129.2	127.8	128.7	128.6	128.9	129.1
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**137.1**	**134.5**	**138.8**	**139.6**	**140.2**	**142.0**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	162.5	159.1	163.6	163.6	163.6	163.6
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	105.4	103.7	108.4	106.5	106.5	104.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	137.2	134.4	139.1	140.3	141.1	143.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	139.8	139.4	138.9	138.5	138.6	137.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	151.7	145.5	157.1	155.8	155.9	155.8
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**157.5**	**155.2**	**157.9**	**158.2**	**158.6**	**160.5**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	157.5	155.2	157.9	158.2	158.6	160.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**147.4**	**147.5**	**151.1**	**153.8**	**154.0**	**159.5**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	146.1	146.0	150.2	153.1	153.3	159.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	186.6	184.4	185.6	200.4	201.4	193.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	150.2	146.6	153.0	152.4	152.7	154.7
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	158.8	158.6	158.7	158.5	158.2	159.4
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	170.4	176.4	167.2	166.7	166.3	166.3
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**174.1**	**173.3**	**171.5**	**171.3**	**172.1**	**173.6**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल-फरवरी		फरवरी	
				2021-22	2022-23	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	130.0	137.1	131.4	138.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	110.4	116.7	123.3	129.0
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	129.7	136.0	129.9	136.8
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	168.2	185.0	160.8	174.0
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	127.3	137.4	130.8	139.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	86.6	98.2	94.5	104.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	142.7	148.1	143.7	143.2
2.4 इंफ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	146.3	158.1	152.0	164.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.84	101.2	113.8	112.4	114.1	112.9	108.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	15.33	142.1	146.7	146.4	147.6	137.6	154.3

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23ः केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-फरवरी			
	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	संशोधित अनुमान के लिए प्रतिशत	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2348413**	**1980828**	**1791017**	**84.3**	**86.2**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2086662	1732193	1480886	83.0	83.9
1.2 करेतर राजस्व	261751	248635	310131	95.0	98.8
2 गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**83500**	**58900**	**36263**	**70.5**	**36.3**
2.1 ऋण की वसूली	23500	20229	22749	86.1	103.5
2.2 अन्य प्राप्तियां	60000	38671	13514	64.5	17.3
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2431913**	**2039728**	**1827280**	**83.9**	**83.9**
जिसमें से:	3458959	2903363	2658694	83.9	83.9
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	798957	671951	84.9	82.6
5 पूंजी व्यय	728274	590227	485181	81.0	80.5
6 कुल व्यय (4+5)	**4187232**	**3493590**	**3143875**	**83.4**	**83.4**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1110546**	**922535**	**867677**	**83.1**	**79.7**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1755319**	**1453862**	**1316595**	**82.8**	**82.7**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**814668**	**654905**	**644644**	**80.4**	**82.9**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2023-24।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2022	2023					
		अप्रै 1	फर 24	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24	मार्च 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	5384	16434	14936	14615	14376	12487	8724
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	20191	22121	20225	23562	24607	20869	20071
1.3 राज्य सरकारें	31320	47800	27121	27121	21921	12921	10738	8038
1.4 अन्य	72109	66123	87550	89626	86505	87018	89874	80452
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	76931	69416	69592	68385	72055	68739	67606
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	67992	63459	68172	79963	89786	93275	97274
2.3 राज्य सरकारें	15763	16763	7568	5587	5587	4587	3592	2592
2.4 अन्य	69259	72166	88604	92897	93799	95806	104230	109742
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	107791	96616	98836	99974	102400	99495	105646
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	172480	158712	155411	144424	152898	143712	146080
3.3 राज्य सरकारें	22836	22836	46233	44008	48172	48221	48221	48284
3.4 अन्य	118392	120479	151423	149681	157330	147088	158273	148827
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	207675	239122	206769	307118	317286	319035	212758
4.4 अन्य	659	194	1678	1153	1004	1075	426	926
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	796938	835256	836094	844238	851764	853504	843335

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि ₹ करोड़ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
मार्च 1	9000	99	25388	1683	46	8817	1683	10500	98.30	6.9391
मार्च 8	9000	124	35578	1080	38	8920	1080	10000	98.29	6.9677
मार्च 15	9000	137	47238	2252	25	8948	2252	11200	98.32	6.8573
मार्च 23	9000	128	34801	1686	21	8831	1686	10517	98.35	6.7366
मार्च 29	9000	164	45950	881	0	0	0	0	–	–
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
मार्च 1	16000	250	45472	174	105	15954	174	16128	96.49	7.2999
मार्च 8	16000	179	40722	21	77	15979	21	16000	96.45	7.3787
मार्च 15	16000	166	40270	56	77	15944	56	16000	96.50	7.2695
मार्च 23	16000	186	58580	182	72	15963	182	16145	96.52	7.2282
मार्च 29	16000	162	50558	36	49	15964	36	16000	96.50	7.2820
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
मार्च 1	14000	188	33838	101	100	13975	101	14076	93.14	7.3901
मार्च 8	14000	243	35525	4183	126	13980	4183	18163	93.06	7.4800
मार्च 15	14000	273	60015	72	48	13977	72	14050	93.21	7.3067
मार्च 23	14000	202	53493	20	35	13980	20	14000	93.27	7.2382
मार्च 29	14000	144	35745	82	44	13980	82	14062	93.21	7.3064

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
मार्च	1, 2023	4.60-6.40	6.36
मार्च	2, 2023	4.60-6.80	6.34
मार्च	3, 2023	4.90-6.35	6.30
मार्च	4, 2023	5.20-6.25	5.72
मार्च	6, 2023	4.00-6.40	6.30
मार्च	8, 2023	5.30-6.50	6.35
मार्च	9, 2023	4.80-6.47	6.35
मार्च	10, 2023	4.80-6.40	6.31
मार्च	13, 2023	4.85-6.65	6.34
मार्च	14, 2023	4.85-6.65	6.32
मार्च	15, 2023	4.85-6.42	6.34
मार्च	16, 2023	4.90-6.68	6.52
मार्च	17, 2023	4.80-6.80	6.63
मार्च	18, 2023	5.30-6.30	5.74
मार्च	20, 2023	4.60-7.00	6.67
मार्च	21, 2023	4.85-6.90	6.65
मार्च	23, 2023	4.60-7.00	6.61
मार्च	24, 2023	4.60-6.90	6.54
मार्च	27, 2023	4.60-6.80	6.63
मार्च	28, 2023	4.60-8.25	6.68
मार्च	29, 2023	4.60-8.25	6.75
मार्च	31, 2023	5.50-8.10	7.34
अप्रैल	3, 2023	4.60-6.40	6.31
अप्रैल	5, 2023	4.60-6.35	6.26
अप्रैल	6, 2023	4.00-6.70	6.39
अप्रैल	10, 2023	4.60-6.40	6.32
अप्रैल	11, 2023	4.60-6.40	6.31
अप्रैल	12, 2023	4.60-6.40	6.31
अप्रैल	13, 2023	4.60-6.50	6.35
अप्रैल	15, 2023	6.50-6.35	6.15

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2022	2023			
	मार्च 25	फर. 10	फर. 24	मार्च 10	मार्च 24
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	181171.43	269679.45	280336.78	290353.28	304521.02
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	34878.78	19835.23	32563.25	45368.65	40358.05
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.82-5.49	7.07-7.35	7.09-8.04	7.28-8.05	7.07-7.80

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2022	2023			
	मार्च 31	फर. 15	फर. 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	352292.55	368908.25	364530.10	371326.70	353688.25
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	71015.75	43347.15	58975.35	65488.90	61469.10
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.79-12.17	6.70-16.31	6.77-12.51	6.92-10.78	6.88-12.67

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2022	2023					
		अप्रै. 1	फर. 24	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24	मार्च 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	19325	29916	24643	19474	23249	23713	23318
2 नोटिस मुद्रा	2122	632	278	4980	921	5462	240	1044
3 मीयादी मुद्रा	515	235	482	813	509	892	219	602
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	703445	760332	697488	536485	664412	514966	673254
5 बाजार रिपो	383844	456559	618929	607475	506628	671157	563292	740470
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	57	1064	2140	3003	6049	2289	2854
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	113833	80089	89330	87882	103027	99542	125368
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	41344	62050	56269	39473	86730	64094	79541
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	8567	6700	7118	9031	7106	13892	15014
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	5923	2664	5061	5255	5462	4121	5710
10.2 182-दिवसीय	3440	6494	4854	3737	5977	8096	5365	6554
10.3 364-दिवसीय	3530	8515	1905	3970	3881	5512	1831	7835
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	70844	78173	76155	63617	112905	89303	114655
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	1300	46	131	921	386	585	7197

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-मार्च)		2022-23 (अप्रै-मार्च)*		मार्च 2022		मार्च 2023*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**164**	**138894**	**237**	**45266**	**16**	**1054**	**37**	**3065**
1ए प्रीमियम	154	136893	154	136893	218	42408	15	983	34	2825
1.1 पब्लिक	121	112567	121	112567	164	38515	10	175	23	996
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	119	111314	161	37158	10	142	23	922
1.2 राइट्स	43	26327	43	26327	73	6751	6	879	14	2069
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	35	25580	57	5250	5	841	11	1903
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**28**	**11589**	**34**	**9221**	**1**	**178**	**3**	**485**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	28	11589	34	9221	1	178	3	485
3.1.1 पब्लिक	28	11589	28	11589	34	9221	1	178	3	485
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**192**	**150484**	**271**	**54487**	**17**	**1231**	**40**	**3550**
4.1 पब्लिक	149	124157	149	124157	198	47736	11	353	26	1481
4.2 राइट्स	43	26327	43	26327	73	6751	6	879	14	2069

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2022-23	2022			2023		
			मार्च	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3616261	339850	285413	313927	293041	305610	340411
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	450427	44574	34887	38068	35780	36995	41368
1.1 तेल	₹ करोड़	781711	74769	66154	68779	63017	64688	68347
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	97396	9806	8086	8341	7694	7831	8306
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2834550	265081	219259	245148	230024	240921	272064
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	353031	34767	26801	29728	28086	29164	33062
2 आयात	₹ करोड़	5733945	481031	465922	504831	427747	439144	493840
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	714041	63091	56951	61218	52228	53160	60013
2.1 तेल	₹ करोड़	1682475	161219	133505	159545	130040	139479	148300
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	209418	21145	16319	19347	15878	16884	18022
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4051470	319812	332417	345287	297707	299665	345540
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	504623	41946	40633	41871	36350	36275	41991
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-2117684	-141181	-180509	-190904	-134706	-133534	-153429
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-263613	-18517	-22064	-23150	-16448	-16165	-18645
3.1 तेल	₹ करोड़	-900764	-86450	-67351	-90765	-67023	-74791	-79953
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-112022	-11339	-8233	-11007	-8184	-9054	-9716
3.2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1216920	-54730	-113158	-100139	-67683	-58744	-73476
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-151592	-7178	-13832	-12143	-8264	-7111	-8929

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2022	2023					
		अप्रै. 29	मार्च 24	मार्च 31	अप्रै. 7	अप्रै. 14	अप्रै. 21	अप्रै. 28
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**करोड ₹**	**4568295**	**4773649**	**4754265**	**4789256**	**4800370**	**4797026**	**4818457**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**597728**	**578778**	**578449**	**584755**	**586412**	**584248**	**588780**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4072243	4204245	4189132	4213256	4229121	4224244	4251387
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	532823	509728	509691	514431	516635	514489	519485
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	317972	375117	371500	382447	377986	378926	373648
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	41604	45480	45200	46696	46175	46151	45657
	मात्रा (मैट्रिक टन)	761.35	794.63	794.63	794.63	794.63	794.63	794.63
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13657	13667	13667	13667	13667	13667	13667
	करोड ₹	139857	151923	151164	151107	150716	151329	151122
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	18299	18419	18392	18450	18412	18431	18466
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	38222	42364	42468	42446	42546	42526	42300
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5001	5151	5165	5178	5190	5176	5172

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2022	2023		2021-22	2022-23
		मार्च	फर.	मार्च	अप्रै.-मार्च	अप्रै.-मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**139022**	**135542**	**137883**	**3234**	**7995**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	16918	18402	19343	-3555	2425
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	100801	94135	95448	3332	2136
1.3 एनआरओ	21303	21303	23005	23092	3456	3433

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2022	2023	
		अप्रै-मार्च	अप्रै-मार्च	मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**38587**	**28014**	**3052**	**1838**	**366**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**56231**	**41622**	**5145**	**2975**	**1116**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**84835**	**70970**	**7155**	**4787**	**4534**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	59684	47424	4676	2932	2464
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	1698	692	60	1	9
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	42932	37097	4226	2113	1901
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	14143	8245	307	736	471
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	910	1390	82	82	82
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	19347	19354	1743	1743	1743
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	5805	4192	736	112	327
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**28605**	**29348**	**2009**	**1812**	**3418**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	27189	27093	1726	1758	3251
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	1416	2255	284	53	166
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**17644**	**13608**	**2093**	**1138**	**751**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	10061	8709	1054	790	698
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	3379	4082	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	7604	4694	1130	374	431
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	3400	3877	372	308	660
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**-16777**	**-5489**	**-4993**	**-426**	**1463**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	-14071	-5407	-4684	-681	1617
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	2706	82	309	-254	154
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**21809**	**22525**	**-1941**	**1411**	**1828**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2022	2023		
		मार्च	जन.	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1968.77**	**2728.17**	**2101.38**	**2956.76**
1.1 जमाराशियां	830.05	182.61	73.14	61.16	194.16
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	16.35	14.98	16.10	33.01
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	746.57	104.51	160.05	132.15	232.86
1.4 उपहार	2336.29	276.19	223.22	245.31	452.95
1.5 दान	16.55	0.65	0.66	0.80	1.08
1.6 यात्रा	6909.04	776.64	1493.17	1070.71	1149.85
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	391.02	342.47	323.43	630.10
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	4.21	6.27	3.93	5.15
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	202.25	395.87	229.34	228.49
1.10 अन्य	153.88	14.33	18.34	18.45	29.11

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2021-22	2022-23	2022	2023	
			अप्रैल	फरवरी	अप्रैल
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.13	91.27	93.12	89.54	89.17
1.2 रीर	104.64	102.78	103.66	100.17	98.37
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.55	93.03	94.72	91.41	91.25
2.2 रीर	103.46	101.04	102.32	98.21	96.45
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	87.03	85.98	87.59	83.38	83.02
1.2 रीर	102.27	102.02	103.22	98.86	98.77
2 आधार : 2020-21 =100					
2.1 नीर	98.39	97.20	99.03	94.27	93.86
2.2 रीर	100.42	100.18	101.35	97.08	96.98

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(अमेरिकी मिलियन डॉलर)

मद	2021-22	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	115	69	134
1.2 राशि	28851	3938	644	3466
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	2	0	1
2.2 राशि	11035	1104	0	374
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	117	69	135
3.2 राशि	39886	5042	644	3840
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	5.90	5.20	5.60
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लाइबोर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	1.23	1.53	1.81
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-11.50	0.01-10.50	0.50-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	680	160	678
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	2987	156	1985
ए) परिवहन	1597	36	37	174
बी) ऊर्जा	8215	1150	111	10
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	0	0	1
डी) संचार	1258	750	1	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	0	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	1051	0	800
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	0	7	1000
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	53	66	31
IV. अन्य संस्थाएं	609	9	0	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	9	9	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	600	0	0	0
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	1216	216	1125
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	5621	1118	0	574
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	93	27	0	74
सी) एनबीफसी - अन्य (एनजीओ)	2282	71	216	477
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	341	97	46	21

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**427124**	**426659**	**465**	**404167**	**393098**	**11069**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**205567**	**227734**	**-22167**	**227491**	**245734**	**-18243**
1.1 पण्य	**108927**	**168677**	**-59750**	**105609**	**178328**	**-72720**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**96640**	**59057**	**37583**	**121883**	**67406**	**54477**
1.2.1 सेवाएं	67016	39207	27809	83422	44702	38719
1.2.1.1 यात्रा	2599	4335	-1735	8123	6910	1213
1.2.1.2 परिवहन	8948	10037	-1089	8758	9409	-651
1.2.1.3 बीमा	844	644	200	783	797	-13
1.2.1.4 जीएनआईई	223	264	-41	185	282	-97
1.2.1.5 विविध	54402	23927	30475	65572	27304	38268
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	31740	3384	28356	37599	4058	33541
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	15312	13722	1590	21198	15125	6073
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1354	1535	-181	1949	1292	657
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	801	276	524	842	329	514
1.2.2 अंतरण	23528	2216	21312	30867	2400	28467
1.2.2.1 आधिकारिक	132	267	-135	58	232	-174
1.2.2.2 निजी	23396	1949	21447	30809	2168	28641
1.2.3 आय	6096	17634	-11538	7594	20304	-12710
1.2.3.1 निवेश आय	4449	16839	-12391	5878	19437	-13559
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1647	794	853	1716	867	850
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**221424**	**198925**	**22500**	**176675**	**146497**	**30178**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**147690**	**148973**	**-1283**	**95253**	**88553**	**6700**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19608	15050	4559	17002	14913	2089
2.1.1.1 भारत में	19032	10192	8840	16107	8796	7311
2.1.1.1.1 इक्विटी	12259	9936	2324	10246	7932	2315
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5072		5072	5067		5067
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1701	257	1444	794	865	-71
2.1.1.2 विदेश में	576	4857	-4281	895	6117	-5222
2.1.1.2.1 इक्विटी	576	2573	-1997	895	3563	-2668
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	845	-845	0	1079	-1079
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1439	-1439	0	1475	-1475
2.1.2 संविभाग निवेश	128082	133924	-5842	78251	73641	4611
2.1.2.1 भारत में	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
2.1.2.1.1 एफआईआई	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	115423	119516	-4093	71477	65940	5537
2.1.2.1.1.2 ऋण	12086	12697	-611	5956	6976	-1020
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	573	1711	-1138	818	724	93
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**29433**	**19410**	**10023**	**25903**	**24110**	**1793**
2.2.1 बाह्य सहायता	2692	1399	1293	3088	1584	1504
2.2.1.1 भारत द्वारा	13	16	-3	8	22	-14
2.2.1.2 भारत को	2680	1383	1297	3080	1562	1518
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6111	6365	-254	4629	7089	-2460
2.2.2.1 भारत द्वारा	352	241	111	439	316	123
2.2.2.2 भारत को	5759	6124	-365	4190	6773	-2583
2.2.3 भारत को अल्पावधि	20629	11645	8984	18186	15437	2749
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	12003	11645	357	17744	15437	2307
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	8626	0	8626	442	0	442
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**25913**	**17707**	**8206**	**36230**	**21795**	**14435**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	25913	17501	8412	36230	21649	14580
2.3.1.1 आस्तियां	11213	6154	5058	18145	6135	12009
2.3.1.2 देयताएं	14700	11346	3353	18085	15514	2571
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	12141	10809	1332	16928	14359	2569
2.3.2 अन्य	0	206	-206	0	145	-145
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	0	0	0	0	1	-1
2.5 अन्य पूंजी	18389	12835	5554	19289	12038	7251
3 भूल-चूक	**132**	0	**132**	0	**866**	**-866**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**465**	**-465**	0	**11069**	**-11069**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वृद्धि -/ कमी +)		465	-465	0	11069	-11069

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3200360**	**3196873**	**3487**	**3322449**	**3231457**	**90992**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1540277**	**1706367**	**-166090**	**1870090**	**2020055**	**-149965**
1.1 पण्य	**816171**	**1263865**	**-447694**	**868155**	**1465946**	**-597791**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**724106**	**442502**	**281604**	**1001935**	**554109**	**447826**
1.2.1 सेवाएं	502141	293771	208370	685767	367473	318293
1.2.1.1 यात्रा	19476	32478	-13002	66776	56807	9970
1.2.1.2 परिवहन	67048	75208	-8160	71994	77348	-5354
1.2.1.3 बीमा	6327	4826	1501	6438	6548	-110
1.2.1.4 जीएनआईई	1668	1976	-309	1520	2317	-797
1.2.1.5 विविध	407623	179283	228340	539038	224454	314584
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	237819	25352	212467	309080	33356	275723
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	114730	102817	11913	174257	124338	49919
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	10149	11503	-1354	16021	10624	5397
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	6000	2071	3929	6924	2701	4223
1.2.2 अंतरण	176292	16607	159685	253741	19726	234014
1.2.2.1 आधिकारिक	991	2002	-1011	478	1907	-1429
1.2.2.2 निजी	175301	14605	160696	253262	17819	235443
1.2.3 आय	45673	132125	-86452	62427	166910	-104482
1.2.3.1 निवेश आय	33333	126174	-92841	48318	159784	-111466
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12340	5951	6389	14109	7126	6984
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1659091**	**1490505**	**168586**	**1452359**	**1204279**	**248080**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**1106614**	**1116227**	**-9613**	**783028**	**727953**	**55075**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	146921	112764	34157	139765	122591	17174
2.1.1.1 भारत में	142606	76370	66235	132411	72310	60101
2.1.1.1.1 इक्विटी	91856	74446	17411	84230	65203	19027
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	38004	0	38004	41657	0	41657
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	12745	1925	10821	6524	7107	-583
2.1.1.2 विदेश में	4315	36393	-32078	7353	50281	-42928
2.1.1.2.1 इक्विटी	4315	19279	-14964	7353	29287	-21934
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	6329	-6329	0	8871	-8871
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	10786	-10786	0	12123	-12123
2.1.2 संविभाग निवेश	959694	1003463	-43770	643263	605362	37901
2.1.2.1 भारत में	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
2.1.2.1.1 एफआईआई	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	864845	895510	-30665	587580	542060	45520
2.1.2.1.1.2 ऋण	90555	95135	-4580	48959	57346	-8387
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	4293	12818	-8525	6723	5955	768
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**220533**	**145432**	**75101**	**212938**	**198199**	**14739**
2.2.1 बाह्य सहायता	20174	10483	9690	25384	13021	12363
2.2.1.1 भारत द्वारा	95	120	-26	63	180	-117
2.2.1.2 भारत को	20079	10363	9716	25321	12841	12480
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	45789	47692	-1902	38055	58276	-20221
2.2.2.1 भारत द्वारा	2638	1806	833	3608	2599	1010
2.2.2.2 भारत को	43151	45886	-2735	34447	55677	-21231
2.2.3 भारत को अल्पावधि	154570	87257	67313	149499	126902	22597
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	89934	87257	2677	145866	126902	18964
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	64636	0	64636	3633	0	3633
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**194158**	**132675**	**61483**	**297825**	**179162**	**118663**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	194158	131130	63028	297825	177967	119858
2.3.1.1 आस्तियां	84016	46113	37902	149160	50436	98724
2.3.1.2 देयताएं	110142	85016	25126	148665	127531	21135
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	90969	80991	9978	139159	118040	21119
2.3.2 अन्य	0	1546	-1546	0	1195	-1195
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	0	0	0	0	4	-4
2.5 अन्य पूंजी	137786	96171	41615	158568	98961	59607
3 भूल-चूक	**992**	0	**992**	0	**7123**	**-7123**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**3487**	**-3487**	0	**90992**	**-90992**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	3487	-3487	0	90992	-90992

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**205556**	**227712**	**-22156**	**227486**	**245714**	**-18227**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**175944**	**207884**	**-31940**	**189030**	**223030**	**-34000**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**108927**	**168677**	**-59750**	**105609**	**178328**	**-72720**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	108811	154622	-45811	105247	170206	-64959
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	116	0	116	362	0	362
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		14055	-14055		8123	-8123
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**67016**	**39207**	**27809**	**83422**	**44702**	**38719**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	129	17	112	553	108	446
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	68	394	-326	55	255	-200
1.अ.ख.3 परिवहन	8948	10037	-1089	8758	9409	-651
1.अ.ख.4 यात्रा	2599	4335	-1735	8123	6910	1213
1.अ.ख.5 निर्माण	750	592	158	1129	573	556
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	844	644	200	783	797	-13
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1354	1535	-181	1949	1292	657
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	238	2363	-2125	318	3435	-3116
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	32638	3813	28825	38538	4590	33947
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	15312	13722	1590	21198	15125	6073
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	834	1205	-371	997	1155	-158
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	223	264	-41	185	282	-97
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	3079	286	2793	835	770	65
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**6096**	**17634**	**-11538**	**7594**	**20304**	**-12710**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1647	794	853	1716	867	850
1.आ.2 निवेश आय	3067	16552	-13485	3746	18994	-15249
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1750	11634	-9884	1784	11461	-9677
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	88	1941	-1853	69	2853	-2784
1.आ.2.3 अन्य निवेश	82	2975	-2892	146	4579	-4433
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1147	2	1144	1746	101	1645
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1382	287	1094	2132	443	1689
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**23516**	**2194**	**21322**	**30862**	**2379**	**28483**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	23396	1949	21447	30809	2168	28641
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	22443	1359	21084	29973	1548	28425
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	953	590	363	836	619	216
1.इ.2 सामान्य सरकार	121	245	-125	53	212	-158
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**227**	**430**	**-202**	**127**	**188**	**-62**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	94	166	-71	23	37	-14
2.2 पूँजी अंतरण	133	264	-131	104	151	-47
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**221209**	**198982**	**22226**	**176553**	**157398**	**19155**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**19608**	**15050**	**4559**	**17002**	**14913**	**2089**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19032	10192	8840	16107	8796	7311
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17331	9936	7396	15314	7932	7382
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	12259	9936	2324	10246	7932	2315
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5072		5072	5067		5067
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1701	257	1444	794	865	-71
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1701	257	1444	794	865	-71
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	576	4857	-4281	895	6117	-5222
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	576	3418	-2842	895	4642	-3747
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	576	2573	-1997	895	3563	-2668
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		845	-845		1079	-1079
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1439	-1439	0	1475	-1475
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1439	-1439		1475	-1475
3.2 संविभाग निवेश	**128082**	**133924**	**-5842**	**78251**	**73641**	**4611**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	115423	119516	-4093	71477	65940	5537
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12086	12697	-611	5956	6976	-1020
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	573	1711	-1138	818	724	93
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (आरक्षित निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**4851**	**6752**	**-1902**	**5509**	**5955**	**-446**
3.4 अन्य निवेश	**68668**	**42792**	**25876**	**75792**	**51821**	**23971**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	12141	11015	1125	16928	14505	2424
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	206	-206	0	145	-145
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	12141	10809	1332	16928	14359	2569
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	22575	14456	8120	27018	15963	11055
3.4.3अ भारत को ऋण	22211	14199	8012	26572	15625	10947
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	365	257	108	447	338	109
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	70	89	-19	30	38	-8
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	20629	11645	8984	18186	15437	2749
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	13253	5586	7667	13628	5878	7751
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**465**	**-465**	0	**11069**	**-11069**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	465	-465	0	11069	-11069
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**221209**	**198982**	**22226**	**176553**	**157398**	**19155**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	138824	141421	-2597	94043	85231	8811
4.2 ऋण लिखत	69132	51510	17622	68882	55220	13662
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	13253	6051	7202	13628	16947	-3318
5. निवल भूल-चूक	**132**		**132**		**866**	**-866**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1540189**	**1706202**	**-166013**	**1870049**	**2019887**	**-149838**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1318312**	**1557635**	**-239324**	**1553922**	**1833419**	**-279497**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**816171**	**1263865**	**-447694**	**868155**	**1465946**	**-597791**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	815302	1158554	-343253	865182	1399175	-533992
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	869	0	869	2973	0	2973
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	105311	-105311	0	66771	-66771
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**502141**	**293771**	**208370**	**685767**	**367473**	**318293**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	967	127	839	4547	885	3663
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	506	2950	-2444	451	2097	-1646
1.अ.ख.3 परिवहन	67048	75208	-8160	71994	77348	-5354
1.अ.ख.4 यात्रा	19476	32478	-13002	66776	56807	9970
1.अ.ख.5 निर्माण	5621	4437	1183	9284	4710	4575
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6327	4826	1501	6438	6548	-110
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	10149	11503	-1354	16021	10624	5397
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1784	17709	-15926	2616	28234	-25618
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	244549	28566	215983	316797	37734	279063
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	114730	102817	11913	174257	124338	49919
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	6250	9030	-2780	8199	9498	-1299
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1668	1976	-309	1520	2317	-797
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	23068	2142	20925	6865	6334	531
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**45673**	**132125**	**-86452**	**62427**	**166910**	**-104482**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12340	5951	6389	14109	7126	6984
1.आ.2 निवेश आय	22980	124021	-101040	30791	156142	-125352
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	13111	87172	-74062	14664	94217	-79553
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	661	14541	-13881	569	23452	-22883
1.आ.2.3 अन्य निवेश	617	22289	-21672	1203	37645	-36442
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	8592	18	8574	14355	829	13527
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	10353	2153	8199	17527	3641	13886
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**176205**	**16442**	**159763**	**253700**	**19559**	**234141**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	175301	14605	160696	253262	17819	235443
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	168163	10186	157977	246394	12727	233667
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	7138	4419	2719	6868	5092	1776
1.इ.2 सामान्य सरकार	903	1837	-933	438	1740	-1302
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1704**	**3220**	**-1516**	**1043**	**1549**	**-506**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	707	1241	-535	190	307	-117
2.2 पूँजी अंतरण	998	1979	-981	852	1242	-390
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1657474**	**1490938**	**166537**	**1451356**	**1293890**	**157467**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**146921**	**112764**	**34157**	**139765**	**122591**	**17174**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	142606	76370	66235	132411	72310	60101
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	129860	74446	55415	125887	65203	60684
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	91856	74446	17411	84230	65203	19027
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	38004	0	38004	41657	0	41657
3.1.अ.2 ऋण लिखत	12745	1925	10821	6524	7107	-583
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	12745	1925	10821	6524	7107	-583
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4315	36393	-32078	7353	50281	-42928
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4315	25608	-21293	7353	38158	-30805
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4315	19279	-14964	7353	29287	-21934
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	6329	-6329	0	8871	-8871
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	10786	-10786	0	12123	-12123
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	10786	-10786	0	12123	-12123
3.2 संविभाग निवेश	**959694**	**1003463**	**-43770**	**643263**	**605362**	**37901**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	864845	895510	-30665	587580	542060	45520
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	90555	95135	-4580	48959	57346	-8387
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	4293	12818	-8525	6723	5955	768
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**36345**	**50593**	**-14248**	**45283**	**48951**	**-3668**
3.4 अन्य निवेश	**514515**	**320631**	**193885**	**623046**	**425994**	**197052**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	90969	82537	8432	139159	119235	19924
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	1546	-1546	0	1195	-1195
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	90969	80991	9978	139159	118040	21119
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	169152	108314	60838	222105	131224	90881
3.4.3अ भारत को ऋण	166419	106388	60031	218433	128445	89988
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2733	1926	807	3671	2779	893
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	522	668	-146	250	315	-65
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	154570	87257	67313	149499	126902	22597
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	99302	41855	57447	112033	48318	63715
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**3487**	**-3487**	**0**	**90992**	**-90992**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	3487	-3487	0	90992	-90992
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1657474**	**1490938**	**166537**	**1451356**	**1293890**	**157467**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1040181	1059643	-19462	773077	700643	72434
4.2 ऋण लिखत	517992	385953	132039	566247	453937	112310
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	99302	45342	53960	112033	139310	-27277
5. निवल भूल-चूक	**992**	**0**	**992**	**0**	**7123**	**-7123**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021		2022			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश में/ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521632	208096	514112	217335	510150	222557	510719
1.1 इक्विटी पूंजी*	132765	493987	130904	487895	136255	481972	140002	482118
1.2 अन्य पूंजी	78807	27645	77192	26217	81080	28178	82554	28601
2 पोर्टफोलियो निवेश	10642	270484	9716	284708	10983	245793	10890	245679
2.1 इक्विटी	1110	156381	6113	172794	6312	137013	8624	140469
2.2 कर्ज	9533	114103	3603	111914	4671	108779	2266	105209
3. अन्य निवेश	90974	486635	76447	481692	85917	477453	79570	493790
3.1 व्यापार ऋण	18561	118147	12849	113439	24675	123520	26125	126252
3.2 ऋण	10474	195290	8856	194917	8084	188463	8628	194842
3.3 मुद्रा और जमाराशि	42081	140994	34796	143502	33528	135621	27093	136132
3.4 अन्य आस्तियां/ देयताएं	19858	32203	19946	29833	19630	29850	17723	36564
4 आरक्षित निधियां	607309		633614		532664		562721	
5 कुल आस्ति/ देयताएं	920498	1278751	927873	1280511	846899	1233395	875737	1250187
6 निवल आईआईपी (आस्ति-देयताएं)	-358253		-352638		-386496		-374451	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित अर्जन शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2022-23	2022	2023		वि.व 2021-22	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	41.44	3.25	3.51	3.66	258797336	20588727	22281370	22458408
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	15.00	1.04	1.27	1.25	172251292	13682354	14888685	14269424
1.1.1 आउटराईट	7.99	0.46	0.68	0.65	10090700	660443	895740	952079
1.1.2 रेपो	4.07	0.30	0.38	0.40	68032487	5341282	6436404	6682508
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.94	0.27	0.21	0.20	94128105	7680629	7556541	6634836
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	25.16	2.11	2.11	2.28	78932050	6232193	6602897	7329087
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.27	0.11	0.13	0.13	7613994	674180	789788	859897
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2425.62	230.04	200.50	248.01	149946286	14458955	12053579	16122902
1.1 ग्राहक लेनदेन	2411.19	228.68	199.35	246.66	131667176	13069669	10566198	14416322
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.43	1.36	1.14	1.35	18279111	1389286	1487381	1706580
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	983694.78	66517.82	88613.03	100851.12	55012192	5062466	4650034	5906936
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	5.90	0.56	0.31	0.36	356	35	22	24
2.2 एपीबीएस $	17898.09	1400.66	2584.03	1932.07	247580	15565	35514	26400
2.3 आईएमपीएस	56532.64	4920.01	4478.13	4970.56	5585441	462279	468647	546235
2.4 एनएसीएच जमा $	19267.00	1825.88	1527.38	1962.73	1544342	131428	134032	178757
2.5 एनईएफटी	52847.43	4314.20	4675.61	5469.06	33719541	3492578	2775972	3750569
2.6 यूपीआई @	837143.73	54056.51	75347.57	86516.34	13914932	960582	1235847	1404951
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.21	0.91	1.51	1.50	197	12	17	18
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	15343.22	1136.67	1360.85	1403.39	1289393	98645	115315	126113
3.1 भीम आधार पे @	214.22	19.47	11.50	12.92	6791	640	454	492
3.2 एनएसीएच नामे $	13502.69	979.27	1210.19	1246.53	1280001	97801	114630	125376
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1626.31	137.93	139.16	143.94	2601	204	231	246
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63331.67	5512.70	4588.51	5003.95	2152016	171159	168378	190626
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	29145.25	2237.51	2323.20	2634.29	1432255	107107	118684	137311
4.1.1 पीओएस आधारित $	15598.70	1134.33	1255.88	1404.60	541944	38777	44611	50920
4.1.2 अन्य $	13546.54	1103.18	1067.32	1229.69	890311	68330	74073	86391
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	34186.42	3275.19	2265.31	2369.66	719760	64052	49693	53315
4.2.1 पीओएस आधारित $	22893.88	2078.45	1581.95	1628.85	476161	40770	33432	34691
4.2.2 अन्य $	11292.54	1196.73	683.36	740.82	243599	23282	16261	18624
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	74667.44	6469.96	6050.89	6225.98	287111	25615	22399	22988
5.1 वालेट	59112.76	5016.86	4929.04	5036.24	221896	20054	18356	18801
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15554.69	1453.10	1121.85	1189.74	65215	5561	4043	4188
5.2.1 पीओएस आधारित $	1013.09	164.77	63.07	64.17	14777	2860	792	825
5.2.2 अन्य $	14541.60	1288.34	1058.78	1125.57	50438	2701	3251	3363
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	7087.81	702.93	538.79	642.40	7162537	694335	554113	701109
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	7087.81	702.93	538.79	642.40	7162537	694335	554113	701109
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1144124.92	80340.08	101152.07	114126.84	65903249	6052221	5510239	6947772
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1146550.54	80570.12	101352.56	114374.85	215849535	20511176	17563818	23070674
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1139462.73	79867.19	100813.78	113732.45	208686998	19816841	17009704	22369565

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2022-23	2022	2023		वि. व. 2022-23	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	904589.17	57121.32	82667.18	92896.30	23341498	1648626	2068090	2401075
1.1 अंतबैंक $	62306.62	4218.03	5107.77	5868.83	4191430	298559	353815	436885
1.2 अंतर-बैंक $	842282.55	52903.29	77559.40	87027.47	19150068	1350067	1714274	1964190
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	42630.64	3924.86	3319.04	3879.51	91539296	8850603	7380904	8981727
2.1 अंतबैंक @	10703.78	962.84	834.55	987.21	53506133	5341587	4172937	4769894
2.2 अंतर-बैंक @	31926.86	2962.02	2484.49	2892.30	38033163	3509016	3207966	4211833
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	69456.67	5966.82	5471.86	5914.54	3304574	287373	263673	286347
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	88.28	6.80	7.39	8.18	4291	344	358	396
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	68963.07	5927.87	5433.00	5871.80	3286320	285893	262090	284540
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	405.32	32.15	31.47	34.56	13963	1137	1225	1411
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	27.80	2.30	2.18	2.33	284	22	22	24
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	27.47	2.21	2.17	2.32	282	21	22	23
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.33	0.09	0.01	0.02	2	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	12375.16	1032.68	918.44	1083.61	333966	28479	25483	30015
5.1 एईपीएस @	12375.16	1032.68	918.44	1083.61	333966	28479	25483	30015

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2023 तक	2022	2023	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10465.62	9912.93	10374.87	10465.62
1.1 क्रेडिट कार्ड	853.03	736.27	833.66	853.03
1.2 डेबिट कार्ड	9612.59	9176.66	9541.22	9612.59
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16185.26	15553.69	16109.65	16185.26
2.1 वालेट @	13384.68	12787.93	13335.10	13384.68
2.2 कार्ड @	2800.58	2765.76	2774.55	2800.58
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.59	2.52	2.57	2.59
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.23	2.20	2.21	2.23
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.36	0.31	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	16.11	9.16	15.59	16.11
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	77.90	60.70	77.58	77.90
6 भारत क्यूआर @	61.42	49.72	52.22	61.42
7 यूपीआई क्यूआर *	2563.77	1727.34	2500.89	2563.77

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: दिसंबर 2021 से शामिल सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक शृंखला

सं. 44: अल्प बचत

(₹ करोड़)

योजना		2021-22	2021	2022		
			जून	अप्रै.	मई	जून
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**203175**	**18523**	**13348**	**13031**	**15622**
	बकाया	**1463777**	**1299066**	**1477127**	**1490164**	**1505765**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**144749**	**13852**	**10328**	**9612**	**12260**
	बकाया	**1012241**	**897008**	**1022569**	**1032182**	**1044441**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17581	1943	1924	81	2808
	बकाया	188433	172973	190357	190438	193247
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	23748	1365	2125	1642	1611
	बकाया	58783	38569	60907	62550	64161
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-1524	-29	-39	-39	-29
	बकाया	1894	3360	1856	1817	1787
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-352	-4	-4	-3	-2
	बकाया	-177	167	-181	-184	-186
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	14441	1389	478	747	810
	बकाया	235820	224414	236298	237045	237855
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	22281	2298	1361	1522	1727
	बकाया	119333	102008	120694	122216	123943
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	43725	4546	3117	3713	3199
	बकाया	251282	217390	254399	258112	261310
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	118282	110643	119088	120377	121273
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8008	7616	8092	8185	8242
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6918	7164	6889	6869	6858
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	118074	91967	120330	122681	124937
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	24840	2344	1272	1948	2136
	बकाया	156869	138131	158141	160089	162225
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	7	0	0	0	0
	बकाया	-19	-25	-19	-19	-19
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	2	0	0	0	0
	बकाया	23	21	23	23	23
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	..	..	94	1	0
	बकाया	..	..	94	95	95
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**45307**	**4408**	**2615**	**3111**	**3145**
	बकाया	**333189**	**296108**	**335806**	**338922**	**342047**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19696	2057	812	1028	1057
	बकाया	155043	139709	155856	156884	157941
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-16	0	0	0	0
	बकाया	143	159	142	142	142
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-1115	-208	-178	-190	-308
	बकाया	-7891	-7314	-8069	-8258	-8566
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	26619	2559	1981	2273	2396
	बकाया	174560	153387	176541	178814	181210
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	92	0	0	0	0
	बकाया	-22	-114	-22	-22	-22
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	31	0	0	0	0
	बकाया	-44	-74	-44	-44	-44
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	11400	10355	11402	11406	11386
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13119**	**263**	**405**	**308**	**217**
	बकाया	**118347**	**105950**	**118752**	**119060**	**119277**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियों से घटाने पर प्राप्त सकल भुगतान
स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**8439811**	**8529036**	**8784931**	**9098788**	**9373372**
1. वाणिज्यिक बैंक	35.40	35.93	36.16	36.44	36.13
2. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.27	0.29	0.33	0.38	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	25.74	25.89	26.34	25.94	26.14
4. म्यूच्युअल फंड	3.08	2.91	2.32	2.58	2.87
5. सहकारी बैंक	1.82	1.81	1.84	1.80	1.70
6. वित्तीय संस्थाएं	1.69	0.94	1.09	0.98	1.07
7. कॉरपोरेट	1.37	1.47	1.52	1.58	1.57
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.66	1.56	1.43	1.38	1.31
9. भविष्य निधियां	4.33	4.60	4.77	4.66	4.67
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	16.92	16.62	16.06	15.28	14.73
11. अन्य	7.73	7.97	8.18	8.98	9.37
11.1 राज्य सरकार	1.69	1.82	1.84	1.83	1.88

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**4257578**	**4410250**	**4472011**	**4589128**	**4712902**
1. वाणिज्यिक बैंक	34.41	34.39	34.22	34.37	34.34
2. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.40	0.38	0.41	0.36	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	28.85	28.42	28.39	27.71	27.42
4. म्यूच्युअल फंड	1.91	1.82	1.89	2.08	2.02
5. सहकारी बैंक	4.07	4.04	4.06	3.89	3.80
6. वित्तीय संस्थाएं	1.73	1.72	1.73	1.71	1.77
7. कॉरपोरेट	1.70	1.82	1.98	1.85	1.94
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	20.66	20.79	20.52	20.18	20.31
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.83	0.80	0.79	0.79	0.75
11. अन्य	5.40	5.81	5.99	7.05	7.19
11.1 राज्य सरकार	0.19	0.20	0.21	0.21	0.24

खज़ाना बिल

श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**692869**	**757198**	**1022053**	**920205**	**839931**
1. वाणिज्यिक बैंक	47.01	49.04	51.37	50.91	49.15
2. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.53	4.20	2.49	2.12	2.17
3. बीमाकृत कंपनियां	6.29	6.58	5.34	5.46	5.81
4. म्यूच्युअल फंड	13.72	14.01	14.86	11.98	14.23
5. सहकारी बैंक	1.49	1.79	1.34	1.48	1.27
6. वित्तीय संस्थाएं	2.36	3.53	3.73	4.17	4.52
7. कॉरपोरेट	3.13	3.47	4.27	3.86	3.59
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.72	0.49	0.40	0.53	0.50
9. भविष्य निधियां	0.85	0.21	1.70	3.21	1.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.89	16.69	14.50	16.27	17.39
11.1 राज्य सरकार	18.92	11.54	10.99	12.27	13.38

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7453320**	**8008684**
1.1 गतिविधियां	2635110	2882758	3074492	3823423	4489442	4761567
1.1.1 राजस्व	2029044	2224367	2446605	3150221	3444624	3536719
1.1.2 पूंजी	519356	596774	588233	550358	963856	1144725
1.1.3 ऋण	86710	61617	39654	122844	80962	80123
1.2 गैर गतिविधियां	1812455	2078276	2253027	2442941	2864084	3140466
1.2.1 राजस्व	1741432	1965907	2109629	2271637	2653832	2928102
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	814757	894520	955801	1060602	1244104	1408929
1.2.2 पूंजी	69370	111029	141457	169155	178038	209892
1.2.3 ऋण	1654	1340	1941	2148	32214	2472
1.3 अन्य	68381	79713	83368	86995	99794	106652
2. कुल प्राप्तियां	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7193029**	**7944834**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3376416	3797731	3851563	3688030	4894050	5497245
2.1.1 कर प्राप्तियां	2978134	3278947	3231582	3193390	4026487	4551271
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1853859	2030050	2012578	2076013	2608666	2904479
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1121189	1246083	1216203	1114805	1414088	1642678
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3086	2814	2800	2572	3732	4115
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	398282	518783	619981	494640	867564	945974
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	34224	36273	31137	33448	40481	46552
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	142433	140287	110094	64994	117937	90824
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	42213	44667	59515	16951	33188	19835
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	100219	95621	50578	48044	84748	70989
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2441333**	**2420614**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	144792	387091	571872	890012	627255	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-144847	325987	190241	107493	350911	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	844375	710119	868676	1640143	1794332	2401363
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	794856	795845	971378	1696012	1377060	1808401
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	71222	88961	209232	458801	565522	398870
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	42351	51004	38280	41273	45133	44731
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	18423	-18298	10411	4545	-1675	5824
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	25138	66289	-14227	25682	32945	34029
3ख.1.6 नकद शेष	-12476	17395	-323279	-43802	260291	63850
3ख.1.7 अन्य	49653	96014	548753	347643	142310	45659
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*26.4*	*26.7*	*27.0*	*32.1*	*31.5*	*31.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*26.5*	*26.6*	*28.6*	*32.3*	*30.4*	*30.8*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.8*	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.7*	*21.3*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.4*	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.0*	*17.6*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*10.3*	*9.4*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2023 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	393.39	20	1711.47	16	1301.75	8
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	1936.70	4	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	332.52	9	248.19	4	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	814.47	17	178.58	6
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	70.62	4	1182.93	4	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	204.97	26	88.80	18
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	59.81	8	-	-
19	नगालैंड	-	-	119.99	4	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	861.39	17	-	-	-	-
23	राजस्थान	5530.23	27	516.87	6	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	581.17	24	1422.24	21	895.23	12
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	217.32	5	166.28	4	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियां: 1. राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ का लाभ समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) शेष और सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य निवेशों के संपार्श्विक पर लिया जाता है।
2. डब्ल्यूएमए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को अस्थायी नकदी बेमेल को पूरा करने के लिए अग्रिम है।
3. ओडी राज्य सरकारों को उनकी डब्ल्यूएमए सीमा से परे अग्रिम दिया जाता है।
4. प्राप्त किया गया औसत: कुल सहायता (एसडीएफ/ डब्ल्यूएमए/ ओडी) को दिनों की संख्या से विभाजन करने पर प्राप्त मान है जिसके लिए महीने के दौरान सहायता बढ़ाई गई थी।
5. - : शून्य।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मार्च 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10143	996	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2260	4	0	100
3	असम	5150	78	0	0
4	बिहार	8164	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6447	-	1	4008
6	गोवा	833	401	0	0
7	गुजरात	9790	585	0	0
8	हरियाणा	1787	1486	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	0	0
11	झारखंड	1053	-	0	0
12	कर्नाटक	14217	313	0	24491
13	केरल	2613	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1119	0	0
15	महाराष्ट्र	58404	1230	0	2000
16	मणिपुर	61	123	0	0
17	मेघालय	1032	82	8	0
18	मिज़ोरम	372	66	0	0
19	नगालैंड	1562	41	0	0
20	उड़ीसा	15914	1789	103	16493
21	पुदुचेरी	473	-	0	1100
22	पंजाब	6437	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	7900
24	तमिलनाडु	8173	-	18	2396
25	तेलंगाना	6915	1512	0	0
26	त्रिपुरा	982	21	0	425
27	उत्तराखंड	4305	177	0	0
28	उत्तर प्रदेश	5756	-	116	0
29	पश्चिम बंगाल	11186	816	239	0
	कुल	**184029**	**10839**	**613**	**58913**

टिप्पणियां: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						जनवरी		फरवरी		मार्च			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	40498	46443	36103	3000	1834	3557	1807	5618	4452	57478	45814
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	-	-	-	-	-	-100	559	389
3	असम	15030	14230	12753	10753	800	800	2400	2400	1000	305	17100	16105
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	-	-1300	6000	5500	5800	2345	36800	27467
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-2000	-	-	2000	-287	2000	-2287
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	300	150	-	-	-	-200	1350	500
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	2500	1000	5000	4000	9500	9500	43000	28300
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	2500	1360	6000	4660	8658	4198	45158	28638
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	1500	1500	1300	1011	3200	2990	14000	11941
10	जम्मू और कश्मीर	9328	6020	8562	5373	700	200	500	500	1728	964	8473	5969
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	-	-	1000	-	-	-1655	4000	-155
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	4000	4000	-	-1000	-	-1000	36000	26000
13	केरल	28566	23066	27000	18120	4103	1603	2000	1000	7800	5567	30839	15620
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	-	-2000	13000	11000	15158	8349	40158	26849
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	5000	4063	-	-3375	22000	18375	72000	42815
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	150	150	200	200	200	200	1422	1147
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	-	-80	-	-	-	-68	1753	1356
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	100	100	100	100	125	54	1315	1129
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	193	193	248	248	91	-114	1854	1199
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-500	-	-1500	-	-1000	-	-7500
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	-	-302	500	500	-	-	1200	698
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	500	-	4200	3700	8900	7414	45500	33660
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	1500	500	4000	3826	11306	6615	46057	30110
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	-	-	437	437	100	76	1414	1320
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	10000	8000	9000	6600	19000	17119	87000	65722
26	तेलंगाना	43784	38782	45716	39256	3500	2666	3500	2250	5150	3424	40150	30922
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-	-	-	-	-330	-	-645
28	उत्तराखंड	75500	59185	62500	42355	7000	7000	12500	12500	22112	20084	55612	41797
29	उत्तरप्रदेश	6200	5208	3200	1800	500	500	750	-350	1450	1450	3200	1450
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	4000	3200	1000	500	21000	18300	63000	42500
	कुल	798816	651777	701626	492483	51846	32637	77192	56514	171896	127026	758392	518829

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**238613.6**	**476724.8**	**386450.4**	**530769.8**	**1632558.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*9.8*	*7.5*	*10.3*	*8.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**398076.7**	**567753.2**	**517351.0**	**924069.3**	**2407250.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.1*	*11.7*	*10.1*	*18.0*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	12239.0	296625.6	124015.7	451698.3	884578.5
(ए) बैंक जमाराशि	-10550.9	278124.4	116211.9	444044.6	827830.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	2742.9	8649.0	49545.2	-1962.1	58975.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117873.1	108209.1	110373.8	37714.2	374170.2
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	104681.1	98426.3	103356.1	193739.0	500202.5
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटी	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	57038.5	46514.1	69053.6	91117.2	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**159463.1**	**91028.5**	**130900.6**	**393299.5**	**774691.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.6*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	159429.6	90994.9	130867.1	393266.0	774557.6
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	140261.4	58074.4	114905.9	196581.1	509822.8
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**600422.5**	**573643.2**	**481433.5**	**719844.5**	**2375343.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.5*	*12.1*	*8.8*	*12.5*	*12.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**805869.5**	**612224.3**	**651241.3**	**1092617.4**	**3161952.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.8*	*13.0*	*12.0*	*19.0*	*16.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297412.4	278631.7	158172.2	525550.7	1259767.1
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	527056.7	1219909.2
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	55325.8	63575.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	123291.4	142365.7	156438.6	141120.0	563215.8
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	119666.9	110916.6	108512.2	207604.5	546700.1
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	55760.7	70924.2	67947.4	86862.2	281494.6
II. वित्तीय देयताएँ	**205447.0**	**38581.1**	**169807.8**	**372772.9**	**786608.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.5*	*4.0*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	205490.3	38624.3	169851.0	372816.9	786782.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	284732.6	648626.4
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	88084.4	138156.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**519781.2**	**358325.2**	**453302.7**	**636259.8**	**1967668.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.1*	*6.4*	*7.2*	*9.6*	*8.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**382780.7**	**547346.2**	**834009.6**	**796341.7**	**2560478.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.5*	*9.7*	*13.2*	*12.0*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-84377.1	202652.1	425821.4	151374.9	695471.4
(ए) बैंक जमाराशि	-106507.3	197301.2	422819.5	140297.2	653910.7
i. वाणिज्यिक बैंक	-108037.7	195617.4	418642.9	145510.5	651733.1
ii. सहकारी बैंक	1530.4	1683.8	4176.7	-5213.3	2177.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9	3001.9	11077.7	41560.7
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0	103154.9	95681.7	440810.4
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	126469.7	108777.0	91543.9	254877.2	581667.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50980.8	227976.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	71423.1	93829.6	79877.9	95524.7	340655.3
II. वित्तीय देयताएँ	**-137000.5**	**189021.0**	**380706.9**	**160081.8**	**592809.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.7*	*3.4*	*6.0*	*2.4*	*2.5*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	-137021.8	188999.7	380685.6	160060.6	592724.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-113662.5	134166.1	320160.2	153323.3	493987.0
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	-108061.2	135728.8	317452.5	152364.2	497484.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7	60525.5	6737.3	98737.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1	29479.8	-31016.3	-3774.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	317.4	4045.2
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-50.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन को घटाकर उनकी वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को दर्शाती है।
2. लघु बचत और पीपीएफ में संशोधन मुख्य रूप से लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के मासिक डेटा से प्राप्त तिमाही आंकड़ों के कारण होता है।
3. 2021-22 के लिए बैंक जमा में संशोधन का श्रेय बीएसआर-2 के अनुसार कुल जमा में हाउसहोल्ड की कम हिस्सेदारी को दिया जाता है।
4. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनंतिम अनुमानों के आधार पर की गई है।
5. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16315506.3**	**16632816.5**	**17010694.5**	**17180616.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*84.7*	*85.4*	*86.2*	*85.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8858293.4	9136417.9	9252629.8	9696674.3
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	726750.2	735399.2	784944.4	782982.3
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6370092.6**	**6461087.5**	**6591954.6**	**6985220.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.1*	*33.2*	*33.4*	*34.8*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5148115.0	5206189.4	5321095.3	5517676.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	478956.2	479656.9	506946.6	501074.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**18039169.4**	**18606364.4**	**19333484.1**	**20168953.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*94.9*	*98.6*	*100.8*	*101.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9977865.6	10242430.9	10389526.9	10916583.6
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	846557.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7772003.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.6*	*39.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5728735.3	5741948.3	5881570.2	6166302.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	542221.2
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605700.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20508115.7**	**21057343.4**	**21673261.7**	**22104312.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*95.9*	*95.0*	*93.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	10810076.3	11007377.6	11430197.1	11570494.3
i. वाणिज्यिक बैंक	9961988.0	10157605.4	10576248.3	10721758.8
ii. सहकारी बैंक	848088.3	849772.1	853948.8	848735.5
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1	5175997.5	5287980.3
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1	2737059.4	2883904.4
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5	2126112.0	2152140.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7634981.2**	**7823980.9**	**8204666.6**	**8364727.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.3*	*35.6*	*36.0*	*35.3*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6052640.2	6186806.3	6506966.5	6660289.7
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5514625.2	5650354.1	5967806.6	6120170.8
ii. सहकारी बैंक	536604.9	535027.3	537720.1	538664.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6	1697700.1	1704437.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7	813759.5	782743.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अनंतिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2020-21 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
- बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
- जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2022-23 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2022-23 से लिया गया है।

डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डेटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2023	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 43, सं. 1, 2022	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 2, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. नगरपालिका वित्त संबंधी रिपोर्ट	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियांः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) ।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेशः

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाने चाहिए:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार विभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश-ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां कहीं भी रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण spsdepr@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए या डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

   ए. एनईएफटी हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित विवरण अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर-डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।